उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश काल और उसके बाद हुए उच्च शिक्षा के विकास का एक तुलनात्मक अध्ययन

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की पी-एच०डी०

(शिक्षा शास्त्र) उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

2000

शोध निर्देशक :

डा० एच० डी० श्रीवास्तव

रीडर – शिक्षा संकाय

दयानन्द वैदिक स्नातकोत्तर

महाविद्यालय, उरई (जालौन) उ०प्र०

शोधकर्ता :

मुजीब अहमद

एम०ए०, एम०एड०

आभार-स्वीकृति

उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस शोध प्रबन्ध के सृजन में अनेक विद्वानों, शिक्षाविदों तथा विषय विशेषज्ञों ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में प्रेरणा तथा सहयोग देकर मेरे इस कार्य को अभिसिंचित किया है। ऐसे व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता तथा आभार अभिव्यक्ति आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य रूप से मेरा परम कर्तव्य है ।

सर्वप्रथम मै अपने शोध प्रबन्ध **"उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश काल और उसके बाद हुए उच्च शिक्षा के विकास का एक तुलनात्मक अध्ययन"** के सुयोग्य निर्देशक डॉ0 एच0 डी0 श्रीवास्तव, रीडर, शिक्षा संकाय, डी0 वी0 कालेज, उरई, का चिर ऋणी रहूँगा। मैं अपनी वाणी से उनके सहयोग को प्रदर्शित नहीं कर सकता। आपकी प्रेरणा, विशद ज्ञान तथा विषय विशेषज्ञ के रूप में मार्गदर्शन के कारण ही यह शोधकार्य पूर्ण हो सका, यदि आपका इस दिशा में सहयोग प्राप्त न होता तो मैं किंचित मात्र भी इस कार्य को पूर्ण करने में समर्थ न होता। मै अन्तर्मन से अपने सुयोग्य तथा सहृदयी निर्देशक के प्रति कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ, जिन्होनें अपना अमूल्य समय मुझे प्रदान किया तथा पग-पग पर मेरा पथ प्रर्दशन किया।

मै डॉ0 श्रीमती शारदा श्रीवास्तव, अध्यक्ष, शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, डी0 वी0 कालेज, उरई का आजीवन आभारी रहूँगा, जिनकी महान कृपा दृष्टि एवं सफल प्रयासों से इस अल्पज्ञ का प्रस्तुत शोध कार्य पूर्ण हो सका है।

मै डॉ0 एम0 एस0 सिसोदिया, अध्यक्ष, भूगोल विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दतिया के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ जिनकी प्रेरणा तथा सहयोग से मेरे शोधकार्य को यह स्वरूप प्राप्त हो सका तथा पूर्णता की ओर अग्रसर हो सका।

मैं अपने विद्यालयी साथी डा0 श्रीमती सुनीता सिसोदिया, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, जवाहर नवोदय विद्यालय, बीकर दतिया के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होनें हिन्दी भाषा के परिमार्जन में विशेष रूप से सहयोग प्रदान किया।

अन्त में मैं शिक्षा जगत से जुड़े सभी अधिकारियों अपने सभी स्नेही भाइयों व मित्रों का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होनें इस शोध कार्य को पूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान किया है।

शोधकर्ता

मुजीब अहमद

घोषणा - पत्र

मैं घोषित करता हूँ कि प्रस्तुत शोध ग्रन्थ **"उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश काल और उसके बाद हुए उच्च शिक्षा के विकास का एक तुलनात्मक अध्ययन"** जो कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी में पी- एच0 डी0 उपाधि हेतु प्रस्तुत किया गया है, मेरा मौलिक कार्य है तथा उसे इससे पूर्व कहीं अन्यत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

शोधकर्ता

(मुजीब अहमद)

डा0 एच0 डी0 श्रीवास्तव

अनुशासन अधिकारी
रीडर, शिक्षक शिक्षा विभाग
डी० वी० कालेज, उरई

☎ 52992

आवास—
५०, हजारीपुरा
उरई (जालौन)- २८५००१

प्रमाण - पत्र

मै प्रमाणित करता हूँ कि श्री मुजीब अहमद ने **“उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश काल और उसके बाद हुए उच्च शिक्षा के विकास का एक तुलनात्मक अध्ययन”** विषय पर बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी के शोध अध्यादेश में उल्लिखित निर्धारित अवधि तक उपस्थित रहकर मेरे निर्देशन में कठिन परिश्रम के साथ शोध कार्य पूर्ण किया है। शोध ग्रन्थ की विषय सामिग्री पूर्णतः मौलिक है। यह बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के पी-एच0डी0 के सभी उपबन्धों की पूर्ति करता है । मै संस्तुति करता हूँ कि यह इस योग्य है कि मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाये ।

(डा0 एच0 डी0 श्रीवास्तव)

अनुक्रमणिका

अध्याय पृष्ठ संख्या

प्रथम अध्याय

द्वितीय अध्याय

तृतीय अध्याय

चतुर्थ अध्याय

पंचम अध्याय

षष्टम अध्याय

सप्तम अध्याय

परिशिष्ट

TABLES

Table No.	Topics	Page No.

प्रथम अध्याय

"उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश काल और उसके बाद हुए उच्च शिक्षा के विकास का एक तुलनात्मक अध्ययन"

"A Comparative Study of Higher Education in Uttar Pradesh During British Period and after that"

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना

शिक्षा ही मानव जीवन को श्रेष्ठतम मार्ग प्रशस्त करने का एक माध्यम एवं गहन प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को जब हम उच्चतम दृष्टिकोण से जानने, समझने, एवं मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं तो पाते है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात ही मनुष्य अपने व्यवसाय या उद्योग का सफलतम मार्ग चयन करने में एवं सामाजिक समायोजन स्थापित करने में सफल हो पाता है क्योंकि किसी भी देश की प्रगति का प्रमुख तथा महत्वपूर्ण आधार उच्च शिक्षा ही है। उच्च शिक्षा ही मानव को अपने मूल्यों को प्राप्त करने का एक साधन है जिससे देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों को निभाने एवं भावी जीवन को सुदृढ़ मार्ग दर्शन प्रदान करने का कार्य कर सकता है तभी शिक्षा का सही मूल्यांकन किया जा सकता है और देश का सर्वागीण विकास सम्भव हो सकता है।

उच्च शिक्षा का मापन जब हम विश्व दृष्टिकोण से करते है तो देखते है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ ही लोगों के विचारों, उनके परिवेशों, रहन सहन के स्तर तथा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक प्रगति के आधार एवं मानव की संस्कृति में भी परिवर्तन आ जाता है. उच्च शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के सम्पूर्ण क्षेत्रों में नये नये ढंगों और तरीकों, सिद्धान्तों एवं प्रगति के आधारों, उन्नतिशील आयामों को अपनाकर स्वयं के विकास के साथ-साथ राष्ट्र का भी सर्वांगीण उत्थान करने का प्रयास करते है।

उच्च शिक्षा, शिक्षा की अन्तिम सीढ़ी है और इसके बाद कोई शिक्षा शेष नहीं रह जाती। उच्च शिक्षा के बाद ही व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक रूप में प्रवेश करता है। उच्च शिक्षा ही जीवन के विकास को एक आधार प्रदान करती है। यह माना जाता है कि माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त ही उच्च शिक्षा का प्रारम्भ होता है जिसका आयोजन महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में किया जाता है इस दृष्टिकोण से उच्च शिक्षा के अर्न्तगत उन सभी संस्थाओं को रखा जा सकता है जिसका कार्यक्रम माध्यमिक स्तर से अधिक विकसित है। उच्च शिक्षा का जो स्वरूप आज हमारे

सामने है उसमें उच्चता का तात्पर्य माध्यमिक स्तर से ऊपर की शिक्षा से ही होता है। उच्च शिक्षा की परिकल्पना भारतीय शिक्षा परम्परा में पर्याप्त प्राचीन है। नालन्दा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र आदि विश्वविद्यालयों की एतिहासिकता साक्ष्याधारित है परन्तु आधुनिक उच्च शिक्षा का स्वरूप काफी अर्वाचीन है जिसका प्रारम्भ 18 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से माना जा सकता है। पिछली दो शताब्दियों में उच्च शिक्षा के स्वरूप में अनेक परिवर्तन हुये फिर भी उसके मूलभूत प्रतिमान में कोई अन्तर नहीं आया।

उच्च शिक्षा का महत्व अपने आप में अत्याधिक है क्योंकि उच्च शिक्षा पर ही सम्पूर्ण देश एवं विश्व का विकास निर्भर करता है। उच्च शिक्षा ही एक राष्ट्र को योग्य अध्यापक, चिकित्सक, वैज्ञानिक, इन्जीनियर, एवं अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले उच्च प्रतिभा से सम्पन्न व्यक्ति प्रदान करती है। किसी देश में शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है इस बात की जानकारी उच्च शिक्षा से लगायी जा सकती है उच्च शिक्षा देश के विकास को एक आधार एवं गति प्रदान करती है। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा का महत्व अत्याधिक बढ़ गया है क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग माना जाता है और प्रत्येक तथ्य को वैज्ञानिक आधार पर सत्य प्रमाणित कर लेने के बाद ही स्वीकार किया जाता है।

वर्तमान समय में भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अत्याधिक विकास हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में नये विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्रों की व्यवस्था की गयी है। संस्थाओं में वृद्धि के साथ ही साथ विद्यार्थियों की संख्या में असीमित रूप से विस्तार हुआ है। विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुये सभी साधनों में वृद्धि की गयी है परन्तु इतनी सब व्यवस्था होते हुये भी उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट आयी है। विद्यार्थी जिस स्तर की शिक्षा प्राप्त करता है उसके अनुकूल उसके ज्ञान में वृद्धि नहीं हो पाती है यदि इस आधार पर देखा जाये तो उच्च शिक्षा की स्थिति सोचनीय नजर आती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त प्रगति हुई यह प्रगति भारत की बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में संतुलित नहीं है। आज पर्याप्त विश्वविद्यालय खुलने पर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि होने पर भी इच्छुक छात्रों को सुगमता से अपनी रूचि के अनुसार पाठ्यक्रम प्रवेश नहीं मिलता है।

वर्तमान समय में उच्च शिक्षा यद्यपि व्यक्तिगत मूलभूत अधिकार है लेकिन वर्तमान समय के और आने वाले वर्षो में विज्ञान और तकनीकी बदलाव से युक्त समाज में सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा जीवन की सत्त चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रकार वर्तमान समाज के दोषों और कमियों के इलाज के रूप में शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिये। शिक्षा में विभिन्न उद्देश्यों के साथ, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक वातावरण के साथ तालमेल होना चाहिये, इस प्रकार व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को शिक्षा द्वारा ही पूरा किया जा सकता है।

वर्तमान समय की विभिन्न आवश्यकताओं में शिक्षा के समक्ष रोजगार का ज्वलन्त प्रश्न है। वर्तमान समय में पूर्णरूप से स्पष्ट हो गया है कि पुरातन जीवन पद्धति तथा शिक्षा पद्धति में बदलाव की आवश्यकता है। इस प्रकार वर्तमान समय के शैक्षिक अवसरों का विभाजन व्यक्तिगत और सामाजिक परिप्रेक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। हमारे देश में उच्च शिक्षा के स्तर पर अपव्यय की समस्या अत्यन्त गम्भीर है। औपचारिक शिक्षा की बदलती हुई कीमतें जिसमें भवन, शिक्षकों व प्रबन्धों के वेतन पर अधिक धन व्यय करना पड़ता है। जिससे छात्र एवं अभिभावकों के समय एवं धन की बर्बादी होती है।

नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की तुलना में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सभी योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा से वंचित रह जाना पड़ता है। विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यलयों में प्रत्येक प्रवेशार्थी को प्रवेश नहीं मिल पाता है। अधिकाधिक स्नातक एवं उत्तर स्नातक नागरिक तैयार करने से देश का कल्याण होने की सम्भावना नहीं है। इस स्तर पर उन्हीं छात्रों को प्रवेश मिलना चाहिये जो अच्छा एवं उच्च शैक्षिक स्तर, उच्च शिक्षा के प्रति गहरी रूचि एवं क्षमता रखते हो। विश्वविद्यालय शिक्षा शोध एवं अनुसंधान का क्षेत्र है जिसे प्रत्येक विद्यार्थी नहीं कर पाता है अतः इस स्तर पर योग्यतम छात्रों को प्रवेश दिया जाना आवश्यक है। इस स्थिति में अयोग्य छात्र प्रवेश पा जाते है और योग्य छात्र जो इस शिक्षा को पाने के अधिकारी है प्रवेश से वंचित रह जाते है।

आज देश की वर्तमान प्रचालित शिक्षा पद्धति योग्यता एवं गुणों का मूल्यांकन कम करती है अपितु पुस्तकीय ज्ञान की परीक्षा करती है। शिक्षा के उद्देश्यों से दूर यह शिक्षा पद्धति मनुष्य का नहीं कुछ उपाधि युक्त लोगों का निर्माण कर रही है। जाकिर हुसैन के अनुसार, " प्रचालित शिक्षा प्रणाली न तो वर्तमान परिस्थितियों का हल करती है और न उसका कोई रचनात्मक तथा जीवनदायक महत्व ही है। "

अंग्रेजो द्वारा निर्मित शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिये समय-समय पर प्रयत्न किये जाते रहे है। गाँधी जी द्वारा प्रस्तावित वर्धा शिक्षण योजना, मुदालियर, कोठरी, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, सम्पूर्णानन्द आदि की अध्यक्षता में बने आयोगों और समितियों ने शिक्षा में व्यापक परिर्वतन लाने के सुझाव प्रस्तुत किये लेकिन इनके विचारों और सुझावों पर आश्वश्यकता के अनुरूप अमल नहीं किया गया।

समस्या चयन

वर्तमान उच्च शिक्षा विभिन्न समस्याओं जैसे छात्रों के प्रवेश की समस्या, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र अशांति, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार की समस्या, शिक्षकों की समस्या आदि से ग्रस्त है। उच्च शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये यह नितांत आवश्यक है कि उसके अतीत के स्वरूप का अध्ययन किया जाये। किसी भी शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थी और अध्यापक महत्वपूर्ण अंग है। ब्रिटिश काल में और उसके बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन दोनों की ही संख्या में अमूलभूत परिर्वतन हुआ है इनके कारणों को जानना भी जरूरी है। वर्तमान उच्च शिक्षा का निर्धारण करने के लिये ब्रिटिश कालीन उच्च शिक्षा का सहारा लेना पड़ता है यद्यपि, दोनों ही कालों की उच्च शिक्षा की परिस्थितियों एवं संसाधनों में पर्याप्त अन्तर है। ब्रिटिश कालीन उच्च शिक्षा के विभिन्न आयोगों एवं समितियों की रिर्पोटों के आधार पर स्वतंत्रता के बाद के विभिन्न आयोगों एवं समितियों की रिर्पोटों के आधार पर तुलना करने पर उच्च शिक्षा के विकास की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

विषय के विस्तार को देखते हुये शोधकर्ता ने अपने शोध के लिये सम्पूर्ण भारतवर्ष को कार्यक्षेत्र न बनाते हुये केवल एक प्रान्त की उच्च शिक्षा को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाया है

इस कारण शोधकर्ता ने शोध के लिये निम्नलिखिल समस्या चुनीः-

"उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश काल और उसके बाद हुये उच्च शिक्षा के विकास का एक तुलनात्मक अध्ययन"

अध्ययन की आवश्यकता

किसी राष्ट्र के जीवन में उच्च शिक्षा का बड़ा महत्व होता हैः उच्च शिक्षा में शिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही राष्ट्र की उस जनशक्ति की पूर्ति होती है जो ऐसे सभी कार्य करने में सक्षम होती है जिनके लिये सूक्ष्म विवेक व बुद्धि तथा उच्च कोटि के कौशल की आवश्यकता होती है। राष्ट्र की उत्पादन शक्ति, सैनिक शक्ति और उच्चतम साहित्य और संस्कृति के निर्माण की पूर्ति भी उच्च शिक्षा द्वारा ही सम्भव होती है।

उच्च शिक्षा का इतना अधिक महत्व होते हुये भी इसकी स्थिति ठीक नहीं है। वह अनेक समस्याओं में उलझा हुई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्यों के सम्बन्ध में विवाद बहुत समय से चला आ रहा है। एक ओर वे लोग है जो उच्च शिक्षा को जीवन के सत्य और शास्वत मूल्यों से सम्बन्ध रखना चाहते है। उनकी दृष्टि में शिक्षा शिक्षा के लिये होनी चाहिये। व्यकितत्व का विकास ही उसका चरम लक्ष्य है। जीवन की भौतिक उपयोगिताओं एवं यथार्थ से उच्च शिक्षा का उनकी दृष्टि में कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। दूसरी ओर वे लोग है जो उच्च शिक्षा को या यों कहा जायें कि सम्पूर्ण शिक्षा को जीवन की वास्तविकता और यथार्थता से सम्बन्ध रखना चाहते है, उनकी दृष्टि में उच्च शिक्षा केवल शिक्षा के लिये ही नहीं, केवल व्यकितत्व के चरम विकास के लिये हीं नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्यों को लेकर चलनी चाहिये, दूसरे शब्दों में उच्च शिक्षा का जीवन के उद्योग धन्धों और रोजगारों से गहरा सम्बन्ध होना चाहिये।

उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में भी अनेक विवाद है बहुधा यह सुनने में आता है कि सामान्य रूप से शिक्षा का जिसमें उच्च शिक्षा भी सम्मिलित है जीवन से सम्बन्ध नहीं है। वह जीवन की आवश्यकता से सन्दर्भ में अप्रसांगिक है। उसमें बहुत सा ऐसा तत्व है जो आधुनिक नहीं है। उसका मूल आधार अब भी गुलामी के समय में निर्धारित संकल्पनाओं पर निर्भर है। अभी हाल में उच्च शिक्षा की प्रथम डिग्री को अधिक व्यापक पाठ्यक्रम पर आधारित करने का प्रयास विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग द्वारा किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत कुछ फाउन्डेशन कोर्स होगा, कुछ डिसिप्लिन परक होगा कुछ व्यवहारिक एवं कार्योन्मुख होगा और कुछ विस्तार सेवा और समाज सेवा से सम्बन्धित होगा। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के इन चार स्तम्भों पर आधारित पाठ्यक्रम के विभिन्न पक्ष अत्यन्त विवाद ग्रस्त है।

शिक्षण विधियों के क्षेत्र में एक निष्क्रियता सी व्याप्त है और तीन शिक्षक विधियां विशेष रूप से प्रयोग में लायी जाती है – व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक से शिक्षा देने की विधि और नोट्स लिखाने की विधि। इस प्रकार की स्थिति भी विदेशी शासन की देन है और जीवन से असम्बद्धता इसका मूल कारण है। उत्तम शिक्षण विधि की कसौटी वह है जो युवकों में अपना भावी जीवन विवेकपूर्ण तरीके से चुनने की क्षमता उत्पन्न करें।

शिक्षकों की समस्या अलग ही है। सरकारी नियंत्रण बढ़ने के साथ साथ शिक्षकों में दायित्वहीनता बढ़ती जा रही है और परिणामतः शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है।

उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों का नितान्त आभाव है। विभिन्न विषयों में संदर्भ ग्रन्थ प्रायः शून्य है। इसी से सम्वद्ध प्रश्न भाषा के विकास का भी है। यह बारम्बार निर्णय लिया जा चुका है कि प्रारम्भिक शिक्षा मातृ भाषा द्वारा ही दी जायेगी किन्तु फिर भी कुछ लोग इस विसंगति में पड़े हुये है कि उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिये। अंग्रेजी के प्रति मोह भी पुरानी गुलामी का द्योतक है। यह बात समझने में कठिनाई न होनी चाहिये कि जब प्रारम्भिक शिक्षा मातृ भाषा द्वारा दी जायेगी तो ऊपर की कक्षाओं में किसी अन्य भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता। अंग्रेजी के पक्ष में तर्क अन्तर्विश्वविद्यालयी ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान के आधार पर दिया जाता है। इस समस्या का समाधान अंग्रेजी का प्रयोग नहीं है बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि तकनीकी शब्दावली भारतीय भाषाओं को आधार मानकर एक कर ली जाये और सामान्य आदान प्रदान के लिये हिन्दी का प्रयोग किया जाये। अर्न्तराष्ट्रीय ज्ञान–विज्ञान के आदान प्रदान के लिये न्यूनतम अंग्रेजी फ्रेंच, जर्मन, जापानी, रूसी आदि भाषायें सीखी जायें। मातृ भाषा के रूप में नहीं बल्कि एक विदेशी भाषा के रूप में और वह भी अत्यन्त सीमित अर्थो और क्षेत्रों में।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा की प्रणाली भी गम्भीर विवाद का विषय है। बाह्य और आन्तरिक द्वन्द्व का प्रश्न बहुत पुराना है। अनुचित साधनों का प्रयोग एक व्यापक समस्या है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा सम्बन्धी सुधार के लिये अनेक प्रयास किये है। जैसे आन्तरिक मूल्यांकन पर आधारित सिमेस्टर सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, प्रश्न बैंक आदि। इन सभी प्रयासों की उपयोगिता अत्यन्त विवाद ग्रस्त है।

तीन प्रश्न और भी ऐसे है जिनके कारण उच्च शिक्षा की जटिलता बढ़ती जा रही है, पहला तो यह है कि उच्च शिक्षा सबके लिये सुलभ बनायी जाये या कुछ सीमित लोगो को ही। और उतने ही लोग उच्च शिक्षा में शिक्षित किये जायें जितने लोगों और जितने प्रकार के लोगों की आवश्यकता हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सन् 1978 में जो पालिसी फ्रेम प्रस्तुत किया है उसमें इस बात की विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है और यह बताया गया है कि किस प्रकार विश्वविद्यालय पर सरकार का दबाब कम हो सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग फ्रेम का उद्धरण निम्नवत् है:

The policy to be adopted in this regard should, therefore, consist of the following -

(1) Adoption of measure which will reduce pressures on the university system such as effective vocationalisation at the secondary stage, delinking most of the Jobs from degrees, and changing the present recruitment policies which virtually make a degree a minimum qualification for any good job.

(2) Exercising great restraint in the establishment of new institutions, which should not be set up (except in backward areas) unless their need is clearly established on sound academic considerations and adequate resources in terms of men, mate rial and money are available.

(3) Planning the location of new institutions very carefully and rationlising that of the existing ones to the extent possible.

(4) Adopting a policy of selective admissions to full time institutions of higher educa

tion at first degree and post graduate levels on the basis of merit with reservation of at least half the seats for all weaker sections.

(5) Enabling talented but economically weaker students to pursue their studies on a whole time basis by ensuring to them the full cost of their education through appro priate bursaries for which funds may be raised from public and private bodies.

(6) Providing facilities for expension of higher education through channels of non-formal education such as correspondence courses.

(7) Opening Board and University examination to private condidates to encourage self - study.

दूसरा प्रश्न उच्च संस्थाओं के प्रांगण में अंसतोष एवं अशांति से सम्बन्धित है। तीसरा प्रश्न विश्वविद्यालय के प्रशासन से सम्बन्धित है। उपयुर्क्त से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का आभास मिलता है। इन समस्याओं का सही समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक उच्च शिक्षा के उदगम और विकास के क्रम को सही रूप से न समझ लिया जाये। शोधकर्ता ने इस दृष्टि से प्रस्तुत विषय के अध्ययन की आवश्यकता का अनुभव किया साथ ही यह भी अनुभव किया कि समस्याओं का सही निदान और उपचार भी बिना ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के ज्ञात करना सम्भव नहीं है। तीसरी आवश्यकता इसलिये भी प्रतीत होती है कि उच्च शिक्षा के विकास के क्रम को अभी तक सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत नही किया गया है।

शोधकर्ता का यह प्रयास होगा कि उच्च शिक्षा के विकास के क्रम को और उनकी विविध समस्याओं को सही दृष्टिकोण से समझा जाये और शोध के आधार पर तत्सम्बन्धी समस्याओं के निदान और उपचार प्रस्तुत किये जाये।

शोधकर्ता की अपनी जानकारी में अभी तक इस प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। इसलिये प्रस्तुत विषय पर शोध अध्ययन और उच्च शिक्षा के विकास के संदर्भ का एक मौलिक और महत्वपूर्ण योगदान होगा।

अध्ययन के उद्देश्य

नवीन तथ्यों के द्वारा उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास के स्वरूप का अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य है, जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर दृष्टि पात करना शोधकर्ता का प्रथम प्रयास होगा।

1. उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुये विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
2. उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश कालीन उच्च शिक्षा के बाद से लेकर सन् 1991 तक हुये उच्च शिक्षा के विकास का वृहत अध्ययन करना।
3. ब्रिटिश काल में स्थापित विभिन्न आयोगों एवं समितियों का विस्तृत अध्ययन करना।
4. ब्रिटिश काल के पश्चात स्थापित विभिन्न आयोगों एवं समितियों का विस्तृत अध्ययन करना।
5. उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश कालीन में एवं ब्रिटिश काल के बाद हुये उच्च शिक्षा के विकास का तुलनात्मक अध्ययन करना।
6. ब्रिटिश कालीन उच्च शिक्षा के संदर्भ में वर्तमान उच्च शिक्षा का मूल्यांकन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पना

1. उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता उपरान्त उच्च शिक्षा का विकास आवश्यकतानुसार उचित दिशा में नहीं हुआ है।
2. उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का विकास गुणात्मक रूप से संतोषजनक नहीं है।

सीमांकन

उच्च शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जिसमें विद्यार्थी स्कूली शिक्षा समाप्त करने के पश्चात प्रवेश पाता है! स्कूली शिक्षा अपने देश में विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होती रही है। इस शताब्दी के प्रारम्भ में स्कूली शिक्षा से तात्पर्य मैट्रीकुलेशन से था जो वर्तमान हाईस्कूल के समकक्ष मानी जाती है। वर्तमान इण्टरमीडिएट कक्षाएं उच्च शिक्षा के अर्न्तगत आती थी और वे उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने

के लिये तैयारी की दृष्टि से मध्यस्थ कक्षाएं मानी जाती थी। सन् 1917 के सैडलर कमीशन या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की रिर्पोट के पश्चात इण्टरमीडिएट कक्षाऐ उच्च शिक्षा की कक्षाओं से अलग कर दी गयीं और इस प्रकार से स्कूली शिक्षा का अंग बन गयी। सन् 1953 में मुदालियर कमीशन की रिर्पोट के पश्चात स्कूली शिक्षा दस के बजाये ग्यारह वर्ष कर दी गयी। केवल उत्तर प्रदेश में वह बारह वर्ष की पूर्ववत रही। अन्य प्रदेशों में इण्टरमीडिएट का एंक वर्ष पी0यू0सी0 (प्री-यूनीवर्सिटी कोर्स) के नाम से उच्च शिक्षा से सम्बद्ध कर दिया गया और उसे तैयारी का एक वर्ष माना गया। इस प्रकार उच्च शिक्षा का प्रारम्भ ग्यारह वर्ष की स्कूली शिक्षा एक वर्ष पी0यू0सी0 के पश्चात होने लगा और उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कक्षाओं के बाद उच्च शिक्षा का प्रारम्भ स्वीकार कर लिया गया।

एक दूसरे अर्थ में उच्च शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा है जो विश्वविद्यालय के अर्न्तगत और उसके नियंत्रण में नियमित रूप से विभिन्न प्रकार के कालेज अथवा संस्थाओं में दी जाती है और जहाँ से विद्यार्थियों को प्रथम डिग्री अथवा उसके बाद की डिग्रियाँ प्राप्त होती है। कुछ विश्वविद्यालय विशेष विषयों में डिप्लोमा कोर्स भी चलाते है और डिग्री न होते हुये भी उच्च शिक्षा के अर्न्तगत आते है। इसके अन्तर्गत वे कोर्स और कक्षायें भी आती है जो मेडिकल, इंजीनियरिंग और टैक्नोलोजीकल कोर्स से सम्बन्धित होती है।

उच्च शिक्षा के अर्न्तगत निम्न प्रकार की संस्थायें मानी जा सकती है।

1. महाविद्यालय - स्नातकीय, स्नातकोत्तर, तथा विशिष्ट पाठ्यक्रमों से युक्त, अध्यापक प्रशिक्षण, विधि शिक्षा, कृषि शिक्षा आदि।
2. विश्वविद्यालय- सामान्य तथा विशिष्ट
3. विशिष्ट शिक्षा संस्थान
4. अनुसंधान केन्द्र

उच्च शिक्षा की प्रथम डिग्री की अवधि पहले दो वर्ष थी किन्तु इस समय सभी विश्वविद्यालयों में तीन वर्ष की अवधि कर दी गयी है। स्नाकोत्तर डिग्रियों का कोर्स सामान्यतः दो वर्ष का और शोध डिग्रियों के लिये 1,2 या उससे अधिक वर्षो का माना जाता है। प्रोफेशनल कोर्सो में

सामान्यतः 5 वर्ष प्रथम डिग्री में लगते है और स्नाकोत्तर डिग्री के लिये एक या उससे अधिक वर्ष। अध्ययन के शीर्षक में विकास से अर्थ गुणात्मक विकास से नहीं है बल्कि संख्यात्मक विकास से है जिसके अर्न्तगत छात्र संख्या, संस्थाओं की संख्या, अध्यापकों की संख्या को मुख्यतः ध्यान में रखा जायेगा।

द्वितीय अध्याय

द्वितीय अध्याय

सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा

मानव मस्तिष्क की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह अनुभवों को संचित कर आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्रयोग करने के लिये प्रस्तुत करता है। यदि इन अनुभवों को पुस्तक के रूप में लेखवद्ध कर दिया जाये तो अन्य लोग भी उससे लाभ• उठा सकते है। विषय से सम्बन्धित इन पुस्तकों को सम्बन्धित साहित्य की संज्ञा दी जाती है। वास्तव में समस्त मानव ज्ञान पुस्तकों तथा पुस्तकालयों में उपलब्ध हो सकता है। अन्य जीवधारियों से भिन्न जो प्रत्येक नई पीढ़ी के साथ पुनः पुनः नये सिरे से कार्य आरम्भ करते हैं मनुष्य अतीत के संचय एंव आलेखित ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का सृजन करता है।

इसी बात को जॉन डब्लयू बेस्ट ने अपने प्रभावशाली शब्दों में इस प्रकार कहा है:-

" Practically all human knowledge can be found in books and libraries. Unlike other animal that must start a new with each generation. Man builds upon the accumulated and recorded knowledge of the Past. His constant adding to the vast store of knowledge makes possible progress in all areas of human endeavour." [1]

सम्बन्धित साहित्य का अनुसंधान के क्षेत्र में अपना अलग ही स्थान हैं। जब तक यह पता न चल जाये कि अमुक क्षेत्र में कितना कार्य हुआ है या कौन सी विधि प्रयुक्त करके परिणाम निकाले गये है तब तक न तो समस्या का उचित रूप से निर्धारण ही किया जा सकता है और न ही उसकी रूपरेखा को आगे ही बढ़ाया जा सकता है। सम्बन्धित साहित्य जंजीर की लड़ियों के समान है जिस प्रकार जंजीर की प्रत्येक लड़ी महत्वपूर्ण होती है ठीक उसी प्रकार अनुसंधान हेतु प्रत्येक चरण महत्वपूर्ण होता है।

सम्बन्धित साहित्य सर्वेक्षण द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत समस्या के क्षेत्र में अनुसंधान की स्थिति क्या है तथा किसने कब कहाँ क्या और कैसे अनुसंधान कार्य किया है।

---

1. Best, John, W. - Research in Education.
   Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1959, P. 31

इसके ज्ञान द्वारा अपने अध्ययन की योजना बनाना सुविधाजनक हो जाता है। सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण इस बात का भी आभास देता है कि चयन किया गया अनुसंधान कार्य किस सीमा तक सफल हो सकेगा और प्राप्त निष्कर्षो की उपयोगिता क्या होगी।

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से हमारा तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोषो, पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबन्धों एंव अभिलेखों आदि से है जिनके अध्ययन से अनुसंधान कर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रुपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के बिना अनुसंधानकर्ता का कार्य अंधे में तीर के समान होगा। इसके आभाव में उचित दिशा में वह एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक उसे यह ज्ञात न हो कि अमुक क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है और उसके निष्कर्ष क्या आये है। इस प्रकार शेक्षिक अनुसंधान के प्रत्येक क्षेत्र में सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण आवश्यक एवं उपयोगी होता है। सम्बन्धित साहित्य अनुसंधान सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं के समाधान में सहायता करके भावी शोध कार्य के प्रति प्रोत्साहित करता है। अनावश्यक पुनरावृत्ति, समय, श्रम, आदि से बचाता है साथ ही बौद्धिक ज्ञान व कार्यकुशलता की उत्तरोत्तर वृद्धि करता है।

कभी कभी समस्या के अध्ययन की पुनरावृत्ति आवश्यक होती है क्योंकि एक संदर्भ में जो अध्ययन किया जाता है वही अध्ययन दूसरें संदर्भ में भी उपयोगी हो सकता है। जैसे एक न्यादर्श पर किया गया अध्ययन दूसरे न्यादर्श पर भी उपयोगी हो सकता है। कभी कभी एक न्यादर्श पर किये गये

अध्ययन के निष्कर्ष सन्देहात्मक हो सकते है, ऐसी स्थिति में उसी न्यादर्श पर दूसरा अध्ययन उपयोगी हो सकता है और सत्य की खोज में क्रास चैकिंग हो सकती है। कभी कभी अध्ययन की तकनीक पर निष्कर्ष आधारित हो जाते है इसलिये दूसरी तकनीक अपना कर विषय पर अध्ययन करके नयी दिशा और नये निष्कर्ष प्राप्त किये जा सकते है समय और परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्षो के अर्थो में कालान्तर में परिर्वतन होता रहता है। इन सभी निष्कर्षो और

उनके अर्थो से शोधकर्ता को परिचित होना आवश्यक है इससे उसे अपने शोध के निष्कर्षो एवं अर्थो को परिभाषित करने में बड़ी सुविधा होती है।

पूर्व किये गये शोध कार्यो का विवरण

पूर्वकृत अध्ययनों की समीक्षा की अच्छी सुविधायें अपने देश में अभी भी नहीं है, इसलिये किसी भी शोधकर्ता को विभिन्न अध्ययनों की जानकारी ठीक ढंग नहीं मिल पाती है। विभिन्न विषयों के अध्ययनों के डाकयूमेन्टेशन की कोई उचित व्यवस्था नहीं है फिर भी शोधकर्ता ने विभिन्न सूत्रों से पूर्ववत अध्ययनों की समीक्षा करने का प्रयास किया है।

शोधकर्ता ने पाश्चात्य शोध अध्ययनों को निम्नलिखित ग्रन्थों से देखा किन्तु कोई उपयोगी सामग्री प्राप्त नहीं हुई।

1. ईवेल, आर. एल.- इनसाइकलोपीडिया आफ एजूकेशन एन्ड रिसर्च चतुर्थ संस्करण, 1964
2. मनरो वाल्टर एस. एन.- इनसाइकलोपीडिया आफ एजूकेशनल रिसर्च संशोधित संस्करण, 1956
3. मितजल, एच.ई. - (एजूकेशन) इनसाइकलोपीडिया आफ एजूकेशनल रिसर्च पंचम संस्करण - वाल्यूम -2 दि फ्री प्रेस, लन्दन, 1982

अपने देश के अध्ययनों के लिये मुख्यतः निम्नलिखित चार ग्रन्थों का आश्रय लिया गया है:-

1. बुच, एम0 बी0- ए सर्वे आफ रिसर्च इन एजूकेशन
   सोसाइटी फार एजूकेशनल रिसर्च एन्ड डवलपमेंट, बड़ौदा
2. बुच, एम0 बी0- सेकेन्ड सर्वे आफ रिसर्च इन एजूकेशन- 1972-78
   सोसाइटी फार एजूकेशनल रिसर्च एन्ड डवलपमेंट बड़ौदा, 1979
3. बुच, एम0 बी0- थर्ड सर्वे आफ रिचर्स इन एजूकेशन - 1978-83
   एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली, 1986
4. फोर्थ सर्वे आफ रिसर्च इन एजूकेशन 1983-1988 वाल्यूम -1
   फोर्थ सर्वे आफ रिसर्च इन एजूकेशन 1983-1988 वाल्यूम-2
   एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली-1991

Abstracts

A Survey of Research in Education - M.B. Buch

49. NABAR R. A.

The history of education in the city of Bombay. (1820-1920)

Ph.D Edu. Bombay University 1964

The aim of this project was to find out as many factors as possible which had contributed to the progress of education in the city of Bombay during the period between 1820-1920

Some of the ralient findings of the study are the following -

(1) During the period under study. Education in Bombay could progress in various branches of Knowledge such as primary education, seconoary education, and higher education in arts and science technical, commercial and legel education, educa tion of art, physical education and education of the educator, most satisfactorily because there had been a happy co-operation between the officers of the govern ment and private individuals.

(2) Medical and technical education was not only possible but popular too in Bombay, but institution for such education were not encouraged by the government which wanted all education through the medium of English alone.

(3) Among other finding are those the progress of literacy among different communi ties, the success of morning classes in professional schools and the unsatisfactory progress of night schools, the percentage of literacy among Mohammedans de

yet strangely enough the Mohammedans had been demanding special favour for their children, schools and colleges.

55- PRASAD, S.

Education in Bihar. (1854-1904)

Ph.D. Hist. Mag. U. 1967

The main aim of the study was to trace the growth of education in Bihar during 1854 to 1904. The period between 1813 and 1853 was a period of experiements - experiements imparting education in oriental as well as accidental languages. Education of the period might be termed as a dark one for Bihar. The real progress in education in Bihar began with the Despatch of 1854. It outlined a complete and eleborate system, touching all the aspects of education. The aim of education was the diffusion of arts, science philosophy and literature of Europe. The Despatch of 1859 made recommendations to establish universities to expand secondary education and to encourage private enterprise to come into the field of higher education through the grant-in- aid system.

The Patna colleges attracted moreand more stndents, from the province four new colleges were established. The missionaries also set up the St. Columbas college at Hazaribagh for the uplift of the ab-origines. The private colleges were popular among the people, because they charged less fees than the government colleges.

60. RENU DEBI

Progress of Education in Asssm. (1882-1937)

Ph. D. Edu. Gau. U. 1971

The aim was to Survey and critically analyse the progress of education in Assam during the period 1882-1937.

The old records, reports, minutes and review publications of the

government were consulted as source material. A brief review of the progress of education in Assam from 1826 to 1881 was made to serve as the background for the study. collegiate education in Assam was imported, up to 1930, in only two colleges, private colleges could not prosper due to lack of official interest in regard to their needs. another handicap was the lack of a separate university for the province.

68. UPRETI, D. C.

Political development and growth of Education in British India. 1904-1947

PH. D. Edu. MSU., 1972

The aim of the present study is to reinterpret the evolution of education policies in British India in relation to contemporary political developments. An ancillary aim was also to unravel the hither to unknown facts about educational developments during that period. The evidences heve been called out from the educational records of that period mainly from National Archives of India, New Delhi. The evidendces heve been sorted from official files, quinquennial reviews. contemporary news papers and also from same secondary sources.

The change in educational policy in 1904 was a major challange to the assumption held till then that higher education acted as a establishing influence of the British rule. Carzon wanted to circumscribe higher education but his policies did not succeed. The reappraisal of educational policies during this period finally culminated in the Government of India Resolution of an education in 1913. The demand for a separate Muslim University was voiced since the beginning of this century.

Second Survey of Research in Education.

(1972-1978) M.B. Buch.

40. MURUGHENDRAPPA, D.R.

Twenty five years of Education in the State of Mysore (1947to1972)

R.V. Teachers college, Bangalore. 1972

The purpose of the present study was to survey the progress of education in Mysore state during the post independence period.

For the collection of data annual reports of Government, reports of the educational surveys, university reports etc. were consulted. This project surveyed the progress of education at pre- primary, primary, secondary, pry- university, colleges, university and professional education levels.

The number of universities increase went up from one to five. The colleges of genaral education went up from 4 to 197. There were sixteen commerce colleges. thirteen law Colleges. Fifteen Engineering Colleges, four Medical Colleges.

742. BOSE, P.K.

Calcutta University, some problems and their Remedies.

Cal.U. 1973 (UGC& MOE Financed)

The objectives of the project were -

(i) To assess broadly the needs for higher education and research and to examine in particular, the development of the university deparments.

(ii) To examine the question of conferring the status of autonomous colleges on selected institutions.

(iii) To suggest organisational and structural changes in the university and .

(iv) To endicate the financial implications of the recommendations.

Some of the major findings were as follows-

(i) The problems of the university as detected were the increase in number of the institutions, students and examinees irrespective of the constant remaining resources at the disposal of the university shortcomings in the administrative arrangements over consciousness among students and employees about their rights and privileges, paucity of funds, paucity of space, recurring deficits, problems related to the opening of new departments and starting new cources, developing university press, maintenance and repair of buildings, starting hostels, providing students with satis factory welfare services, holding examinations, maintaining adequate and able staff (teachers and administrative officers) financial position of some affiliated colleges, the demand for teachers and improvement in the library and laboratory facilities.

(ii) As regards the undergraduate education, the percentages of passer were less than forty in the university examinations in a large number of private colleges, the main causes being inadequate number of working days. Poor college libraries, ill-equipped laboratories, disproportionate teacher-student ratio and lack of motiva tion on the part of teachers and students. The percapita expenditure of the affiliated colleges was less than the government sponsored colleges. Some of the important remedial suggestions with regard to the affiliated colleges. were to provide more inputs in the nature of grants, equipments and books. formation of under graduate college boards responsible for introducing new types of examinations, teaching methods and admission policies.

(iii) Almost all the colleges had financial difficulties except two or three. Every college had common problems of library, laboratory, building and furniture. However, the emoluments of teachers did not differ remarkably. The enrolment in commerce

stream was found to be higher, conclusively, studends explosion and the extreme paucity of funds were the two main factors which hindered the functioning of the university efficiently.

PIMPALKHARE, M.H.

A Study of Arts, Science and Commerce Colleges in Maharashtra.(1971-72)

Ph.d. Edu. Poona University, 1976

The purpose of investigation was to conduct a status of the non government arts, science and commerce colleges in Maharashtra in the year 1971-72, with a view to finding out the growth of these types of colleges during the period 1966 to 1972, studying the pattern of enrolment in the year 1971-72, the teaching and the non teaching staff the physical facitities and the financial position of the colleges, and teaching subjects under the faculties of arts, science and commerce.

Out of the 329 colleges teaching arts, science and commerce in Maharashtra in 1972-72, as many as 303 colleges responded to the study. The data were callected through a mailed question naire visits to some of these colleges were also made. Reports of various commissions and committees both Indian and foreign dealing with higher education were also used.

There were 95 arts, science and commerce in 1960 when the Maharashtra state came into being. The number of such colleges increased to 189 in 1965-66 and further to 329 in 1971-72. The figures of enrolment for 1966-67 and 1971-72. were 138765 and 271584 respectivily. During the period 1966-70 the maximum enrolment was in the arts faculty followed by science and commerce. In 1966-67 the average enrolment per college was 806 and it increased to 896 in 1971-72. Nearly 7.27 percent of the total seats available were lying vacant 1971-72. In the same year, out of the total

enrolment, girls formed 23.24 percent. The percentage of girls varied from university to university, the maximum being 36.67 in Bombay and 7.23 in the colleges affiliated to the Marathawada University. About 4.23 percent of the teachers had to their credit the Ph.D. degree. The pay scale of the non teaching staff varied from the jurisdiction of each university and even among colleges affiliated to the same university compared to the norms of physical facilities laid down by the committee an improvement of standards of university education appointed by the UGC, a number of colleges fell below the expected norms. The state government incurred an expenditure of rupees grant in aid to non government colleges. It increased to rupees 74.21 lakhs in 1966-67 and to rupees 257.47 lakhs in 1971-72. nearly 44.30 percent of the student availed themselves of the facility of commission available to the economically backward classes.

773. SHAHNAZ MUSHRAT.

A Critical Study of American Influences on post-Independence Higher Education in India.

Ph.D. Edu. AMU. 1975

The study aimed at exploring American interest in Indian education and critically assessing American influence on the development of higher education in India, mainly its theory and practice, during the post independence period. The study also tried to take into account the attitudes and opinions of those Indian scholars who had studied in the U.S.A. and other European countries and were now associated with various Indian Institutions of higher learning.

The findings of the study were -

(i) American assistance to Indian can at a time when the nation possessed insufficient school too few text books, out moded system of education.

(ii) The U.S. aid was provided in such programme as Marshal plan, point four programmes, PL-480 programme, Mutual Security Act, TCM USAID and Fulbright, etc.

(iii) The total financial assistance for development of higher education in India through U.S. Governmental agencies came to about Rs. 719.85 crores. During the same period. the assistance from Ford Foundations came to about Rs. 261.7 crores. Apart from this, the equipments, apparatus and thousands of books given as gifts and donations from the American Government and various private publishers, organisation etc.

(iv) From 1951 to 1970, under the Fulbright programme 1151 and under USAID programme 3000 American specialists served as teachers and consultants in India.

(v) The total number of Indian specialists who visited U.S.A. was 2449 under Fulbright scheme and 5758 under USAID scheme. Moreover, till 1969 about 68000 Indians students studied in U.S.A. in the year 1969 alone. 8000 Indian students, 3000 Indian medical doctors, 4000 Indian university faculty members were in the U.S.A. studying for various degrees or engaged in research work.

781. SINHA, N.

University Administration in Bihar.

Ph.D. Soc. Pat. U. 1975

The main purpose of the study was to analyse the present administrative structure of Universities in Bihar and suggest some saort of planning in university manner.

The major finding of the study were as follows-

(i) The evils, such as casteism, petty politics, low level of morality resulting from mass

illiteracy, were reflected in the universities.

(ii) The authoritarian traits of the society too were reflected in the universities, e.g. rigid hierarchy emphasis on compliance, and resistance towards innovation and experi mentation. The power of decision making concentrated in the hands of a few.

(iii) Principles of democracy, election for example, whenever or wherever introduced, failed mainly due to social factors, lack of training and half hearted efforts. Demo cracy was privalent in the form of 'casteocracy'.

(iv) Channels of communication between the different components of the universities were restricted, and the junior teacher and students were prevented from taking active part in the affairs of the universities. This frustrated the sense of belongingness to the universities and resulted in problems of discipline and lower level of academic out put.

(v) The universities on the whole were not performing their role as the main producer of knowledge and intellect or trained personnel. They were, thus, unable to become agents of social change.

Third survey of Research in Education.(1978-1983)

M.B. Buch.

49. DESAI, H.G.

A Decade of Educational Research in the Universities of Gujarat.

Dept. of Edu. Sau. U. 1973 (Sau. U. Financed)

The study was carried out with the following objectives

(i) To find out the areas and extent of research work done in various universities of Gujarat.

(ii) To produce reference material for future researchers who may want to review re

search work carried out in their areas of interest.

(iii) To help avoid duplication of research work, and

(iv) To suggest topics for research in unexplored areas. The study was an extensive survey of research done in the five universities of Gujarat during 1961-70. The study covered 685 studies and investigations carried out for M.Ed. and Ph.D. degrees. The study revealed

The number of studies and investigations in various universities were -

(i) Gujarat university 232, M.S. University of Baroda-244, Sardar Patel University-105 Saurashtra Univestiy-78, and South Gujarat-26

(ii) The number of studies and investigations in various areas were : educational evalu ation-163, education and social change-115, educational administration-76 teacher education-60, child development and adolescence test construction-51, curricu lum-50, and measurement-50, methods of teaching-34, basic education-17, social education-5, process of learing-4, economics of education-3,

(iii) The almost unexplored areas were economics of education, law and education, psychology of learning medical education, technical education, moral education etc.

(iv) The same terms had been used with different researchers, by different research ers.

(v) The studies submitted for the same degree differed greatly in precision of sampling, coverage, depth procedures of analysis, conclusions, etc.

(vi) Investigations had been repeated in the same university (duplicated).

(vii) Survey and studies were conducted on the same topics by various universities. There were instances of doctoral theses submitted on the same topics in the same

year in two or more universities.

(viii) Researchers had many misconceptions about term and procedures.

(ix) Most studies were based on questionaires, the use of other tools interdisciplinary approach in studies.

53- DOCTOR, T.H.

Progress of University Education in Gujarat State after Independence.

Ph.D. Edu. Guj.U. 1979

This study starts with the position of university education in Gujarat from the year 1950-51 and stretches it upto the year 1974-75, there were only two universities in 1950-51 while in 1974-75, there were five academic and two professional universties. The study was done in blocks of four years and traced the growth of all the five universities in the matter of enrolment, faculty wise number of colleges, strength of faculty members, post graduate centres, enrolment of postgraduate students, amount of research work done, addition of books in the library, number of readers of library books, external examinations, income and expenditure of the university, students welfare activities and such other aspects. The growth study of each university was done reporately for each block of four years and for the whole period under study.

At the end of the thesis the progress of university education for the whole of Gujarat was also studies. The trends of development were crystallized and suggetions were made for improvement.

59. LANDAGE, C.N.

The History and Survey of Education in Sholapur District.

Ph.D. Edu. Shi-U. 1980

The main objectives of the study were -

(i) To take a historical review of the educational development at the pre-primary, pri mary, secondary, and higher stages of education as well as technical education during the pre- independence and the post- independence period.

(ii) To study the facilities available in the district of Sholapur at all stage of education including technical as well as teacher education.

(iii) To make constructive suggestions for the development education at all levels in the district of Sholapur.

The normative survey method was adopted in the investigation with a question aire was administered to pre-primary schools, primary schools, secondary schools, and colleges of education, Government offices and field workers concerned were interviewed. The data were also collected from diffierent documents, reports of schools and the Government publications.

The recommendations were classified under different heads, such as

(i) General recommendations.

(ii) Higher educations

There should be a sub centre of the Shivaji University at Sholapur.

64. MISHRA, M.

Education in Uttar Pradesh from 1858 to 1900

Ph.D. History, Luc. U. 1969.

The study was an attempt. to critically survey the educational policy carried out by the Government in Uttar Pradesh from 1858 to 1900. The study was based on the original material (both published and unpublished) available in the National Archives, New Delhi, The Record Office Lucknow Secretariat, Lucknow the Central Record Office Allahabad, the annual reports in the secretariat library Lucknow, and the District

Gazetteers available in the District Gazetteers Office, Lucknow. Material was also collected from the Pioneers Press, Lucknow, Kashi Nagri Pracharini Sabha, Varanasi, and other libraries.

The finding were: The Wood's Despatch of 1854 and the Hunter Commission 1887 proved the way for educational revival carried on in North Western provinces. The advice tendered by the Wood's Despatch and the Education Commission of 1882 to pay more attention to regional languages was disregerded and not given effect to keeping the needs of collegiate educations in focus, the entire secondary course was dominated by the university. The Muir central College Allahabad was at table shed with the object of creating a centre for vernacular education and was expected to develop into a vernacular university, but it belied the expectations of its sponsors and turned out to be only a supervisory authority for the vernacular middle examination.

66. NAGAR. R .S.

Development of Education in Manipur from 1891 to 1970

Ph.D. Edu.Gau.U. 1975

The objectives of the study were

(i) To trace the cultural background of Manipur and its relation with various aspects of Indian culture.

(ii) To trace the growth of indigenous system of education in Manipur and its relation with the mainstream of National Culture.

(iii) To trace the growth of education after Manipur accession to India.

(iv) To study the growth and impact of the Western Education on Manipur.

(v) To trace the growth of education from 1891 to 1970 and

(vi) To study the educational administration in Manipur.

The sources of data were the records of the government, the books written by the local authorities and the information collected by the statistical department. The research methods used were the historical and the library methods.

The major finding were the affiliation of educational institutions to the Gauhati university also presented problems, the high schools were affiliated to the Gauhati University where as the higher srcondary schools were affiliated to the Central Board of Secondary Education. Again, the colleges were under the Gauhati University and post-graduate education under the Jawahar Lal Nehru University.

83. VERMA, G.C.

Growth and Development of Modern Education in Rajasthan

Ph.D. Hist. Raj. U, 1968.

The study aimed at describing the growth and development of education in Rajasthan from 1819 to 1949 onwards. The investigator used all possible sources in carrying out the study. He mainly depended on the unpublished relevant documents in the National Archives of India, New Delhi, and also utilized the education department files of the various former states of Rajastan, prescribed in the Rajasthan Archives, Bikaner, The annual reports of the Scottish Presbyterian Mission were also made use of.

The study reported the following findings. There were three colleges functioning in Rajastan in the beginning of the present century.

These were: The Government College Ajmer, the Maharaja College, Jaipur and the Jaswant College Jodhpur. There was very limited demand for higher education in Rajasthan till the twenties of the present century and these colleges located in three distant places, fully met that demand. But in reality, the demand for collegiate education in the province was so small that even these colleges did not have for a long time,

sufficient number of students in them.

Fourth Survey of Research in Education. (1983-88)

volume I M.B. Buch.

48. ACHARYA, S.

Education in Bengal. (1813-59)

A Historical Study and Analysis.

Ph.D. Hist. Burd. U. 1980

The study sought to analyse and explain the emergence and growth of a new education system in Bengal (1813-59) and its role in the advent of modern waves in Bengali society. The chronological limit of the study was set by the Charter of 1813 and Lord Stanley's Despatch of 1859.

The major issues discussed and the outcomes of the study were -

(i) A brief sketch of the evangelical and utilitarian movements which dominated British liberal ideas and found expression through T.B. Macaulay in Bengal.

(ii) The state of classical Hindu and Islamic education in the first half of the 19th century and official efforts to revive them by adaptation with Western Culture.

(iii) The state of varnacular mass education in the early 19th century and the official policy to encourage it.

(iv) Evolution of higher education in Bengal from Bentinck's Resolution of 1935 to Stanley's Despatch of 1859.

(v) An account of official and non-official enterprises in stimulating awareness of the need for varnacular Mass Education in Bengal.

(vi) Some special aspects of new education in Bengal like female education, profes sional education etc.

(vii) Nature and causes of slow development of a central authority for educational supervision from the early amateur bodies of ultimate assumption of government control.

(viii) Explanation of the growth of the new elite and its role in the modernization of the Bengal Society.

(ix) Stress on the anslysis of the development of education from inside along with the larger social context in which the educational institutions had to grow.

61. INDERJIT KAUR.

Higher Education in Punjab from 1882 to 1982.

Ph. D. Edu. Punjab. U. 1985

The objectives of the study were -

(i) To represent the educational scene obtaining in Punjab in 1882.

(ii) To trace the development of higher education in Punjab from 1882 to 1947.

(iii) To find out how development of higher education in Punjab was influenced by the country's independence i. e. by the Government National Policy.

(iv) To find out the impact of territorial reorganization of Punjab on higher education there.

(v) To review the problems of higher education in Punjab as they varied from time to time and how their resolution were attempted.

(vi) To suggest measure to solve current problems and to improve prospects of developing higher education in Punjab.

The study revealed with the foundation of Punjab University in 1882, higher education in the state started spreading gradually. In 1947, the Punjab University went to Lahore and a new Punjab University was started in India and all the colleges

located in indian East Punjab were affiliated to the new university in India. The East Punjab University was renamed Punjab University in 1950. In 1957, the Punjab University was shifted to Chandigarh along with its library and teaching departments. In 1956 another university was started at Kurukshetra with the bifurcation of Punjab in 1966 Chandigarh was declared Union Territory. Consequently, Punjab University was no longer under the administrative control of Punjab Government. In 1961, the Punjab Agricultural University was established. The university was modelled on the pattern of the Land Grant Institutions of the U.S.A. In 1962, Punjabi University was established with the objective of promoting the study of Punjabi language. The Guru Nanak Dev University was founded in 1969. This University had 19 teaching departments and 75 affiliated colleges.

80. SIDDIQUI, M.A.

Growth of Modern Education in India from Curzon to 1947.

Ph.D.Hist. A.M.U. 1985.

The objectives of the research was to study the evolution and growth of university. Education from 1900 to 1947 with an appraisal of its rule in the social, economic and political spheres. Charters discuss the main provisions of Wood's Despatch of 1854 and their impact on Indian education, the structure and working of the universities and affiliated colleges, the circumstances leading to the establishment of the universities of Punjab and Allahabad and the recommendations of the Education Commission of 1882 and their impact of Indian Education. Lord Curzon considered Indian schools and colleges as seed beds of anti-British agitation and wanted greater control over them. As a result of the repressive policies of the Government, the number of colleges decreased from 192 in 1902 to 174 in 1907. Education expanded rapidly from 1907 to 1918. The number of college going students increase from 18001 in 1906-07 to 36, 533 in 1911-12.

There was great increase in the privately managed schools and colleges. The government appointed the Calcutta University Commission to survey the counditions prevailing in Indian universites. The number of universities increased from 5 in 1907 to 8 in 1921. The number of university students rose to 66,865 in 1921-22. During 1921-37 the government appointed the Auxiliary Committee of Statutory Commission on education as adjunct of the Simon Commission and revived the Central Advidsory Board of Education. The number of universities increased from 8 to 19. The number of colleges and university students rose to 128623 in 1936-37. The Sargent Committee was appointed which suggested opening of more polytechnics and provision of better facilities for training of teachers. The quaility of instruction remained as poor in 1947 as it had been in 1858.

Fourth survey of Research in education. (1983-88)

Volume II M. B. Buch

1530. BENAL, B.I.

A critical study of development of higher education in the State of Karnataka during six five year plan (1950-1985), with special reference to Karnataka University.

Ph.D. Edu. Kar. U. 1987

The major objectives of the study were :

(i) To study the development of higher education in Karnataka University.

(ii) To study qualitative development through institutional material.

(iii) To study the improvement of quality of teachers.

(iv) To study the problems of examinations and evaluation.

(v) To critically evaluate the nature and extent of development with respect to the trends in developed states in the country.

(vi) To suggest steps for improvment of higher education.

The major findings of the study were :

(i) There was a consider able quantitative growth of the member of institutions, namely, the affiliated and constituent colleges and university post. graduate departments during the plan period.

(ii) It was also seen that the receipts and expenditures had significantly increased due to the developmental programmes initiated and implemented. Simalarly, it was seen that the sources of income had increased to the best advantage of the educational institutions.

(iii) The library of the Karnataka University had expended considerably and it was believed to be second biggest in Asia.

(iv) With regard to modernization of Science departments, Physics, Chemistry and Geology had greatly expended and were offering leadership courses in their disci plines in the country.

(v) For student facilities, financial efforts had not been made to the extent expected.

(vi) Quantitative improvement at the affiliated colleges and also at the university was not very significent.

1544. JOSEPH, T.M.

Progress and Problems of Higher Education in Maharashtra since Independence 1947-1982.

Ph.D. Edu. Bom. U. 1987.

The objectives of the inquiry were:

(i) To study the progress of higher education in Maharashtra as evidenced by qualita tive and quantitative measures.

(ii) To study the innovative schemes launched by the universites.

(iii) To identify the problems in higher education.

(iv) To study the extent, causes, consequences and effects of these problems on higher education in Maharashtra.

(v) To suggest alternative and changes in the pattern of higher education.

The study revealed -

(i) There had been a tremendous increase in student enrolment since independence.

(ii) There had been a noticeable increase in women's enrolment in the Marathwara University area.

(iii) The curriculum and syllabi for the various courses had been along traditional line with little attempt to adopt to local needs and resources.

(iv) Poona University had started a programme of distance education with the prepara tion of audio-visual material in the university's television studio.

(v) Many university post had not been filled because funds were not forthcoming, particularly all the universities had deficit budgets that were carried forward from year to year.

(vi) The introduction of the 10+2+3 system had resulted in declining enrolment at the +3 stage in all universites.

(vii) There was an acute lack of hostels for women students belonging to these groups in almost all universities.

(viii) There was little co-ordiniation among the universities state and central government and the UGC.

प्रस्तुत शोधकार्य हेतु अध्ययन के स्रोत

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य एक ऐतिहासिक शोधकार्य है जिसको पूर्ण तथा सम्पन्न करने के लिये ऐतिहासिक स्रोतों को माध्यम बनाया गया है! प्रदत्तों के संकलन में समयानुसार एंव आवश्यकतानुसार विभिन्न स्रोतों का सहारा लिया गया है! प्रदत्तों का संकलन प्रायः प्राथमिक स्रोतों द्वारा हुआ है! ये स्रोत हैः शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित शिक्षा की प्रगति की आख्याएं, नियोजन विभाग उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध अन्य अभिलेखों एवं दस्तावेजों का भी अध्ययन किया गया है! ये सभी प्रपत्र एवं पुस्तके सरकार द्वारा तैयार की गयी है अतः उनकी विश्वसनीयता स्वंयसिद्ध है! शोध सामिग्री के संकलन के मुख्य स्रोत विभिन्न आयोगों एवं समितियों के प्रतिवेदन, विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिाओं में प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धी लेख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्टे, विभिन्न विश्वविद्यालयों के समय-समय पर प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धी लेख, विश्वविद्यालय एक्ट और उससे सम्बन्धित साहित्य, विश्वविद्यालय एवं कालेज सम्बन्धी डायरेक्ट्री आदि है!

तृतीय अध्याय

तृतीय अध्याय

अनुसंधान विधि

विभिन्न प्रयोजनों एवं उपागमों के आधार पर अनुसंधानात्मक अध्ययनों में भेद किया जाता है और वस्तुतः इस भेद को विधियों का ही भेद कहा जा सकता है! विविध विधियो का प्रयोग करने वाले अध्ययनों की प्रक्रियाओं में सामान्यतः कोई विशेष भेद नहीं होता है! समस्या का चयन, निरूपण एवं उसकी परिभाषा, सम्बन्धित सूचना का सर्वेक्षण, नवीन दत्तों का संग्रह, विश्लेषण एवं व्याख्या तथा किये गये कार्य का प्रतिवेदन– सभी प्रकार के अनुसंधान की विधियों में सामान्य रूप से प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया के सोपान है अतः यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक अनुसंधान में प्रक्रिया के सोपान समस्त शैक्षिक अन्वेषणों के लिये समान रूप से प्रयोग में लाये जाने वाले तत्व है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की विधियां विभिन्न प्रकार के शोधो में स्पष्ट व विस्तृत विभेद करने वाली विशेषतायें है!

अनुसंधान की विधियों का वर्गीकरण विविधतापूर्ण है! अनुसंधानात्मक दत्तों को एकत्रित करने विश्लेषित करने व प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनेक विधियाँ एंव साधन है! दत्तों के संग्रहीकरण एवं प्रयुक्तीकरण की तथा काथित विधियों के सम्बन्ध में शिक्षा शास्त्री पूर्णतः एक मत नहीं है। अनुसंधान साहित्य में विभिन्न शब्दों का प्रयोग विभिन्न अर्थो में किया जाता है। अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुरूप शब्दों का प्रयोग करते है तथा अपने अभिप्राय को व्यक्त करते है!

किसी विशिष्ट अध्ययन में यद्यपि सामान्यतः विधियों में से कोई एक ही विधि प्रयुक्त की जाती है, तथापि यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक विधियों को उपयुक्त करने का कोई कारण नहीं है! अनुसंधानकर्ता किसी समस्या का समाधान करने के लिये पहले वह उसके इतिहास का अध्ययन ऐतिहासिक विधि से करे, फिर उस के वर्तमान स्तर का निर्धारण वर्णनात्मक विधि से। किसी भी दिये हुये अनुसंधान में दो या दो से अधिक अनुसंधान की विधियों का सामान्य प्रकार का संयुक्त प्रयोग न केवल बाछ्नीय होता है वरन् आवश्यक भी होता है! प्रयुक्त की जाने वाली विधि अथवा विधियों का निर्णय सदैव चयन की गयी समस्या की प्रकृति तथा उसके समाधान हेतु आवश्यक दत्तों के प्रकार पर निर्भर करता है! चयन की गई विधियां सदैव अध्ययन के विषय के अनुकूल, व्यवहारिक, पूर्व

नियोजित तथा बोधनीय होनी चाहिये! जैसे जैसे अध्ययन की प्रक्रिया सम्पन्न होती हुई आगे बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे विधियों में कुछ परिर्वतन एवं नवीन बातों के योग की आवश्यकता हो सकती है! प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्ता ने दो विधियों-ऐतिहासिक विधि एंव वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया है:

अ. ऐतिहासिक विधि

इतिहास, किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में अतीत की घटनाओं का एकीकृत वर्णन है जो सम्पूर्ण सत्य के लिये समालोचनात्मक खोज का प्रतिनिधित्व करता है किसी भी विषय के अध्ययन का ऐतिहासिक उपागम अतीत के जीवन के किसी पक्ष के वर्णन करने के प्रयास की और संकेत करता है! ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु सम्भावित क्षेत्र स्वंय जीवन के सामान विस्तृत है! शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक साधनों एवं प्रविधियों का प्रयोग वैज्ञानिक एवं सामाजिक क्षेत्रों सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन में ऐतिहासिक उपागम के विश्व व्यापी व्यावहारिक प्रयोग से लिया गया है।

अनुसंधान की विभिन्न विधियो में ऐतिहासिक विधि का अपना अलग वर्चस्व है! एक समाज का इतिहास प्रायः उसकी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का मूलाधार होता है! एक समाज की वर्तमान संस्थाओं, समस्याओं तथा विचारधाराओं के विशिष्ट स्वरूप को ज्ञात करने के लिये ऐतिहासिक अनुसंधान का आश्रय लिया जाता है तथा समस्या के समाधान के लिये एक नया हल प्रस्तुत किया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान का सम्बन्ध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से रहता है इसके विभिन्न पद भूत के सम्बन्ध में एक नई सूझ पैदा करते है जिसका सम्बन्ध वर्तमान और भविष्य से होता है।

प्रस्तुत शोधकार्य में भी ऐतिहासिक विधि के माध्यम से अनुसंधानकर्ता ने अपनी अध्ययन समस्या को स्पष्ट करके, सीमाबद्ध करके, वैद्य विषय सामिग्री को संकलित करके, अध्ययन सम्बन्धी विभिन्न घटनाओं, तथ्यों, विचारों का विस्तृत विश्लेषण करके विश्वसनीय तथा संदेह रहित साधनों, साक्ष्यों व अभिलेखो का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है और ऐतिहासिक तथ्यों की खोज करके अतीत की घटनाओं के आधार पर वर्तमान व भविष्य की भावी रूपरेखा का निर्धारण किया है जिससे वर्तमान के यथार्थ ज्ञान में शिक्षा व समाज में सुधार सम्भव हो

सके। इतिहास व्यक्ति की उपलब्धियों का सार्थक लिखित प्रमाण है! यह केवल विशेषताओं एंव अतीत से सम्बन्धित घटनाओं की सूची ही नहीं है बल्कि व्यक्तियों, घटनाओं, समय तथा स्थानों के बीच सम्बन्धों का एक तथ्यात्मक विवरण है। मनुष्य इतिहास का प्रयोग अतीत के समझने के लिये तथा पुरानी घटनाओं और विकास के संदर्भ में वर्तमान को समझने के लिये करता है! इतिहास मानव ज्ञान की एक शाखा है जो प्राचीन घटनाओं के लिखित आलेखों का अध्ययन करता है। इतिहासकार, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक एंव साहित्यकार ऐतिहासिक उपागम को समाज के एक गतिशील जीवन के रूप में प्रयोग करते है।

अनुसंधानकर्ता को शोध करने की अन्य किसी विधि को प्रयुक्त करने वाले के समान ही समस्या के चयन करने, परिभाषित करने तथा उसका परिसीमन करने के प्रारम्भिक सोपानों का अनुगमन करना पड़ता है परन्तु उसकी समस्या के समाधान का प्रमुख कार्य अन्य अनुसंधान कताओं से भिन्न होता है, क्योकि यह प्रयोगात्मक अथवा प्रत्यक्ष निरीक्षण पर आधारित नहीं होता, वरन् निरीक्षकों के ऐसे प्रतिवेदनों पर आधारित होता है जिनकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती! ऐतिहासिक विधि के अन्तर्गत दत्तों का संकलन करने के लिये मुख्य रूप से प्राथमिक स्रोत एंव गौण स्रोत का सहारा लेना पड़ता है।

प्राथमिक स्रोत

मौलिक अभिलेखों अथवा उन अवशेषों को जो किसी भी घटना अथवा तथ्य के प्रत्यक्ष साक्षी होते है प्राथमिक स्रोत कहलाते है! केवल प्राथमिक स्रोत ही ऐतिहासिक अनुसंधान के ठोस आधार है। इनका सम्बन्ध प्रदत्त के मूल व मौलिक साधनों से होता है। इसके अर्न्तगत किसी एक ऐतिहासिक घटना से सम्बन्धित ठोस प्रमाण प्रारम्भिक तथा प्रत्यक्ष सामग्री के रूप में सम्मलित रहते है। इस तथ्य को विस्तृत करते हुये करलिंगर ने लिखा है।

" A Primary sourece is the original repository of an historical datum, like an original record kept of an important occassion, an eye-witness description of an event, a photograph, minutes of organization meeting and so on" [1]

---

1. Kerlinger F. N. "Foundations of Behavioural Research, Holt 1964, P-689

मौखिक अथवा लिखित प्रमाणपत्रों के रूप में अथवा किसी घटना विशेष में भाग लेने वाले या उसको देखने वालो द्वारा लिखे गये अथवा आलेख रखे गये जैसे-संविधान, चार्टर, न्यायालय के निर्णय, शासकीय आलेख, आत्म चरित्र वर्णन, पत्र, दैनन्दिनी, वंशावली, समझौते, परमिट, लाइसैस, घोषणापत्र, उदघोषणा, प्रमाण पत्र, विधेयक, रसीदे, पत्रिका, तथा समाचार पत्र, प्रचार पत्र, मानचित्र, रेखाचित्र, पुस्तके, सूची पत्र, फिल्म, चित्र, चित्रकारी, शिलालेख, आलेख, प्रतिलेखन तथा अनुसंधान प्रतिवेदन जीवाश्म, अस्थि पंजर, (जमीन से खोद कर निकाले गये अवशेष, औजार, हथियार, घरेलू वस्तुयें तथा वस्त्र) भाषायें, साहित्य, कला एंव विभिन्न प्रकार की संस्थाएं। जाने एवं अनजाने दोनों ही प्रकार के प्रमाणों में केवल निरीक्षक का मस्तिष्क ही मौलिक घटना और उस घटना के सम्बन्ध में सूचना को प्रयोग करने वाले के मध्य कार्य करता है।

गौण स्रोत

जिन व्यक्तियों ने न तो मौलिक घटना को देखा और न उसमें सक्रिय रूप से भाग ही लिया है उनके द्वारा लिखित अथवा वर्णित पुस्तकें लेख आदि सूचना के गौण स्रोत कहें जाते है। वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यो हेतु इन साधनों का उपयोग सामान्यतः सीमित होता है क्योकि इन साधनो द्वारा दी गई सूचना वास्तविक घटना में भाग लेने वाले या देखने वालो द्वारा कही गई या लिखी गई बाते ही प्रस्तुत की जाती है, ऐसी सूचनायें बहुधा मौलिक घटना से कई गुना दूर होती है! उसमें अधिक तोड़ मरोड़ की सम्भावना रहती है और उसकी मौलिकता की विश्वसनीयता में तदनुसार कमी आती चली जाती है! गौण स्रोत किसी एक ऐतिहासिक घटना या स्थिति से अपने मूल स्रोतों से एक या अधिक चरण दूर हटे हुये होते है। इसमें मौलिक प्रमाण का आभाव रहता है, परन्तु उसका प्रमाण व विवरण अन्य साधनों से उपलब्ध रहता है! करलिंगर के शब्दों में,

" A secondary source is an account or record of an historical event or circumstance one or more steps removed from an original repository." [2]

इतिहास शोध के किसी भी क्षेत्र में पूर्ण सत्य के लिये एक समालोचनात्मक खोज को प्रस्तुत

2. Kerlinger F. N. "Foundations of Behavioural Research, Holt 1964, P-699

करने वाली प्राचीन घटनाओं की सम्पूर्ण कहानी है। किसी भी विषय के अध्ययन में ऐतिहासिक उपागम प्राचीन जीवन के कुछ रूपों को जोड़ने का एक प्रयास है! ऐतिहासिक शोध का सम्भावित क्षेत्र उतना ही बड़ा है जितना स्वंय जीवन है! ऐतिहासिक शोधा मानव वंश के अतीत का एक विश्वसनीय तथा अर्थपूर्ण आलेख है जो उसके विस्तृत एवं अधिक सामान्य रूपों को कार्यान्वित करता है। जैसा कि प्रस्तुत शोधकार्य एक ऐतिहासिक अध्ययन है और इस अध्ययन के ज्ञान से उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश काल और उसके बाद हुये उच्च शिक्षा के विकास का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया जायेगा!

ब. वर्णनात्मक विधि

अतीत में जो कुछ विद्यमान था उसको खोजना, उसका वर्णन करना तथा उसकी व्याख्या करना ऐतिहासिक अध्ययनों का कार्य है, परन्तु कुछ अन्य प्रकार के अनुसंधान भी होते है जो वर्तमान में विद्यमान तथ्यों का अध्ययन, वर्णन एवं व्याख्या करते है! उनका सम्बन्ध-वर्तमान में उपस्थित स्थितियों अथवा सम्बन्धों, प्रचलित व्यवहारो, विश्वासों, दृष्टिकोणों या अभिवृत्तियों जो कि स्थापित हो चुके है, प्रक्रियाएं जो कि गतिशील है, प्रभाव जो कि अनुभव किये जा रहे है, प्रवृत्तियां जो कि विकसित हो रही है- इन सबसे होता है। इस प्रकार के अनुसंधानों के अर्न्तगत वर्णनात्मक, सर्वेक्षण, आदर्शमूलक, स्तर या प्रवृति जैसी अभिवृत्तियां सम्मलित होती है।

वर्णनात्मक विधि में अपेक्षाकृत संख्या में अधिक मामलों से दत्त एकत्र किये जाते है! इस विधि का सम्बन्ध व्यक्तियों की विशेषताओं से न होकर पूर्ण जनसंख्या या उसके न्यादर्श की सामान्यीकृत सांख्यिकी से होता है! यह अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित समस्या तथा निश्चित उद्देश्य सम्मलित होते है! इसके लिये कल्पना प्रधान आयोजन, दत्तों का सावधानीपूर्ण विश्लेषण एवं व्याख्या तथा निष्कर्षो की तर्कयुक्त एंव निपुणता पूर्ण प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है। इस विधि में वैज्ञानिक नियमों के संगठित स्वरूप को विकसित करने की आकांक्षा नहीं की जाती, वरन् केवल स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी जानकारी प्रदान की जाती है फिर भी वह अधिक मौलिक प्रकृति के अनुसंधान का आधार निर्मित करने हेतु दत्त प्रस्तुत कर सकता है। जटिलता की दृष्टि से वर्णन पर्याप्त रूप से विविधतापूर्ण होते है, कुछ वर्णन घटनाओं की आवृत्तियों

से सम्बन्धित होते है, जबकि अन्य घटनाओं के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करते है! वर्णन गुणात्मक या संख्यात्मक दोनों ही प्रकार के हो सकते है! एक स्तर के वर्णन में विभिन्न तथ्यों, विभिन्न अंगों के नाम प्रस्तुत करने एवं उनको परिभाषित करने का कार्य सम्मलित होता है। दूसरे स्तर पर उनमें अंगों या विशेषताओं की मात्रा का निर्धारण सम्मलित है! वर्णन या तो शाब्दिक हो सकता है अथवा गणितीय संकेतों में व्यक्त किया जा सकता है! नये क्षेत्र में अनुसंधान के लिये परिचय प्राप्त करने की अवस्था के रूप में इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है।

वैज्ञानिक बहुधा वर्णनात्मक विधि द्वारा किये गये अनुसंधानों की गणना उत्कृष्ट प्रकार के अनुसंधानों में नहीं करते परन्तु जिस प्रकार की जानकारियां वर्णनात्मक विधि द्वारा प्राप्त की जाती है, उनकी अत्यधिक माँग है।

यह विधि वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करती है तथा वर्तमान व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण करती हैं। इस विधि के द्वारा विभिन्न समयों पर समान दशाओं अनुप्रस्थ काट के चित्रों को श्रंखलाओं के द्वारा ऐतिहासिक न्यादर्श की प्राप्ति होती है। यह विधि भावी विकासों के क्रम की ओर संकेत करती है। यद्यपि यह उल्लेखनीय ढंग से अग्रदर्शी नहीं है तथापि यह आवश्यकताओं की और ध्यान आकर्षित करने, सामान्य से अच्छे रीति रिवाजों को स्पष्ट करने, अग्रदर्शी व्यक्तियों (जो भविष्य के लिये योजना बनाने में संलग्न है) को उचित दत्तों को प्रदान करने के लिये प्रयुक्त की जा सकती हैं। यह विधि ज्ञान के विकास में योग देती है, क्योकि यह किसी व्यक्ति के कार्य (जिसे वह कर रहा है) की प्रकृति के लिये तीक्ष्ण दृष्टि प्रदान करती है। यह विधि पृष्ठभूमि के विचार और दत्त प्रस्तुत करती है जिनसे कई कारणात्मक सम्बन्धों के शोधित प्रयोगात्मक एवं नियन्त्रित अध्ययन किये जा सकते है।

2. प्रस्तुत शोध कार्य में प्रयुक्त उपकरण

साधित अथवा असाधित उचित परिस्थितियों में, चाहे वे नियंत्रित हो या अनियंत्रित, व्यक्ति के बाह्य व्यवहार के अध्ययन हेतु अवलोकन अनुसंधान के उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है! सिद्धान्ततः यह न तो साक्षात्कार के समय व्यक्ति क्या कहता है उससे सम्बन्धित होता है, और न उससे सम्बन्धित

होता है, जिस पर कि कोई व्यक्ति छपे हुये प्रपत्र पर चिन्ह अंकित करता है। यह नियमहीन अथवा आयोजनहीन नहीं होता है! अवलोकन अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधि है! पी. वी. यंग के शब्दों में, " Observation is a systematic and deliberate study through the eye of spontaneus occurrences at the time they occur. The purpose of observation is to perceive the nature and extent of significant interrelated elements within complex social phonomena. culture pattern or human conduct," [3]

अवलोकन व अनुसंधान तकनीक के रूप में परिशोधन एवं विकास उस सीमा तक किया जा रहा है कि सम्भवतः वर्णनात्मक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके! सामाजिक अनुसंधानों में अवलोकन का व्यापक उपयोग किया जाता है। वास्तव में सामाजिक अनुसंधान की यह सर्वप्रचालित विधि है! अवलोकन विधि में ज्ञान इन्द्रियों विशेषताः नेत्रों का विस्तृत उपयोग किया जाता है। अतः सम्बन्धित घट्नाओं का आनुभविक अध्ययन इस विधि के उपयोग का एक प्रमुखतः विशेष गुण है। इस विधि के द्वारा वास्तविक व्यवहार के अध्ययन की अपूर्व सुविधा रहती है, क्योकि इसमें अध्ययन घट्ना से सम्बन्धित प्राकृतिक परिवेश में ही किया जाता है प्रयोगशाला के कृत्रिम परिवेश में नहीं! अवलोकन के द्वारा एक व्यवहार, घट्ना व स्थिति के विभिन्न पक्षों का व्यापक अध्ययन लगभग पूर्ण रूप से सम्भव तथा साध्य रहता है। इसके द्वारा एक समुदाय के सामाजिक जीवन का एक सफल तथा सजीव चित्रण प्रायः सरलत.पूर्वक प्रस्तुत किया जा सकता है। अवलोकन विधि का उपयोग एक समस्या के गहन अध्ययन की पूर्व स्थिति के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का कार्य करता है।

अवलोकन के माध्यम से एक सामाजिक स्थिति के प्रति अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का विस्तृत ज्ञान उपलब्ध होता है ऐसे ज्ञान के आधार पर विभिन्न वैज्ञानिक परिकल्पनाओं की रचना में अवलोकन विधि के उपयोग से विशेष योगदान मिलता है। अवलोकन विधि द्वारा दो या दो से अधि
ाक चरों के पारस्परिक अन्तर्सम्बन्धों का गहन अध्ययन किया जा सकता है। चूँकि एक व्यवहार, घट्ना अथवा स्थिति से सम्बन्धित अध्ययन अवलोकन विधि से उसके सम्बन्धित स्थानीय परिवेश में ही सम्पन्न किया जाता है अतः इस विधि से प्राप्त निष्कर्षो की वैद्यता का स्तर प्रायः उच्च श्रेणी का रहता है।

3. Young P. V. Scientific Social Survey and Research(Prentice Hall) 1956 P. 154

अवलोकन विधि से एक सम्बन्धित घटना का निरंतर अध्ययन किया जा सकता है अतः इस विधि से निश्चित व सुसंगत परिणामों की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध रहती है, जिससे प्राप्त निष्कर्षो की विश्वसनीयता का स्तर भी प्रायः उच्च श्रेणी का रहता है। अवलोकन के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष पर्याप्त मात्रा में उच्च स्तर के होते है और इस प्रकार के निष्कर्षो के आधार पर दी गयी स्थिति में भविष्य कथन की पर्याप्त क्षमता सुलभ रहती है। शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोधकार्य को पूरा करने के लिये अवलोकन विधि का प्रयोग किया है।

चतुर्थ अध्याय

चतुर्थ अध्याय

अ. ब्रिटिश कालीन उच्च शिक्षा का स्वरुप

मध्य युगीन भारत में विश्वविद्यालय मानदन्डो के अनुसार विश्वविद्यालय नहीं थे। वैदिक युगीन विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य समाप्त प्रायः हो गया। मुस्लिम शिक्षा के अर्न्तगत विश्वविद्यालयों का निर्माण नहीं हुआ। यद्यपि कई मकतब उच्च शिक्षा के लिये अत्यन्त प्रसिद्ध थे। तथापि उन्हें विश्वविद्यालय की कोटि में नही रखा जा सकता। सामान्यतः इस युग मे शिक्षा मन्दिरो, मस्जिदो, निजी आवासों आदि तक ही सीमित थीं। पाश्चात्य जगत में भी शिक्षा प्रारम्भ से चर्च के ही जिम्में थी।

ब्रिटिश शासन काल में ईस्ट इंडिया कम्पनी को प्रदत्त 1813 के आज्ञापत्र का विशेष महत्व है। इस आज्ञापत्र के द्वारा भारतीय जनता की शिक्षा को निश्चयात्मक रूप से कम्पनी के कर्तव्यों में समाविष्ट कर दिया गया। शैक्षिक क्रियाकलापों के लिये प्रतिवर्ष अपेक्षाकृत धनराशि प्राप्त कर ली गयी। 1813 के आज्ञापत्र में दी हुई धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में शिक्षा समिति दो भागों में विभक्त हो गई। प्राच्यवादी इस धनराशि को भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के शिक्षण एवं उत्थान में व्यय करने के पक्ष में थे। इसके विपरीत पाश्चात्यवादी इस अनुदान को योरोपीय साहित्य, विज्ञान शिक्षण में बल दे रहे है। यह विवाद पर्याप्त समय तक चलता रहा। इस विवाद की समाप्ति मैकाले, जो इस समय गर्वनर जनरल की काउंसिल का लॉ मेम्बर था। के विवरण पत्र के प्रकाश में आने के पश्चात समाप्त हुई।

मैकाले का विवरण पत्र सन् 1835 में प्रकाश में आया । मैकाले सामान्य शिक्षा समिति का सदस्य होते हुये भी इसके बैठकों में होने वाले विवाद में भाग नहीं लेता था क्योंकि वह जनता था कि कार्यकारिणी परिषद का सदस्य होने के कारण यह विषय पुनः उसके सामने उपस्थित होगा। अतः जब इस विवाद से सम्बन्धित विषय परिषद के सम्मुख आया तो मैकाले ने नई शिक्षा नीति सम्बन्धी अपना विवरण पत्र तैयार किया। यह 2 फरवरी, 1835 को गर्वनर जनरल के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। भारतीय शिक्षा जगत में इसका ऐतिहासिक महत्व है। आज भी मैकाले की शिक्षा नीति के विरोध की बात की जाती है। यद्यपि उसने जो बिन्दु अपने विवरण पत्र में मुख्य रूप से रख ये वे थे - विज्ञान और अंग्रेजी की शिक्षा।

मैकाले ने 1813 के आज्ञापत्र की धाराओं को अपने विवरण पत्र में आंगलिक दल के पक्ष में विश्लेषित किया। मैकाले द्वारा अपने मत के सर्मथन में प्रस्तुत की गई युक्तियों को लार्ड विलियम वेटिंग ने स्वीकार कर लिया। मैकाले के विवरण पत्र ने बंगाल, बम्बई तथ मद्रास आदि प्रेसिर्डेसियों में प्राच्य तथा पाश्चात्य शिक्षा सम्बन्धी विवाद को समाप्त कर दिया तथा उच्च शिक्षा ने एक निश्चित दिशा ग्रहण की। मैकाले के विवरण पत्र के फलस्वरूप ही भारत में भावी विश्वविद्यालयों की नीवं स्थापित हुई।

सन् 1854 के बुड के घोषणापत्र में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु अनुमोदन किया। 19 जुलाई, 1854 का आज्ञापत्र प्राप्त होने के पश्चात ही भारत सरकार ने सन् 1857 में विश्वविद्यालय अधिनियम के अर्न्तगत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु कार्य आरम्भ कर दिया। प्रारम्भिक कार्य अत्यन्त कठिन था। भारत सरकार ने इन तीनों विश्वविद्यालयों के निगमन अधिनियम 1857 में ही बना लिये थे। स्थानीय स्वरूप के कुछ परिर्वतनों के अतिरिक्त ये तीनों अधिनियम एक समान थे। इन विश्वविद्यालयों के लिये एक निगमित निकाय का गठन किया गया। प्रथम कुलाद्यिपति, कुलपति एवं अध्येताओं को इनमें मनोनीत किया। विश्वविद्यालय की सीनेट में कुलद्यिपति, कुलपति और पदेन एवं साधारण दोनों ही प्रकार के अध्येता होते थे। अधिनियम में सीनेट को दैनिक कार्यो के संचालन का अधिकार दिया गया था।

उपयुक्त विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित अधिनियम सर्वथा दोषमुक्त नहीं थे। सीनेट में अध्येताओं की संख्या सीमित नहीं थी इसका परिणाम यह हुआ कि सीनेट का आकार बढ़ जाने से उनका कार्य सहज रूप से नहीं चल सका। विश्वविद्यालयों की परम्परानुसार अभिषद (सिंडीकेट) नामक एक छोटा अधिशाषी निकाय हो और उसे दैनन्दिन प्रशासन का कार्य सौपा जाये परन्तु अधि ानियम में अभिषद का कोई उल्लेख नहीं किया गया और सम्पूर्ण शक्तियां केवल सीनेट को दे दी गयी। अधिनियमों की प्रस्तावना ने विश्वविद्यालयों के कार्यो को केवल परीक्षा लेने और उपाधियां देने तक सीमित कर दिया। निः सन्देह यह कार्य लन्दन विश्वविद्यालय के संविधान के साथ सामंजस्य रखने के लिये किया गया था।

सन् 1857 के अधिनियम द्वारा जिस प्रकार विश्वविद्यालय संस्था का सृजन किया गया उसे तकनीकी दृष्टि से सम्बन्धन विश्वविद्यालय कहा जाता है। इस प्रकार की संस्था में सम्बद्ध महाविद्यालय उच्च शिक्षा के वास्तविक केन्द्र होते है। और स्वंय विश्वविद्यालय शिक्षण इकाई

न होकर केवल प्रशासन की एक इकाई होता है। जिसका एक मात्र कार्य परीक्षाएं लेना एवं उपाधियों देना होता है।

विश्वविद्यालयों की स्थापना होने और भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किये जाने के मध्य 25 वर्षों का अन्तराल रहा और इस मध्य महाविद्यालयों का द्रुतगति से विस्तार हुआ इसका प्रमुख कारण माध्यमिक शिक्षा का द्रुतगति से विकास एवं सरकार द्वारा उदार प्रोत्साहन था।

भारतीय शिक्षा आयोग (हन्टर कमीशन) 1882 के प्रतिवेदन से विश्वविद्यालयी शिक्षा में कोई सुधार नहीं हुआ। आयोग के कार्य क्षेत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि महाविद्यालय शिक्षा में रूचि रखने वाले सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को लेकर गठित किये गये निगमों के नियंत्रण में कार्य करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों के सामान्य कार्यक्रम की जाँच करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इन विश्वविद्यालयों के कार्य के परिणाम के सम्बन्ध में सदैव स्वतन्त्र रूप से ही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आयोग को वृत्तिक महाविद्यालय का अध्ययन करने का भी प्रतिबन्ध किय गया है। क्योंकि इससे उसका कार्य आवश्यक रूप से बढ़ जायेगा। अतः आयोग महाविद्यायलीय शिक्षा का विशद अध्ययन नहीं कर सका इसलिये इस सम्बन्ध में उसने जो अनुसंशाएं की वे प्राथमिक अथवा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अनुसंशाओं की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है।

भारतीय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालयों मे शिक्षा प्रदान करने हेतु माध्यम निशिचत करने का प्रयास किया। इसके अनुसार आधुनिक भारतीय भाषायें इस योग्य नहीं है कि इनके माध्यम से महाविद्यालयीय शिक्षा प्रदान की जा सके अतः महाविद्यालयीय चरण में आधुनिक भारतीय भाषाओं को शिक्षा माध्यम के रूप में स्वीकार किये जाने की कोई गुजांइश नहीं रही। सन् 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग को विश्विद्यालय सम्बन्धी सुधारों के विषय में प्रतिवेदन देने से प्रतिबंधित कर दिया गया था अतएव इस आयोग ने विश्वविद्यालयीय सुधारों के सम्बन्ध में अपनी अनुसंशाएं प्रस्तुत नहीं की। इस प्रकार सन् 1902 तक विश्वविद्यालयीय शिक्षा में कोई विशेष परिर्वतन नहीं हुये।

सन् 1898 में लार्ड कर्जन भारत का वाइसराय नियुक्त हुआ। उसने अपने कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों के सुधार में सर्वोच्य प्राथमिकता इसलिये प्रदान की थी कि उसके अनुसार

विश्वविद्यालय स्तर पर अत्यन्त कठिन प्रयत्न करने की आवश्यकता थी अतः भारत आने के कुछ समय बाद ही उसने अपने शिक्षा कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों में व्याप्त दोषों के कारण उनके सुधार को प्राथमिकता दी। अभी तक विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने और डिग्रियां प्रदान करने का कार्य कर रहे थे। उनका छात्रों से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था। सन् 1904 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को सम्बोधित करते हुये कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति की कड़ी आलोचना की और कहा कि आदर्श विश्वविद्यालय के दो पहलू होने चाहिये, उसे ज्ञान के प्रसार और विषय के प्रोत्साहन का स्थान होना चाहिये। और उसे एक मानवीय कारखाना होना चाहिये जहाँ चरित्र का निर्माण अनुभव रूपी अग्निशाला में किया जाये और जहाँ उसको सत्य की कसौटी पर कसा जाये।

लार्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालयों के सामने एक नया आदर्श रखा। यह आदर्श था। ऑक्सफोर्ड और क्रैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों का। वहाँ कालेज और विश्वविद्यालय एक दूसरे के अभिन्न अंग थे। वहाँ विश्वविद्यालय छात्रों की शिक्षा, परीक्षा और अनुशासन पर पूर्ण अधिकार रखते थे। वे छात्रों के जीवन को प्रभावित करते थे और उनके चरित्र का निर्माण करते थे। भारतीय विश्वविद्यालय इन सभी बातों से बहुत परे थे अतः कर्जन का विचार था कि भारतीय विश्वविद्यालयों में सुधार किये जाने की आवश्यकता थी।

कर्जन ने सुधार इसलिये भी आवश्यक समझा क्योंकि जब से विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी तब से किसी ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया था फलतः उनका रूप रंग बिरंगा हो गया था। कालेजों की संख्या बहुत अधिक हो जाने के कारण उनका कार्यभार बहुत बढ़ गया था। सीनेट के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं थी जिसके कारण वे आवश्यकता से अधिक हो गये थे। सीनेट में अध्यापकों का कोई प्रतिनिधित्व नही था। मान्यता देने और परीक्षा लेने के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों का कालेजों पर कोई नियंत्रण नहीं था। इनकी और इन सम्बन्धित कारणों की जाँच की जानी थी अतः कर्जन ने एक आयोग नियुक्त करने का निश्चय किया।

अपने निश्चय के अनुसार, कर्जन ने 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। नियुक्ति की घोषणा के समय आयोग में किसी भारतीय को स्थान नही दिया गया था पर कुछ समय के बाद थोड़ा सोचविचार करके इसमे दो भारतीयों को स्थान दिया गया। ये भारतीय थे। डाक्टर गुरुदास बनर्जी और सैयद हसन विलग्रामी। इस आयोग का कार्य

ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में स्थापित किये गये विश्वविद्यालयों की दशा और उनके कार्यो के सम्बन्ध में जाँच करना और उनके संगठन एवं कार्य संचालन को सुधारने के उपायों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। आयोग ने अपना प्रतिवेदन उसी वर्ष प्रस्तुत कर दिया। इसी प्रतिवदेन के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 निर्मित हुआ। सन् 1857 के अधिनियम के अर्न्तगत सीनेट का आकार बहुत बड़ा हो गया था अतः सन् 1904 के अधिनियम के अर्न्तगत यह व्यवस्था की गयी कि सीनेट में अध्येताओं की संख्या 50 से कम और 100 से अधिक नहीं होगी और अध येता जीवन पर्यन्त पद पर रहने के बजाय केवल 5 वर्ष के लिये ही पद ग्रहण करेगे। 1904 के अधिनियम के द्वारा निर्वाचन के सिद्धान्त को लागू कर दिया गया और इसके अनुसार अब तीन विश्वविद्यालयों में बीस और अन्य दो विश्वविद्यालयों (पंजाब और इलाहाबाद) में 15 अध येता निर्वाचित हो।

अधिनियम द्वारा तीसरा परिर्वतन यह किया गया कि अभिषदों को सर्वाधिक मान्यता प्रदान की गयी और विश्वविद्यालय के अध्यापकों को सम्बन्धित अभिषदों में पर्याप्त प्रतिनिधि त्व दिया गया।

अधिनियम द्वारा चौथा परिर्वतन यह था कि विश्वविद्यालय से महाविद्यालय के सम्बद्ध होने की शर्ते कड़ी कर दी जाये।

अधिनियम का पॉचवा परिर्वतन यह था कि इस अधिनियम ने गर्वनर जनरल को यह अधिकार दे दिया कि वह विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाओं को निश्चित कर दे। 1857 के अधिनियम में इस विषय को भविष्य के लिये छोड़ दिया गया था।

अधिनियम द्वारा छ्टा परिर्वतन यह किया गया था कि सीनेट द्वारा बनाये जाने वाले विनियमों के सम्बन्ध में सरकार को कुछ अधिकार दे दिये गये। सन् 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी थी कि सीनेट द्वारा बनाये गये विनियमों का अनुमोदन करते समय सरकार आवश्यक परिर्वतन कर सकती है और यदि सीनेट एक निर्दिष्ट अवधि में विनियम बनाने में असमर्थ रहती है तो वह विनियम भी बना सकती है।

अधिनियम का सातवॉं परिर्वतन यह था कि विश्वविद्यालय से महाविद्यालय के सम्बद्ध होने की शर्ते अधिक कड़ी कर दी गयीं और यह व्यवस्था की गयी कि अभिषद महाविद्यालयों का निरीक्षण करेंगे और उनकी कार्यकुशलता का अवलोकन करने के उपरान्त ही

मान्यता एवं सम्बन्धन हेतु अनुमोदन करेगे।

उपर्युक्त अधिनियम भी सन् 1857 के अधिनियम की भांति त्रुटिपूर्ण था। 1904 के अधिनियम में विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं था। दूसरी बात यह थी कि निर्वाचन सिद्धान्त स्वागत योग्य था परन्तु निर्वाचन के लिये रखे गये स्थानों की संख्या न्यून थी तीसरी बात यह थी कि विश्वविद्यालय में अध्येताओं की संख्या सीमित कर दी गयी दूसरे सरकार का आशय था कि भारतीय विश्वविद्यालय के संगठन में योरोपीय लोगों का बहुमत हो जाये। चौथी बात यह थी कि महाविद्यालयों के सम्बन्धन और असम्बन्धन के लिये अब उपबन्धों को और कड़ा कर दिया गया इससे पुर्नगठित विश्वविद्यालय निकायों में अधिकाशतः योरोपीय लोग आ गये। अन्ततः सर्वाधिक त्रुटि यह थी कि अधिनियम में ऐसे उपबन्धों का प्रावधान किया गया कि सरकार को विश्वविद्यालयों के प्रशासन में अधिक अधिकार प्राप्त हो गये।

उल्लिखित त्रुटियों के होते हुये 1904 के अधिनियम की अपनी विशेषताएं थी यदि सामान्य दृष्टि से विचार किया जाये तो ज्ञात होगा कि अधिनियम का घोषित लक्ष्य विश्वविद्यालयों के प्रशासन को पूर्व काल की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल बनाना था और उसे इस कार्य में यथेष्ट सफलता मिली। महाविद्यालयों के सम्बन्धन सम्बन्धी शर्तो को कड़ा कर देने से दुर्बल महाविद्यालय समाप्त हो गये। अन्तिम बात यह थी कि इस अधिनियम के कारण ही भारतीय विश्वविद्यालयों को प्रथम अनुदान उपलब्ध हुआ।

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को अधिक सफलता नहीं मिली अतः इस अधिनियम द्वारा सम्पन्न किये गये कार्य को सुरक्षित रखते हुये इस बात को भी सामान्य रूप से समझा गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में सरकारी नीति को और भी व्यापक बनाया जाये। इंग्लैड़ की गतिविधियों का प्रभाव भी इस आन्दोलन पर पड़ा। ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के इतिहास में 1903-13 का काल अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस काल में विश्वविद्यालय व्यावस्था की मूल समस्या पर पुर्नविचार किया गया। विशेषज्ञों की राय थी कि विश्वविद्यालय का संघीय स्वरूप संतोषप्रद नहीं है। अतः 1913 के आसपास संघीय स्वरूप वाली व्यवस्था का परित्याग कर दिया और अधिकांश विश्वविद्यालयों को एकात्मक एवं आवासीय संस्थानों के रूप में पुर्नगठित किया गया। इन गतिविधियों की गूँज भारत में भी हुई अतः सरकार को विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बनने

के एक दशक के अन्दर ही इस समस्या पर पर्नुविचार करना पड़ा। यह कार्य 21 फरवरी, 1913 के शिक्षा नीति सम्बन्धी सरकारी संकल्प में किया गया। इस संकल्प में विश्वविद्यालयीय शिक्षा सम्बन्धी अनेक घोषणाएं की गयी परन्तु इन घोषणाओं को क्रियान्वित करने के पूर्व विशेषज्ञों द्वारा जाँच करा लेना आवश्यक समझा गया।

1917 में सरकार ने उपर्युक्त समस्या का अध्ययन करने और प्रतिवेदन देने के लिये डा. एस. ई सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यांलय आयोग नियुक्त किया गया, इसके सदस्य अनेक भारतीय विद्वान भी थे। आयोग का प्रतिवेदन अर्न्तप्रान्तीय महत्व का था यद्यपि यह कलकत्ता विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में था तथापि प्रतिवेदन का सम्पूर्ण भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा।

21 फरवरी, 1913 के शिक्षा नीति सम्बन्धी सरकारी संकल्प और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917-19 के प्रतिवेदन के परिणामस्वरूप 1917-22 की अवधि में अनेक नवीन विश्वविद्यालयों का सृजन हुआ। यह बात ध्यान देने योग्य है कि 1854 को वुड के घोषणा पत्र के आधार पर 1857 में विश्वविद्यालयीय सम्बन्धी अधिनियम पारित हुआ था इसके द्वारा कलकत्ता, मद्रास, और बम्बई में लन्दन विश्वविद्यालय के समान विश्वविद्यालयों का सृजन हुआ था। 1867 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किये गये थे। सभी सम्बन्धन विश्वविद्यालय थे। सन् 1916 तक इन पाँच विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं की गयी यद्यपि इस अवधि में महाविद्यालयों एवं उनमें ज्ञानार्जन करने वाले छात्रों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई इस वृद्धि के फलस्वरूप विद्यमान विश्वविद्यालयों का कार्य पर्याप्त बढ़ गया इसलिये नये विश्वविद्यालयों के खोलने का निर्णय एक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जिन नये विश्वविद्यालयों का सृजन हुआ उनके सम्बन्ध में टिप्पणी निम्नलिखित है। सन् 1915 में एक अधिनियम द्वारा बनारस में एक अध्यापन एवं आवासीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया और 1917 में उसने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। यह विश्वविद्यालय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात है। यह पंडित मदन मोहन मालवीय के महान कार्य के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। यह विश्वविद्यालय केन्द्र सरकार के आधीन है।

सन् 1920 में अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया। यह विश्वविद्यालय स्वर्गीय सर सैयद अहमद खान के महान कार्यो

का एक जीवित स्मारक है। यह विश्वविद्यालय केन्द्र सरकार के अधीन है।

सन् 1921 में लखनऊ में एक विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया।

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि 1916-20 के मध्य आवासीय एवं सम्बन्धान विश्वविद्यालयों का विकास हुआ इनसे सम्बन्धित महाविद्यालयों की भी स्थापना हुई। विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता में भी वृद्धि की गयी। अनेक आधुनिक विषयों का प्रावधान किया गया। कुछ विश्वविद्यालयों में आचार्य पदों की स्थापना की गई। श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा भाषण माला का आयोजन किया जाता था। विश्वविद्यालयों में संकाय अध्यक्षों की नियुक्तियां की गयी।

सन् 1920-21 के मध्य राष्ट्रीय एवं राजनैतिक चेतना का अर्विभाव हुआ। इसके परिणामस्वरूप अनेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रकाश में आये। महात्मा गाँधी ने तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था को परतंन्त्रता का प्रतीक माना और उन्होनें समूची शिक्षा की संकल्पना को देश के समक्ष प्रस्तुत किया, इसकी आवश्यकता इसलिये भी पड़ी कि गाँधी जी ने इसी समय असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था जिसका नारा था - शिक्षकों, विद्यार्थियों, का स्वतंत्रता के युद्ध में भाग लेने के लिये आवाहन और उसी क्रम में राष्ट्रीय स्कूलों तथा राष्ट्रीय विद्यापीठो (विश्वविद्यालयो) की स्थापना। गाँधी जी स्वयं गुजरात विद्यापीठ के आजीवन कुलाधिपति रहें। ये विश्वविद्यालय भारतीय राष्ट्रीय चेतना तथा संस्कृति को मूलभूत मानकर शिक्षा प्रदान करते थे। ये सेवा सहिष्णुता, आत्म नियंत्रण और आत्म संयम की भावना पैदा करते थे। आत्म प्रकाशन के लिये निंरतर अवसर प्रदान करते थे। इस सदंर्भ में जामिया मिलिया इस्लामियाँ, दिल्ली, गुजरात, बिहार तथा काशी के विद्यापीठों का उल्लेख किया जा सकता है। महाकवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने शान्ति निकेतन का प्रयोग इस शताब्दी के प्रारम्भ में किया था जो प्राचीन उपनिषदों की शिक्षण कला (शिक्षा शैली) के अनुरूप था और स्वतंत्रता के बाद उच्चतम शिक्षा का एक अर्न्तराष्ट्रीय केन्द्र बन गया। बाद में उसे औपचारिक विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता भी मिल गयी। इसी अवधि में गुरूकुल विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1902 में आर्य प्रतिनिधि सभा ने पंजाब में गुरूकुल विश्वविद्यालयों की स्थापना की।

भारत सरकार ने सन् 1919 में पुनः एक अधिनियम जारी किया। इस अधिनियम द्वारा लागू किया हुआ संविधान द्वैध शासन प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध है। इस द्वैध शासन प्रणाली के अधीन प्रणाली प्रान्तीय सरकार के क्रियाकलाप के क्षेत्र को दो भागों में बाँट दिया

गया – आरक्षित विभाग और अंतरित विभाग, राज्यपाल को, जो प्रान्तीय सरकार का शासनाध्यक्ष था, कुछ कार्यकारी पार्षदों की सहायता से आरक्षित विभागों का प्रशासन करना था तथा उनके उचित प्रबन्ध के लिये भारतीय कार्य मंत्री के प्रति उत्तरदायी रहता था। इसके अतिरिक्त उससे यह भी आशा की जाती थी। कि वह अंतरित विभागों का उन मंत्रियों की सहायता से प्रशासन करेगा जो भारत मंत्री के प्रति उत्तरदायी नहीं वरन् एक ऐसे प्रान्तीय विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी थे जिसमें निर्वाचित लोगों का भारी बहुमत था। प्रान्तीय कार्यपालिका के दो भागों में बँट जाने के कारण ही इस प्रणाली का नाम द्वैध शासन पड़ा और इसी असमान्य ढंग के राजनीतिक संविधान के कारण पहली बार भारतीयों का शिक्षा विभाग पर नियंत्रण हुआ।

सन् 1919 के अधिनियम में वित्तीय व्यवस्था इस प्रकार की गयी थी कि भारतीय मंत्रिमण्डल अपने कार्यो को सुचारू रूप से संचालन करने में असमर्थ थे। द्वैध शासन प्रणाली की दूसरी विशेषता यह थी कि देश की शिक्षा सेवाओं पर भारतीय मंत्रियों का निंयत्रण बहुत सीमित था। इस अधिनियम की तीसरी विशेषता यह थी कि प्रान्तीय सरकारों को केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता अचानक बन्द हो गई। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप शासकीय एवं अशासकीय क्षेत्रो में अत्याधिक असंतोष बढ़ गया। इस अंसतोष को देखते हुये सन् 1927 में एक राजकीय आयोग की नियुक्ति हुई। इस आयोग ने अपनी सहायता के लिये एक सहायक समिति की नियुक्ति की। यह हरटोग समिति के नाम से प्रसिद्ध है। इस समिति का प्रतिवेदन तत्कालीन समय का अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

सामान्यतः 1921 से 1937 तक विश्वविद्यालीय शिक्षा में पर्याप्त प्रगति हुई। इस काल में अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड, नये विश्वविद्यालयों का निगमन, प्राचीन सम्बन्धन, विश्वविद्यालयों में परिवर्तन, विश्वविद्यालयीय शिक्षा का प्रसार, अनुसंधान की व्यवस्था तथा इण्टरमीडिएट कालेजों का सूत्रपात हुआ।

भारत पूर्ण राजनीतिक स्वाधीनता की और जो प्रयास कर रहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 उस प्रयास में आगे की ओर बढ़ाया गया एक अगला कदम था इस अधिनियम ने प्रशासन की सहज रूप से दोषपूर्ण द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, आरक्षित और अंतरित विभागों का भेद खत्म कर दिया गया। यह मंत्रालय एक ऐसे विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी था जिसमें निर्वाचित सदस्यों का प्रचुर बहुमत था। यह नई शासन प्रणाली प्रान्तीय

स्वशासन के नाम से प्रसिद्ध है।

1919 में अधिनियम में शिक्षा को एक ऐसा विषय बना दिया था जो अंशतः अखित भारतीय, अंशतः आरक्षित, अंशतः परिसीमाओं के रहते हुये अंतरित और अंशतः परिसीमाओं के बिना अंतरित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने इस असंगत स्थिति में काफी सुधार किया और सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलापों को केवल दो श्रेणियों में विभक्त कर दिया, ये श्रेणियां थी – संघीय (केन्द्रीय) और राज्य (प्रान्तीय) क्रियाकलापों का विभाजन निम्नलिखित ढंग से किया गया था।

संघीय अथवा केन्द्रीय विषय-

1. साम्राज्यिक पुस्तकालय, कलकत्ता, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता, साम्राज्यिक युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक, कलकत्ता, और संघ द्वारा नियंत्रित अथवा अर्थयुक्त की गई कोई अन्य सदृश संस्था।
2. रक्षा सेवाओं मे शिक्षा
3. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
4. प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का परीक्षण,
5. पुरातत्व
6. केन्द्रशासित क्षेत्रों में शिक्षा

राज्य अथवा प्रान्तीय विषय-

जिन विषयों को उपयुक्त संघीय सूची में शामिल कर लिया गया है उन्हें छोड़कर शिक्षा सम्बन्धी सभी विषयों को राज्य अथवा प्रान्तीय विषय माना गया था।

द्वैध शासन की समाप्ति के साथ ही आरक्षित और अंतरित विषयों का पुराना भेद समाप्त हो गया और आंगल भारतीयो तथा योरोपीय लोगों को शिक्षा आरक्षित विषय नहीं रही। भारत सरकार अधिनियम 1935 से केन्द्रीय सरकार का स्वरूप नहीं बदला क्योंकि उस के द्वारा अपेक्षित संघ 1947 तक नहीं बना अतः सम्पूर्ण विचाराधीन काल में केन्द्रीय सरकार ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी बनी रही तो भी 1946 में जब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अन्तरिम मंत्रिमण्डल बनाया तो केन्द्रीय सरकार का शिक्षा विभाग पहली बार राष्ट्रवादी नियंत्रण में आया। 15 अगस्त 1947 को उसे एक पूर्ण मंत्रालय बना दिया गया और मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रथम संघीय शिक्षा मंत्री बने।

ब. ब्रिटिश कालीन उच्च शिक्षा के विभिन्न आयोगों एवं समितियों का विकासात्मक अध्ययन

ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा के विकास के लिये सरकार के द्वारा विभिन्न आज्ञापत्र, विवरणपत्र जारी किये गये, विभिन्न योजनाएं जारी की गयी, विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठ्न किया गया।

इन सभी का क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है।

1. वुड के घोषणापत्र से पहले घोषित किये गये विभिन्न आज्ञापत्र विवरण पत्र एंव घोषणापत्र

1793 का आज्ञापत्र (Charter of 1793)

इस चार्टर में भारत वासियों की शिक्षा की व्यवस्था के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत किये गये परन्तु उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में पृथक रूप से कोई भी सुझाव प्रस्तुत नहीं किया गया।

मिन्टो का विवरण पत्र - 1811

लार्ड मिन्टो ने मार्च सन् 1811 ई. को एक विवरणपत्र प्रस्तुत किया जिसमें शिक्षा के विभिन्न तत्वों का वर्णन किया गया परन्तु उच्च शिक्षा के विकास के लिये कोई सुझाव प्रस्तुत नहीं किये गये।

1813 का आज्ञापत्र (Charter of 1813)

सन् 1813 ई. मे कम्पनी को पुनः भारत में अपने प्रदेशों का शासन करने के लिये नया आज्ञापत्र अंग्रेजी संसद से प्राप्त हुआ उसमें उल्लेख किया गया कि एक लाख रूपये की व्यवस्था प्रतिवर्ष साहित्य के पुनरूद्धार एवं विकास के लिये, विद्वान नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिये, विज्ञान में ज्ञान के वृद्धि करने के लिये की जाये। परन्तु इस आज्ञापत्र में उच्च शिक्षा के लिये कोई भी सुझाव प्रस्तुत नहीं किये गये। एक लाख रूपये के खर्च के लिये निश्चित दिशा निर्देश नहीं दिये गये। शिक्षा नीति में शिक्षा के माध्यम को भी स्पष्ट नहीं किया गया। इस आज्ञापत्र में एक विवादित विषय यह भी था कि क्या उच्च शिक्षा कुछ निश्चित लोगों को ही दी जाये या प्राथमिक शिक्षा जनसमूह को दी जानी चाहिये। शिक्षा राज्य सरकार का विषय हो या इसे व्यक्तिगत प्रयत्नों पर छोड़ दिया जाये।

लोक शिक्षा समिति - 1823

General Committee of Public Instruction. 1823

10 जुलाई सन् 1823 को बंगाल मे एक लोक शिक्षा समिति की स्थापना की गई। इस समिति को शिक्षा के लिये निश्चित की गई एक लाख रूपये की धनराशि को व्यय करने का उत्तरदायित्व सौपा गया। इस समय भारत में प्राच्य और पाश्चात्य विवाद भी उठ खड़ा हुआ। समिति के द्वारा इन विवादों को सुलझाया नहीं जा सका। इस समिति ने उच्च शिक्षा के लिये कोई भी सुझाव नहीं दिये।

शिक्षा पर एलफिंस्ट्न का विवरणपत्र.

Elphinstone's Minute on Education.

सन् 1823 में बाम्बे नेटिव एजूकेशन सोसाइटी ने सरकार से शिक्षा अनुदान के लिये प्रार्थना कीं। परिणामस्वरुप 13 दिसंम्बर 1823 में एलफिंसट्न ने शिक्षा प्रसार के लिये अनेक सुझाव प्रस्तुत किये, उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे -

1. भारतीयों को उच्च शिक्षा का अध्ययन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।
2. यूरोपीय विज्ञानों एवं उच्च शिक्षा की शाखाओं की प्रगति करने के लिये विद्यालय स्थापित किये जाये।
3. जो लोग उच्च शिक्षा एवं यूरोपीय अनुसंधानों की अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिये उत्सुक हो उनको अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्रदान करने के लिये विद्यालय स्थापित किये जाये।

मुनरो की योजना (Munro's Scheme)

मद्रास के गर्वनर सर टामस मुनरों ने 10 मार्च 1826 के विवरण पत्र में एक शिक्षा योजना प्रस्तुत की जिसमें उसने प्रान्त के 2 जिलों में उच्च कोटि के दो-दो स्कूल (एक हिन्दुओं के लिये एक मुसलमानों के लिये) अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के लिये 300 तहसीलों में एक-एक वर्नाक्यूलर स्कूल तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये नार्मल स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव रखा परन्तु उसने अपनी इस योजना में उच्च शिक्षा के विकास के लिये कोई सुझाव प्रस्तुत नहीं किया।

1833 का आज्ञा पत्र (Charter of 1833)

सन् 1833 में कम्पनी के आज्ञापत्र को पुनः संशोधित किया गया। इस बार यद्यपि भारतीयों की शिक्षा की प्रगति के लिये कोई धारा नही जोड़ी गई किन्तु शिक्षा के व्यय के लिये एक लाख रूपये से बढ़ाकर धनराशि दस लाख रूपये कर दी गई। धर्म, जन्म स्थान व रंगभेद के बिना सभी को कम्पनी में नौकरी देने का प्रावधान किया गया। गर्वनर जनरल की एक्जयूटिव कौंसिल में लॉ मेम्बर के पद का प्रावधान किया गया। इस आज्ञापत्र में उच्च शिक्षा के विकास के लिये कोई धारा सम्मिलित नहीं की गई।

मैकाले का विवरण पत्र - 1835

Macaulay's Minute - 1835

सन् 1833 में कम्पनी को भारत के प्रदेशों का शासन करने के लिये अंग्रेजी संसद के द्वारा पुनः आज्ञा प्रदान की गई। इस आज्ञापत्र में शिक्षा के लिये स्वीकृत धनराशि एक लाख रूपये से बढ़ाकर दस लाख रूपये कर दी गई परन्तु शिक्षा समिति के सदस्यों में मतभेद ने बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया और शिक्षा सम्बन्धी प्राच्य-पाश्चात्य विवाद अपनी चरम सीमा पर पहँच गया इस कारण शिक्षा क्षेत्र में कोई व्यवहारिक और निश्चित कदम नहीं उठाया जा सका। लार्ड मैकाले गर्वनर जनरल की एक्जयूटिव कौसिल के लॉ मैम्बर के रूप में भारत आये। लार्ड मैकाले को 10 जून 1834 को लोक शिक्षा समिति (General Committee of Public Instruction) का सभापति नियुक्त किया गया। मैकाले ने आज्ञापत्र की 43 वीं धारा की व्याख्या की, शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में अपने सुझाव प्रस्तुत किये, अंग्रेजी भाषा और साहित्य के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किये, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को समाप्त करने के लिये उसने अंग्रेजी भाषा और साहित्य के पक्ष में उच्च कोटि के विचार प्रस्तुत किये। लार्ड विलियम बैंटिंग ने मैकाले द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी सुझावों को अपनी स्वीकृति प्रदान की और इसके आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की, जिस में सरकार की शिक्षा नीति का स्पष्टीकरण कर उसके उद्देश्य साधन एवं माध्यम को निश्चित कर दिया गया और जिसने शिक्षा का अस्थिर और अनिश्चित नीति को सदा के लिये स्थायी बना दिया परन्तु मैकाले ने अपने घोषणापत्र में उच्च शिक्षा के विकास के लिये कोई सुझाव प्रस्तुत नही किये और न ही शिक्षा नीति की घोषणा में उच्च शिक्षा के विकास के लिये कोई रूपरेखा प्रस्तुत की गई।

एडम की योजना (Adam's Plan)

बंगाल की देशी शिक्षा की व्यवस्था की जाँच करने के लिये लार्ड विलियम बैंटिक ने एडम महोदय को नियुक्त किया। वह भारतीयों के नैतिक एंव सामाजिक पतन को देखकर शिक्षा प्रसार द्वारा उनका मानसिक और चारित्रिक विकास करना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये शिक्षा प्रसार एवं शिक्षा सुधार के साधनों एवं उपायों के सम्बन्ध में उसने अनेक सुझाव प्रस्तुत किये। जब यह योजना ऑकलैंड के समक्ष प्रस्तुत की गई तो उसमें मैकाले रिपोर्ट के आधार पर इसे अस्वीकृत कर दिया। इस योजना में एडम ने उच्च शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव प्रस्तुत नहीं किये।

ऑकलैंड का विवरण पत्र – 1839
(Auckland's Minute - 1839)

विज्ञप्ति ने सरकार की शिक्षा नीति को निश्चित दिशा तो प्रदान कर दी, पर वह प्राच्य – प्राश्चात्य विवाद का अन्त न कर सकी, लार्ड ऑकलैंड के भारत आने पर प्राच्य – प्राश्चात्य विवाद ने अत्यन्त गम्भीर रूप धारण कर लिया। लार्ड ऑकलैंड ने लगभग 4 वर्ष तक इस विवाद के कारणों का सर्तकता से अध्ययन किया। इस अध्ययन के परिणामस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि विवाद का मूल कारण यह था कि सरकार द्वारा प्राच्य शिक्षा पर कम धन व्यय किया जा रहा था। प्राच्यवादी दल के लोग केवल इतना चाहते थे। कि वर्तमान प्राच्य संस्थायें चलती रहे और कुछ रुपया बहुमूल्य पुस्तकों के मुद्रण के लिये मिलता रहे।

लार्ड ऑकलैंड प्राच्य-प्राश्चात्य विवाद का अन्त करने के लिये 24 नवम्बर 1839 को एक विवरण पत्र लिखा जिसमें उसने सरकार की भावी शिक्षा नीति की रूपरेखा प्रस्तुत की। लार्ड ऑकलैंड ने इलाहाबाद, बनारस बरेली और आगरा में कालेज स्थापित किये। इन सभी कालेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था।

बुड के घोषणापत्र से पहले उच्च शिक्षा का विकास विधिवत रूप से नहीं हुआ सामान्यतः उच्च शिक्षा का विकास बुड के घोषणापत्र के बाद से माना जाता है।

(2) वुड का घोषणापत्र - 1854.

(Wood's Despatch) - 1854.

सन् 1833 ई. के बाद पुनः सन् 1853 में कम्पनी के आज्ञापत्र (Charter) का नवीनीकरण का अवसर आया उस समय ब्रिटिश लोक सभा (House of Commons) यह अनुभव करने लगी थी। कि अब भारतीय शिक्षा की अवहेलना अधिक समय तक नहीं की जा सकती। इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुये आज्ञापत्र के प्रकाश में लाने के पूर्व सन् 1853 में लोकसभा ने एक संसदीय समिति (Select Committee of the House of Commons) नियुक्ति की। समिति के सदस्यों ने भारत की शिक्षा का सन् 1853 तक गहन अध्ययन किया। समिति ने जाँच के आधार पर कम्पनी के संचालकों को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय शिक्षा के प्रश्न को टालना हितकर न होगा। समिति के सुझावों के आधार पर कम्पनी के संचालको ने 19 जुलाई सन् 1854 ई. को भारतीय शिक्षा की नीति की घोषणा की। उस समय सर चार्ल्स वुड बोर्ड आफ कन्ट्रोल के प्रेसीडेंट थे। अतः उन्हीं के नाम पर कम्पनी का नया आदेश पत्र 'वुड का घोषणापत्र' (Wood's Despatch) प्रकाशित करवाया गया। यह 100 अनुच्छेदों का लम्बा लेखपत्र है, जिसमें भारतीय शिक्षा के अंग प्रत्यंग पर विचार किया गया है और उनके सम्बन्ध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई -

1. घोषणापत्र में इस बात को स्वीकार किया गया कि भारत में शिक्षा का प्रसार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी पर है।
2. घोषणापत्र में भारतवासियों एवं अंग्रेजी राज्य के हितो को ध्यान में रखकर शिक्षा का उद्देश्य निश्चित किया गया। शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय उच्चकला, विज्ञान, दर्शन एवं साहित्य या संक्षेप में यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है।
3. घोषणापत्र में अंग्रेजी का समुचित ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के लिये अंग्रेजी को और अन्य व्यक्तियों के लिये देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम निश्चित किया।
4. घोषणापत्र में अरबी, फारसी और संस्कृत को उपयोगी बताते हुये उनको पाठ्यक्रम में स्थान दिया, किन्तु भारतीयों के लिये यूरोप के समुन्नत कला-कौशल, विज्ञान, दर्शन और साहित्य को अधिक उपयोगी बताकर पाठ्यक्रम में विशेष स्थान प्रदान किया।
5. घोषणापत्र में यह सुझाव दिया कि प्रान्तीय बोर्डो और शिक्षा समितियों (Provincial Board and

Council of Education) को भंग करके भारत के पाँच प्रान्तो-पंजाब, बंगाल, मद्रास, बम्बई, और उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में एक-एक लोक शिक्षा विभाग (Department of Instruction) की स्थापना की जाये। इस विभाग के संचालन का सम्पूर्ण भार लोक शिक्षा - संचालक (Director of Public Instruction) पर रखा जाये। उसे अपने कार्य में सहायता देने के लिये उपशिक्षा संचालकों, विद्यालय निरीक्षको, और सहायक विद्यालय निरीक्षकों, की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की जाये।

6. घोषणापत्र में सम्पूर्ण भारत में क्रमवद्ध विद्यालयों (Graded schools) की स्थापना पर विशेष जोर दिया। क्रमवद्ध विद्यालय प्राथमिक स्कूल मिडिल स्कूल, हाईस्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, के रूप में हो।

7. घोषणापत्र में निस्यन्दन सिद्धान्त को अव्यवहारिक बताते हुये जन साधारण को व्यवहारिक एवं लाभप्रद शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की गयी। देशी विद्यालयों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये सरकार का ध्यान आकषित किया गया।

8. घोषणापत्र ने भारत में जन शिक्षा कार्य को सफल बनाने के उद्देश्य से शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिये सहायता अनुदान प्रणाली को प्रचलित करने का सुझाव दिया, उसने यह भी सुझाव दिया कि भवन निर्माण, छात्रवृत्तियों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, अध्यापकों के वेतन आदि के लिये भी अलग-अलग अनुदान किये जाये।

9. घोषणापत्र में इस बात पर बल दिया कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं का शिलान्यास किया जाये, छात्रों को प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्तियां एवं शिक्षकों को उत्तम वेतन देकर शिक्षा के व्यवसाय को आर्कषक बनाने की चेष्टा की जाये।

10. घोषणापत्र में व्यवसायिक शिक्षा की चर्चा करते हुये कहा गया कि भारत में ऐसे स्कूलों और कालेजों की सृष्टि की जाये जिनमें छात्रों को विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा मिल सके।

11. घोषणापत्र में यह सिफारिश की गयी कि स्त्री शिक्षा को उदारतापूर्वक सहायता अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाये।

12. घोषणापत्र में यह सिफारिश की गई कि प्राच्य साहित्य और देशी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाये। देशी भाषाओं में पुस्तकों की रचना करवाई जाये, उनके लेखकों को उत्तम परिश्रमिक

दिया जाये और पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करवाया जाये।

13. आज्ञापत्र ने इस बात पर बल दिया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियां दी जाये।

14-अ. घोषणापत्र में यह उल्लेख किया गया कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य यूरोप के ज्ञान का प्रसार करना है। केवल अन्तर यह होगा कि प्राथमिक शिक्षा स्तर पर यह ज्ञान साधारण स्तर का होगा और स्थानीय भाषाओं के माध्यम से इसे प्रसारित किया जायेगा।

ब. घोषणापत्र में माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय कला, विज्ञान दर्शन एवं यूरोपीय साहित्य - संक्षेप में यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना निश्चित किया गया।

स. घोषणापत्र में भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिये कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की गई। ये विश्वविद्यालय आदर्श के रूप में लन्दन विश्वविद्यालय का अनुकरण करेगे। प्रत्येक विश्वविद्यालय के संचालन के लिये कुलपति (Chancellor) उपकुलपति (Vice chancellor) और मनोनीत अभिसदस्यों (Fellows) का सुझाव दिया। भारत में विश्वविद्यालयों की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुये - घोषणापत्र में कहा गया कि -

" The time is now arrived for the Establisment of Universities in India, Which any may encourage a regular and liberal course of education by conferring academical degrees as evidence, of attainments in the different branches of arts & science "

भारतीयों में उदार शिक्षा का तीव्र गति से प्रसार तथा भारतीय विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य ज्ञान में अधिक रुचि एवं सिद्धहस्तता प्राप्त हुई देखकर यह समझा जाने लगा कि भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापाना का उपयुक्त अवसर था।

घोषणापत्र में इस सम्बन्ध में सिफारिश की गयी कि भारत में विश्वविद्यालयों की, जो कला एवं विज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निपुणता प्राप्त विद्यालयों को डिग्रिया प्रदान करके उदार शिक्षा को प्रोत्साहित करेंगे, स्थापित किये जाये।

भारत में लन्दन विश्वविद्यालय, जो उस समय परीक्षा लेने वाली संस्था थी, को आधार मानकर विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति दी गयी। यह विश्वविद्यालय कलकत्ता,

बम्बई, मद्रास, और अन्य स्थानों पर, यदि वहाँ पर ऐसी शिक्षा संस्थाएं जो डिग्री प्राप्त करने के लिये योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा देती हो, पर्याप्त संख्या में हो, स्थापित किये जाये।

इन विश्वविद्यालयों के प्रशासन के लिये मुख्य अधिकारी कुलपति (Chancellor), उपकुलपति (Vice Chancellor) और अभिसदस्य (Fellows) होगें जो कि सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेगे। कुलपति, उपकुलपति एवं अभिसदस्यों को मिलाकर सीनेट बनेगी। सीनेट विश्वविद्यालयों के लिये नियम बनायेगी जिन पर सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी।

विश्वविद्यालयों का कार्य सम्बन्धित कालेजों के विद्यार्थियों की परीक्षा लेना होगा। परीक्षा में सफल विद्यार्थियों की विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान की जायेगी। परीक्षा एवं डिग्री प्रदान करने के कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय कुछ प्रोफेसरों की विभिन्न विषयों में नियुक्ति जैसे–कानून, सिविल इंजीनियरिंग, देशी भाषा, संस्कृत, अरबी और फारसी में ज्ञान प्रदान करने के लिये व्याख्यान देने के उद्देश्य से करेगे।

इस प्रकार जिन विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश घोषणापत्र में की गयी वे मूलतः परीक्षा लेने और डिग्री प्रदान करने वाली संस्थाएं थी। इन विश्वविद्यालयों के कुछ विषयों में शिक्षण कार्य का भी उल्लेख था। विश्वविद्यालय पूर्णरूपेण सरकारी नियंत्रण में रखे गये। मुख्य पदाधिकारियों की नियुक्ति और सीनेट के नियमों की अन्तिम स्वीकृति सरकार द्वारा ही हो सकती थी। विश्वविद्यालय स्तर पर पाश्चात्य ज्ञान के साथ ही व्यवसायिक शिक्षा तथा प्राच्य भाषाओं के अध्ययन को भी स्थान दिया गया।

भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रारम्भ बुड के घोषणापत्र की सिफारिशों के परिणामस्वरूप हुआ। सन् 1855 में गर्वनर जनरल लार्ड डलहौजी ने एक समिति की नियुक्ति की जिसका कार्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में एक योजना बनाना था। जिसे संचालक मण्डल के पास स्वीकृति के लिये भेजा जा सके। 12 दिसम्बर 1856 ई. को समिति की इस योजना को स्वीकार कर लिया गया। सन् 1857 ई. में सरकार ने विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करके 24 जनवरी 1857 ई. को कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित किया। बम्बई में 18 जुलाई 1857 ई. को बम्बई विश्वविद्यालय मद्रास में 5 सितम्बर 1857 ई. को मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया।

ये विश्वविद्यालय लन्दन विश्वविद्यालय के आधार पर स्थापित किये गये थे। अतः प्रत्येक विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अनेक कालेज होते थे जो वास्तविक रूप में शिक्षा प्रदान करने का काम करते थे। इन कालेजों का रूप आज के कालेजों से बिल्कुल भिन्न था। स्कूल कक्षाएं भी कालेजों से सम्बन्धित थी और एक ही भवन में स्कूल और कालेज स्तर की शिक्षा दी जाती थी।

सन् 1872 में इलाहाबाद सेन्ट्रल कालेज खोला गया, सन् 1869 में लॉ कालेज और यूनीवर्सिटी कालेज की स्थापना की गई, इसी कालेज को सन् 1887 में विश्वविद्यालय में पारित किया गया।

सरकारी कालेजों में वृद्धि के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाओ और व्यक्तियों द्वारा स्थापित कालेजों की संख्या में वृद्धि हुई। सन् 1864 में अवध के ताल्लुकेदारों ने लखनऊ केनिंग कालेज की स्थापनी की। सन् 1875 में सर सैयद अहमद ख़ॉ ने मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के उद्देश्य से मुस्लिम एंग्लों ओरियन्टल कालेज की स्थापना अलीगढ़ में की। 19 अक्तूबर सन् 1847 को लेफ्टिनेट गर्वनर जेम्स थामसन ने रुड़की में एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की।

(3) स्टेनले का घोषणापत्र

अंग्रेजी संसद द्वारा भारतीय शासन का उत्तरदायित्व लेने के पश्चात भारतमंत्री के नये पद का निर्माण हुआ। लार्ड स्टेनले प्रथम भारतमंत्री नियुक्त किये गये। क्रान्ति का भारतीय शिक्षा नीति से क्या सम्बन्ध था यह जानना आवश्यक था। साथ ही वुड के घोषणापत्र की सिफारिशों की भारत में क्या प्रतिक्रिया हुई इस तथ्य की भी जानकारी होनी चाहिये थी। सन् 1859 में लार्ड स्टेनले ने नया आज्ञापत्र प्रकाशित किया। इतिहास में इसे स्टेनले का घोषणापत्र कहा जाता है। इस घोषणापत्र में वुड के घोषणापत्र के सभी सिद्धान्तों का सर्मथन किया गया परन्तु प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नीति परिवर्तित कर दी गई, स्टेनले घोषणापत्र के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान प्रथा असफल सिद्ध हुई थी, इस कारण यह सुझाव दिया गया कि केवल माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान प्रथा व्यवहार में लाई जाये। प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार सीधे अपने ऊपर ले। प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिये सरकार यदि आवश्यक हो तो स्थानीय कर लगाये।

(4) भारतीय शिक्षा आयोग

The Hunter Commission - 1882-83.

सन् 1854 के घोषणापत्र में जो भारतीय शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी उसे यद्यपि सिद्धान्त का रूप में सरकार ने शिक्षा नीति के रूप में अपना लिया, किन्तु क्रियात्मक रूप में वह उसकी उपेक्षा करती रही। घोषणापत्र में निस्यन्दन सिद्धान्त (Downward Filteration Theory) के अनुकरण करने पर असंतोष प्रकट किया था, किन्तु सरकार अब भी जनसाधारण की शिक्षा की ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही थी। ईसाई मिशनरिया इस बात का स्वप्न देख रही थी कि सरकार सहायता अनुदान प्रणाली पर चलकर स्वयं विद्यालयों को स्थापित करना बन्द कर देगी और उन्हें शिक्षा प्रसार के माध्यम से धर्म प्रचार की खुली छूट मिल जायेगी। किन्तु उनका स्वप्न भी पूरा न हो सका, परिणामस्वरूप उन्होनें सरकार की शिक्षा नीति के विरूद्ध यह आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया कि सरकार सन् 1854 के वुड के घोषणापत्र की सिफारिशों की अवहेलना कर रही है। इस आन्दोलन की लपटें शीघ्र ही इंग्लैड़ पहुँच गई जिस से प्रभावित होकर भारत की शिक्षा में रूचि रखने वाले वहाँ के कुछ उत्साही निवासियों ने (General Council of Education in India) नामक संस्था स्थापित की। तदुपरान्त जब सन् 1880 में ब्रिटिश लोकसभा ने भारत में नये बाइसराय लार्ड रिपन की नियुक्ति की, तब इस संस्था के कुछ सदस्यों के एक शिष्ट मण्डल ने रिपन से भेट की और भारतीय शिक्षा की नीति की जाँच का अनुरोध किया। भारत आने पर लार्ड रिपन ने 3 फरवरी सन् 1882 में बाइसराय की कार्यकारिणी के सदस्य सर विलियम हन्टर की अध्यक्षता में इन्डियन एजूकेशन कमीशन की नियुक्ति की। हन्टर के नाम पर ही इस आयोग को हन्टर कमीशन के नाम से सम्बोधित किया जाता हैं। आयोग ने 10 फरवरी, सन् 1882 से अपना कार्य प्रारम्भ किया और 16 मार्च सन् 1883 को 622 पेज की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

यद्यपि उच्च शिक्षा आयोग की जाँच का विषय नही था, फिर भी उसने सार्वजनिक कालेजों और उनकी शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक लाभप्रद सुझाव दिये जो इस प्रकार है:-

1. कालेजों को सहायता अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि को उनके व्यय, शिक्षकों की संख्या, कार्यकुशलता और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाना चाहिये।
2. कालेजों में समय समय पर फर्नीचर, पुस्तकालय, भवन निर्माण, और शिक्षण सम्बन्धी अन्य

कार्यो के लिये आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये।

3. कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति करते समय यूरोप के विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
4. कालेजों के पाठ्यक्रमों का विस्तार करके छात्रों को उनकी रूचियों के अनुकूल विषयों का चयन करने का अवसर दिया जाना चाहिये।
5. कालेजों के छात्रों के नैतिक स्तर का उत्थान करने के लिये उनके प्रकृति धर्म (Natural Religion) और मानवधर्म के सिद्धान्तों से परिचित कराया जाना चाहिये।
6. कालेजों में छात्रों को मानव और नागरिक कर्तव्यों से अवगत कराने के लिये व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया जाना चाहिये।
7. कालेजों में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिये उचित छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिये।
8. सार्वजनिक कालेजों को राजकीय कालेजों की अपेक्षा कम शुल्क लेने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिये।
9. निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की निश्चित संख्या निर्धारित की जानी चाहिये।
10. योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों प्रदान कर उन्हे विदेश भेजने की व्यवस्था की जाये।

आयोग ने राजकीय कालेजों की अपेक्षा सार्वजनिक कालेजों को ही अधिक प्रोत्साहन दिये जाने का समर्थन किया, अतः उसने यह विचार अंकित किया कि राजकीय कालेजों का संचालन केवल उन्हीं स्थानों पर किया जाये जहाँ कि जनता सार्वजनिक कालेजों की स्थापना करने में असमर्थ है। इस प्रकार आयोग ने स्पष्ट रूप से यह नीति प्रतिपादित की कि सरकार को माध्यमिक शिक्षा की भांति उच्च शिक्षा के उत्तरदायित्व से भी मुक्त हो जाना चाहिये।

"The Commission advocated the withdrawal of Government from direct Enterprise in the field of College Education. [1]

आयोग ने विश्वविद्यालय के प्रशासन के सम्बन्ध में तो कुछ सुझाव दिये थे, परन्तु पाठ्यक्रम तथा शिक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में तो कुछ सुझाव दिये थे, परन्तु पाठ्यक्रम तथा शिक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध मे कोई सिफारिश नहीं की थी, इसका कारण यह था कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखी गई थी, इसलिये प्रत्यक्ष रूप से आयोग के सुझावों का

---

1. Dr. S. N. Mukerji - History of Education in India. P. 162.

विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास पर कोई विशेष प्रभाव नही पड़ा चूँकि आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरुप माध्यमिक शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी, इस कारण विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक ही था। सन् 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सन् 1914 तक एक परीक्षा संस्था के रूप में कार्य करता रहा। सन् 1898 में बनारस में सेन्ट्रल हिन्दू कालेज की स्थापना की गई। कालेजों तथा विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का कारण था सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र से हाथ खीचनें एवं व्यक्तिगत प्रयत्नों का प्रोत्साहन देने की नीति, गैर सरकारी कालेजों को सरकारी कालेजों की तुलना से कम शिक्षा शुल्क लगाने की स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण जनता में जागृति और परिणामस्वरुप उच्च शिक्षा की मांग इस कारण अत्यधिक संख्या में छात्र कालेजों में उदार तथा साहित्यक शिक्षा प्राप्त करने आने लगे।

(5) भारतीय विश्वविद्यालय आयोग

Indian Universities Commission - 1902.

सन् 1899 में लार्ड कर्जन को भारत के वाइसराय के पद पर नियुक्त किया गया। शिक्षा सुधार के कार्य को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के विचार से लार्ड कर्जन ने सितम्बर सन् 1901 से शिमला एजूकेशन कान्फ्रेंस का आयोजन अपने सभापतित्व में किया। कर्जन ने प्रान्तों के शिक्षा संचालकों और मिशनरियों के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये आंमत्रित किया किन्तु उसने भारतीयों के एक भी प्रतिनिधि को इसमें स्थान नहीं दिया। शिमला एजूकेशन कान्फ्रेंस कर्जन के सभापतिव्व में 15 दिन तक चली और उसमें शिक्षा सम्बन्धी 150 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से निश्चित किया गया। कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को इन्हीं प्रस्तावों पर आधारित किया।

लार्ड कर्जन ने शिमला एजूकेशन कान्फ्रेंस में शिक्षा विशेषज्ञों से अत्यधिक विचार विमर्श करने के पश्चात सर थामस रेलेह जो उस समय गर्वनर जनरल की कौंसिल के कानून सदस्य भी थे। की अध्यक्षता में 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न विषयों का विस्तृत छानवीन करने के पश्चात जून सन् 1902 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नालिखित सुझाव प्रस्तुत किये।

1. नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं की जानी चाहिये।
2. वर्तमान विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षण कार्य किया जाना चाहिये।
3. स्नातक पूर्व शिक्षण का कार्य, सम्बद्ध कालेजों में और स्नातकोत्तर शिक्षण का कार्य विश्वविद्यालय में किया चाहिये।
4. प्रत्येक विश्वविद्यालय की प्रादेशिक सीमा स्पष्ट रूप से निश्चित कर दी जानी चाहिये।
5. सीनेट के सदस्यों की संख्या कम कर दी जानी चाहिये और उनकी सदस्यता की अवधि पाँच वर्ष की होनी चाहिये।
6. सिन्डीकेट के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक होनी चाहिये और उनका निर्वाचन सीनेट के द्वारा किया जाना चाहिये।
7. प्रत्येक सम्बद्ध कालेज का प्रबन्ध एक संगठित समिति के द्वारा किया जाना चाहिये।
8. कालेजों को मान्यता देने के नियमों में कड़ाई की जानी चाहिये और द्वितीय श्रेणी के कालेजों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिये।
9. कालेजों और विश्वविद्यालयों के योग्य अध्यापकों को सीनेट में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये।
10. इन्टरमीडिएट की कक्षाओं को तोड़ देना चाहिये और स्नातकों का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का कर देना चाहिये।
11. विद्यार्थियों की अवस्था पर ध्यान देते हुये उनके लिये छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाये।
12. विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली में उचित परिर्वतन एवं संशोधन किया जाये।
13. सम्बद्ध कालेजों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाये।
14. सिर्डीकेट स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मान्यता प्राप्त कालेजों के लिये कम से कम शिक्षा शुल्क की दर निर्धारित करे।
15. आयोग ने अंग्रेजी के स्तर को ऊँचा करने के बारे में सिफारिश की कि अंग्रेजी का शिक्षण तब तक प्रारम्भ न किया जाये जब तक कि छात्रों को अपनी मातृभाषाओं का उचित ज्ञान न हो जाये।
16. एम. ए. की कक्षाओं में अंग्रेजी के साथ भारतीय भाषाओं को भी सम्मिलित किया जाये।
17. आयोग ने विश्वविद्यालयों की परीक्षा में प्राइवेट छात्रों को बैठने पर रोक लगाने का सुझाव दिया।

18. भारतीय विश्वविद्यालयों के कार्यो को विस्तृत किया जाये और विश्वविद्यालय को प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्तियां करने का अधिकार दिया जाये और अनुसंधान कार्य को प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाये।

19. विश्वविद्यालय अभिसदस्यों (University Fellows) के लिये निर्वाचन के सिद्धान्त को प्रारम्भ किया जाये।

(6) भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम - 1904

The Indian Universities Act - 1904

लार्ड कर्जन की सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के सुझावों और सिफारिशों के आधार पर एक विधेयक तैयार किया। इस विधेयक ने 21 मार्च सन् 1904 को इम्पीरियल लेजिसलेटिव कांउसिल द्वारा पारित होकर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का रूप ग्रहण किया। इस अधिनियम द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रशासन अधिकार कार्य क्षेत्र, आदि में अनके महत्वपूर्ण परिर्वतन किये गये जो इस प्रकार है।

1. सीनेट के सदस्यों की संख्या को सीमित करके, यह निश्चित कर दिया गया कि उनकी न्यूनतम संख्या 50 एवं अधिकतम संख्या 100 होगी और वे अपने पद पर आजीवन न रहकर केवल 50 वर्ष रहेंगे।

2. सीनेट के सदस्यों को निर्वाचित करने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालयों के सीनेटों के सदस्यों की संख्या 20 एवं पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर (जो इस समय पाकिस्तान में है) और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेटों के सदस्यों की संख्या 15 निश्चित की गई।

3. सिंडिकेटों को कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को उनमें उचित प्रतिनिधित्व दिया गया।

4. विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक कालेजों के लिये नियम कठोर कर दिये गये, और सिंडीकेटों को इन कालेजों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का अधिकार दे दिया गया।

5. सरकार को सीनेट द्वारा बनाये जाने वाले नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिर्वतन करने या स्वीकृति देने, और उनके द्वारा उचित समय पर नियम न बनाये जाने पर स्वयं नियम बनाने का अधिकार मिल गया।

6. विश्वविद्यालयों के कार्य क्षेत्र में विस्तार कर दिया गया, उनको परीक्षा लेने के अतिरिक्त शिक्षण एवं अनुसंधान करने का भी अधिकार दिया गया।
7. वाइसराय को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं को निश्चित करने का अधिकार दिया गया।
8. सिंडीकेट का प्रधान उपकुलपति होगा तथा शिक्षा विभागों के संचालन के लिये कम से कम 7 और अधिक से अधिक 15 सदस्य सीनेंट या फैकल्टीज द्वारा निर्वाचित होगें
9. कालेजों को मान्यता देने एंव मान्यता रद्द करने के लिये विश्वविद्यालयों को सरकार से स्वीकृति लेना आवश्यक कर दी गई।

(7) शिक्षा नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव – 1913

Government Resolution on Educational Policy - 1913

16 मार्च सन् 1911 को गोपाल कृष्ण गोखले ने एक विधेयक प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिये इम्पीरियल लेजिसलेटिव काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया। 17 मार्च सन् 1912 को इम्पीरियल लेजिसलेटिव कांउसिल में बिल को बहस करने के लिये रखा गया, अन्त में विधेयक 13 वोंटों के विरूद्ध 38 वोटों से रद्द कर दिया गया।

यद्यपि गोखले के विधेयक को सरकार ने अस्वीकार कर दिया किन्तु सरकार को अपनी शिक्षा नीति पर पुनः विचार करना आवश्यक हो गया। इस परिस्थिति से प्रेरित होकर 21 फरवरी सन् 1913 को सरकार ने अपनी शिक्षा नीति में परिर्वतन करके नवीन शिक्षा नीति सम्बन्धी प्रस्ताव Government Resolution on Educational Policy - 1913 प्रकाशित किया, जिसमें शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्तों को निर्धारित करने के बाद शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में सुधार करने के लिये सिफारिशें प्रस्तुत कीं गई।

उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न सुझाव प्रस्तुत किये गये।

1. भारत में अभी अधिक समय तक परीक्षक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता रहेगी फिर भी उनकी प्रादेशिक सीमाओं को निश्चित कर देना आवश्यक है।
2. विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करके प्रत्येक प्रान्त में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये।
3. विश्वविद्यालय के कार्यभार में वृद्धि के कारण उन्हें हाईस्कूल की मान्यता प्रदान करने के कार्य से मुक्त कर दिया जाये और मान्यता प्रदान करने का कार्य प्रान्तीय सरकारों तथा देशी राज्यों

को सौप दिया जाये।

4. इस प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जाये जो शिक्षण कार्य करना चाहते है।
5. विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, एवं छात्रावासों के प्रबन्ध की और विशेष ध्यान दिया जाये।
6. विश्वविद्यालय शिक्षा की दशा असंतोषजनक है। इसलिये उसमें सुधार किया जाना चाहिये।
7. विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली के क्षेत्र में संतोषजनक दशा नहीं है। इसमें सुधार करने का प्रयत्न किया जाये।
8. ढाका में शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना का निश्चय किया गया और शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति अलीगढ़ बनारस एवं आवश्यकतानुसार अन्य स्थानों पर देने की इच्छा प्रकट की गई।
9. विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों में चरित्र निर्माण एवं सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक शक्तियों के विकास के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाये।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह थी कि उसने नवीन शिक्षा विद्यालयों, शिक्षण विश्वविद्यालयों और प्रत्येक प्रान्त में कम से कम एक विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश करके, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये एक नवीन नीति का निर्धारण किया, इसलिये नूरूल्ला व नायक ने प्रस्ताव के सम्बन्ध में लिखा है कि –

" The Resolution may be described as a turning point in the History of Indian Universities"[2]

सन् 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम के पश्चात कालेजों की मान्यता प्रदान करने के नियम कठोर कर दिये गये, परिणाम यह हुआ कि कुछ कालेजों का अस्तित्व समाप्त हो गया, परन्तु विद्यार्थियों की संख्या में धीरे धीरे दिनो दिन वृद्धि होती रही, सरकार द्वारा कालेज शिक्षा में सुधार के लिये उदारता पूर्वक आर्थिक सहायता दी गई।

सन् 1913 के शिक्षा नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव की सिफारिशों के परिणामस्वरूप 4 फरवरी सन् 1916 को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी (शिक्षण एवं आवासीय) का गठन किया गया। कर्जन के समय में विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदान में वृद्धि होती गई। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को एक लाख रूपये वार्षिक अनुदान दिया जाने लगा।

2. Nurullah and Naik - A History of Education in India. P. 500.

इस उदारतापूर्वक अनुदान देने का प्रभाव विश्वविद्यालय के विकास कार्य पर पड़ा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षण और मान्यता दोनों ही प्रदान करता था इसके अतिरिक्त अन्य सम्बन्धित विश्वविद्यालय भी किसी न किसी रूप में शिक्षण कार्य करने लगे।

(8) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग - 1917-1919

The Culcutta University Commission - 1917-1919

कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति का कारण सन् 1910 में श्री हाल्डेन की अध्यक्षता में लन्दन विश्वविद्यालय में सुधार करने के लिये आयोग[3] की नियुक्ति की गई जिसकी प्रेरणा से भारतीय विश्वविद्यालयों में सुधार का विचार उत्पन्न हुआ, द्वितीय भारतीय विश्वविद्यालयों में से कलकत्ता विश्वविद्यालस सबसे बड़ा और पुराना था तृतीय सन् 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में बंगाल के तत्कालीन शिक्षा संचालक श्री आशुतोष मुकर्जी ने पहले पहल स्नातकोत्तर विभाग (Post Graduate Department) खोला, उनकी इच्छा थी कि इस विभाग के द्वारा छात्रों के शिक्षण का कार्य विश्वविद्यालय में ही किया जाये। इस बात की उपयुक्तता की जाँच करने के लिये सरकार ने डॉ. माइकेल सैडलर, जो उस समय यूनीवर्सिटी ऑफ लीड्स के बाइसचांसलर भी थे, की अध्यक्षता में 14 सितम्बर सन् 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। डॉ. माइकेल सैडलर के नाम पर ही इस आयोग को सैडलर कमीशन भी कहते है।

आयोग ने अपनी नियुक्ति के 17 महीने बाद अधिक परिश्रम करके मार्च सन् 1919 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, यह रिपोर्ट अत्यन्त व्यापक तथा विस्तृत थी और 13 भागों मे विभाजित की गई थी। यद्यपि यह आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय की जाँच करने के लिये नियुक्त किया गया था किन्तु तुलनात्मक अध्ययन करने की दृष्टि से इसे अन्य विश्वविद्यालयों एंव शिक्षा के अन्य अंगों की जाँच करने का अधिकार मिल जाने के कारण इस आयोग ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों पर अध्ययन करके सम्पूर्ण देश की माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर महत्वपूर्ण सिफारिशें एवं सुझाव प्रस्तुत किये।

---

3. Haldane Commission of London University

उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में इस आयोग के प्रमुख सुझाव इस प्रकार है।

<u>संगठन</u> – उच्च शिक्षा के संगठन के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये।

1. ढ़ाका में शीघ्र ही आवास शिक्षण विश्वविद्यालय (Residential & Teaching University) की स्थापना की जाये।

2. कलकत्ता नगर की शिक्षा संस्थाओं का इस प्रकार संगठन किया जाये कि एक नवीन शिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सके।

3. कलकत्ता के समीपवर्ती स्थानों में स्थित कालेजों का विकास इस प्रकार किया जाये कि कुछ स्थानों पर नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा सके।

<u>प्रशासनः</u>– कालेजों एवं विश्वविद्यालयों के प्रशासन के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये गये वे इस प्रकार है:–

1. विश्वविद्यालय सरकारी विभाग मात्र न हों। उन पर से सरकार का कठोर नियंत्रण समाप्त होना चाहिये।

2. विश्वविद्यायल के अध्यापकों का शिक्षा सम्बन्धी मामलों पर अधिक अधिकार हो।

3. विश्वविद्यालयों के आन्तरिक प्रशासन के लिये सीनेट के स्थान पर कोर्ट और सिंडीकेट के स्थान पर कार्यकारिणी की स्थापना की जाये।

4. परीक्षा पाठ्यक्रम, उपाधि वितरण एवं अनुसंधान कार्यो की व्यवस्था के लिये शिक्षा परिषद (Academic Council) की स्थापना की जाये।

5. विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों (Faculties) अध्ययन बोर्ड (Board of Studies) आदि की स्थापना की जाये।

6. विश्वविद्यालय के प्रशासन नियम सरल कर दिये जाये।

7. उपकुलपति (vice chancellor) का पद वैतनिक कर दिया जाये।

8. प्रोफेसरों और रीडरों की नियुक्ति एक विशेष समिति द्वारा होनी चाहिये, इस समिति में विश्वविद्यालय से बाहर के विशेषज्ञ भी सम्मिलित किये जाये।

<u>पाठ्यक्रमः</u>– कालेजों एवं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आयोग के सुझाव इस प्रकार है।

1. योग्य छात्रों के लिये पास कोर्स के अतिरिक्त आनर्स कोर्स की स्थापना की जाये।

2. विश्वविद्यालय स्तर पर भिन्न-भिन्न प्रकार के विषयों के शिक्षण की व्यवस्था की जाये।
3. विश्वविद्यालय स्तर पर भारतीय भाषाओं के शिक्षण को महत्व दिया जाये उन्हें पास कोर्स और आनर्स कोर्स में सम्मलित किया जाये।
4. ट्यूटोरियल वर्क और रिसर्च वर्क के संगठ्न की तरफ ध्यान दिया जाये।
5. विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के अधीन शिक्षा विभाग की पृथक से स्थापना की जाये, शिक्षा एक विषय के रूप में इन्टरमीडिएट एवं बी. ए. पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाये।
6. विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं शारीरिक हित की देखभाल के लिये प्रत्येक विश्वविद्यालय में शारीरिक प्रशिक्षण संचालक (Director of Physical Training) नियुक्त किया जाये। इसका पद और वेतन प्रोफेसर के समान हो।
7. प्रत्येक विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की भलाई के लिये एक बोर्ड आफ स्टूडेन्ट वेलफेयर (Board of Student Welfare) स्थापित किया जाये,
8. स्नातकों का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का कर दिया जाये।
9. विश्वविद्यालयों में अरबी, फारसी और संस्कृत के अध्ययन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये।

<u>अन्य सुझाव</u>

1. शिक्षा की दृष्टि से मुसलमान जाति की पिछ्ड़ी हुई अवस्था को ध्यान में रखते हुये मुसलमान विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिये आवश्यक सुविधाएं दी जाये।
2. एक अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड (Inter University Board) स्थापित किया जाये जो समय-समय पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यो में साम्य और सहयोग स्थापित करने के लिये अनेक अधिकारियों का सम्मेलन करवाने की व्यवस्था करें।
3. कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक स्पेशल बोर्ड आफ वीमेन्स एजूकेशन की स्थापना की जाये जो स्त्रियों के लिये उपयुक्त पाठ्यक्रम को तैयार करे।

आयोग की रिपोर्ट के पश्चात सन् 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ एंव सन् 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना की गई, सन् 1927 में आगरा विश्वविद्यालय, आगरा की स्थापना की गई।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ढ़ाका विश्वविद्यालय के आधार पर सन् 1921 में पुर्नगठन किया गया और उसे आवास शिक्षण विश्वविद्यालय का रूप दिया गया, यद्यपि इस

विश्वविद्यालय के अर्न्तगत एसोसिएट कालेज भी रखे गये, शिक्षण विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त जो सम्बन्धित विश्वविद्यालय थे उन्होंने भी किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया। उत्तर स्नातक शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालय में ही प्रदान की जाने लगी।

विश्वविद्यालयों व कालेजों में ट्यूरोरियल प्रणाली भी लागू की गई। सन् 1920 से इन्डियन ट्यूरोटिकल फोर्स एक्ट पारित होने के बाद से विश्वविद्यालयों में सैनिक शिक्षा (University Training Corps) का गठन किया गया।

कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के पश्चात सन् 1921 में ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालयों की सभा (Congress of the Universities of the Empire) ने सन् 1924 से भारतीय विश्वविद्यालय कार्फ्रेन्स ने अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड (Inter University Board) स्थापित करने का सुझाव दुहराया।

सन् 1925 में इस बोर्ड की स्थापना की गई जिसका केन्द्र बंगलौर था।

आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बद्ध वह कालेज जो इलाहाबाद की सीमा के बाहर स्थित थे, उन सभी को आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया।

(9) हरटोग कमेटी - 1927-1929

Hartog Committee. 1927-1929

ब्रिटिश लोक सभा ने 8 नवम्बर सन् 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की। साइमन कमीशन ने पाया कि जो कुछ आन्दोलन हो रहे हैं उनका एक प्रमुख कारण शिक्षा से भी सम्बन्धित है, अतः साइमन कमीशन ने भारतीय शिक्षा का अध्ययन करने के लिये एक सहायक समिति (The Auxiliary Committee of the Indian Statutory Commission) सन् 1928 में गठित की। सर फिलिप हरटोग को इस समिति का चैयरमैन नियुक्त किया गया। इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम हरटोग कमेटी पड़ा। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 11 सितम्बर सन् 1929 को साइमन कमीशन के सम्मुख प्रस्तुत किया इस प्रतिवेदन में उच्च शिक्षा से सम्बनधित दोषों पर गहन दृष्टिपात किया गया और उनके सुधार के लिये व्यापक सुझाव प्रस्तुत किये गये।

समिति के अुनसार उस समय की उच्च शिक्षा में निम्न दोष थे:-

1. विश्वविद्यालयों का संख्यात्मक विकास तो हुआ है किन्तु उनका गुणात्मक विकास न होने के

कारण उनके शैक्षणिक स्तर गिर रहे है।

2. विश्वविद्यालय पारस्परिक प्रतिद्वंदिता के कारण अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को प्रवेश दे रहे है। इससे उनका गुणात्मक विकास की और ध्यान नहीं है।

3. उच्च शिक्षा भारतीय युवकों में नेतृत्व के गुण तथा सामाजिक भावना का विकास करने में असमर्थ है।

4. विश्वविद्यालयों की शिक्षा पूरी तरह सैद्धन्तिक है। उच्च शिक्षा छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने में पूरी तरह असमर्थ है।

5. अधिकांश विद्यार्थियों में यह विश्वास प्रचलित है कि विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्य विद्यार्थियों को परीक्षा में पास करना हैं।

6. विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं अध्यापन की व्यवस्था हो चुकने के बाद भी उनका प्रमुख कार्य परीक्षा का संचालन करना है।

7. विश्वविद्यालयों में उन विद्यार्थियों को प्रवेश प्राप्त हो जाता है जो उच्च शिक्षा के योग्य नहीं है।

8. विश्वविद्यालयों में अच्छे पुस्तकालयों का अभाव है।

9. विश्वविद्यालयों में आनर्स कोर्स का समुचित संगठ्न नहीं किया गया है।

10. विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त स्नातकों में बेरोजगारी बढ़ रही है।

11. विद्यार्थियों का अंग्रेजी के ज्ञान का स्तर काफी गिरा हुआ है।

इन दोषों को दूर करने के लिये समिति ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत कियेः-

1. भारत में सम्बन्धात्मक तथा एकात्मक दोनों ही प्रकार के विश्वविद्यालय स्थापित किये जाये।

2. विश्वविद्यालय में प्रवेश के नियमों में कड़ाई की जाये ताकि अयोग्य विद्यार्थी उच्च शिक्षा में न जा सकें केवल उन विद्यार्थियों को प्रवेश की अनुमति दी जाये जिनमें उच्च शिक्षा का लाभ उठाने की क्षमता हो।

3. सम्बद्ध कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जाये, इससे कालेजों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होगी और उच्च शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा।

4. आनर्स कोर्स की योजना केवल उपयुक्त स्थानों पर लागू की जाये।

5. विश्वविद्यालयों में उपकक्षा पद्धति (Tutorial system) का प्रचलन किया जाये।

6. स्नातकों की बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिये विश्वविद्यालयों में रोजगार कार्यालयों

(Employment Bureau) की स्थापना की जाये।

7. विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं को सुधारा जाये।
8. अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन दिया जाये तथा इसके लिये आवश्यक सुविधाएं जुटाई जायें।
9. पाठ्यक्रमों को व्यवहारिक तथा जीवन उपयोगी बनाया जाये।
10. विश्वविद्यालयों में औद्योगिक शिक्षा (Industrial Education) का पाठ्यक्रम चालू किया जाये।
11. जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार करना विश्वविद्यालयों का प्रमुख कर्तव्य है। इसके लिये विश्वविद्यालयों द्वारा व्याख्यान मालाओं की सुविधाओं का श्री गणेश किया जाये।

प्रान्तीय एवं केन्द्रीय शिक्षा नीतियों में सांमजस्य स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने सन् 1920 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education) की स्थापना की, धनाभाव के कारण सन् 1923 में इस बोर्ड को समाप्त कर दिया गया किन्तु हरटोग कमेटी की रिपोर्ट के सुझाव के आधार पर सन् 1935 में पुनः केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष और प्रान्तीय शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा संचालक बोर्ड के सदस्य होते थे। भारतीय शिक्षा की समुचित व्यवस्था का भार बोर्ड को दिया गया। बोर्ड का वार्षिक अधिवेशन होता था जिसमें शिक्षा की प्रगति और समस्याओं पर विचार किया जाता था। इसी काल में शिक्षा के पुनः वर्गीकरण और साहित्यक शिक्षा के स्थान पर व्यवसायिक और औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था के विषय में बोर्ड ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया।

सार्जेन्ट योजना – 1944

Sargent Scheme - 1944

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के कुछ समय बाद अन्य देशों के समान भारत में भी युद्धोत्तर विकास की योजनाओं के निर्माण कार्य की दिशा में रचनात्मक कदम उठाये गये। इन योजनाओं में शिक्षा का भी स्थान था अतः बाइसराय की प्रबन्धकारिणी कौसिल की पुनर्निमाण समिति (Reconstruction Committee of the Viceroy's Excutive Council) ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education) को भारत में शिक्षा के विकास के लिये एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इस निर्देश का पालन करने के लिये भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेन्ट से उक्त योजना प्रस्तुत करने का

अनुरोध किया। सन् 1944 में उन्होनें अपनी योजना को एक स्मृतिपत्र (Memorandum) में लेखवद्व करके केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया और बोर्ड से उसको स्वीकृति भी प्राप्त हो गई। रिपोर्ट को सार्जेन्ट योजना इसलिये कहा जाता है क्योंकि सर जॉन सार्जेन्ट तत्कालीन भारतीय शिक्षा सलाहकार थे वे यद्यपि रिपोर्ट के एक मात्र लेखक नहीं थे, क्योंकि रिपोर्ट पर 34 हस्ताक्षर थे वे यद्यपि रिपोर्ट के एक मात्र लेखक नहीं थे, क्योकि रिपोर्ट पर 34 हस्ताक्षर थे। इस स्मृति को चार विभिन्न भागों से जाना जाता है।

1. सार्जेन्ट रिपोर्ट – Sargent Report.
2. सार्जेन्ट योजना – Sargent Plan or Sargent Scheme.
3. भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास की योजना – Scheme of Postwar Educational Develop ment in India.
4. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट – Report of Central Advisory Board of Education.

रिपोर्ट में तत्कालीन उच्च शिक्षा के दोषों की ओर संकेत किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा के दोष इस प्रकार है :-

1. विश्वविद्यालय अपने कार्यक्रमों को समाज की व्यवहारिक आवश्यकताओं से सम्बन्धित करनें में असफल हुये है।
2. विश्वविद्यालयों ने स्नातको की आपूर्ति को व्यवसाय के श्रोतों से सम्बनधित करने का कोई प्रयास नहीं किया है।
3. परीक्षाओं पर अनुचित बल दिया जा रहा है।
4. विश्वविद्यालयों के द्वार सभी छात्रों के लिये खोल दिये जाते है। प्रवेश में किसी चयनात्मक प्रणाली का अनुसरण नहीं किया जाता हैं, परिणाम यह होता है कि जनसाधारण का पैसा ऐसे छात्रों की शिक्षा के लिये व्यय होता है जो कि उस शिक्षा के लिये नितान्त अयोग्य और अनुपयुक्त है।
5. योग्य तथा प्रतिभाशाली छात्रों की शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति तथा उदार आर्थिक सहायता का आभाव है।
6. भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुतीर्ण छात्रों की संख्या विश्व के सभी विश्वविद्यालयों से अधिक है।

उपर्युक्त दोषों को दूर करने के लिये रिपोर्ट मे निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये गये-

1. विश्वविद्यालयों के प्रवेश नियमों को इतना कठोर बना दिया जाना चाहिये कि माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने वाले 10-15 छात्रों में से केवल एक छात्र ही विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सके।
2. विश्वविद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों के पारस्परिक सम्बन्धों में घनिष्ठता उत्पन्न करने के लिये ट्यूटोरियल सिस्टम का प्रचलन प्रारम्भ किया जाना चाहिये।
3. इन्टरमीडिएट कक्षा को भंग कर उसकी 12 वीं कक्षा का विश्वविद्यालय में एवं 11 वीं कक्षा को हाईस्कूल में जोड़ दिया जाये।
4. बी. ए. की उपाधि प्राप्त करने के लिये न्यूनतम अवधि 3 वर्ष रखी जाये।
5. विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने के लिये योग्य अध्यापकों को नियुक्त किया जाये।
6. शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाये और उनकी सेवा की दशाओं (Condition of service) में सुधार किया जाये।
7. निर्धन छात्रों को पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाये।
8. स्नातकोत्तर पाठ्य विषयों तथा विशुद्ध एंव प्रायोगिक शोध को अत्यन्त ऊँचे स्तर पर लाने का प्रयत्न किया जाये।
9. विश्वविद्यालयों प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालयों का विकास किया जाये।
10. प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक रोजगार कार्यालय तथा शैक्षिक एवं व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिये केन्द्र स्थापित किये जाये।
11. अध्यापिकाओं की बहुत बड़ी मात्रा की पूर्ति के लिये विश्वविद्यालय में महिलाओं को प्रवेश लेने के लिये प्रोत्साहन दिया जाये।
12. भारत के सभी विश्वविद्यालयों में समानता एंव एकता स्थापित करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान समिति (University Grant Committee) का गठन किया जाये।

सन् 1945 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के फलस्वरूप केन्द्रीय शिक्षा सचिवालय (Central Secretariate of Education) की स्थापना की गई, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन् 1947 में इस को शिक्षा मंत्रालय का अंग बना दिया गया, इसका मुख्य कार्य

सम्पूर्ण भारत की शिक्षा पर नियंत्रण रखना और उसका नियोजन करना था। इसी समय केन्द्रीय शिक्षा सूचना कार्यालय (Central Bureau of Education) की स्थापना की गई, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के परिणामस्वरूप सन् 1945 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति (University Grant Committee) की स्थापना की गई।

उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश काल में स्थापित विभिन्न विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं संस्थान.

अंग्रेजो के द्वारा भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद ईसाई मिशनरियों ने कुछ महाविद्यालय खोलने का प्रयास किया, कुछ महाविद्यालय व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा खोले गये, कुछ संस्थान सरकरी प्रयासों के द्वारा खोले गये, भारत के दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, भारत के दो महान समाज सुधारक पन्डित मदन मोहन मालवीय एवं सर सैयद अहमद खाँ के प्रयासों से अस्तित्व में आये। इन सभी का वर्षवार विवरण इस प्रकार हैं।

1. Agra College, Agra. - 1823

   B.A., B.Sc., M.A., M.Sc., LLB., LLM.

2. Bareilly College, Bareilly. 1837

   B.A., B.Sc., B.Com.,M.A., M.Sc., LLB.

3. St. John's College, Agra. 1850

   B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com.

4. Christ Church College, Kanpur. 1866

   B.A.,B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com.

5. University of Allahabad. Allahabad. 1887

6. Lucknow Christian College, Lucknow. 1888

   B.A. B.Sc. D.P.E.

7. Indian Veterinary Research Institute, Izzat Nagar - 243122. 1889

8. St. Andrews College, Gorakhpur. 1889.

   B.A., B.Sc., M.A., M.Sc., LLB.

9. Meerut College, Meerut. 1892

   B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Ed., LLB., LLM.

10. Mahila Vidyalaya College, Lucknow. 1895

    B.A., B.Sc., B.Ed.

11. Isbella Thoburn College, Lucknow. 1896 B.A., B.Sc., B.Ed., B.Lib.Sc.

12. Ewing Chiristian College, Allahabad. 1902 B.A., B.Sc.

13. GDHG College,Morabad. 1905. B.A., B.Sc.,B.Ed., M.A.

14. Indian Council of Forestry Research & Education. Dehradun. 1906.

15. U. P. Singh College, Varanasi. 1909.

    B.A., B.Sc., B.Com., B.Sc. (Ag), M.A., M.Sc., M.Com., M.Sc. (Ag), B.Ed.

16. Allahabad Agricultural Institute, Naini. Allahabad. 1910.

    B.Sc. (Ag engg), B.Sc. (Home Ecom), M.Sc. (Ag)

17 Govt. Central Texlite Institute, Kanpur. 1914 B. Text.

18. Banaras Hindu University, Varanasi. 04 Feb. 1916

19. Bappa Sri Narain Vocational College, Lucknow. 1917. B.A., B.Sc.

20. D.A.V. College, Kanpur. 1919. B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com.

21. Aligarh Muslim University, Aligarh. 1920

22. Lucknow University, Lucknow. 1921

23. V.S.S.D. College, Kanpur. 1921.

    B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com.,B.Ed., LLB.

24. Kali Prasad University College, Allahabad. 1922 B.A., B.Com.

25. William Holland University College, Allahabad. 1922. B.A.

26. Gurukul Kangri Ayurvedic College, Gurukul Kangri, Haridwar. 1922. B.A.M.S.

27. Agra University, Agra. 1927

28. S.N. Medical College, Agra. 1939.

    M.B.B.S., M.D., M.S., D.C.H., D.O.M.S., D.M.R.E., D.A., D.C.P.

29. Raja Balwant Singh College, Agra. 1940.

    B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com., B.Sc. (Ag), M.Sc. (Ag), B.Ed., M.Ed.

30. Almora Constituent College, Almora. 1940.

    B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com., B.Ed., M.Ed., LLB.

31. A.S. College, Lakhaoti - 245407. 1941

    B.A., B.Sc. (Ag), M.Sc. (Ag)

32. Vasanta College for Women Varanasi. 1946. B.A., B.Ed.

33. D.A.V. PG College, Dehradun. 1946.

    B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com., B.Ed., LLB.

34. NREC College, Khurja. 1946

    B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com., LLB.

35. Jai Narain Degree College, Lucknow. 1946. B.A., B.Sc., B.Com.

36. Karamat Hussain Muslim Girls College, Lucknow. 1946. B.A.

37. S.M. College, Chandausi, Moradabad. 1946.

    B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com.

38. Dharam Samaj College, Aligarh. 1947.

    B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., B.Ed., M.Ed., LLB.

39. K.R. College, Mathura. 1947.

    B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com.

40. Shri Varshney College, Aligarh. 1947.

    B.A.,B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com., B.Ed., LLB.

41. S.C. College, Ballia. 1947. B.A., B.Sc., B.Ed., M.A., M.Sc.

42. D.A.V. College, Varanasi. 1947. B.A., B.Com.

43. Digamber Jain College, Baraut, Meerut. 1947. B.A., B.Sc., M.A., M.Sc., B.Ed.

44. Shia Degree College, Lucknow. 1947. B.A., B.Sc., B.Com., LLB.

45. G. F. College, Shahjahanpur. 1947. B.A., B.Sc., M.A., M.Sc.

नोट – सभी विश्वविद्यालयों का एवं संस्थानों का विस्तृत विवरण, सभी महाविद्यालयों के सम्बद्धता का विवरण विश्वविद्यालय सम्बन्धी परिशिष्ट – 3 में दर्शाया गया है।

पंचम अध्याय

पंचम अध्याय

अ. उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश काल के बाद उच्च शिक्षा के विकास का स्वरूप

शिक्षा मानव के सर्वोन्मुखी विकास का सर्वोतम साधन है। शिक्षा मनुष्य को अपने वातवरण के अनुसार ढालने, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने, स्वस्थ जीविकोपार्जन करने तथा जीवन के उत्कृष्ट मूल्यों के प्रति आस्थावान दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है। प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति में जनता को शिक्षित होने से जहां तक और प्रजातंन्त्र को दृढ आधारशिला मिलती है, वही दूसरी और लोगों को अपने दायित्व को निर्वाह करने की सामर्थ्य भी प्राप्त होती है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये शिक्षा को प्रदेश के नियोजित विकास में प्रमुख स्थान दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न योजना अवधियों में शैक्षिक सुविधाओं मे तीव्र गति से वृद्धि हुई है।

शिक्षा ही मनुष्य की समस्त मानवीय गुणो से सुसम्पन्न करके अखिल विश्व के प्राणि मात्र में उसे गौरवपूर्ण उच्चतम शिखर क्षेणी पर आसीन कराती है। मानव के शारीरिक विकास के साथ-साथ शिक्षा का सशक्त माध्यम ही शनेः शनेः उस मानव को विकासोन्मुख प्रगति की ओर उत्तरोत्तर गतिमान करते हुये धैर्य, विवेक, सहनशीलता, सहिष्णुता, सॉस्कारिक सुसम्पन्नता, बौद्विक और सामाजिक सगजता आदि ऐसे मानवोचित विशिष्ट गुणों से अलंकृत करते हुये एक दिन उसके स्वरूप को परिष्कृत करके उसे युगानुकूल समाज के परिवर्तित परिवेश मे एक सुगम, सहज और सुखमय जीवन जीने की कला के निष्णात बनाकर मानव में महामानव की क्षेणी में पहुंचा देती है। इस कथन की सार्थकता के प्रमाण स्वरूप अतीत के अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनमें शिक्षा के प्रभाव प्रताप से अनेक महापुरूषों ने देश को समय समय पर प्रकारान्तर से कितने दुर्गम आशातीत, अप्रत्याशित लाभ देकर गौरवान्वित किया है। शिक्षा के सर्वागीण विवेचन से यह एक स्वंयसिद्ध तथ्य है कि एक सुशिक्षित व्यक्ति किन-किन अनेक रूपों के देश, प्रदेश और समाज के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उसको और अधिक विश्लेषित करने से वह एक संरक्षक अथवा अभिभावक के रूप में अपने कुटुम्ब के लिये, एक प्रबुघ्द नागरिक के रूप में प्रजातान्त्रिक प्रशासन व्यवस्था के लिये एक सच्चे, समाजसेवी के रूप में समाज के लिये अथवा एक उद्‌बुद्ध नेता अथवा सजग प्रहरी या दिशादाता के रूप में सम्पूर्ण मानव समाज सहित निज देश प्रदेश

से लेकर अर्न्तराष्ट्रीय स्तर तक के लिये लाभ को स्रोत बन सकता है।

इसी दृष्टिकोण के परिक्षेष्य में वर्तमान समय में देश–प्रदेश में सुनियोजित शैक्षिक विकास हेतु सुलभ वित्तीय संसाधनों का अनुपातिक दृष्टि से अधिकांश शिक्षा के लिये प्राविधानित किया जा रहा है। देश के परिवर्तित परिवेश और वर्तमान सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार की योजनाओ/परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ शैक्षिक नीति में परिर्वतन एवं उन्नत परिवर्धन के लिये सत्त चिन्तन चल रहा है।

अब तक शिक्षा के लिये बनाई गई योजनाओं और परियोजनओं में इस बात के लिये सतत् एवं उत्कृष्ट प्रयास किये गये हैं कि इनके क्रियान्वयन के माध्यम से शिक्षा की विषय वस्तु में परिवर्तन,अध्यापन की उन्नति पद्धतियों की ग्राहयता संशोधन और परिवर्तन द्वारा परीक्षा प्रणाली में स्तरोन्ययन,पाठ्य पुस्तक अध्ययन एवं अध्यापन और प्रशिक्षण में प्रत्याशित सुधार लाया जा सके।

इसी सन्दर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की वर्तमान संरचना एवं व्यवस्था में समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप आवश्यक सम्बर्न्धन के निमित्त चिन्तन चल रहा है। भारत सरकार द्वारा "शिक्षा की चुनौती नीति सम्बन्धी परिक्षेप्य" नामक दस्तावेज प्रसारित होने पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में विचार गोष्ठियां अक्टूबर, 1985 तक आयाजित की गयीं। इन गोष्ठियों में प्राप्त सुझावों और संस्तुतियों का संकलन मण्डलीय स्तर पर किया गया, नवम्बर 1985 के प्रथम सप्ताह में राज्य स्तर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें समाज के सभी वर्गो से आमन्त्रित प्रतिभागियों द्वारा शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं आयामों जैसे–प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ एवं सतत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा, महिला शिक्षा, परीक्षा पद्धति, उच्च शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था तथा पाठ्यक्रम एंव पाठ्य पुस्तको के निर्माण आदि पर गम्मभीरता पूर्वक विचार विमर्श किया गया। राज्य स्तरीय विचार गोष्ठी में प्राप्त सुझाव एवं संस्तुतियां भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई थीं।

यह प्रदेश 2,94,411 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में स्थित है। इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र और सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर इसे देश के विशालतम प्रदेश होने का गौरव प्राप्त हैं। शिक्षा जगत की सार्थक और व्यापक व्यवस्था के अनुरुप कार्य सम्पादन में सुविधा की दृष्टि से इन

पूरे प्रदेश का विभाजन विभिन्न मण्डलों में किया गया हैं।

वर्तमान समय में प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों का प्रशासन तथा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शासकीय व्यावस्था के माध्यम से वेतन वितरण तथा उनसे सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक कार्यो का सम्पादन शिक्षा निदेशालय (उच्च शिक्षा) द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय रखते हुये उच्च शिक्षा के नियमों• एवं विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) पर हैं। निदेशालय स्तर शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के सहायतार्थ दो संयुक्त शिक्षा निदेशक, दो उप शिक्षा निदेशक, तीन सहायक शिक्षा निदेशक और दो सहायक उप शिक्षा निदेशक कार्य कर रहे है। शिक्षा निदेशालय से सम्बन्धित वित्तीय मामलों की देखरेख के लिये एक वरिष्ट वित्त एवं लेखाधिकारी, दो लेखाधिकारी तथा दो सहायक लेखाधिकारी भी है। इसके साथ ही शिक्षा निदेशक की सहायता के लिये चार क्षेत्रीय अधिकारी भी हैं। जिनके आधीन कार्य करने के लिये चार सहायक लेखाधिकारी भी है। उप शिक्षा निदेशकों को सहयोग के लिये तीन सांख्यिकी शोध अधिकारी है।

उच्च शिक्षा निदेशालय

उत्तर प्रदेश

निदेशक

क्षेत्रीय अधिकारी	संयुक्त निदेशक	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(4)	(2)	(1)
सहायक लेखाधिकारी	उप निदेशक	लेखाधिकारी
(4)	(2)	(2)
सांख्यिकीय शोध अधिकारी	सहायक निदेशक	सहायक लेखाधिकारी
(3)	(3)	(2)
	सहायक उपनिदेशक	
	(2)	

प्रदेश के विश्वविद्यालयों को सामान्य शिक्षा के लिये सहायक अनुदान प्राप्त करने से सम्बन्धित समस्त

कार्य शासन स्तर पर होता है।

उच्च शिक्षा के स्तर में उन्नयन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 सितम्बर 1994 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों के पूर्णकालिक प्रवक्ताओं को रीडर पदनाम अनुमन्य किये जाने की घोषणा की है।[1]

उत्तर प्रदेश के विभिन्न शैक्षिक स्तरों के अतिरिक्त उच्च शिक्षा में शिक्षा की कार्यनीतियां निम्नवत् हैः-

उच्च शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता की दृष्टि से विद्यमान संस्थाओं की प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों आदि को सुदृढ़ किया जायेगा। नवीन शिक्षण संस्थाएं केवल शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े एवं असेवित क्षेत्रों में तभी प्रारम्भ की जायेगी जब कि मानकों के अनुसार भौतिक सुविधाओं एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था कर ली गई है।

2. स्नातक एवं स्नाकोत्तर स्तर की शिक्षा की विकसित देशों द्वारा दी जा रही उपाधि के समकक्ष लाने की दृष्टि से कला/विज्ञान/वाणिज्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम तीन वर्षीय तथा बी0एस0सी0(कृषि) के चार वर्षीय पाठ्यक्रम लागू किये गये है और उसी अनुरूप पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना की गई है। सामान्य ज्ञान की वृद्धि हेतु फाउन्डेशन कोर्स की व्यावस्था स्नातक पाठ्यक्रमों में की गई है।
3. उच्च कोटि के महाविद्यालयों की स्वायत्ता प्रदान की जायेगी जिससे कि वह क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपने पाठ्यक्रमों को पुर्नगठित कर लागू कर सकें।
4. शैक्षिक कैलेन्डर का निर्धारण कर शैक्षिक सत्रों को नियमित करने, शिक्षण एवं परीक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया जा रहा है।
5. शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु पुनर्वोधात्मक कार्यशालाओं, समर इंसटीट्यूट आदि की व्यवस्था की जा रही है।
6. शोध उन्नयन हेतु प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया जायेगा तथा प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना प्रस्तावित है।

---

1. उ0प्र0शासनादेश संख्या - 4707/15-11-94-14(5)/87, पी0सी0, लखनऊ, दिनांक 16 सितम्बर, 1994.

7. छात्र एवं शिक्षक कल्याण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जायेगी गेम्स स्पोर्टस, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, स्काउटिंग-नाइटिंग, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में छात्रों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

जब हम उच्च शिक्षा के इतिहास का अवलोकन करते है। तो उससे यह ज्ञात होता है कि महाविद्यालयों की स्थापना के बाद विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। सन् 1857 में सर्वप्रथम भारत से विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। उस समय उनके दो प्रमुख कार्य थे : 1- महाविद्यालयों की देखभाल और 2-परीक्षाओं का संचालन। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालयों का कार्य महाविद्यालयों को मान्यता देना था। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में यह एक प्रमुख अवधारणा रही है। बीसवीं सदी के प्रारम्भ में इस अवधारणा का बदलने का प्रयास किया गया। इस दिशा में प्रमुख कार्य कलकत्ता विश्वविद्यालय में परास्नातक कक्षायें खोलने से हुआ। इसके पूर्व परास्नातक शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा दी जाती थी। परास्नातक कक्षायें महाविद्यालयों से तोड़कर विश्वविद्यालयों में चलायी जाने लगी। इसका कारण यह था कि महाविद्यालय में पढ़ाई लिखाई का समुचित स्तर नहीं रख पाते थे। इस शताब्दी के प्रारम्भ में बहुत से नये विश्वविद्यालय खोले गये जैसे बनारस, अलीगढ़, लखनऊ, आगरा, आदि और इन विश्वविद्यालयों में एकरूपता बनाये रखने का प्रयास किया गया। कालान्तर में विश्वविद्यालयों में यूनिटरी पद्धति पर जोर दिया गया।

विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि के कारण विश्वविद्यालयी पद्वति पहले से अधिक उलझनपूर्ण हो गयी। आज जनसंख्या की वृद्धि की दर की अपेक्षा विश्वविद्यालयों में इनरोलमेंट 6 गुना अधिक है जबकि जनसंख्या की वृद्धि 2.2 प्रतिशत है। वहीं पर उच्च शिक्षा में इनरोलमेंट की दर 12 प्रतिशत है।

मुख्यतः पिछ्ले 28 वर्षो के दौरान 1947 से विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है। विश्वविद्यालयों की संख्या में इस रफतार से वृद्धि बहुत सी अन्य सामाजिक समस्याओं एवं वित्तीय समस्या को जन्म देगी। उसके साथ ही उनके प्रबन्ध और पाठ्यक्रम सम्बन्धी प्रश्न खड़ें हो जायेगे। 25 साल पहले सामान्यतः एक विश्वविद्यालय में 15 से 16 हजार विद्यार्थी हुआ करते थे आज उसकी तुलना में यह संख्या 50 हजार से लेकर 1.5 लाख तक पहुँच चुकी

है। राजस्थान विश्वविद्यालय में जहां पर लगभग 220 सम्बद्ध महाविद्यालय है और छात्रों की संख्या लगभग 2.5 लाख पहुंच चुकी है। 1947 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में 50 हजार विद्यार्थी थे आज इस विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या लगभग 2.5 लाख पहुंच चुकी है। इससे यह प्रकट होता है कि उच्च शिक्षा को आसानी से प्राप्त करने की दिशा में आश्चर्यजनक कार्य हुआ है। ऐसा इसलिये सम्भव हो सका कि हमने प्रजातान्त्रिक व समान शिक्षा के अवसर प्रदान किये है। स्वतंन्त्रता के पहले उच्च शिक्षा विशेष वर्ग के व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते थे। जबकि इस समय बिना किसी भेदभाव के जो भी चाहे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यद्यपि इस समय भी उच्च शिक्षा की सुविधाएं शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है। सरकार का यह रूझान रहा है कि उच्च शिक्षा को ग्रामीण आँचलों तक पहुँचाया जाए। कुल मिलाकर देश की उच्च शिक्षा में तीन प्रमुख समस्याएं आज भी विद्यमान हैं – 1- शिक्षा तक सब की पहुँच 2-गुणवत्ता में गिरावट, 3-घटिया शैक्षिक प्रबन्ध। इन पर विजय पाने के लिये भारत के जनमानस, भारत सरकार एवं प्रान्तीय सरकारों को अनवरत संघर्ष करने की आवश्यकता है।

विगत वर्षो में देश की उच्च शिक्षा पद्धति में प्रमुख दो बातों 1- बढ़ती हुई विद्यार्थियों की संख्या को तुष्टि करना व 2-दूसरी तरफ शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखना भी प्रमुख समस्या है। इन सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में स्पष्ट रूप से इस बात पर बल दिया गया है। कि उच्च शैक्षणिक संस्थाओं से यह आशा की जाती है कि उनके पास वांछित स्तर की भौतिक संसाधन, तकनीकी शोध सहायता, और कितने उपकरण आदि खरीदने के साधन उपलब्ध होगे। आयोग का यह प्रयास रहा है कि आवश्यक सुविधाओं को मुहैया कराया जाये जिससे कि उच्च शिक्षा पद्धति की गुणवत्ता व मात्रा में सन्तुलन बना रहे। प्रदेश की उच्च शिक्षा में पिछ्ले दशकों में छात्रों के नामांकन, शैक्षिक स्टाफ तथा संस्थाओं की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है इसके साथ ही प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या वर्ष 1991 से बढ़कर 22 तक पहुँच गई। यदि हम विद्यार्थी और संस्थाओं की बढ़ती हुई संख्या के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम पाते है कि विगत वर्षो में छात्रों के नामांकन और संस्थाओं में निरंतन वृद्धि हुई है। वर्ष 1980-81 में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 4,59481 विद्यार्थियों का नांमाकन हुआ। एक संस्था डीम्ड विश्वविद्यालय थी। वर्ष 1991 तक महाविद्यालयों की संख्या 441 हो गई एवं विद्यार्थियों का नांमाकन 9,97514 तक पहुँच गया।

20 वर्षो के दौरान (1970-71से 1990-91तक) विद्यार्थियों का नामांकन देखने से ज्ञान होता है कि 1970-71से 1980-81के दशक में विद्यार्थियों का नामांकन 459481 था जबकि 1980-81 से 1990-91 के मध्य 997514 था। यदि हम 1970-71 से 1990-91 के मध्य के नामांकन को देखें तो उसमें एक निश्चित बढ़ात्तरी की दर नहीं पाते है।

वर्ष 1990-91 में विभिन्न विश्वविद्यालयौं एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में विभिन्न स्तरों पर नामांकन 6,54000 था। इन सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का स्नातक स्तर का नामांकन 5,04000 था जबकि परास्नातक स्तर का नामांकन 1,50000 था।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का वर्ष 1950-51 में अध्यापकों की संख्या 2521 थी। इनमें 2376 पुरूष अध्यापक एवं 145 महिला अध्यापक थे। वर्ष 1990-91 में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापनरत अध्यापकों की संख्या 22576 हो गई। जिनमे पुरूष - अध्यापकों की संख्या 18304 एवं महिला अध्यापकों की संख्या 4272 थी।

वर्ष 1983-84 में प्रदान की गई डाक्टरेट उपाधियों की संख्या 1677 थी। वर्ष 1983-84 में कला संकाय में सबसे अधिक 761 डिग्री प्रदान की गई। उसके बाद विज्ञान संकाय में प्रदान की गई डिग्रियों की संख्या आती है जो 580 है। व्यवसायिक संकाय में सबसे अधिक डाक्टरेट डिग्री कृषि संकाय में 161 प्रदान की गई। अभियांत्रिकी/तकनीकी संकाय का स्थान दूसरा है इसमें प्रदान की गई डिग्रियों की संख्या 64 थी। वाणिज्य संकाय में 44 तथा शिक्षा संकाय में 47 डिग्रियां प्रदान की गई थी। अन्य संकायो की स्थिति इस प्रकार है। मेडिसिन-07, पशु चिकित्सा विज्ञान-05, विधि-01 व अन्य संकायो में 07 डाक्टरेट डिग्रिया प्रदान की गई थीं।

ब. ब्रिटिश काल के बाद उच्च शिक्षा के विकास के लिये गठित विभिन्न आयोगों एवं समितियों का विस्तृत अध्ययन

ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात भारत सरकार के द्वारा विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया जिनका क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है -

(1) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग. 1948-49

The University Education Commission. 1948-49.

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत कालेजो एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में दिन प्रतिदिन तीव्र गति से वृद्धि होने लगी किन्तु उच्च शिक्षा में किसी प्रकार के सुधार न होने के कारण वह नवीन राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में एक प्रजातान्त्रिक देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ सिद्ध हो रही थी, अतः देश के पुनर्निर्माण के लिये उच्च शिक्षा का पुर्नगठन करना अति आवश्यक समझा गया। इसी समय में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education) और अन्तर्विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद (Inter University Board of Education) ने भी सरकार से एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त करने की सिफारिश की जो देश की नवीन आवश्यकताओं के अनूकूल विश्वविद्यालय शिक्षा के पुर्नगठन के लिये सुझाव दे। अन्त में इन परिस्थितियों एवं सिफारिशों से प्रेरित होकर भारत सरकार ने 04 नवम्बर सन् 1948 में डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की डॉ राधाकृष्णन के नाम पर ही इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा उन सुधारों एवं विकासो के विषय में सलाह देना था जो देश की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के उपयुक्त होने के लिये बांछनीय हो।

आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर सुझाव दिये जो इस प्रकार है:-

1. विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य

Aims of University Education:

1. देश में ऐसे नागरिकों को जन्म देना जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, वाणिज्य, आदि क्षेत्रों में नेतृत्व ग्रहण कर सकें।
2. देश की भौतिक समृद्धि के विकास एवं संरक्षण के साथ उसकी सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण एवं सम्बर्धन करना।
3. प्राचीन मर्यादाओं का समुचित आदर करके नई मान्यताओं और नवीन विचारधाराओं को जन्म देना।

4. विविध प्रकार के ज्ञान का समन्वय करना और उसकी उपलब्धि के अवसर तथा साधन देना तथा ज्ञान के साथ-साथ आत्मा का भी विकास करना।
5. जनतांत्रिक आदर्शों की सुरक्षा करना, व्यक्ति एवं समाज में सामन्जस्य स्थापित करना।
6. नैतिकता एवं सदव्यवहार के आदर्शों की स्थापना करना तथा चरित्र, व्यक्तित्व, अनुशासन आदि का निर्माण करना।
7. अर्न्तराष्ट्रीय भावना का विकास करना।

2. अध्यापक वर्ग - Teaehing Staff.

1. अध्यापक की पदोन्नति न केवल ज्येष्ठता (Seniority) के आधार पर होना चाहिये बल्कि योग्यता (Ability) के आधार पर भी होना चाहिये।
2. शिक्षको को भविष्य निधि (Provident Fund) की अधिक उत्तम सुविधा प्रदान की जानी चाहिये। इस फन्ड में शिक्षक एवं विश्वविद्यालय दोनो को 8-8 प्रतिशत देना चाहिये।
3. शिक्षकों को 60 वर्ष की अवस्था में अपने पद से सेवा निवृत करना चाहिये। अच्छे स्वास्थ्य वाले शिक्षकों को 64 वर्ष की अवस्था तक अपने पदों पर कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिये।
4. शिक्षकों को अध्ययन के लिये एक बार में एक वर्ष का और सम्पूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष का आधे वेतन पर अवकाश दिया जाना चाहिये।
5. शिक्षकों को एक सप्ताह में 18 घण्टे (Periods) से अधिक का शिक्षण कार्य नहीं दिया जाना चाहिये।
6. विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं अध्यापकों के मध्य यदि किसी प्रकार का विवाद हो जाता है। तो उसे निपटाने के लिये न्यायाधीश की नियुक्ति की जाये।

3. शिक्षण का स्तर - Standard of Teaching.

1. छात्रों की बढ़ती हुई भीड़ को रोकने के लिये, शिक्षण विश्वविद्यालयों में 3000 और उनसे सम्बद्ध कालेजों में 1500 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिये।
2. कालेजों और विश्वविद्यालयों में परीक्षा दिवसों को छोड़कर एक वर्ष में कम से कम 180 दिन शिक्षण कार्य किया जाना चाहिये।
3. अध्यापक अपने भाषण को अति परिश्रम से तैयार करे। उपकक्षाओं (Tutorial Classes) की व्यवस्था

की जाये और पुस्तकालय में अध्ययन एवं लिखित कार्य पर जोर दिया जाये।

4. स्नातकोत्तर कक्षाओं में विचार गोष्ठियों की योजना क्रियान्वित की जानी चाहिये।
5. किसी पक्ष के लिये पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तके निशिचित न की जाये।
6. छात्रों के लिये पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की जाये।
7. स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों को व्याख्यान सुनने के लिये बाध्य न किया जाये।
8. छात्रों की 18 वर्ष की आयु हो जाने पर विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाये।
9. परीक्षाओं के स्तर को उचाँ उठाने के लिये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, श्रेणी के लिये न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 70,55 और 40 प्रतिशत होने चाहिये।
10. विभिन्न व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के लिये सायंकालीन कक्षाएं (Evening Classes) प्रारम्भ की जानी चाहिये।

4. पाठ्यक्रम (Course of Study)

1. स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के लिये अध्ययन की अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिये।
2. स्नातकोत्तर उपाधि-स्नातक बनने के 2 वर्ष पश्चात और आनर्स के एक वर्ष पश्चात दी जानी चाहिये।
3. विशेषीकृत शिक्षा (Specialization) के दोषों का निवारण करने के लिये विश्वविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में सामान्य शिक्षा के सिद्धान्त एवं प्रयोग (Theory and Practical of General Education) का शिक्षण प्रारम्भ किया जाना चाहिये।
4. शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य और विशेषीकृत शिक्षा में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये।
5. कालेजों और विश्वविद्यालयों में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिये, जो 12 वर्ष की विद्यालय शिक्षा समाप्त कर चुके हो।
6. उपाधि कक्षाओं के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को स्थान दिया जाना चाहिये -

I - संघीय भाषा, प्राच्य या आधुनिक भारतीय भाषा
(जिनकी मातृ-भाषा संघीय भाषा है)

II - अंग्रेजी

III- एवं IV - कला विद्यार्थियो के लिये कम से कम एक विषय प्रत्येक समूह में से एक -

प्रथम समूह

अ- एक प्राच्य या आधुनिक भारतीय शास्त्र
ब- फ्रेन्चं या जर्मन
स- इतिहास
द- गणित
य- ललित कला

द्वितीय समूह

अ- राजनीति
ब- समाज शास्त्र
स- मनोविज्ञान
द- मानविकी
य- भूगोल
र- अर्थशास्त्र

III एवं IV विज्ञान के विद्यार्थियों के लिये निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषय -

अ- गणित
ब- रसायन शास्त्र
स- वनस्पति शास्त्र
द- प्राणी शास्त्र
य- भौतिकी

5. स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य :

(Post graduate Training & Research Work)

1. एम.ए. और एम.एस-सी. की उपाधियों में अखिल भारतीय स्तर पर एकरूपता स्थापित की जाये।
2. स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में एक विशेष विषय के उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान की विधियों के प्रशिक्षण को स्थान दिया जाना चाहिये।
3. पी-एच.डी. के छात्रों का चयन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाना चाहिये और उनके अनुसंधान कार्य की अवधि दो वर्ष से कम नही होनी चाहिये।
4. पी-एच.डी. एवं अन्य अनुसंधान कार्य के लिये विद्यार्थियों के लिये छात्रवृतियों के मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये।
5. डी. लिट. और डी. एस-सी. उपाधि केवल उच्च कोटि के मौलिक एवं प्रकाशित कार्यो पर दी जानी चाहिये।
6. उपकक्षाओं में शिक्षण कार्य भाषण, गोष्ठी एवं प्रयोगशाला कार्य पर आधारित हो।

7. विश्वविद्यालय में मुख्य ध्यान विशुद्व तथा आधारभूत अनुसंधान की ओर होना चाहिये।

6. परीक्षाएं Examinations

1. छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये यथाशीघ्र वस्तुनिष्ठ प्रगति परीक्षाओं का सैट तैयार किया जाना चाहिये।

2. त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स की परीक्षा 3 वर्ष पश्चात न ली जाकर प्रत्येक वर्ष के अन्त में ली जानी चाहिये। यह परीक्षा स्वतः पूर्ण इकाइयों (Self Contained Units) में ली जानी चाहिये। और छात्रों के लिये प्रत्येक इकाई अर्थात प्रति वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होना चाहिये।

3. परीक्षाओं के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय, श्रेणी के न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 70,55 एवं 40 प्रतिशत होने चाहिये।

4. सब विश्वविद्यालयों को सब परीक्षाओं में क्रपांक (Grace Marks) देने की पद्वति समाप्त कर दी जानी चाहिये।

5. प्रत्येक विश्वविद्यालय में कम से कम 5 वर्ष के शिक्षण का अनुभव रखने वाले 3 सदस्यों का एक पूर्णकालिक बोर्ड संगठित किया जाना चाहिये। इस बोर्ड के 3 मुख्य कार्य होने चाहिये-

   क. विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध कालेजों के शिक्षकों को वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की नवीन योजनाएं बनाने में सहायता देना।

   ख. उक्त परीक्षाओं को पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिये सामिग्री देने की व्यवस्था करना।

   ग. सम्बद्ध कालेजों के छात्रों की प्रगति का समय-समय पर प्रगति परीक्षाओं द्वारा मूल्यांकन करना।

6. स्नातकोत्तर एवं व्यवहारिक परीक्षाओं में लिखित के साथ-साथ मौखिक परीक्षाओं (Viva-Voce Tests) को प्रधानता दी जाये।

7. छात्रों के कक्षा कार्य को महत्व दिया जाये और इसके लिये 1/3 अंक निर्धारित किये जाये।

8. विश्वविद्यालयों और शिक्षा मंत्रालय द्वारा परीक्षा लेने की वैज्ञानिक प्रणालियों की खोज की जाये और छात्रों के परिणामों से लाभ उठाया जाये।

9. शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक या दो ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाये जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के

निर्माण तथा प्रोग्राम मे निपुण हो। इन विशेषज्ञों का कार्य विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान केन्द्रो को परामर्श देना हो।

10. राजकीय पदों के लिये विश्वविद्यालयों की उपाधियों को मान्यता न दी जाये, सेवा आयोग के द्वारा राजकीय पदों के लिये परीक्षाओं की व्यवस्था की जाये।

7. शिक्षा का माध्यम Medium of Instruction

1. हिन्दी भाषा का संघीय भाषा के रूप में विकास किया जाये और देश के सभी भागों में उसे उच्च माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर अनिवार्य विषय बना दिया जाये।
2. उच्च शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा हो किन्तु राष्ट्रभाषा अर्थात हिन्दी को एक या अधिक विषयों की शिक्षा का माध्यम बनाया जाये।
3. राज्य सरकारें उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कालेजों एवं विश्वविद्यालयों की समस्त कक्षाओं में संघीय भाषा की शिक्षा का प्रबन्ध करें।
4. बाह्य विश्व एवं नवीन ज्ञान के साथ सम्पर्क बनाये रखने के लिये स्कूली एवं विश्वविद्यालयों की समस्त कक्षाओं में संघीय भाषा की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाये।
5. उच्च माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्र को अग्रलिखित तीन भाषाओं का ज्ञान कराया जाये।

   क. क्षेत्रीय भाषा

   ख. राष्ट्र भाषा

   ग. अंग्रेजी भाषा
6. संघीय भाषा के लिये केवल देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाये और इस लिपि के दोषों को यथाशीघ्र दूर किया जाये।

8. ग्रामीण विश्वविद्यालय. Rural University

1. ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे आवास पूर्ण स्नातक कालेज स्थापित किये जाये और इनके केन्द्र में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये।
2. एक कालेज के छात्रों की संख्या लगभग 300 और विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध सब कालेजों

के छात्रों की संख्या 2500 से अधिक नहीं होनी चाहिये।

3. सब कालेजों के लिये प्रथक अध्यापक होने चाहिये, किन्तु एक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अधिक से अधिक कालेजों के लिये पुस्तकालयों प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयो, खेल के मैदानों आदि की व्यवस्था एक ही स्थान पर होनी चाहिये।
4. ग्रामीण कालेजों में स्नातक पूर्व शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के विश्वविद्यालय में या व्यवसायिक स्कूल में किसी विशेष विषय का अध्ययन करने की सुविधा होनी चाहिये।
5. स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में इस प्रकार विभाजन किया जाना चाहिये कि जो छात्र, स्नातक पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे है, वे कुछ विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षा भी ग्रहण कर सकें।
6. ग्रामीण विश्वविद्यालय में अनुसंधान का प्रबन्ध किया जायें।
7. ग्रामीण शिक्षा का उचित विकास करने के लिये अखिल भारतीय स्तर पर एक ग्रामीण शिक्षा परिषद की स्थापना की जायें।

9. छात्र कल्याण कार्य : Student Welfare Activities

आयोग ने छात्रों के सर्वांगीण विकास का महत्व स्पष्ट करते हुये निम्नलिखित कल्याण कार्यो का सुझाव दिया।

1. समस्त योग्य छात्रों को समान रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा को प्राप्त करने की सुविधा दी जाये।
2. प्रवेश के समय एवं इसके बाद वर्ष में एक बार प्रत्येक छात्र की निशुल्क स्वास्थ्य की परीक्षा की जाये।
3. प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रों की चिकित्सा के लिये चिकित्सालय की व्यवस्था की जाये।
4. प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक डाईरेक्टर आफ फिजिकल एजूकेशन की नियुक्ति की जाये।
5. प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार समिति (Advi sory Board of Student Welfare) का विकास किया जायें।
6. छात्रों की उत्तम प्रशासन में रूचि पैदा की जाये और प्रैक्टिकल सिस्टम का विकास किया जायें।
7. विश्वविद्यालय में छात्रावासों की समुचित व्यवस्था की जायें एक छात्रावास में 50 से अधिक विद्यार्थी न हो।
8. समस्त शिक्षा संस्थाओं में एन0 सी0 सी0 (National Cadet Corps) का संगठन किया जाये।

(2) माध्यमिक शिक्षा आयोग The Secondary Education Commission.

(1952-53)

भारत सरकार ने 23 सितम्बर सन् 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग के अध्यक्ष पद पर मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉ0 ए0 लक्ष्मण स्वामी मुदालिपर को नियुक्त किया गया।

आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है। इन्टरमीडियट पाठ्यक्रम जो दो वर्ष का है उसके पहले वर्ष को माध्यमिक स्तर में स्थानान्तरित कर दिया जाये और स्कूल शिक्षा की अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष से 11 वर्ष कर दिया जाये। इन्टरमीडिएट पाठ्यक्रम को समाप्त करके डिग्री पाठ्यक्रम 3 वर्ष का कर दिया जाये। केवल दो राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने आयोग के इस सुझाव को स्वीकार किया और उस पर अमल किया।

(3) शिक्षा आयोग (Education Commission)

1964-66

भारत सरकार ने 14 जुलाई सन् 1964 को अपने 'प्रस्ताव' मे नवीन शिक्षा आयोग की नियुक्ति के कारणों एवं प्रायोजनों का स्पष्टीकरण करके उसी 'प्रस्ताव' के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) के अध्यक्ष प्रो0 डी0 एस0 कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। प्रोफेसर कोठारी के नाम से इस आयोग को कोठारी आयोग भी कहा जाता है।

शिक्षा आयोग को अपना प्रतिवेदन 31 मार्च 1966 तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था, किन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण, उसने अपने प्रतिवेदन को निर्धारित तिथि से लगभग 3 माह पश्चात 29 जून 1966 को भारत सरकार के तत्वकालीन शिक्षा मंत्री एम0 सी0 छागला के समक्ष प्रस्तुत किया। 673 पेजों का यह प्रतिवेदन तीन भागों में विभाजित है और इसका नाम 'शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति' (Education and National Development) है।

इस आयोग ने शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अपने सुझाव प्रस्तुत किये है। उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में इस आयोग के प्रमुख सुझाव इस प्रकार है।

1. विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य

Aims of University Education

1. नवीन ज्ञान की खोज एवं उसका विकास करना।
2. सत्य की खोज के लिये साहस एवं निर्भयता से काम करना।
3. सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं को कम करना।
4. सामानता एवं सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना।
5. राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने के लिये कार्य करना।
6. नवीन खोजों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राचीन ज्ञान का विश्लेषण करना।
7. प्रतिभाशाली नवयुवकों की खोज करना और उनको अपनी शक्तियों एवं प्रतिभाओं का विकास करने में सहायता देना।
8. देश में कला, कृषि, विज्ञान, चिकित्सा, प्रौद्यिगिकी एवं अन्य व्यवसायों के लिये कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण करना।
9. छात्रों एवं शिक्षकों में और उनके द्वारा समाज के व्यक्तियों में उचित मान्यताओं, और दृष्टिकोणों का विकास करना।

2. वरिष्ठ विश्वविद्यालयों का विकास

Development of Major Universities :

आयोग ने उच्च शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण स्थान 'वरिष्ठ विश्वविद्यालयो' के विकास को दिया है जहाँ पर सर्वोत्तम प्रकार का स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान कार्य किया जा सके। इन विश्वविद्यालयों के विकास के लिये आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दियेः-

1. प्रत्येक वरिष्ठ विश्वविद्यालय पूर्व स्नातक स्तर के लिये कुछ छात्रवृतियों को निश्चित करे ताकि वह स्नातकोत्तर कार्य के लिये पर्याप्त संख्या में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राप्त कर सकें।
2. प्रत्येक वरिष्ठ विश्वविद्यालय में उन्नत अध्ययन केन्द्रों के समूह (Clusters of Advanced Centres) स्थापित किये जाये।
3. शिक्षकों की नियुक्ति राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय आधार पर की जाये। जहाँ आवश्यक हो वहाँ चुने हुये शिक्षकों के विशेष वेतन दर या अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की जायें।

4. वरिष्ठ विश्वविद्यालयों का व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाये।

वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के विषय में आयोग ने अपने विचार इस प्रकार उपस्थित किये, उच्च शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सुधार – कुछ वरिष्ठ विश्वविद्यालयों का विकास करना है। जिनमें सर्वोत्तम प्रकार का स्नातकोत्तर कार्य एवं अनुसंधान सम्भव होगा और जिनके स्तर की संसार के किसी भाग में इस प्रकार की सर्वोत्तम संस्थाओं के स्तर से तुलना की जा सकेगी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जल्दी से जल्दी वर्तमान विश्वविद्यालयों में से लगभग 6 विश्वविद्यालयों को वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित करने के लिये चुन लेना चाहिये, इनमें से कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय और एक आई0 आई0 टी0 होना चाहिये, वरिष्ठ विश्वविद्यालयों में असाधारण क्षमता एवं अध्यव्यवसाय के छात्र एवं अध्यापक होने चाहिये।

3. नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना

Establishment of New Universities :

आयोग का मत है कि नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

1. कोई नवीन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहमति के बिना स्थापित नहीं किया जाना चाहिये।

2. नवीन विश्वविद्याल सामान्य रूप से उस स्थान पर स्थापित नहीं किये जाने चाहिये, जहाँ कुछ समय से कोई विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है।

3. नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना तभी की जानी चाहिये, जब इस बात का पूरा भरोसा हो कि उससे शिक्षा के स्तरों में उन्नति होगी, उसके लिये योग्य शिक्षक उपलब्ध होगे और उसमें उच्च स्तर का शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य किया जायेगा।

4. जिन स्थानों पर अनेक स्नातकोत्तर कालेज कार्य कर रहे हैं उनको संगठित करके विश्वविद्यालयों का रूप प्रदान किया जाना चाहिये।

5. दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, एवं मद्रास, प्रत्येक नगर में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दो विश्वविद्यालय है। केरल और उड़ीसा में भी एक और विश्वविद्यालय की स्थापना की माँग स्वीकार की जाये तथा उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिये भी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार

किया जाये।

6. उचित मात्रा में धन की व्यवस्था के बिना भविष्य में नये विश्वविद्यालयों की स्थापना न की जाये।

4. विश्वविद्यालयों और कालेजों में सुधार

Improvement in Universities and Colleges

1. वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के प्रतिभाशाली तथा योग्य विद्यार्थियों में ऐसी भावना उत्पन्न की जाये कि अध्ययन के बाद वे शिक्षण कार्य को अपनाये।
2. वरिष्ठ विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बन्धित कालेजों को उत्तम शिक्षक प्रदान करे।
3. विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध कालेज अपने नर्व निर्वाचित शिक्षकों को कुछ समय के लिये वरिष्ठ विश्वविद्यालयों में भेजे जिनमे वे अपने विषय से सम्बन्धित नवीन विचारों और प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करें।
4. विश्वविद्यालयों में उन्नत अध्ययन केन्द्रों की स्थापना के लिये प्रत्येक सम्भव सहायता दी जाये।
5. प्रतिभाशाली एवं योग्य विद्वानों और वैज्ञानिकों को अनुसंधान तथा सेमिनारों को संचालित करने के लिये आमंत्रित किया जाये।
6. विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों पर उनके कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया जाना चाहिये।
7. यदि किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई असाधारण कालेज है तो उसे स्वायत्तशासी कालेज (Autonomous College) बना दिया जाना चाहिये। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 50 कालेजों को यह पद दिया जाये।
8. बड़े कालेजों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाये। एक कालेज में कम से कम छात्रों की संख्या 500 हो तथा जहाँ सम्भव हो वहाँ इस संख्या को बढ़ाकर 1000 या इससे अधिक किया जा सकता है।
9. विश्वविद्यालय नये कालेजों को मान्यता देने के स्थान पर वर्तमान स्थित कालेजों के विस्तार पर बल दे। नये कालेजों को मान्यता देते समय यह ध्यान रखा जाये कि वे स्थित कालेजों के विकास में बाधक सिद्ध न हों।

5. विश्वविद्यालय स्वाधीनता University Autonomy,

विश्वविद्यालय स्वीधानता की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुये आयोग ने लिखा - "It is important to recognise that without autonomy universities can not discharge effectively their principal functions of teaching, research and service to the community. [1]

आयोग ने अग्रलिखित क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की स्वाधीनता का समर्थन किया - छात्रों का चुनाव, शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति और पाठ्य विषयों शिक्षण विधियों एवं अनुसंधान कार्य के क्षेत्रों एंव समस्याओं का निर्धारण इन क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की स्वाधीनता को ध्यान में रखते हुये आयोग ने निम्नालिखित विचार प्रकट किये है।

1. विश्वविद्यालयों को अपने विभागों को कार्य की पर्याप्त स्वतंन्त्रता देनी चाहिये।
2. प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष की अधीनता में एक प्रबन्ध समिति का निर्माण किया जाना चाहिये। इस समिति को व्यापक आर्थिक एवं प्रशासकीय शक्तियों से सम्पन्न किया जाना चाहिये।
3. विश्वविद्यालयों को अपने प्रशासन में इस सिद्धान्त को ध्यान में रखना चाहिये कि श्रेष्ठ विचारों का जन्म साधारणः निम्न स्तरों में होता है।
4. विश्वविद्यालयों को कालेजों की स्वतंत्रता का उतना ही आदर करना चाहिये जितना कि वे अपनी स्वतंत्रता का करते है।
5. विश्वविद्यालयों कों साहित्यक परिषदों (Academic Council) एवं सभाओं (Courts) में छात्र प्रतिनिधियों की उपयुक्त संख्या को स्थान दिया जाना चाहियें।
6. विश्वविद्यालयों को अपनी स्वाधीनता को बनाये रखने के लिये सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिये। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिये उनको बोद्धिक एवं सामाजिक कार्यो को सदैव तत्परता से करना चाहिये।
7. प्रत्येक कालेज के प्रत्येक विभाग में छात्रों एवं अध्यापकों की संयुक्त समितियों (Joint Committees) का निर्माण किया जाना चाहिये।

1- Education Commission Report, P.- 326

8. प्रत्येक कालेज में प्राचार्य की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का संगठ्न किया जाना चाहिये, जिसके द्वारा कालेज की सामान्य समस्याओं एवं कठिनाइयों का अध्ययन किया जाना चाहिये ।
9. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अन्तरविश्वविद्यालय परिषद (Inter university Board) एवं शिक्षित व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय स्वाधीनता के पक्ष में जनमत का निर्माण किया जाना चाहिये।

6. विश्वविद्यालय प्रशासन

University Administration

1. विश्वविद्यालयों को उपकुलपति के चुनाव में पूर्ण स्वतंत्रता हो, परन्तु वर्तमान समय में उपकुलपति की नियुक्ति के लिये देहली विश्वविद्यालय की पद्धति अपनाई जा सकती है, उपकुलपति एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एवं अनुभव प्राप्त व्यक्ति होना चाहिये, उपकुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष का हो जिसे एक कार्य अवधि के लिये और बढ़ाया जा सकता है। उपकुलपति का पद पूर्णकालिक एंव वैतनिक होना चाहिये।
2. विश्वविद्यालय कोर्ट, नीति निर्धारण संस्था का कार्य करे। कोर्ट के सदस्यों की संख्या 100 हो जिसमें से आधे सदस्य विश्वविद्यालय के बाहर से हो।
3. कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष उपकुलपति हो तथा कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 15 से 20 तक हो। इनमें से आधे सदस्य विश्वविद्यालय के बाहर के हो।
4. राज्य प्रमुख-राज्य में स्थित सभी विश्वविद्यालयों का बिजिटर हो तथा इन विश्वविद्यालयों की जाँच एवं निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार हो।

7. शिक्षण में सुधार

Improvement in Teaching

आयोग ने विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध कालेजों में शिक्षण में सुधार करने के विचार से निम्नलिखित सुझाव दिये।

1. कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में उत्तम पुस्तकालयों की व्यावस्था की जानी चाहिये।
2. छात्रों में प्रचलित निष्क्रिय रटने की प्रवृति को निरूत्साहित किया जाना चाहिये और उसमें मौलिक चिन्तन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

3. व्याख्यान के बाद उसकी सामिग्री को याद करने के लिये छात्रों की 45 मिनट का समय दिया जाना चाहिये।
4. औपचारिक कक्ष कार्य और प्रयोगशाला कार्य के घन्टें की कमी की जानी चाहिये। छात्रों द्वारा इस प्रकार बचने वाले समय का प्रयोग एक निर्देशक (Instructor) के मार्गदर्शन में स्वाध्याय, लेखन कार्य, समस्या समाधान, अनुसंधान कार्य आदि के लिये किया जाना चाहिये।
5. नये अध्यापकों की नियुक्तियां गर्मी की छुट्टियों में कर दी जानी चाहिये, ताकि नियुक्त किया जाने वाला प्रत्येक अध्यापक सत्र के प्रारम्भ से ही शिक्षण कार्य करने लगे।
6. सत्र के मध्य में किसी अध्यापक को एक संस्था को छोड़कर दूसरी संस्था में जाने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिये।
7. शिक्षण विधियों में सुधार के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक विशेष समिति की नियुक्ति की जानी चाहिये।

8. मूल्यांकन में सुधार

Improvement in Evaluation

आयोग ने मूल्यांकन में सुधार करने के लिये निम्नालिखित सुझाव प्रस्तुत कियेः-

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों की सहायता से केन्द्रीय परीक्षा सुधार यूनिट (Central Examination Reform Unit) का निर्माण करना चाहिये।
2. समस्त शिक्षण विश्वविद्यालयों में बाहय परीक्षाओं के स्थान पर आन्तरिक तथा क्रमिक मूल्यांकन (Internal Assessment and Continuous Evaluation) की प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाये।
3. विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को मूल्यांकन की नवीन एवं उन्नत प्रकार की प्रविधियों (Technique) से परिचित कराया जाये।
4. परीक्षकों की उत्तर पुस्तिकाओं की जॉंच करने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले परिश्रमिक को समाप्त कर दिया जाये।
5. एक परीक्षक को एक वर्ष में 500 से अधिक उत्तर पुस्तिकाएं जॉंचने के लिये नहीं दी जानी चाहिये।

6. विश्वविद्यालय के अध्यापकों को सेमिनार, वर्कशाप, एवं विचार सम्मेलन का आयोजन करके, मूल्यांकन की नवीन एवं उन्नत विधियों की जानकारी प्रदान की जानी चाहिये।

9. शिक्षा का माध्यम

Medium of Instruction

आयोग ने कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के बारे में अग्रलिखित सुझाव प्रस्तुत किये है।

1. पूर्व स्नातक स्तर पर शिक्षा का माध्यम यथा सम्भव क्षेत्रीय भाषाएं और स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा का माध्यम-अंग्रेजी होनी चाहिये।
2. क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषाओं (Regional languages) को 10 वर्ष की अवधि में विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बना दिया जाना चाहिये।
3. उच्च शिक्षा की संस्थाओं में कार्य करने सब शिक्षकों को यथा सम्भव दो भाषाओं का ज्ञान होना चाहिये।
4. आधुनिक भारतीय भाषाओं (जिनमे उर्दू भी है) के विकास के लिये उच्च अध्ययन केन्द्रो की व्यवस्था की जानी चाहिये।
5. शास्त्रीय एवं आधुनिक भारतीय भाषाओं को विश्वविद्यालयों में अनिवार्य विषयों में स्थान न देकर वैकल्पिक विषयों में स्थान दिया जाना चाहिये।
6. विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध कालेजों में छात्रों को अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिये विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिये।
7. उक्त शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को रूसी भाषा का अध्ययन करने के लिये उपयुक्त सुविधाएं दी जानी चाहिये।

10. चयनात्मक प्रवेश - प्रणाली

System of Selective Admission

आयोग का मत है कि भविष्य में जिस अनुपात में उच्च शिक्षा की माँग में वृद्धि होगी, उस अनुपात में उच्च शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार करना सम्भव नहीं होगा, अतः जनबल

(Manpower) की आवश्यकता को ध्यान में रखकर 'चयनात्मक प्रवेश प्रणाली' का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। इस प्रणाली की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुये आयोग ने लिखा है- सामान्य रूप से यह होता है कि श्रेष्ठ क्षमताओं वाले थोड़े से छात्रों को उच्च शिक्षा की संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिल पाता है, और उनमें छात्रों की उस विशाल संख्या का प्रवेश हो जाता है जो उच्च शिक्षा के लिये पूरी तरह से तैयार नहीं होते है। इस दोष का निवारण करने के लिये, आयोग ने चयनात्मक प्रवेश प्रणाली के प्रयोग पर बल दिया है और उसके सम्बन्ध में अग्रलिखित सुझाव दिये है:-

1. विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवेश योग्यताओं के नियमों का निर्माण किया जाना चाहिये।
2. विश्वविद्यालयों में प्रवेश चाहने वाले छात्रों में से योग्यतम छात्रों का ही चुनाव किया जाना चाहिये।
3. उच्च शिक्षा की संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या का निश्चय इन संस्थाओं में उपलब्ध शिक्षक संख्या और शिक्षक सुविधाओं के आधार पर किया जाना चाहिये।
4. जब तक प्रवेश सम्बन्धी नवीन विधियों की खोज न की जाये तब तक परीक्षाओं में प्राप्त होने वाले अंकों को प्रवेश का आधार बनाया जाना चाहिये।
5. प्रत्येक विश्वविद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये 'विश्वविद्यालय प्रवेश परिषद' का गठन किया जाना चाहिये।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा छात्रों को प्रवेश देने सम्बन्धी नियमों का निर्माण करने के लिये एक समिति का गठन किया जाये।

11. पाठ्यक्रम का पुनर्गठन

1. स्नातक स्तर पर चुने जाने वाले विज्ञान एवं कला के पाठ्यक्रम के अर्न्तगत विषय समूहों को लचीला बनाया जाये।
2. स्नातक स्तर पर सामान्य एवं प्रवीण पाठ्यक्रम दोनों की ही व्यावस्था की जाये।
3. स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यचर्या का इस प्रकार संगठन किया जाये कि छात्र एक या दो विषयों का प्रगाढ़ अध्ययन कर सके।
4. पी-एच. डी. के लिये छात्रों को 2 से 3 वर्ष का अनुसंधान कार्य करना आवश्यक हो। इस स्तर पर छात्रों का चयन ध्यानपूर्वक किया जाये। इन छात्रों के लिये एक दूसरी विश्व भाषा का अध्ययन

करना आवश्यक हो।

5. भारतीय विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थाओं में समाज विज्ञान के अध्ययन को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाये।
6. मानविकी के अध्ययन क्षेत्र में महत्वपूर्ण रचनाओं द्वारा इसके अध्ययन को शक्तिशाली बनाया जाये।

12. छात्र सेवायें

1. छात्रों को उचित मात्रा में स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार की केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के आधार पर छात्रों एवं शिक्षकों के लिये स्वास्थ्य सेवा का संगठन करे।
2. स्नातक स्तर पर 25% एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 50% छात्रों को छात्रावास की सुविधाएं प्राप्त हो।
3. छात्रावासों में न रहने वाले स्थानीय छात्रों में से कम से कम 25% के लिये सस्ते जलपान गृह सहित दिवस अध्ययन केन्द्रों की व्यावस्था की जाये।
4. छात्रों के लिये विविध प्रकार की सहगामी क्रियाओं के सजीव कार्यक्रम का विकास किया जाये।
5. छात्र कल्याण सेवाओं का प्रबन्ध करने के लिये पूर्णकालिक छात्र कल्याण डीन की नियुक्ति की जाये।

13. स्त्री शिक्षा

Women's Education

1. उच्च स्तर पर छात्राओं की संख्या का अनुपात जो छात्रों की संख्या की तुलना में इस समय 1:4 है, बढ़ाकर 1:3 कर दिया जाये।
2. उनके लिये छात्रवृतियां एवं सस्ते छात्रावास की सुविधाओं का विकास किया जाये।
3. स्नातक स्तर पर शिक्षा देने के लिये महिला कालेज स्थापित किये जाये, परन्तु स्नातकोत्तर स्तर पर उनके लिये अलग कालेज की स्थापना करना उचित नहीं है।
4. छात्राओं के लिये कला, मानविकी, विज्ञान एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों की व्यवस्था तथा गृहविज्ञान, नर्सिग शिक्षा तथा समाज कार्य पाठ्यक्रमों का और अधिक विकास किया जाये।

(4) शिक्षा की राष्ट्रीय नीति – 1967

National Policy of Education - 1967

शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली के विषय में जो विचार अंकित किये, उनको संसद के सदस्यों, विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों, राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और भारतीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों ने कुछ संशोधन के पश्चात स्वीकार किये। भारत सरकार ने संसद सदस्यों की शिक्षा समिति की स्थापना 5 अप्रैल सन् 1967 को की, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1967 को प्रस्तुत की। इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने शिक्षा की राष्ट्रीय नीति को सरकारी प्रस्ताव के रूप में 24 जुलाई सन् 1968 को जारी किया।[1]

स्वतन्त्र भारत की इस प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 17 कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है। इसके अर्न्तगत शिक्षा के सब महत्वपूर्ण पक्षोः सिद्धान्तों, स्तरों एवं संरचना को स्थान दिया गया है और शिक्षा के आधारभूत लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को भी निर्धारित किया गया है। इसके निहित 17 कार्यक्रम अधोलिखित है।[2]

1. परीक्षाओं में सुधार :
2. खेलकूद की व्यवस्था :
3. कार्य अनुभव एवं राष्ट्रीय सेवा :
4. शैक्षिक अवसरों में समानता की स्थापना :
5. साक्षरता एवं व्यस्क शिक्षा का प्रसार :
6. अल्पसंख्यकों की शिक्षा की व्यवस्था :
7. कृषि एवं उद्योगों के लिये शिक्षा का विकास :
8. विज्ञान एवं अनुसंधान की शिक्षा का समान स्तर :
9. अध्यापकों के वेतन शिक्षा एवं पदस्थिति में सुधार :

---

1. भारत : 1975, पृष्ठ – 55
2. हिन्दुस्तान ईयर बुक : 1969, पृष्ठ – 179

10. सस्ती पाठ्यपुस्तकों के स्तर एवं उत्पादन में सुधार :
11. त्रिभाषा सूत्र एवं प्रादेशिक भाषाओं का विकास :
12. प्रतिभाशाली छात्रों की खोज एवं उनकी प्रतिभा का अधिकतम विकास :
13. अल्पकालीन शिक्षा एवं पत्राचार पाठ्यक्रमों की विशाल पैमाने पर व्यवस्था :
14. 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिये निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था :
15. माध्यमिक स्तर पर तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार
16. उच्च शिक्षा के केन्द्रो की सुविधाओं में सुधार और स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसंधान एवं पाठ्यक्रमों में सुधार।
17. शिक्षा की संरचना - 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा एवं 3 वर्ष का प्रथम डिग्री कोर्स :

टिप्पणी - उपयुक्त कार्यक्रमों पर राष्ट्रीय आय का 6% धन व्यय करने का निश्चय किया गया।[1]

उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में इस समिति ने जो सुझाव प्रस्तुत किये है वे इस प्रकार है :-

1. विश्वविद्यालय स्तर पर किसी भाषा का अध्ययन अनिवार्य न हो, परन्तु वैकाल्पिक विषय के रूप में भाषाओं के अध्ययन की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो।
2. कालेज स्तर पर संस्कृत के अध्ययन को विस्तृत बनाया जाये।
3. विश्वविद्यालयों में विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को उद्योग एवं कृषि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विशेष रूप से विकसित किया जाये।
4. प्रथम स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम की अवधि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात 3 वर्ष की होनी चाहिये।
5. स्नातक स्तर पर छात्रों के प्रवेश की शैक्षणिकं योग्यता एवं नियमों को स्पष्ट किया जायेः कम शैक्षिणिक योग्यता वाले छात्रों को अपनी योग्यता में वृद्धि करने के लिये पुनः परीक्षा लेने की सुविधा हों।

---

1. भारत : 1975, पृष्ठ - 55

6. निर्धारित योग्यता रखने वाले छात्रों को जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक है, प्रवेश देने की व्यवस्था की जाये।

7. प्रातः या सांय कालेजों एंव पत्राचार द्वारा शिक्षा देने की सुविधाओं में उदारतापूर्वक वृद्धि हो जायें।

8. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिये चयन की विधि को और कठोर बना दिया जाये।

9. सहगामी क्रियाओं के कार्यक्रम को अधिक सजीव बनाया जांये।

10. पाठ्य पुस्तकों के स्तर मान को ऊँचा किया जाये। भारत सरकार श्रेष्ठ पुस्तकों की रचना, उत्पादन एवं उपलब्धि का उत्तरदायित्व ले।

11. परीक्षाओं में सुधार करने के लिये बाहृय परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाये।

12. परीक्षाओं को प्रमाणिक और विश्वसनीय बनाया जाये।

13. आन्तरिक मूल्यांकन की योजना लागू की जाये।

14. परीक्षाओं की समाप्ति और परीक्षा परिणामों की घोषणा के बीच की अवधि 8 सप्ताह से अधिक न हो।

15. प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने मानवीय एवं भौतिक साधनों का विकास कर उच्च अध्ययन केन्द्र का स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न करे।

16. कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में सस्तें जलपान गृह एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध की जाये।

17. दिवस अध्ययन केन्द्रों एवं छात्रावासों की व्यवस्था की जाये।

18. विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति के रूप में कर्ज देने का प्रबन्ध हो।

19. विश्वविद्यालय को तीन क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंन्त्रता होनी चाहियेः-

    अ. छात्रों का चयन

    ब. अध्यापकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति

    स. अध्ययन के लिये पाठयचर्या, शिक्षण पद्वति, तथा अनुसंधान के लिये समस्याओं का निर्धारण।

20. विश्वविद्यालयों की इस स्वतंन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिये केवल उन्ही शिक्षाशास्त्रियों एंव विद्वानों को, जिन्हें पर्याप्त भाषा में प्रशासन का अनुभव हो, उपकुलपति के पद पर नियुक्त किया जाये।

21. विश्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त साधनों की व्यवस्था हो।
22. अनेक विश्वविद्यालय अधिनियमों में संशोधन करना आवश्यक है, अतः शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में परामर्श करे।
23. उच्च शिक्षा स्तर पर प्रवेश के लिये छात्रों का चयन करते समय गॉव, शहर की गन्दी बस्ती एवं पिछड़ी जातियों के छात्रों के वातावरण में उपस्थित बाधाओं का भी ध्यान रखा जाये तथा उन्हें कुछ रियायतें दी जाये।

यह पूर्व अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि समिति के अनेक सुझावों को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त है परन्तु समिति की रिपोर्ट में शिक्षा आयोग के एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त की, जिसमे माध्यमिक एंव उच्च शिक्षा के प्रसार को मानव शक्ति की मॉग पर निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है, पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। यह शायद इसलिये हुआ है क्योंकि समिति शिक्षा शास्त्रियों, वैज्ञानिकों, शिक्षा प्रशासकों, एंव आयोजकों की समिति न होकर राजनीतिज्ञों की समिति थी।

(5) गजेन्द्र गडकर कमेटी – 1969–70

जून 1969 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वैधानिक संस्थाओं के आकार उनके कार्यो, उत्तरदायित्वों और शक्तियों, स्टाफ की सेवा दशाओं, विद्यार्थियों के योगदान और दूसरे भारत में विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक मामलों में सुझाव देने के लिये एक समिति का गठ्न किया। इस समिति का अध्यक्ष डॉ0 पी0 वी0 गजेन्द्र गडकर (भारत के पूर्व मुख्य–न्यायाधीश और बम्बई विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति) को नियुक्त किया गया इस समिति को गजेन्द्र गडकर कमेटी या 'Committee of the Governance of Universities' के नाम से जाना जाता है।

इस समिति ने सन् 1970 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें मूल्यावान तथ्य और सिफारिशें प्रस्तुत की।

इस समिति का सुझाव था कि –

" A Flexible Pattern of Organisation which is responsive to the changing needs of society as well as knowledge can be a powerful factor in accelerating progress"[1]

---

1. Report of the committee on the Governance of Universities P- 15

समिति ने 'विश्वविद्यालय स्वायत्ता' के विषय में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किये और स्पष्ट रूप से कहा कि विश्वविद्यालय अपने आप में एक स्वायत्व संस्था है न कि राज्य के नियंत्रण में एक संस्था समिति ने अनुभव किया कि स्वायत्ता एक वैधानिक अवधारणा नहीं है और न ही एक संवैधानिक अवधारणा है। फिर भी विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों की दृष्टि में समिति ने कहा कि विधान मन्डल के द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासन और जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये चाहे वह क्षेत्र शैक्षिक हो या गैर शैक्षिक। समिति ने अनुभव किया कि स्वायत्ता का अधिकार कोई विशेष अधिकार नहीं है लेकिन यह कर्तव्यों को सहीं ढंग से निर्वाह करने में सहायक है।

समिति ने अनुभव किया कि विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों के प्रभावपूर्ण योगदान के लिये यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय स्वायत्ता की अवधारणा को और वरिष्ठ सदस्यों के विशेषाधिकार को समाप्त किया जाना चाहिये।

समिति ने न केवल विश्वविद्यालय के शासन में विद्यार्थियों के योगदान का जोरदारी से समर्थन किया बल्कि उसने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय के संचालन की प्रणाली में विद्यार्थियों का आन्तरिक योगदान होना चाहिये। समिति ने आगे कहा कि पाठ्यक्रम के निर्धारण करने में और प्रशासन में भी विद्यार्थियों का योगदान होना चाहिये जिससे कि शैक्षणिक प्रणाली अर्थयुक्त बन सके। समिति ने कहा कि विश्वविद्यालय और राज्य के सम्बन्ध पूरी विश्वविद्यालय प्रणाली में अनुदान के लिये मुख्य रूप से निर्भर है इसलिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को राज्य सरकारों को यह सुझाव देना चाहिये कि राज्य सरकारें विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदान की मात्रा निश्चित कर दे।

समिति ने यह सुझाव दिया कि विवादों को टालने के लिये विश्वविद्यालय प्रणाली में उपयुक्त मशीनरी को शक्तिशाली बनाया जाये जिससे कि प्रणाली के सभी तीन अंग विद्यार्थी अध्यापक और प्रशासनिक स्टाफ की क्षति को कम किया जा सके। बहुत से विश्वविद्यालय अधिनियमों में परिर्वतन किया गया है और नये अधिनियम इस प्रकार की मशीनरी का प्रयोग करने के लिये निर्मित किये गये है।

इस प्रकार की प्रणाली क्षतिपूर्ति में प्रत्यक्ष रूप से सहायक सिद्ध होगी। इस प्रकार की प्रणाली अपनाने से निर्णय लेते समय प्रजातांन्त्रिक दृष्टिकोण का मजबूती मिलेगी और एक या दो

प्रशासकों के निर्णय को महत्व नहीं दिया जायेगा। अब यह आवश्यक है कि मशीनरी के कार्यो का पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाये ताकि जहाँ भी सुधार की आवश्यकता है वहाँ सुधार किया जा सके। समिति ने सिफारिश की है कि विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में हिंसात्मक घटनाओं को निपटाने में असफल होने की दशा में उपयुक्त मशीनरी होते हुये भी उपकुलपति को चाहिये कि वे स्थानीय प्रशासन से सहायता माँगे। समिति ने यह सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों के साथ मित्र, दार्शनिक, मार्ग दर्शक, के रूप में व्यवहार करें।

(6) 10+2+3 पर राष्ट्रीय समिति

National Committee on 10+2+3

भारत सरकार के शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय (Ministery of Education and Social Welfare) ने 20 अगस्त 1972 को अपने एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा 10+2+3 की शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति की। इस समिति ने अपनी प्रतिवेदन 'Report of the National Committee on 10+2+3 Educational Structure' के नाम से भारत सरकार को नवम्बर 1973 को प्रेषित किया इस समिति के चैयरमैन डॉ. पी. डी. शुक्ला थे।

इस समिति का कार्य क्षेत्र सब राज्यों तथा संघीय क्षेंत्रो में विद्यालय तथा कालेज कक्षाओं के लिये 10+2+3 की शिक्षा संरचना को लागू करने के लिये व्यवहारिक सुझाव देना, इस शिक्षा संरचना को लागू करने मे व्यय होने वाली धनराशि का अनुमान लगाना था अनुमानित व्यय के सम्बन्ध में सुझाव देना था।

समिति के द्वारा उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में ये सिफारिशें प्रस्तुत की गयीः-

1. यह संरचना विश्वविद्यालयों के लिये अधिक ज्ञान युक्त एवं परिपक्व छात्र प्रदान करेगी।
2. यह सरंचना विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा के केन्द्रों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की भीड़ में कमी करेगी।
3. विश्वविद्यालय की प्रथम डिग्री के लिये सामान्य शिक्षा के कोर्स को उन्नत तथा पुर्नसंगठित किया जाना चाहिये।
4. विश्वविद्यालयों में परम्परागत साहित्यक विषयों के साथ-साथ कुछ व्यावसायिक विषयों को भी

संचालित किया जाना चाहिये, ये विषय प्रचलित प्रोफेशनल कोर्सो के विषयों से भिन्न होने चाहिये।

वित्तीय व्यवस्था

Financial Implication - 1974-75 to 1978-79

समिति के अनुसार नवीन शैक्षिक संरचना को लागू करने पर निम्नलिखित धनराशि व्यय होने की सम्भावना है–

1. जिन राज्यों में सामान्य शिक्षा में 14 वर्ष में प्रथम उपाधि प्राप्त होती है वहाँ इस संरचना को लागू करने पर व्यय	32.5 करोड़ रूपये
2. जिन राज्यों में सामान्य शिक्षा में 15 वर्ष में प्रथम उपाधि प्राप्त होती है वहाँ इस नवीन संरचना को लागू करने पर व्यय	10.0 करोड़ रूपये
3. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण पर कुल व्यय	17.0 करोड़ रूपये
सम्पूर्ण कार्यक्रम पर कुल व्यय	59.5 करोड़ रूपये

विभिन्न आयोगों एवं समितियों के विचारों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने 10+2+3 की शैक्षिक संरचना को देश की वर्तमान परिस्थितियों के सर्वोतम माना है, अतः सरकार ने विद्यालय एवं विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिये इस नवीन संरचना की योजना को कार्यान्वित करने का निश्चय किया, सरकार और योजना के संचालकों के कार्य को सुगम बनाने के लिये राष्ट्रीय समिति ने व्यापक एवं सुदूर गामी सुझाव दिये हैं।

इस सम्बन्ध में हमारे समक्ष एवं स्वाभाविक प्रश्न यह उपस्थित होता है इस संरचना को देश की वर्तमान परिस्थितियों के लिये सर्वोतम क्यों माना गया है और इसमें शिक्षा की अवधि 15 वर्ष ही क्यों रखी गयी है।

उक्त प्रश्न से नवीन शैक्षिक संरचना के विषय में जो शंका उत्पन्न होती है, उसका

समाधान करने के लिये निम्नलिखित तर्क उपस्थित किये गये हैः-

1. विद्यालय शिक्षा की अवधि 10 वर्ष की हो जाने से शिक्षा के स्तर का उन्नयन होगा।

2. दो वर्ष के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण हो जाने से लगभग 50% छात्र ही विश्वविद्यालय शिक्षा के अभिलाषी रह जायेगें। परिणामतः विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों की भीड़ कम हो जायेगी अतः उनके प्रवेश के लिये चयनात्मक प्रणाली का प्रयोग करना सुविधाजनक हो जायेगा। इस प्रणाली का प्रयोग करने से केवल योग्य छात्र ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेगें। इससे विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा।

3. तीन वर्ष का प्रथम डिग्री कोर्स, वर्तमान दो वर्ष प्रथम डिग्री कोर्स से निश्चित रूप से उत्तम होगा। शिक्षा की अवधि में वृद्धि हो जाने से छात्रों को प्रायोगिक कार्य और विभिन्न विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त करने के अधिक उत्तम अवसर उपलब्ध होगें।

4. इस समय हमारे देश में विश्वविद्यालय की प्रथम डिग्री की शिक्षा की अवधि में भिन्नता है। नवीन शैक्षिक संरचना विविधता को समाप्त करके एकरूपता स्थापित करेगी। यह एकरूपता छात्रों के लिये हितकर होगी, क्योंकि उनको स्थान परिर्वतन के कारण शिक्षा की प्राप्ति में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा।

उपर्युक्त तर्को के आधार पर हम निसंकोच रूप से कह सकते है कि शिक्षा की नवीन संरचना भारत की वर्तमान परिस्थितियों के लिये सर्वोतम है। इसीलिये इसको अत्यन्त महत्वपूर्ण शैक्षिक सुधार बताते हुये प्रो0 एस0 नूरूल हसन ने इसके सम्बन्ध में यह मत प्रकट किया हैः-

" The new pattern of 10+2+3 for school and college classes in an educational reform of great significance, is vastly superior to the alternative patterns that now prevail, and its universal adoption in all parts of the country will bring in several advantages." [1]

1. S. Nural Hasan in 10+2+3 : A Major Change in School Education. P. 13

(7) नयी शिक्षा नीति - 1986

New Education Policy - 1986

श्री राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही राष्ट्र के नाम अपने संदेश में 5 जनवरी, 1985 को एक ऐसी शिक्षा नीति का वचन दिया जो कि राष्ट्र को 21 वीं सदी में प्रवेश के लिए वैज्ञानिक तथ्हा आर्थिक दृष्टि से तैयार करे ।

तत्कालीन शिक्षामंत्री श्री कृष्ण चन्द्रपंत ने प्रधानमंत्री को 20 अगस्त, 1985 को शिक्षा पर स्टेटस रिपोर्ट पेश की, जिसका शीर्षक था 'शिक्षा की चुनौती – नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य'। इस दस्तावेज की प्रतियाँ संसद में रखी गयीं तथा सभी राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित की गयी । यह परिपेक्ष्य 29-30 अगस्त, 1985 को हुये राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में विचार विमर्श का आधार भी बना। नयी शिक्षा नीति पर राष्ट्रव्यापी परिचर्चा के एक भाग के रूप में, भारत सरकार तथा उसकी एजेन्सियों द्वारा 12 राष्ट्रीय सेमिनार तथा 17 प्रायोजित सेमिनार आयोजित किये गये।

राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में नयी शिक्षा नीति तैयार करने से सम्बन्धित विभिन्न विषयों की गहराई से जाँच करने तथा उनके कार्यान्वयन के लिये नीतियां तैयार करने के लिये मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रियों के तीन राष्ट्रीय दल बनाये गये।

1. जनशक्ति प्रक्षेपण और व्यवसायीकरण
2. वित्तीय संसाधन
3. परीक्षा सुधार

23-24 जनवरी, 1986 को हुये राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मलेन के विचारार्थ, विभिन्न वर्गो के प्राप्त सुझावों पर आधारित नई शिक्षा नीति से सम्बन्धित विषय तैयार किये गये।

नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिये अप्रैल, 1986 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार (शिक्षा विभाग) द्वारा "राष्ट्रीय शिक्षा

नीति–1986. एक प्रस्तुति" नामक दस्तावेज पर विचार विमर्श हुआ । नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप पर राष्ट्रीय विकास परिषद तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किया गया। लोकसभा ने शिक्षा नीति के प्रारूप को तीन दिन की बहस के पश्चात 8 मई, 1986 को स्वीकृति दी, तत्पश्चात दो दिन की बहस के पश्चात राज्य सभा ने 13 मई 1986 को शिक्षा नीति के प्रारूप को स्वीकृति दी, इस प्रकार नई शिक्षा–नीति–1986 का निर्माण हुआ।

नई शिक्षा नीति में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किये गये। उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न सुझाव प्रस्तुत किये गयेः–

1. उच्च शिक्षा लोगों को आलोचनात्मक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और अध्यात्मिक समस्याओं, जिनका सामना मानव जाति को करना पड़ता है, का चिन्तन करने का मौका प्रदान करती है। इससे विशिष्ट ज्ञान और दक्षताओं के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के क्षेत्र में योगदान होता है। अतः यह जीवित रहने के लिये एक निर्णायक तत्व होगा। शैक्षणिक सूची स्तम्भ का शिरो–बिन्दु होने के नाते इसकी, शिक्षा प्रणाली के लिये आध्यापक तैयार करने में, एक प्रमुख भूमिका है।
2. ज्ञान के अद्बितीय खोज के संदर्भ में उच्च शिक्षा लगातार अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश कर रहीं है, उच्च शिक्षा को इतनी सक्रिय होना है जितनी सक्रिय पहले कभी न हुई थीं।
3. आज भारत में लगभग 150 विश्वविद्यालय और करीबन 5000 कालेज है। इन संस्थाओं में सुधार करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुये यह प्रस्ताव है कि निकट भविष्य में प्रमुख जोर मौजूदा संस्थाओं में सुविधाओं को संयोजित और उनका विस्तार करने पर दिया जाना चाहिये।
4. इस पद्बति को अवक्रमण से बचाने के लिये तत्काल कदम उठाये जायेगे।
5. सम्बद्धता पद्बति के साथ मिश्रित अनुभवों को ध्यान में रखते हुये काफी बड़ी संख्या में स्वायत्व कालेजों को विकसित करने में सहायता की जायेगी जब तक कि सम्बद्धता की प्रणाली को स्वतंन्त्र और विश्वविद्यालयों को और अधिक रचानात्मक संघ के साथ बदला नहीं जाता है। इसी तरह से चयनात्मक आधार पर विश्वविद्यालयों में स्वायत्त विभागों के सृजन को प्रोत्साहित किया जायेगा। स्वायत्तता और स्वंतन्त्रा को उत्तरदायित्व के साथ जोड़ा जायेगा।

6. विशिष्टीकरण की माँगों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिये पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को फिर से तैयार किया जायेगा। भाषाई क्षमता पर विशेष बल दिया जायेगा। पाठ्यक्रमों के मेल में अधिक लचीलापन होगा।

7. उच्च शिक्षा परिषदों के माध्यम से उच्च शिक्षा का राज्य स्तरीय आयोजन एवं समन्वय किया जायेगा। स्तरों पर निगरानी रखने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और ये परिषदें समन्वय पद्धतियां विकसित करेगी।

8. न्यूनतम सुविधाओं के लिये व्यवस्था की जायेगी और प्रवेश ग्रहण क्षमता के अनुसार दिया जायेगा। अध्यापन के तरीकों को बदलने की दिशा में भी मुख्य प्रयास किया जायेगा। श्रव्य दृश्य सामिग्री और इलैक्ट्रोनिक उपकरण तथा विज्ञान और प्रौद्यिगिकी का प्रयोग पाठ्यचर्या और सामिग्री अनुसंधान और शिक्षक उच्च प्रशिक्षण के विकास के कारगर बनाने के लिय शुरू किया जायेगा। तत्पश्चात सेवा और सतत शिक्षा के आरम्भ में इसके लिये शिक्षकों को तैयार करना आवश्यक होगा। शिक्षक के निष्पादन का मूल्यांकन सुव्यवस्थित ढंग से किया जायेगा। सभी पद पूर्ण रूप से योग्यता के आधार पर भरे जायेगे।

9. विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के लिये अधिक सहायता प्रदान की जायेगी और इसकी उच्च कोटि को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में कदम उठाये जायेगे। विश्वविद्यालयों में विशेषरूप से अन्य एजेन्सियों द्वारा किये गये अनुसंधान के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रबल क्षेत्रों में अनुसंधान को समन्वित करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी। विश्वविद्यालय प्रणाली के अर्न्तगत राष्ट्रीय अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जायेगें और स्वायत्त प्रबन्ध के समुचित प्रारूपों की व्यावस्था की जायेगी।

10. भारत विद्या, मानविकी विषयों और सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान को पर्याप्त सहायता मिलेगी। ज्ञान के संश्लेष की आवश्यकता की पूर्ति के लिये अन्तर्विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जायेगा। भारत के प्राचीन ज्ञान भंड़ार का खोजने और इसे समकालीन वास्वविकताओं से जोड़ने के प्रयास किये जायेगे। इस प्रयास से संस्कृत और अन्य श्रेष्ठ भाषाओं के गहन अध्ययन के लिये सुविधाओं का विकास होगा।

11. नीति के और अधिक समन्वय और सामंजस्य, सुविधाओं की साझेदारी और अन्तर्विषयक अनुसंधान के विकास के हित में सामान्य रूप से उच्चतर शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, तकनीकी, विधिक और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों को शामिल करते हुये एक राष्ट्रीय निकाय स्थापित किया जायेगा।

खुला विश्वविद्यालय और सुदूर अध्ययन

1. खुला विश्वविद्यालय प्रणाली शुरू की गयी है ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर अधिक मात्रा मे मिल सकें और शिक्षा को लोकतांन्त्रिक साधन बनाया जा सके।
2. इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये सन् 1985 में स्थापित इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय को अधिक सुदृढ़ किया जायेगा।
3. इस प्रबल साधन को ध्यानपूर्वक विकसित करके सावधानी से इसका विस्तार करना होगा।

डिग्रियों को नौकरियों से अलग करना

1. चुने हुये क्षेत्रों में डिग्रियों को नौकरियों से अलग करने के समबन्ध में कार्यवाही शुरू की जायेगी।
2. यह प्रस्ताव इंजीनियरिंग, औषधि, विधि, शिक्षण कार्य आदि जैसे व्यवसाय विशिष्ट पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में लागू नहीं किया जा सकता। इसी तरह मानविकी, सामाजिक विज्ञानों, विज्ञानों आदि में शैक्षिक योग्यता वाले विशेषज्ञों की सेवाएं नौकरी की विभिन्न स्थितियों में अपेक्षित बनी रहेगी।
3. उन सेवाओं में डिग्री को नजरअंदाज किया जायेगा जिनके लिये विश्वविद्यालय की डिग्री अपेक्षित योग्यता के रूप में आवश्यक नहीं है। इसके कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप विशिष्ट कार्य से सम्बन्धित पाठ्यक्रम पुनः तैयार हो सकेगें और उन उम्मीदवारों को और अधिक स्थान मिल सकेगा जो निर्धारित नौकरी के लिये योग्य होने के बावजूद भी, स्नातक उम्मीदवारों के लिये आवश्यकता अधिमान के कारण नौकरी प्राप्त करने में असमर्थ रहते है।
4. डिग्रियों को हटाने के लिये राष्ट्रीय परीक्षण सेवा जैसी उपयुक्त व्यवस्था, उपयुक्त चरणों में कायम की जायेगी, ताकि निर्धारित नौकरियों के लिये परीक्षायें शैक्षिक आधार पर आयोजित की जा सकें तथा विदेशों में बराबर की क्षमता के मानदन्ड़ों को प्राप्त करने के लिये मार्ग तैयार किया जा सके।

ग्रामीण विश्वविद्यालय

ग्रामीण विश्वविद्यालय की नई पद्धति को महात्मा गॉधी के शिक्षा सम्बन्धी क्रान्तिकारी विचारों के आधार पर समेकित तथा विकसित किया जायेगा ताकि मूल स्तरों पर सूक्ष्म आयोजना और ग्रामीण क्षेत्रों में परिर्वतन की चुनौतियों का सामना किया जा सके। गॉधी जी की बुनियादी शिक्षा की संस्थाओं और कार्यक्रम को समर्थन दिया जायेगा।

ब्रिटिश काल के बाद स्थापित विभिन्न विश्वविद्यालय, संस्थान एवं महाविद्यालय

15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंन्त्रा के पश्चात उत्तर प्रदेश में विभिन्न नये विश्वविद्यालय संस्थान एवं महाविद्यालय स्थापित किये गये। उनका वर्षवार विवरण इस प्रकार हैः-

सन् 1948 में स्थापित महाविद्यालय

1. टी.डी. कालेज, जौनपुर
2. एम.एम.एच. कालेज, गाज़ियाबाद
3. रघुनाथ गर्ल्स कालेज, मेरठ
4. डी.ए.वी. डिग्री कालेज, लखनऊ
5. के.जी.के. कालेज, मुरादाबाद
6. दयानन्द सुभाष नेशनल कालेज, उन्नाव

सन् 1949 में स्थापित विश्वविद्यालय

1. रूड़की विश्वविद्यालय, रूड़की

महाविद्यालय

1. बुन्देलखण्ड डिग्री कालेज, झॉसी
2. एस.डी. कालेज, मुज़फ्फर नगर
3. गवर्मेंट रजा कालेज, रामपुर
4. हिन्दू कालेज, मुरादाबाद
5. युवराज दत्ता कालेज, लखीमपुर खीरी

सन् 1950 में स्थापित महाविद्यालय एवं संस्थान

1. इन्स्टीट्यूट आफ ओरिएन्टल फिलॉसफी, ब्रिदांवन
2. डी. ए. वी. कालेज, मुजफ्फर नगर
3. मदन मोहन मालवीय यूनीवर्सिटी कालेज, इलाहाबाद
4. सी. पी. एम. डिग्री कालेज, इलाहाबाद

सन् 1951 में स्थापित महाविद्यालय

1. के. एस. साकेत पी. जी. कालेज, फैज़ाबाद
2. एच. सी. कालेज, वाराणसी
3. एस. एस. वी. कालेज, हापुड़
4. डी. एस. वी. कालेज, नैनीताल
5. डी. वी. कालेज, उरई
6. के. एन. गवर्मेन्ट कालेज, ज्ञानपुर वाराणसी

सन् 1952 में स्थापित महाविद्यालय

1. एन. ए. एस. कालेज, मेरठ
2. जी. एस. वी. एम. मेडिकल कालेज, कानपुर

सन् 1953 में स्थापित महाविद्यालय

1. नवयुग कन्या विद्यालय, लखनऊ
2. एस. एन. सेन बालिका विद्यालय डिग्री कालेज, कानपुर

सन् 1954 में स्थापित महाविद्यालय

1. बसन्त कन्या महाविद्यालय, वाराणसी
2. विध्यांत हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ
3. बी. आर. डी. डिग्री कालेज, देवरिया

सन् 1955 में स्थापित महाविद्यालय

1. एम. एल. के. पी. जी. कालेज, बलरामपुर, गोंडा
2. श्री एम. एम. टी. डी. कालेज, बलिया
3. जे. वी. जैन कालेज, सहारनपुर
4. के. वी. डिग्री कालेज, मक्षरा - 250106
5. जुबली गर्ल्स कालेज, लखनऊ
6. बुद्धा डिग्री कालेज, कुशीनगर, देवरिया
7. आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, बाँदा

सन् 1956 में स्थापित विश्वविद्यालय

1. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
2. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी.

महाविद्यालय

1. नारायण पी. जी. कालेज, शिकोहाबाद
2. डी. ए. वी. कालेज, बुलन्दशहर
3. किशन डिग्री कालेज, सिम्भौली
4. अवध गर्ल्स डिग्री कालेज, लखनऊ
5. इलाहाबाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद

सन् 1957 में स्थापित महाविद्यालय

1. ए. के. पी. जी. कालेज, शिकोहाबाद
2. के. आर. गर्ल्स कालेज, मथुरा
3. श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय, अलीगढ़
4. डी. ए. वी. कालेज, आज़मगढ़
5. हिन्दू डिग्री कालेज, जमिनिया, गाज़ीपुर
6. के. बी. डिग्री कालेज, मिर्ज़ापुर

7. पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, गाज़ीपुर

8. महाराज सिंह कालेज, सहारनपुर

9. मुलतानी मल मोदी कालेज, मोदीनगर, गाज़ियाबाद

10. बी. वी. कालेज, शामली

11. दयानन्द गर्ल्स कालेज, कानपुर

सन् 1958 में स्थापित महाविद्यालय

1. बाबू शिवनाथ अग्रवाल कालेज, मथुरा

2. गंजडुडंवारा कालेज, गंजडुंडवारा

3. पी. सी. बाग्ला पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, हाथरस

4. एस. डी. जे. कालेज, चन्देश्वर, आज़मगढ़

5. एस. एन कालेज, आज़मगढ़

6. आर्य महिला डिग्री कालेज, वाराणसी

7. महादेव कन्या पाठशाला (पी.जी.),देहरादून

8. देव नागरी कालेज, मेरठ

9. राजा महेन्द्र प्रताप प्रेम विद्यालय कालेज, नरसान

10. राष्ट्रीय किसान कालेज, शामली

11. आर. एस. एम. डिग्री कालेज, धामपुर, बिजनौर

12. डी. एन. डिग्री कालेज, फतेहगढ़

13. दयानन्द कालेज आफ लॉ, कानपुर

14. दयानन्द वीमेन्स ट्रेनिग कालेज, कानपुर

15. एच. बी. टेकनालोजीकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर

सन् 1959 में स्थापित संस्थान

1. इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, कानपुर

महाविद्यालय

1. विपिन बिहारी डिग्री कालेज, झाँसी
2. आर. आर. पी. जी. कालेज, अमेठी, सुल्तानपुर
3. सी. एल. जैन डिग्री कालेज, फिरोज़ाबाद
4. एस. आर. के. कालेज, फिरोज़ाबाद
5. आर. आर. के. डी. डिग्री कालेज, जौनपुर
6. आर्य कन्या पाठशाला डिग्री कालेज, हापुड़
7. चौधरी छोटूराम डिग्री कालेज, मुज़फ्फर नगर
8. गोचर एग्रीकलचर कालेज, रामपुर (मनी आरन)
9. जनता स्वरूप कालेज, सिकन्दराबाद
10. महामना मालवीय डिग्री कालेज, खेरा
11. खुनखुन जी कालेज, लखनऊ
12. सशि भूषण बालिका विद्यालय, लखनऊ
13. किसान डिग्री कालेज, बस्ती
14. डी. बी. वी. कालेज, कानपुर
15. हलीम मुस्लिम डिग्री कालेज, कानपुर
16. जनता कालेज, बकेवर, इटावा
17. कर्मक्षेत्र कालेज, इटावा
18. पी. पी. एन. कालेज, कानपुर

सन् 1960 में स्थापित विश्वविद्यालय

1. गोविन्द बल्लभ पन्त यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एडं टेक्नोलाजी पन्त नगर, नैनीताल

महाविद्यालय

1. अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, अतर्रा, बाँदा
2. बी. एन. वी. कालेज, राठ, हमीरपुर
3. किसान पी. जी. कालेज, बहराइच
4. मुनीश्वर दत्त पी. जी. कालेज, प्रतापगढ़
5. टी. एन. पी. जी. कालेज, टांडा, फैज़ाबाद
6. के. डी. वी. दुवाहार, बलिया
7. एस. जी. आर. आर. कालेज, देहरादून
8. बी. एस. एम. कालेज, रुड़की
9. दिगम्बर कालेज, दिवाई, बुलन्दशहर
10. के. एल. डी. ए. वी. कालेज, रूड़की
11. राजा शिक्षा शिविर डिग्री कालेज, पालीखावा
12. डी. ए. के. कालेज, मुरादाबाद
13. डी. एस. एम. डिग्री कालेज, कांथ, मुरादाबाद
14. के. एम. वी. भूर कालेज, बरेली
15. जे. एस. एच. कालेज, अमरोहा, मुरादाबाद
16. वर्धमान कालेज, बिजनौर
17. नेशनल डिग्री कालेज, बरहाल गंज, गोरखपुर
18. बद्री विशाल डिग्री कालेज, फर्रूखाबाद
19. फीरोज गांधी कालेज, रायबरेली
20. कुल भाष्कर आश्रम डिग्री कालेज, इलाहाबाद

सन् 1961 में स्थापित महाविद्यालय

1. नेशनल डिग्री कालेज, भौगाँव, मैनपुरी
2. श्री चित्रगुप्त डिग्री कालेज, मैनपुरी

3. बिरला पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, श्रीनगर, गढ़वाल
4. दयानन्द ब्रजेन्द्र स्वरूप पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, देहरादून
5. दयानन्द वीमेन्स ट्रेनिंग कालेज, देहरादून
6. ए. एस. डिग्री कालेज, मवाना
7. श्रावण नाथ मुथ जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज, हरिद्वार
8. श्री कुंड कुन्ड जैन डिग्री कालेज, खटौली
9. विधावती मुकुन्द लाल गर्ल्स डिग्री कालेज, गाज़ियाबाद
10. जी. बी. पन्त डिग्री कालेज, कचला, बदाँयू
11. संत विनोबा डिग्री कालेज, देवरिया
12. मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद
13. मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद
14. ब्रहमानन्द डिग्री कालेज, कानपुर
15. हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सीतापुर
16. महात्मा गाँधी डिग्री कालेज, फतेहपुर
17. आर. एम. पी. कालेज, सीतापुर

सन् 1962 में स्थापित विश्वविद्यालय

1. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

महाविद्यालय

1. आर्य कन्या डिग्री कालेज, झाँसी
2. पंडित जवाहर लाल नेहरू कालेज, बाँदा
3. इस्माइल नेशनल डिग्री कालेज फार वीमेन, मेरठ
4. शम्भू दयाल कालेज, गाज़ियाबाद
5. जी. एस. हिन्दू कालेज, चाँदपुर, बिजनौर
6. एम. एम. एम. इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर
7. टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, सीतापुर

सन् 1963 में स्थापित महाविद्यालय

1. के. ए. पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, कासगंज, एटा
2. म्युनिसपल पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, मंसूरी
3. जैन कन्या पाठशाला डिग्री कालेज, मुजफ्फर नगर
4. गर्वमेंट पी. जी. कालेज, पिथौरागढ़
5. नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ
6. मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज, भटपार-रानी, देवरिया
7. आचार्य नरेन्द्र देव महिला महापालिका महाविद्यालय, कानपुर
8. जे. डी. विद्या मन्दिर डिग्री कालेज, कानपुर
9. जुहारी देवी गर्ल्स डिग्री कालेज, कानपुर

सन् 1964 में स्थापित महाविद्यालय

1. जे. एल. एन. पी. जी. कालेज, बाराबंकी
2. पी. बी. डिग्री कालेज, प्रतापगढ़ सिटी
3. श्रीमती भगवती देवी जैन गर्ल्स कालेज, आगरा कैन्ट
4. जी. बी. पन्त डिग्री कालेज, प्रतापगंज, जौनपुर
5. एस. जी. आर. पी. जी. कालेज, दोभी, जौनपुर
6. एन. के. बी. एम. जी. कालेज, चन्दौसी, मुरादाबाद
7. उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत
8. शिवपति डिग्री कालेज, शोहरतगढ़, बस्ती
9. जनता महाविद्यालय, अजीतमल, इटावा

सन् 1965 में स्थापित विश्वविद्यालय

1. कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर
2. मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ

महाविद्यालय

1. राजा हरपाल सिंह डिग्री कालेज, सिंगरामऊ, जौनपुर
2. सकलदिहा डिग्री कालेज, वाराणसी
3. शिवा डिग्री कालेज, तेहारी कप्तान गंज, आज़मगढ़
4. श्री गाँधी डिग्री कालेज, मलतारी, आज़मगढ़
5. दुर्गा प्रसाद डिग्री कालेज, अनूप शहर
6. कन्या महाविद्यालय, सतीकुन्ड, कंरवाल
7. मुन्ना लाल गर्ल्स कालेज, सहारनपुर
8. एस. आर. एस. गर्ल्स डिग्री कालेज, बरेली
9. एस. एस. डिग्री कालेज, शाहजहाँपुर
10. साहू जैन कालेज, नजीवाबाद, बिजनौर
11. बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कालेज, बुद्ध नगर, नौगढ़, बस्ती
12. भगवान दीन आर्य कन्या डिग्री कालेज, लखीमपुर खीरी
13. केन सोसायटीज नेहरू डिग्री कालेज, हरदोई
14. गुरुनानक गर्ल्स डिग्री कालेज, कानपुर
15. नारायण आर्य कन्या पाठशाला, फर्रुखाबाद

सन् 1966 में स्थापित महाविद्यालय

1. लाल बहादुर शास्त्री पी. जी. कालेज, गोन्डा
2. एम. एम. एम. पी. जी. कालेज, कालाकंकर, प्रतापगढ़
3. जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज, एटा
4. अग्रसेन महिला महाविद्यालय, आज़मगढ़
5. डी. सी. एस. के. पी. जी. कालेज, मऊनाथ भंजन
6. एल. एल. आर. एम. मेडीकल कालेज, मेरठ
7. आर्य कन्या पाठशाला डिग्री कालेज, खुर्जा

8. देव नागरी कालेज, गुलोटी
9. लाला लाजपत राय मेमोरियल कालेज, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद
10. एस. डी. पी. पी. गर्ल्स कालेज, रुड़की
11. हीरालाल राम निवास डिग्री कालेज, खालिदाबाद, बस्ती
12. जवाहर लाल नेहरू स्मारक डिग्री कालेज, महाराजगंज, गोरखपुर
13. बेसवारा डिग्री कालेज, लाल गंज, रायबरेली
14. श्री नारायण गर्ल्स डिग्री कालेज, उन्नाव
15. गवर्मेन्ट पी. जी. कालेज, गोपेश्वर, चमोली

सन् 1967 में स्थापित संस्थान

1. सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ हायर तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी

महाविद्यालय

1. गणपत सहाय पी. जी. कालेज, सुल्तानपुर
2. बैकुन्ठी देवी कन्या महाविद्यालय, आगरा
3. एन. एम. एस. एन. दास कालेज, बदायूँ
4. महिला महाविद्यालय, बस्ती
5. तिलक डिग्री कालेज, औरेया, इटावा

सन् 1968 में स्थापित महाविद्यालय

1. नेहरू कालेज, ललितपुर
2. एस. बी. जे. डिग्री कालेज, विसाबार, मथुरा
3. कमला महेश्वरी आर्य कन्या डिग्री कालेज, मिर्ज़ापुर
4. मिहिर भोज डिग्री कालेज, दादरी
5. आर. पी. डिग्री कालेज, मीरगंज, बरेली
6. रतन सेन डिग्री कालेज, बन्सी, बस्ती
7. भवन्स मेहता कालेज, भर वारी, इलाहाबाद

8. केन ग्रोवर्स नेहरू डिग्री कालेज, गोला गोरखनाथ, लखीमपुर खीरी
9. नेहरू कालेज, छिबरामऊ, फर्रूखाबाद

सन् 1969 में स्थापित महाविद्यालय

1. एम. एल. बी. मेडिकल कालेज, झाँसी
2. बी. एन. के. बी. पी. जी. कालेज, अकबरपुर, फैज़ाबाद
3. भदावर विद्या मन्दिर डिग्री कालेज, बाह, आगरा
4. पालीवाल डिग्री कालेज, शिकोहाबाद
5. जी. डी. बिन्नानी डिग्री कालेज, मिर्ज़ापुर
6. एल. बी. एस. डिग्री कालेज, मुगलसरायं, वाराणसी
7. मरीयाहू डिग्री कालेज, जौनपुर
8. गर्वमेन्ट पी. जी. कालेज, उत्तरकाशी
9. कनोहर लाल महिला महाविद्यालय, मेरठ
10. कृषक कालेज, मवाना
11. एस. बी. डी. कालेज, धामपुर, बिजनौर
12. दिगविजयनाथ डिग्री कालेज, गोरखपुर
13. महात्मा गाँधी डिग्री कालेज, गोरखपुर
14. महिला महाविद्यालय, किदवई नगर, कानपुर
15. राम प्रसाद कालेज, कमाल गंज, फर्रूखाबाद
16. राम स्वरूप ग्रामोद्योग डिग्री कालेज, पुखरायाँ, कानपुर
17. गाँधी महाविद्यालय,उरई

सन् 1970 में स्थापित महाविद्यालय

1. बृजबिहारी डिग्री कालेज, कोसीकलाँ, मथुरा
2. डॉ. राम मनोहर लोहीया डिग्री कालेज, भैरव तालाब, वाराणसी
3. गाँधी शताब्दी स्मारक डिग्री कालेज, कोइलसा, आज़मगढ़

4. गाँधी स्मारक डिग्री कालेज, बरादाह, आज़मगढ़
5. जगतपुर डिग्री कालेज, जगतपुर, वाराणसी
6. नागरिक डिग्री कालेज, जमूहाई, जौनपुर
7. सहकारी डिग्री कालेज, मेहराबा, जौनपुर
8. डॉ. बी. जी. रेड्डी पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, पौढ़ी
9. स्वामी रामतीर्थ कालेज, टहरी
10. ईश्वर दयाल परसन्दी देवी डिग्री कालेज, बुलन्दशहर
11. बाबा राघवदास भगवान दास डिग्री कालेज, बरहाज, देवरिया
12. बापू डिग्री कालेज, पीपीगंज, गोरखपुर
13. दयानन्द डिग्री कालेज, गोरखपुर
14. आर्य कन्या डिग्री कालेज, हरदोई
15. ब्रहमावर्त डिग्री कालेज, मन्धना, कानपुर
16. लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कालेज, सिरसा, इलाहाबाद,
17. महिला सेवा सदन, इलाहाबाद

सन् 1971 में स्थापित महाविद्यालय

1. कालपी कालेज, कालपी, जालौन
2. बाबा बरूआदास पी. जी. कालेज, परूइआहराम, फैज़ाबाद
3. बजरंग डिग्री कालेज, कुन्डा, प्रतापगढ़
4. डिग्री कालेज, पाट्टिल, प्रतापगढ़
5. राणा प्रताप डिग्री कालेज, सुल्तानपुर
6. सेवा आश्रम डिग्री कालेज, घिघुई, प्रतापगढ़
7. बी. वी. रूरल इंस्टीटयूट, विचपुरी, आगरा
8. डी. डी. गर्ल्स डिग्री कालेज, फिरोज़ाबाद
9. आर. सी. ए. गर्ल्स डिग्री कालेज, मथुरा

10. बजरंग महाविद्यालय, दादर आश्रम, बलिया
11. बालादेव डिग्री कालेज, बारागावा, वाराणसी
12. कुवंर सिंह डिग्री कालेज, जौनपुर
13. सर्वोदय डिग्री कालेज, घोसी, आज़मगढ़
14. गवर्मेन्ट पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, कोटद्वार
15. जनता बेदिक कालेज, बड़ौत, मेरठ
16. एम. जी. एम. कालेज, सम्भल, मुरादाबाद
17. आर. बी. डी. कालेज, बिजनौर
18. कुतार डिग्री कालेज, चाक्के, जौनपुर
19. ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत
20. लक्ष्मी यदुनन्दन डिग्री कालेज, कायमगंज, फर्रूखाबाद
21. नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ ओप्थेलमोलोजी एन्ड रिचर्स, सीतापुर
22. प्रयाग महिला विद्यापीठ महाविद्यालय, इलाहाबाद
23. साहू राम नारायण मुरली मनोहर आयुर्वेदिक कालेज, बरेली
24. तक-मील-उत-तिब आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ
25. यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद
26. विद्या मन्दिर महाविद्यालय, कायम गंज, फर्रूखाबाद
27. नेशनल होम्योपेथिक कालेज, लखनऊ

सन् 1972 में स्थापित महाविद्यालय

1. अग्रसेन महाविद्यालय, मऊरानीपुर, झाँसी
2. गायत्री विद्यापीठ डिग्री कालेज, रिसिया, बहराइच
3. आर. एम. गर्ल्स डिग्री कालेज, फैज़ाबाद
4. वायालासी डिग्री कालेज, जलालपुर, जौनपुर
5. महन्थ राम शराय दाश डिग्री कालेज, भूरकुरा, गाज़ीपुर

6. महात्मा गाँधी सती स्मारक डिग्री कालेज, गरूवा, मकाशूदापुर, गाज़ीपुर

7. मर्यादा पुरूषोत्तम डिग्री कालेज, रतनपुरा, मऊ

8. मथुरा डिग्री कालेज, रसाना, बलिया

9. राजकीय डिग्री कालेज, जखिनी, वाराणसी

10. राष्ट्रीय डिग्री कालेज, जूमहाई, जौनपुर

11. सुदरिशथी बाबा डिग्री कालेज, सुदरिशथपुरी, बलिया

12. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, जहारीखाल, लेन्सडाउन, 246155

13. गवर्मेन्ट पी. जी. कालेज, ऋषिकेश

14. ए. एस. डिग्री कालेज, सिकन्दराबाद

15. मुम्ताज डिग्री कालेज, लखनऊ

16. बाबू राघवदास मेडीकल कालेज, गोरखपुर

17. अम्बिका प्रताप नारायण डिग्री कालेज, बस्ती

18. महाजन डिग्री कालेज, चौरी चौरा, गोरखपुर

19. राम जी सहाय डिग्री कालेज, रूद्रपुर, देवरिया

20. श्यामेश्वर महाविद्यालय, शिकारीगंज, गोरखपुर

21. भारतीय डिग्री कालेज, फर्रूखाबाद

22. बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कालेज, झाँसी

23. कालेज आफ नर्सिग, कानपुर

24. एच. एस. डिग्री कालेज़, कानपुर

25. इन्टरनेशनल सेन्टर आफ एजूकेशन, कानपुर

26. ऋषिकुल अयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार

27. विवेकानन्द ग्रामोद्योग डिग्री कालेज, दिवियापुर, इटावा

सन् 1973 में स्थापित विश्वविद्यालय

1. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल,

2. कुमांयूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

संस्थान

1. दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा

महाविद्यालय

1. मथुरा प्रसाद कालेज, कोंच, जालौन
2. ए. एन. डी. किसान पी. जी. कालेज, वभनान, गोंड़ा
3. एच. एन. बहुगुणा पी. जी. कालेज, लालगंज, प्रतापगढ़
4. के. एन. इंस्टीट्यूट आफ फिजीकल एन्ड सोशल साइन्स, सुल्तानपुर
5. महिला डिग्री कालेज, बहराइच
6. संत तुलसीदास डिग्री कालेज, कादीपुर, सुल्तापपुर
7. बी. डी. एम. म्यूनिपिसल गर्ल्स, कालेज, शिकोहाबाद
8. म्यूनिसिपल गर्ल्स कालेज, कासगंज, एटा
9. आर. डी. ए. गर्ल्स कालेज, हाथरस, अलीगढ़
10. अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, टाउन हाल, वाराणसी
11. डिग्री कालेज, दुबे छपरा, बलिया
12. डिग्री कालेज, मलिकपुरा, गाज़ीपुर
13. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, दुधी, सोनभद्र
14. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, चन्दौली, वाराणसी
15. कालिकाधाम डिग्री कालेज, सेवापुरी, वाराणसी
16. खरादिहा डिग्री कालेज, खरादिहा, गाज़ीपुर
17. कृष्ण गीता राष्ट्रीय डिग्री कालेज, लाल गंज, आज़मगढ़
18. महाराजा बलवन्त सिंह डिग्री कालेज, गोहानपुर, वाराणसी
19. सलतनत बहादुर डिग्री कालेज, बुद्धपुर, रामोला, मेरठ
20. जी. वी. एन. डिग्री कालेज, बादलापुरा, जौनपुर

21. जे. ए. वी. गर्ल्स कालेज, पाट्ला, मेरठ

22. जनता डिग्री कालेज, बड़ौत, मेरठ

23. गवर्मेन्ट पोस्ट ग्रजुएट कालेज, रानीखेत, अल्मोड़ा

24. आर. एच. गवर्मेन्ट पोस्ट ग्रजुएट कालेज, काशीपुर, नैनीताल

25. नेशनल डिग्री कालेज, लखनऊ

26. जी. एस. कालेज, सुरजान नगर, मुरादाबाद

27. एम. एच. डिग्री कालेज, मुरादाबाद

28. भट्वाली बाजार डिग्री कालेज, गोरखपुर

29. कृषक एम. वी. गौर डिग्री कालेज, बस्ती

30. लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज, अनन्द नगर, गोरखपुर

31. पवित्र डिग्री कालेज, मनीराम, गोरखपुर

32. हंडिया डिग्री कालेज, इलाहाबाद

33. के. एन. डिग्री कालेज, तेजगाँव, रायबरेली

34. पी. एस. मेमोरियल डिग्री कालेज, कन्नौज, फर्रूखाबाद

35. सदानन्द डिग्री कालेज, छिवलहा, फतेहपुर

सन् 1974 में स्थापित विश्वविद्यालय

1. नरेन्द्र देव यूनीवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एन्ड टैक्नोलॉजी, फैज़ाबाद

2. चन्द्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एन्ड टैक्नालॉजी,कानपुर

3. काशी विद्यापीठ, वाराणसी

महाविद्यालय

1. गवर्मेन्ट पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, अगस्तमुनि, चमोली

2. गवर्मेन्ट पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, बागेश्वर, अल्मोड़ा

3. गवर्मेन्ट पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, रूद्रपुर, नैनीताल

4. कृष्णा देवी डिग्री कालेज, लखनऊ

5. श्री बी. एम. महाविद्यालय, पावा नगर, देवरिया

6. स्वामी कल्याण देव आयुर्वेदिक कालेज, बघारा, मुज़फ्फनगर

सन् 1975 में स्थापित विश्वविद्यालय

1. अवध विश्वविद्यालय, फैज़ाबाद

2. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

3. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

महाविद्यालय

1. गवर्मेन्ट कालेज, हमीरपुर

2. आर्य कन्या डिग्री कालेज, अल्मोड़ा

3. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, बेरीनाग, पिथौरागढ़

4. गवर्मेन्ट पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, रामनगर, नैनीताल

5. आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद

6. हमीदिया गर्ल्स डिग्री कालेज, इलाहाबाद

7. जगत तरन गर्ल्स डिग्री कालेज, इलाहाबाद

8. राजऋषि टंडन महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद

9. संवल दास एस. लाल खन्ना गर्ल्स डिग्री कालेज, इलाहाबाद

सन् 1976 में स्थापित महाविद्यालय

1. के. एन. इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलॉजी, सुल्तानपुर

2. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, बिसालपुर, पीलीभीत

3. गवर्मेन्ट गर्ल्स डिग्री कालेज, रामपुर

4. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, महमूदाबाद, सीतापुर

5. सर्वोदय महाविद्यालय, सोलन, रायबरेली

सन् 1977 में स्थापित महाविद्यालय

1. गन्ना कृषक डिग्री कालेज, ताखाशानगंज, जौनपुर

2. ईश्वर शरण डिग्री कालेज, इलाहाबाद

3. राजकीय महिला डिग्री कालेज, गाज़ीपुर

सन् 1978 में स्थापित महाविद्यालय

1. गवर्मेन्ट कालेज, चरखारी, हमीरपुर

2. गवर्मेन्ट गर्ल्स कालेज, बांदा

3. देवेन्द्र डिग्री कालेज, बेलथरा रोड, बलिया

4. जी. एस. डिग्री कालेज, समोधपुर, जौनपुर

5. राजकीय डिग्री कालेज, चौकिया, वाराणसी

6. समता डिग्री कालेज, सादात, गाज़ीपुर

7. जी. यू. डिग्री कालेज, बहेरी, बरेली

8. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, ऊंचाहार, रायबरेली

सन् 1979 में स्थापित महाविद्यालय

1. सेवरा डिग्री कालेज, सेवरा, फैज़ाबाद

2. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, मुहम्मदाबाद, गोहना, मऊ नाथ

3. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, धानापुर, वाराणसी

4. गुलाब देवी गर्ल्स डिग्री कालेज, बलिया

5. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, वेदीखाल, पौढ़ी गढ़वाल

6. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, चम्पा, टहरी गढ़वाल

7. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, चौबट्टाखाल, पौढ़ी गढ़वाल

8. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, कर्णप्रयाग, चमोली

9. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, लोहाघाट, पिथौरागढ़

10. अर्मापुर डिग्री कालेज, अर्मापुर, कानपुर

11. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, हरदोई

12. गवर्मेन्ट गर्ल्स डिग्री कालेज, कंधाला, मुज़फ्फनगर

सन् 1980 में स्थापित महाविद्यालय

1. गाँधी महाविद्यालय, सिद्धौली, सीतापुर

सन् 1981 में स्थापित महाविद्यालय

1. जालौन गवर्मेन्ट कालेज, जालौन
2. ललितपुर गवर्मेन्ट कालेज, ललितपुर
3. इन्दिरा गाँधी डिग्री कालेज, गौरीगंज, सुल्तानपुर
4. रामनगर डिग्री कालेज, रामनगर, बारावंकी
5. बृज किशोर होम्योपैथिक मेडीकल कालेज, फैज़ाबाद
6. गाजीपुर होम्योपैथिक मेडीकल कालेज, गाज़ीपुर
7. होम्योपैथिक मेडीकल कालेज, तिगरी (नगीना) बिजनौर
8. के. जी. के. होम्योपैथिक मेडीकल कालेज, मुरादाबाद
9. आर. सी. महिला डिग्री कालेज, मैनपुरी
10. लाल बहादुर होम्योपैथिक मेडीकल कालेज, इलाहाबाद
11. मोहन होम्योपैथिक मेडीकल कालेज, लखनऊ
12. श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडीकल कालेज, चन्द्रेश्वर, आज़मगढ़
13. स्टेट कानपुर होम्योपैथिक मेडीकल कालेज, जौनपुर
14. टी. डी. होम्योपैथिक मेडीकल कालेज, कानपुर
15. एस. एस. एस. एस. डिग्री कालेज, रसाना, मेरठ
16. सेन्ट जोसेफ गर्ल्स डिग्री कालेज, सरधना, मेरठ
17. दयानन्द बछरॉया डिग्री कालेज, बछरॉया, रायबरेली
18. श्री लाल बहादुर शास्त्री आयुर्वेदिक कालेज, हन्डिया, इलाहाबाद

सन् 1982 में स्थापित महाविद्यालय

1. महंती परननाथ कालेज, मऊ, बाँदा
2. संजय गांधी डिग्री कालेज, चौकिया, सुल्तानपुर

3. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, ओबरा, सोनभद्र

4. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, नोएडा, गाज़ियाबाद

5. संजय गांधी मेमोरियल जनता डिग्री कालेज, सरोआरपुर खुर्द, मेरठ

6. मोतीराम बाबूराम गवर्मेन्ट पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, हल्द्वानी, नैनीताल

सन् 1983 में स्थापित संस्थान

1. संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइन्सेज, लखनऊ

महाविद्यालय

1. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, जलेसर, एटा

2. गिन्नी देवी मोदी गर्ल्स डिग्री कालेज, मोदीनगर, गाज़ियाबाद

3. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, देवबन्द, सहारनपुर

4. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, नारायण नगर, दिघीहाट, पिथौरागढ़

5. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, द्वारहाट, अल्मोड़ा

6. गिन्दो देवी महिला महाविद्यालय, बदायूँ

7. चौधरी चरण सिंह डिग्री कालेज, हेवरा, इटावा

सन् 1984 में स्थापित संस्थान

1. इन्डियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट, लखनऊ

महाविद्यालय

1. इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एन्ड टैक्नोलॉजी, लखनऊ

2. आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहजहाँपुर

3. विद्या मन्दिर डिग्री कालेज, कानपुर

सन् 1985 में स्थापित महाविद्यालय

1. लोक राष्ट्रीय डिग्री कालेज, जसराना

2. पंचायत राज महिला महाविद्यालय, इटावा

सन् 1986 में स्थापित महाविद्यालय

1. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर
2. महात्मा गाँधी बालिका विद्यालय डिग्री कालेज, फिरोज़ाबाद
3. ठाकुर बीरी सिंह डिग्री कालेज, टूंडला, आगरा

सन् 1987 में स्थापित विश्वविद्यालय

1. पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

महाविद्यालय

निरंक

सन् 1988 में स्थापित महाविद्यालय

1. ग्रामोदय आश्रम डिग्री कालेज, साया, फैज़ाबाद
2. राजकीय डिग्री कालेज, सैदपुर, गाज़ीपुर
3. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, खटीमा, नैनीताल
4. श्रीमती इन्द्रिरा गांधी डिग्री कालेज, बांगरमऊ, उन्नाव
5. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, कर्वी, बाँदा

सन् 1989 में स्थापित विश्वविद्यालय

1. डॉ. भीमराम अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

सन् 1989 में प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्तरीय शोध तथा शिक्षा एवं प्रोघोगिकी के बीच समन्वय स्थापित करके ज्ञान विज्ञान की परिधि में नये आयाम जोड़ते हुये शिक्षा के स्वरूप को विकसित करने के उददे्श्य से भारतीय संविधान के निर्माता महान समाज सुधारक एवं विचारक डॉ. भीमराव अम्बेडकर की पुण्य स्मृति में डॉ. भीमराम अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस विश्वविद्यालय का स्वरूप ऐकिक आवासीय रखा गया।

महाविद्यालय

1. गवर्मेन्ट डिग्री कालेज, मैलानी, अल्मोड़ा

सन् 1990 में स्थापित महाविद्यालय

1. गवर्मेन्ट गर्ल्स कालेज, फतेहपुर

नोट- सभी विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों का विस्तृत विवरण, सभी महाविद्यालयों के सम्बद्धता का विवरण विश्वविद्यालय सम्बन्धी परिशिष्ट -3 में दर्शाया गया है ।

TABLE NO. 5.1

District Wise Number of Students and Teachers in Degree Colleges in Uttar Pradesh upto 30.9.1980

Sl. No,	Name of District	Name of the University to which college is affiliated	No. of Colleges	No. of Students	No. of Teachers
1	2	3	4	5	6
1	Faizabad	Avadh University	6	7976	265
2	Bahraich	- do -	3	2055	60
3	Gonda	- do -	3	3081	138
4	Pratapgarh	- do -	7	3880	138
5	Sultanpur	-do-	5	3961	125
6	Gorakhpur	Gorakhpur university	13	11787	323
7	Azamgarh	-do-	14	10611	363
8	Basti	-do-	8	7290	225
9	Deoria	-do-	11	11661	409
10	Varanasi	B.H.U.& Gorakhpur uni.	19	16212	597
11	Ballia	Gorakhpur university	10	7389	348
12	Ghazipur	-do-	9	3919	167
13	Jaunpur	-do-	14	11141	404
14	Mirzapur	-do-	4	2392	121
15	Allahabad	Allahabad & Kanpur uni.	16	16287	470
		Total (EASTERN)	143	119651	4153
1	Dehradun	Gurhwal university	7	8469	350
2	Uttar Kashi	-do-	1	369	33
3	Tehri Garhwal	-do-	1	676	35

1	2	3	4	5	6
4	Pauri Garhwal	-do-	4	2454	150
5	Chamoli	Kumaon university	3	1231	51
6	Pithouragarh	-do-	3	2298	97
7	Almorah	-do-	4	2761	108
8	Nainital	-do-	4	4753	151
		Total (HILL)	27	23011	975
1	Jhansi	Bundelkhand university	4	6835	132
2	Lalitpur	-do-	2	562	20
3	Hamirpur	-do-	3	1234	45
4	Jalaun	-do-	5	3775	128
5	Banda	-do-	3	3786	118
		Total (Bundelkhand)	17	16192	443
1	Agra	Agra university	13	19098	790
2	Aligarh	-do-	6	17980	380
3	Etah	-do-	5	3486	152
4	Manpuri	-do-	6	4767	187
5	Mathura	-do-	7	5493	227
6	Bareilli	Rohilkhand University	5	6858	252
7	Bijnaur	-do-	6	4314	268
8	Bandaun	-do-	2	1586	44
9	Moradabad	-do-	11	11999	435
10	Pilli Bhit	-do-	2	1106	25
11	Rampur	-do-	2	1842	107
12	Shahjahanpur	-do-	2	1699	75

1	2	3	4	5	6
13	Meerut	Meerut university	16	21913	820
14	Bulandsahar	-do-	10	6753	282
15	Muzzafar nagar	-do-	8	7543	277
16	Saharanpur	-do-	10	8286	264
17	Etawah	kanpur university	5	4187	202
18	Farrukhabad	-do-	9	4405	150
19	Ghaziabad	Meerut university	11	12938	482
		Total	136	146253	5419
1	Lucknow	Lucknow university	19	21768	688
2	Hardoi	Kanpur university	3	3060	63
3	Lakhimpur Kheri	-do-	3	2936	86
4	Raibarelli	-do-	5	3353	142
5	Sitapur	-do-	5	2569	77
6	Unnao	Kanpur university	2	2356	76
7	Barabanki	Avadh university	1	1498	21
8	Fatehpur	Kanpur Universty	2	1389	29
9	Kanpur	Kanpur university	21	28500	1118
		Total	61	67429	2300
	Total, UTTAR PRADESH		387	372536	13290

Source – Shiksha Ki Pragati, 1981-82, Directorate of Education, Uttar Pradesh, Allahabad.

TABLE – 5-2

DISTRICT WISE NO. OF STUDENTS & TEACHERS & DEGREE COLLEGES IN U.P. UP TO 31ST MARCH 1988

S.N.	Name of District	Name of university to which college is affiliated.	No. of colleges	No. of Students	No. of Teachers
1	Lucknow	Lucknow university	19	28128	715
2	Sitapur	Kanpur university	5	2426	74
3	Kheri	Kanpur university	3	3853	85
4	Hardoi	Kanpur university	3	4452	59
5	Unnao	Kanpur university	2	4749	89
6	Raibareli	Kanpur university	6	3753	136
	Total LUCKNOW REGION		38	47361	1158
7	Pratapgarh	Avadh university	7	4266	140
8	Sultanpur	Avadh university	8	6490	181
9	Faizabad	Avadh university	6	9693	237
10	Barabanki	Avadh university	2	1628	29
11	Bahraich	Avadh university	3	2107	64
12	Gonda	Avadh university	3	4233	150
	Total FAIZABAD REGION		29	28417	801
13	Basti	Gorakhpur university	06	6269	166
14	Gorakhpur	Gorakhpur university	15	9434	375
15	Deoria	Gorakhpur university	11	11110	374
16	Azamgarh	Gorakhpur university	14	10097	409
	Total GORAKHPUR REGION		46	36910	1324
17	Ballia	Purvanchal university	11	8520	292

1	2	3	4	5	6
18	Ghazipur	-do-	09	8550	214
19	Jaunpur	-do-	14	10994	445
20	Varanasi	Kashi Hindu &			
		Purvanchal university	19	18319	616
21	Mirzapur	Purvanchal university	5	3847	107
	Tatal BARANASI REGION		58	50230	1674
22	Bijnore	Rohelkhand university	6	5123	190
23	Moradabad	Rohelkhand university	11	12549	415
24	Rampur	Rohelkhand university	2	1418	106
	Total MORADABAD REGION		19	19090	711
25	Allahabad	Allahabad & Kanpur University	16	21124	580
26	Fatehpur	Kanpur university	02	2179	27
27	Kanpur				
28	Kanpur Dehat	Kanpur university	22	39559	1144
29	Farrukhabad	Kanpur university	9	6569	186
30	Etawah	Kanpur university	7	6661	236
	Total	ALLAHABAD REGION	56	76092	2173
31	Jalaun	Bundelkhand university	5	7360	140
32	Hamirpur	Bundelkhand university	4	1881	81
33	Banda	Bundelkhand university	4	4754	150
34	Lalitpur	Bundelkhand university	2	659	20
35	Jhansi	Bundelkhand university	4	12326	139
	Total	JHANSI REGION	19	26980	530
36	Agra	Agra university	11	20804	702

1	2	3	4	5	6
37	Mainpuri	-do-	08	6276	185
38	Etah	-do-	05	4840	136
39	Mathura	-do-	07	6224	223
40	Aligarh	-do-	06	12514	389
	Total	AGRA REGION	37	50658	1635
41	Bulandsahar	Meerut university	10	7331	274
42	Ghaziabad	-do-	13	14094	503
43	Meerut	-do-	17	20172	770
44	Muzaffarnagar	-do-	08	8225	317
45	Saharanpur	-do-	11	10571	322
	Total	MEERUT REGION	59	60393	2186
46	Bandaun	Rohilkhand university	03	1662	053
47	Shahjahanpur	-do-	03	2484	089
48	Bareilli	-do-	05	8600	255
49	Pilibhit	-do-	02	0901	033
	Total	BAREILLI REGION	13	13647	430
50	Nainital	Kumaon university	04	3142	132
51	Almorah	-do-	05	0790	060
52	Pithoragarh	-do-	04	1659	112
	Total	KUMAON RRGION	13	5591	304
53	Pauri Garhwal	Garhwal university	04	1381	080
54	Tehri Garhwal	-do-	01	58	6
55	Uttar Kashi	-do-	o1	759	49
56	Chamoli	-do-	03	1324	97

57	Dehradun	-do-	07	11793	398
	Total	PAURI REGION	16	15315	630
	GRAND TOTAL	UTTAR PRADESH	403	430684	13556

Souce: Shiksha Ki Pragati, 1988-89, Directorate of Education, Uttar Pradesh, Allahabad.

TABLE – 5.3

EXAMINATION RESULTS – 1980 (ANNUAL & SUPPLEMENTARY) OF THE UNIVERSITIES (GRADUATE AND POST GRADUATES).

Examination	University/Institution	Number Appeared	Number Passed	Division I	Division II
1	2	3	4	5	6
B.A.	Agra	13658	10676	221	4884
	Allahabad	5433	4641	324	2763
	Avadh	11,705	4822	Break – up not avilable	
	Banaras Hindu	4538	2818	174	1201
	Bundelkhand	8763	6890	Break – up not Availlable	
	Garhwal	3516	2987	85	1126
	Gorakhpur	22530	18930	280	9668
	Kanpur	24193	16218	162	5537
	Kashi Vidyapith	2257	1032	6	588
	Kumaon	4360	2905	63	1648
	Lucknow	5436	3939	172	1482
	Meerut	15054	8528	Break up not available	
	Rohilkhand	16109	11226	152	5227
	Gurukul Kangri	20	19	-	14
	Total	137572	95631	1639	34138

1	2	3	4	5	6	7
B.A. (Hons,)	Aligarh Muslim	821	633	47	344	242
	Banaras Hindu	75	58	27	31	-
	Lucknow	16	12	2	9	1
	Total	912	703	76	384	243
B.A. (Household)						
Arts	Agra	62	53	16	41	-
B. Theology	Aligarh Muslim	4	4	4	-	-
M.A.	Agra	6044	5223	265	2219	2739
	Aligarh Muslim	472	351	80	224	47
	Allahabad	1439	1256	174	690	392
	Avadh	3436	1474	Break up no available		
	Budelkhand	1878	1665	Break up no available		
	Banaras Hindu	1507	1098	191	659	248
	Garhwal	1283	1137	50	404	683
	Gorakhpur	4576	4287	163	1561	1563
	Kanpur	7010	5904	124	1462	4318
	Kashi Vidyapith	1263	1134	41	526	567
	Kumaon	1445	1253	56	536	641
	Lucknow	1229	994	107	523	364
	Meerut	8447	5601	Break up no available		
	Rohilkhand	5589	4144	180	1757	2207
	Gurukul Kangri	38	38	12	25	1

	Total	45856	35559	1443	10586	14790`
M.A. (Household Arts)	Agra	24	24	5	19	-
M Stat.	Agra.	8	6	5	1	-
M. Theology	Aligarh Muslim	2	2	1	1	-
Alankar	Gurukul kangri	14	14	10	4	-
Shastri	Banaras Hindu	11	9	5	4	-
	Lucknow	8	7	5	2	-
	Sampurnanand Sanskrit	2062	1983	52	1848	83
	Total	2081	1999	62	1854	83
Acharya	Banaras Hindu	37	20	10	9	1
	Lucknow	5	3	-	2	1
	Sampurnanand Sanskrit	962	982	471	511	-
	Total	1034	1005	481	522	2
B.Sc.	Agra	2075	1578	261	1026	291
	Allahabad	947	576	102	280	194
	Avadh	861	169	Break up not available		
	Banaras Hindu	645	391	76	208	107
	Bundelkhand	661	459	Break up not available		
	Garhwal	912	602	95	452	55
	Gorakhpur	2590	1966	223	1446	275
	Kanpur	3024	2341	298	1782	261
	Kumaon	410	269	39	177	53

	Lucknow	1643	1188	191	536	461
	Meerut	3045	1937	Break up not available		
	Rohilkhand	1849	1064	165	743	156
	Gurukul Kangri	37	37	6	27	4
	Total	18699	12577	1456	6677	1857
B.Sc.(Hons.)	Aligarh Muslim	521	343	122	175	46
	Banaras Hindu	155	122	60	62	-
	Lucknow	32	26	20	6	-
	Total	708	491	202	243	46
B.Sc. (Home science)	Agra	56	46	12	34	-
	Allahabad	17	17	3	13	1
	G.B. Pant University	56	56	41	15	-
	Total	129	119	56	62	1
M.Sc.	Agra	465	411	196	191	24
	Aligarh Muslim	335	244	169	70	5
	Allahabad	252	230	115	106	9
	Avadh	62	33	Break up not available		
	Banaras Hindu	438	332	191	131	10
	Bundelkhand	80	61	Break up not available		
	Garhwal	362	340	123	175	42
	G.B. Pant University	17	17	14	3	-
	Gorakhpur	640	555	156	364	35

	Kanpur	750	653	101	450	102
	Kumoan	181	170	47	113	10
	Lucknow	289	246	127	100	19
	Meerut	56	247	Break	up not	available
	Rohilkhand	333	252	163	88	1
	Roorkee	57	56	Grade	System	
	Gurukul Kangri	3	3	3	-	-
	Total	4820	3850	1405	1791	257
M.Sc. (Home science)	Agra	27	25	18	7	-
	G. B. Pant University	7	7	7	-	-
	Total	34	32	25	7	-
B.Com.	Agra	2337	1962	63	1312	587
	Allahabad	1228	898	48	519	331
	Avadh	322	55	Break	up not	available
	Banaras Hindu	1002	497	42	253	202
	Bundelkhand	596	436	Break	up not	available
	Garhwal	731	516	32	263	231
	Gorakhpur	1374	1138	16	580	481
	Kanpur	1881	1412	28	584	800
	Kumaon	338	298	8	162	128
	Lucknow	1628	1273	101	635	537
	Meerut	5380	3472	Break	up not	available
	Rohilkhand	1608	1320	64	999	257

	Total	18425	13277	402	5307	354
B.Com. (Hons.)	Aligarh Muslim	184	149	19	87	43
M.Com.	Agra	743	579	89	305	185
	Aligarh Muslim	81	59	30	28	1
	Allahabad	234	210	34	127	49
	Avadh	36	3	Break	up not	available
	Banaras Hindu	106	73	18	41	14
	Garhwal	184	164	8	92	64
	Gorakhpur	206	191	8	78	105
	Kanpur	229	197	14	73	110
	Kumaon	60	54	7	23	24
	Lucknow	228	188	43	89	54
	Meerut	525	414	Break	up not	available
	Rohilkhand	470	364	141	170	53
	Total	3111	2496	392	1026	661
M.B.A.	Aligarh Muslim	31	30	12	17	1
	Allahabad	29	29	17	12	-
	Lucknow	43	43	Break	up not	available
	Total	103	102	29	29	1
M.B.M.	Lucknow	55	55	Break	up not	available
	Banaras Hindu	126	106	46	5	-
	Total	181	161	46	5	-
M.B.S.	Allahabad	6	4	3	1	-
B.Ed./B.T.	Agra	1398	1317	16	492	809

		129	101	43	39	19
	Aligarh Muslim	1346	1013	Break	up not	available
	Avadh	378	375	55	298	22
	Banaras Hindu	861	710	Break	up not	available
	Bundelkhand	762	730	1	306	423
	Garhwal	3532	3520	547	2699	2074
	Gorakhpur	3194	2851	506	581	2264
	Kanpur	378	350	-	163	187
	Kumaon	488	459	08	295	156
	Lucknow	739	396	Break	up not	available
	Meerut	1253	1122	23	726	373
	Rohilkhand	717	708	Break	up not	available
	Sampurnanad Sanskirt	15175	13652	699	5599	4527
	Total	75	66	12	54	-
M.Ed.	Agra	21	18	7	11	-
	Aligarh Muslim	24	24	1	22	1
	Allahabad	38	29	Break	up not	available
	Avadh	30	25	16	8	1
	Banaras Hindu	29	26	6	13	7
	Garhwal	42	34	4	21	9
	Gorakhpur	187	155	29	121	5
	Kanpur	19	17	-	17	-
	Kumaon	26	21	4	17	-
	Lucknow	64	38	Break	up not	available
	Meerut	34	18	4	10	4
	Rohilkhand					

	Sampurnanand Sanskrit	22	21	4	17	-
	Total	601	492	87	311	27
B.E./B.Sc. Engineering	Agra	47	41	34	7	-
	Aligarh Muslim	296	152	138	16	-
	Allahabad	211	194	150	44	-
	Gorakhpur	182	181	Break up not available		
	Kanpur	95	94	75	19	-
	Roorkee	258	252	Break up not available		
	Total	1089	914	397	84	-
B.E./B.Sc. (Metallurgy)	Banaras Hindu	31	31	25	6	-
	Roorkee	13	10	Break up not available		
	Total	44	41	25	6	-
B.E. (Mining)	Banaras Hindu	14	14	10	4	-
B.Arch	Roorkee	22	22	Break up not available		
B.E. Computer science	Allahabad	11	9	9	-	-
M.E./M.Sc. (Engg.)	Aligarh Muslim	21	16	9	7	--
	Allahabad	25	25	10	14	1
	Roorkee	137	137	Break up not available		

	Total	183	178	19	21	1
B.Tech/	Allahabad	17	16	16	-	-
B.Sc. (Tech.)/	Banaras Hindu	182	155	50	66	39
B.E. Tech.	G.B. Pant University	132	132	187	5	-
	Kanpur	64	64	55	9	-
	Total	395	367	248	80	39
B. Tech./ B.Sc./						
B. Tech. (Chem.)	Banaras Hindu	11	10	6	1	3
B.Tech. /B.E.	Allahabad	33	33	17	16	-
B.Sc. (Ag. Engg)	G. B. Pant University		Data	is	not	available
B.Tech. (Food Science)	G.B. Pant University	3	3	3	-	-
B. Tech. (Matallurgy)	Banaras Hindu	18	18	8	4	6
M. Tech.	Allahabad	9	9	7	2	-
M.Sc. Tech/ M.E.	Banaras Hindu	5	5	5	-	-

Tech./						
	G.B. Pant University	9	9	9	-	-
	Roorkee	7	7	No	division	awarded
	Total	30	30	21	2	-
M.Tech./ M.Sc. Tech. / M.E.Tech. Metallurgy	Banaras Hindu	1	1	1	0	-
M.Tech./ M.Sc. Tech. / M.E.Tech. Mining	Banaras Hindu	1	1	1	0	-
M.Tech./ M.Sc. (Ag.Engg.)	Allahabad	15	15	13	02	-
M.Sc. (Food Tech.)	G. B. Pant University	1	1	1	-	-
M.B.B.S.	Agra	150	118	PASSED	PASSED	PASSE
	Aligarh Muslim	55	53	PASSED	PASSED	PASSE
	Allahabad	107	70	PASSED	PASSED	PASSE
	Banaras Hindu	74	64	PASSED	PASSED	PASSED
	Gorakhpur	106	92	PASSED	PASSED	PASSED

	Kanpur	275	177	PASSED	PASSED	PASSED
	Lucknow	287	185	PASSED	PASSED	PASSED
	Meerut	146	83	PASSED	PASSED	PASSED
	Total	1200	842			
M.D.	Agra	25	22	No	division	awarded
	Aligarh Muslim	21	10	No	division	awarded
	Allahabad	38	26	No	division	awarded
	Banaras Hindu	94	72	No	division	awarded
	Kanpur	53	37	No	division	awarded
	Lucknow	109	69	No	division	awarded
	Meerut	19	8	No	division	awarded
	Total	359	244			
M.S.	Agra	12	12	No	division	awarded
	Aligarh Muslim	23	19	No	division	awarded
	Allahabad	31	28	No	division	awarded
	Banaras Hindu	30	23	No	division	awarded
	Kanpur	34	19	No	division	awarded
	Lucknow	42	28	No	division	awarded
	Total	172	129	No	division	awarded
M.Ch.	Banaras Hindu	2	2	No	division	awarded
D.M.	Banaras Hindu	4	4	No	division	awarded
B.D.S.	Lucknow	50	34	No	division	awarded
M.D.S.	Banaras Hindu	1	No Pass	No	division	awarded
	Lucknow	26	13	No	division	awarded
	Total	27	13	-	-	-

B. Pharmac	Banaras Hindu	28	27	11	16	-
B.A.M.S./ B.S.A.M./ G.A.M.S.	Sampurnanand Sanakrit	99	78	-	-	-
M.D. (Ayurveda)	Banaras Hindu	25	23	-	-	-
Ayurveda charya	Lucknow	53	35	-	-	-
B.U.M.S.	Aligarh Muslim	62	50	-	-	-
	Kanpur	472	259	-	--	-
	Total	534	309	-	-	-
B.U.M.S./ M.D. (Unani)	Aligarh Muslim	2	2	-	-	-
B.Sc. (Ag.)	Agra	251	181	31	150	-
	Allahabad	78	72	22	50	-
	Banaras Hindu	74	74	50	24	-
	Bundelkhand	214	170	Break	up not	available
	C.S. Azad Ag. Un iv.	121	121	Grade system		
	GBS. Pant Un iv.	177	177	154	23	-
	Gorakhpur	1076	955	Break	up not	available
	Kanpur	227	196	37	159	-
	Meerut	1058	842	Break	up not	available
	N.D. univ.	43	43	No	division	awarded

	Rohilkhand	62	58	11	47	-
	Total	3381	2929	305	453	-
M.Sc. (Ag)	Agra	94	94	61	33	-
	Allahabad	51	47	35	12	-
	Banaras Hindu	67	67	62	5	-
	C.S. Azad Ag. Univ.	115	115	No	division	awarded
	G.B. pant Univ.	78	78	78	-	-
	Gorakhpur	144	133	Break	up not	available
	Kanpur	147	143	82	59	2
	Meerut	10434	Break	up	not	available
	Total	800	721	318	109	02
B.V.Sc./	Agra	30	26	No	division	awarded
	C.S. Azad. univ.	48	47		-do-	
	G.B. Pant Un iv.	72	72	65	07	-
	Total	150	145	65	07	-
M.V.Sc.	Allahabad	07	07	07	-	-
	C.S. Azad . Univ.	34	34	No	division	awarded
	G. B. Pant Univ.	15	15	15	-	-
	Total	56	56	22	-	-
M.Sc. (Animal Sc.)	Allahabad	07	07	07	-	-
L.L.B./B.L.	Agra	1772	836	19	817	-
	Aligarh Muslim	267	65	4	61	-
	Allahabad	2046	1821	20	1801	-

	Avadh	587	367	Break up not available		
	Banaras Hindu	184	80	1	79	-
	Bundelkhand	932	689	Break up not available		
	Garhwal	528	220	03	217	-
	Gorakhpur	1862	1341	45	1296	-
	Kanpur	1061	968	35	933	-
	Kumaon	59	40	-	40	-
	Lucknow	Session was declared zero`	....			
	Meerut	1863	1028	Break up not available		
	Rohilkhand	993	434	8	426	-
	Total	12154	7859	135	5670	-
L.L.M.	Agra	09	03	-	03	-
	Aligarh Muslim	43	22	-	22	-
	Banaras Hindu	04	04	-	04	-
	Gorakhpur	05	05	-	05	-
	Lucknow	Session was declared zero				
	Meerut	42	23	Break up not available		
	Total	103	57	-	34	-
Music/ Fine Arts	Banaras Hindu	10	08	02	06	-
B.A. (Fine Arts)	Banaras Hindu	37	37	18	19	-

M.Music/ M.A.(Music)	Allahabad	13	11	05	05	01
	Banaras Hindu	08	08	06	01	01
	Total	21	19	11	06	02
M.A. (Fine Arts)	Banaras Hindu	10	10	05	05	-
B. Journalism	Banaras Hindu	31	14	00	14	-
B.Lib./B.Lib Sc.	Aligarh Muslim	72	56	25	24	7
	Banaras Hindu	47	38	8	16	12
	Lucknow	54	43	10	33	-
	Sampurnanand Sanskrit	38	23	2	18	03
	Total	211	158	45	91	22
M.P. Ed.	Banaras Hindu	90	78	8	53	17
M.Lib./ M.Lib. Sc.	Aligarh Muslim	12	08	7	1	-
	Banaras Hindu	26	17	2	15	-
	Total	38	25	9	16	-

Sourses- University Development in India, Pt. II. Basic Facts & Figures 1982-83, U.G.C. New Delhi, (1990)

TABLE – 5.4

DOCTORATE DEGREES AWARDED IN UTTAR PRADESH DURING 1983-84 (FROM 1.7.83 TO 30.6.84) – FACULTY WISE

S. No	University/Institution deemed to be University	Arts	Science	Commerce	Education	Engg/ Tech.	Medicine	Agri.	Vet. Sci.	Law	Others	Tota
1	Agra	148	86	10	8	-	1	13	-	-	02	268
2	Aligarh Muslim	39	55	-	1	-	-	-	-	-	-	95
3	Allahabad	66	48	3	1	2	-	-	-	-	-	120
4	Avadh	41	7	1	3	-	-	-	-	-	-	52
5	Banaras Hindu	88	51	11	4	6	6	33	-	-	01	200
6	Bundelkhand	2	5	-	1	-	-	-	-	-	-	8
7	Chandrashekhar Azad univ. of Ag. & Tech.	-	-	-	-	-	-	35	3	-	-	38
8	Garhwal	3	15	-	-	-	-	-	-	-	01	19
9	G. B. Pant Univ. of Ag. & Tech.	-	-	-	-	2	-	29	1	-	-	32
10	Gorakhpur	55	44	02	8	-	-	-	-	-	-	109
11	Kanpur	30	29	-	-	2	-	31	-	-	-	92
12	Kashi Vidyapith	30	-	-	-	-	-	-	-	-	01	31
13	Kumaon	51	34	3	3	-	-	-	-	-	-	91
14	Lucknow	71	84	5	4	-	-	-	-	1	2	167
15	Meerut	106	86	6	14	-	-	20	-	-	-	232
16	Narendradeo Univ. of Ag & Tech.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Rohilkhand	4	1	3	-	-	-	-	1	-	-	9
18	Roorkee	4	35	-	-	52	-	-	-	-	-	91
19	Sampurnanand Sanskrit	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
20	Gurukul Kangri	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21	Dayalbagh Educational Institute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Indian Veterinary Research Unit.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	761	580	44	47	64	7	161	5	1	7	1,677

Source – University Development in India, Basic Facts & Figures, Prat III, Doctorate degrees Awarded 1979-80 to 1983-84, U.G.C. , New Delhi.

Medical Colleges and Institute

1- Jawahar Lal Nehru Medical College, Aligarh. 1962 (Under Control of AMU, Aligarh)

2- Institute of Medical Sciences. Varanasi. (Under Control of BHU Varanasi)

3- S.N. Medical College, Agra. 1939 (Affiliated to Agra University, Agra.)

4- King George's Medical College, Lucknow. (Constituent College of Lucknow University Lucknow)

5- G. S. V. M. Medical College, Kanpur. 1952 (Constituent College of Kanpur University, Kanpur)

6- Motilal Nehru Medical College, Allahabad. 1961 (Constituent College of Allahabad University, Allhabad)

7- L L R M Medical College, Meerut. 1966 (Constituent College of Meerut University, Meerut)

8- M L B Medical College, Jhansi. 1969 (Constituent College of Bundelkhand University. Jhansi)

9- Babu Raghava Das Medical College, Gorakhpur. 1972. (Associated College of Gorakhapur University, Gorakhpur)

Ayurvedic and Unani Medical Colleges

1- Ajmal Khan Tibbiya College, Aligarh. B.U.M.S. M.D. (Unani) (Under Control of A.M.U. Aligarh)

2- State College of Ayurveda. Lucknow. Ayurvedacharya. (Constituent College of Lucknow University, Lucknow)

3- Gurukul Kangri Ayurvedic College, Gurakul Kangri, Haridwar 1922 B.A.M.S.

4- Ayurvedic College, Atarra, Banda. 1955 B.A.M.S.

5- Sahu Ram Narain Murli Manohar Ayurvedic College, Bareilly. 1971. B.A.M.S.

6- Tak-Mil-Ut-Tib Ayurvedic College, Lucknow. 1971 B.U.M.S.

7- Unani Medical college, Allahabad. 1971 B.U.M.S.

8- Bundelkhand Ayurvedic College, Jhansi. 1972 B.A.M.S.

9- Rishikul Ayurvedic College, Haridwar. 1972 B.A.M.S.

10- Swami Kalyan Dev Ayurvedic College. Baghara, Muzaffarnagar. 1974. B.A.M.S.

11- Shri Lal Bahadur Shastri Ayurvedic College. Handia, Allahabad. 1981, B.A.M.S.

(College from Sl. No. 3 to Sl. No. 11 Affiliated to Kanpur univerisity, Kanpur)

Table 5.5

Ayurvedic and Unani Medical Colleges which are affiliated to different universities.

S.N.	Name of University	No. of Colleges.
1-	Aligarh Muslim University, Aligarh	1
2-	Lucknow University, Lucknow.	1
3-	Kanpur University, Kanpur.	9
		Total 11

Homeopathic Medical College

1- National Homeopathic College, Lucknow. 1971 BHMS/BMS (Affiliated to Kanpur university, Kanpur)

2- Brij Kishore Homeopathic Medical College. Faizabad. 1981. BHMS/BMS.

3- Ghazipur Homeopathic Medical College, Ghazipur. 1981 BHMS/BMS

4- Homeopathic Medical College, Tigri (Nagina) Bijnor. 1981 BHMS/BMS

5- KGK Homeopathic Medical College, Moradabad. 1981 BHMS/BMS.

6- Lal Bahadur Homeopathic Medical college, Allahabad. 1981 BHMS/BMS.

7- Mohan Homeopathic Medical College, Lucknow. 1981 BHMS/BMS

8- Shri Durgaji Homeopathic Medical College, Chandreshwar, Azamgarh. 1981 BHMS/BMS.

9- State Kanpur Homeopathic Medical College, Kanpur. 1981 BHMS/BMS.

10- TD Homeopathic Medical College, Jaunpur. 1981. BHMS/BMS.

(Colleges from Sl. No. 2 to Sl. No. 10 Affiliated to Agra university, Agra.)

Engineering Colleges and Institutes

1- Zakir Husain College of Engineering & Technology. Aligarh. (Under Control of AMU. Aligarh)

2- College of Technology, Pant Nagar, Nainital. (Under Control of Govind Ballabh Pant University of Agriculture & Technology, Pant Nagar, Nainital)

3- Institute of Technology, Varanasi. (Under Control of BHU. Varansi)

4- Govt. College of Architecture. Lucknow. B.Arch. (Constituent College of Lucknow University, Lucknow)

5- Govt. Central Textile Institute, Kanpur, 1914 B. Text. (Affiliated to Kanpur University, Kanpur)

6- H.B. Technological Institute, Kanpur, 1958 (B.Tech Engg.), B. Tech (Chem Tech), M. Tech. (Affiliated to Kanpur University, Kanpur)

7- Motilal Nehru Regional Engineering College, Allahabad. 1961 B.E. M.E. (Associted College of Allahabad University, Allahabad)

8- M M M Engineering College, Gorakhpur, 1962 B.E. (Associated College of Gorakhpur University, Gorakhpur)

9- K.N. Institute of Technology, Sultanpur. 1976 B.Tech. (Affiliated to Avadh University, Faizabad)

10- Institute of Engineering & Technology, Lucknow. 1984 B. Tech. (Constituent College of Lucknow University, Lucknow)

11- S.D. College of Engineering & Technology, Muzaffar Nagar. Meerut university. B. Tech. (Computer Science & Engineering, Chemical & Alcohal Technology, Sugar Technology)

Table 5.6

Engineering Colleges and Institutes which are Affiliated to different universities.

S.N.	Name of University	No. of Colleges
1-	Aligarh Muslim University, Aligarh.	1
2-	Banaras Hindu University, Varanasi.	1
3-	G.B. pant. University, of Ag.&Tech. Pant nagar.	1
4-	Lucknow University, Lucknow.	2
5-	Kanpur University, Kanpur.	2
6-	Allahabad University, Allahabad.	1
7-	Gorakhpur University, Gorakhpur.	1
8-	Avadh University, Gorakhpur.	1
9-	Meerut University, Meerut.	1
	Total	11

Management Institutes

1- Lal Bahadur Shastri Institute of Management & Technology. Bareilly.

Post graguate Diploma in Bussiness Management.

2- Institute of Management, Social Studies & Research. Deharadun.

P G Diploma in Porsonnel Management & Industrial Relation.

3- Unique Institute of Management. Modi Nagar. (Affiliated to Ch. Charn Singh University, Meerut) M.B.A., B.B.A., B.C.A.

4- Institute of Productivity & Management. 1977 Meerut. Ghaziabad, Lucknow. kanpur.

PGD in Business Administration.

PGD in Personnel Management & Industrial Relations.

PGD in Markating & Sales Management.

(Affiliated to Board of Technical Education, Lucknow)

(Courses are recognised by the Govt. of U.P.)

5- Regional Institute of Rural Development.

(Directorate of Rural Development & Panchayat Raj)

Govt. of U.P. Lucknow.

Lucknow, Raebareli, Agra, Bulandshahr, Gorakhpur, Meerut, Hardwar, (Seven Centres)

Diploma in computer programming)

6- Motilal Nehru Institute of Research and Bussiness Administration, Allahabad. M.B.A.

7- Shiva Institute of Management Studies, Ghaziabad. B.B.A.

8- Institute of Finance and Management. Lucknow. under Control of Lucknow universtiy, Lucknow.

BMS (Bachelar of Management Science)

PGDFMPM (Post graduate Diploma in Financial Markets and portfolio Management)

Agricultural Colleges, Institute and Degree Colleges

In which B.Sc. (Ag), and M.Sc. (Ag), Classes are running

Allahabad University

1- Allahabad Agricultural Institute Naini. 1910

B.Sc. (Ag. Engg) B.Sc. (Home Ecom) M.S.C. (Ag)

Associated College of Allahabad University, Allahabad.

Banaras Hindu University

Institute of Agricultural Sciences. B.H.U. Varanasi.

Agra University, Affiliated Colleges

2- Narain (PG) College, Shikohabad. 1956 B.Sc. (Ag)

3- Raja Balwant Singh College, Agra. 1940 B.Sc. (Ag) M.Sc. (Ag)

Gorakhpur University, Affiliated Colleges

4- BRD Degree College, Deoria. 1954. B.Sc. (Ag), M.Sc. (Ag)

5- National Degree College, Barhalganj, Gorakhpur, 1960 B.Sc. (Ag)

Kanpur University, Affiliated Colleges

6- Janta College, Bakewar. Etawah. 1959 B.Sc. (Ag)

7- Janta Mahavidyalaya, Ajitmal, Etawah. 1964 B.Sc. (Ag)

8- Kulbhaskar Ashram Degree College, Allahabad, 1960 B.Sc. (Ag) M.Sc. (Ag)

Meerut University. Affiliated Colleges

9- A S College, Lakhaoti- 245407. 1941 B.Sc. (Ag) M.Sc. (Ag)

10- Ch. Chhoturam Degree College, Muzaffar Nagar. 1959 B.Sc. (Ag) M.Sc. (Ag)

11- Gochar Agricultural College, Rampur. (Maniaran) 1959 B.Sc. (Ag)

12- Janta Vedic College, Baraut, Meerut. 1971 B.Sc. (Ag) M.Sc. (Ag)

13- K.V. Degree College, Machhra-250106. 1955 B.Sc. (Ag)

14- Kishan Degree College, Simbhaoli, 1956 B.Sc. (Ag)

15- Raja Mahendra Pratap Prem Vidyalaya College, Narsan. 1958 B.Sc. (Ag) M.Sc.(Ag)

16- Rana Shiksha Shivir Degree college, Palikhava. 1960 B.Sc. (Ag)

17- Rashtriya Kisan College, Shamli, 1958 B.Sc. (Ag)

Rohilkhand University. Affiliated Colleges

18- RSM Degree College, Dhampur, Bijnor. 1958 B.Sc. (Ag)

Bundelkhand University Jhansi, Affiliated College

19- BNV College, Rath,Hamirpur, 1960 B.Sc. (Ag) M.Sc. (Ag)

Purvanchal University. Affiliated Colleges

20- Rajakiya Mahila Degree College, Ghazipur. 1977 B.Sc. (Ag)

21- Rajakiya Degree College, Jakhini, Varanasi. 1972. B.Sc. (Ag)

22- SDJ College, Chandeshwar. Azamgarh. 1958. B.Sc. (Ag) M.Sc. (Ag)

23- Sri MMTD College, Ballia. 1955. B.Sc. (Ag) M.Sc. (Ag)

24- T.D. College, Jaunpur. 1948. B.Sc. (Ag)

25- U.P. Singh College, Varanasi. 1909. B.Sc. (Ag) M.Sc. (Ag)

Table - 5.7

Agricultural Colleges, Institute and Degree colleges under Different universities in which B.Sc. (Ag) and M.Sc. (Ag) Classes are running.

S.N.	Name of University	No. of colleges.
1-	Allahabad University, Allahabad.	1
2-	Agra University, Agra.	2
3-	Gorakhpur University. Gorakhpur.	2
4-	Kanpur University. Kanpur.	3
5-	Meerut University. Meerut.	9
6-	Rohilkhand University, Bareilly.	1
7-	Bundelkhand University, Jhansi.	1
8-	Purvanchal University, Jaunpur.	6
	Total	25

Teacher's Training College and Degree Colleges in which B.Ed. and M.Ed. classes are running

Banaras Hindu University Affiliated colleges

1- Arya Mahila Degree College, 1958 B.Ed.

2- Vasanta College for Women. 1946 B.Ed.

Lucknow University. Associated Colleges

3- Isbella Thoburn College, Lucknow, 1896, B.Ed.

4- Mahila Vidyalaya College, Lucknow. 1895 B.Ed.

5- Navyug Kanya Vidyalaya, Lucknow. 1953, B.Ed.

Agra university. Affiliated Colleges

6- Baikunthi Devi kanya Mahavidyalaya, Agra. 1967. B.Ed., M.Ed.

7- Dharam Samaj College, Aligarh. 1947. B.Ed., M.Ed.

8- Ganjdundwara College, Ganjdunwara. 1958. B.Ed.

9- K.R. Girls College, Mathura. 1957. B.Ed.

10- Raja Balwant Singh College, Agra. 1940. B.Ed. M.Ed.

11- Smt. Bhagwati Devi Jain Girls College, Agra Cantt. 1964. B.Ed.

12- Shri Tikaram Kanya Mahavidyalaya, Aligarh. 1957. B.Ed.

13- Shri Varhney Colllege, Aligarh. 1947. B.Ed.

Gorakhpur University, Affiliated Colleges

14- B.R.D. Degree College, Deoria, 1954. B.Ed.

15- Buddha Degree College, Kushinagar, Deoria. 1955. B.E.d M.Ed.

16- Madan Mohan Malviya Degree College, Bhatpar, Rani, Deoria, 1963. B.Ed.

Kanpur University Affiliated colleges

17- Acharya Narendra Deo Mahila Mahapalika Mahavidyalaya, Kanpur. 1963. B.Ed. M.Ed.

18- Baiswara Degree College, Lalganj. Rae Bareli. 1966. B.Ed.

19- D.B.V. College, Kanpur. 1959. B.Ed.

20- Dayanand Girls College, kanpur. 1957. B.Ed.

21- Dayanand Subhash National College, Unnao. 1948. B.Ed.

22- Dayanand Women's Training College, Kanpur. 1958. B.Ed., M.Ed.

23- Feroz Gandi College, Rae Bareli. 1960. B.Ed.

24- Halim Muslim Degree College, Kanpur. 1959. B.Ed.

25- Handia Degree College, Allahabad. 1973. B.Ed.

26- Hindu Kanya Mahavidyalaya, Sitapur. 1961. B.Ed.

27- International Centre of Education, Kanpur. 1972. B.Ed.

28- Mahila Mahavidyalaya, Kidwai Nagar, Kanpur. 1969. B.Ed.

29- Sadanand Degree College, Chhivalaha, Fatehpur. 1973. B.Ed.

30- Shri Narain Girls Degree College, Unnao. 1966. B.Ed.

31- Teacher's Training College, Sitapur. 1962. B.Ed.

32- Tilak Degree College, Auraiya, Etawah. 1967. B.Ed.

33- V S S D College, Kanpur. 1921. B.Ed.

Meerut University. Affiliated Colleges

34- D.A.V. College, Muzaffar Nagar. 1950. B.Ed.

35- Digambar Jain College, Baraut. Meerut. 1947. B.Ed.

36- J V Jain College, Saharanpur. 1955. B.Ed., M.Ed.

37- K L D A V College, Roorkee. 1960. B.Ed.

38- K V Degree College, Machhra-250106. 1955. B.Ed.

39- Meerut College, Meerut. 1892. M.Ed.

40- NAS College, Meerut, 1952. B.Ed., M.Ed.

41- Vidyawati Mukundlal Girls Degree College, Ghaziabad. 1961. M.Ed.

Kumaun University

42- Almora Constituent College, Almora, 1940. B.Ed. M.Ed.

Constitnent College of Kumaun University, Nainital.

43- Govt. P G College, Pithoragarh. 1963. B.Ed.

Affiliated to Kumaun University, Nainital.

HNB Garhwal University. Constituent Colleges

44- Birla Post graduate College, Sri Nagar, Garhwal. 1961. B.Ed., M.Ed.

45- Swami Ramtirth College, Tehri. 1970. B.Ed., M.Ed.

Affiliated colleges

46- DAV PG College, Dehradun. 1946. B.Ed.

47- Dayanand Women's Training College, Dehradun. 1961. B.Ed.

48- Govt. PG College, Gopeshwar, Chamoli. 1966. B.Ed.

49- Govt. Post Graduate College, Kotdwara. 246149. 1971. B.Ed.

Avadh University. Affiliated Colleges

50- B.N.K.B. PG College, Akbarpur. Faizabad. 1969. B.Ed.

51- K.N. Institute of Physical and Social Science. Sultanpur. 1973. B.Ed. M.Ed.

52- K.S. Saket PG College, Faizabad. 1951. B.Ed.

53- Kisan PG College, Bahraich. 1960. B.Ed.

54- L B shastri PG College, Gonda. 1966. B.Ed.

55- M L K PG College, Balrampur. Gonda. 1955. B.Ed.

56- M M M PG College, Kala Kankar. Pratapgarh. 1966. B.Ed. M.Ed.

57- Munishwar Dutt PG College, Pratapgarh. 1960. B.Ed.

58- R.R. PG College, Amethi, Sultanpur. 1959. B.Ed., M.Ed.

59- Sewa Asram Degree College, Dhidhui, Pratapgarh. 1971. B.Ed.

Rohilkhand University. Affiliated Colleges

60- D A K College, Muradabad. 1960. B.Ed.

61- G D H G College, Muradabad. 1905. B.Ed.

62- Govt. Raza College, Rampur. 1949. B.Ed.

63- Hindu College, Muradabad. 1949. B.Ed., M.Ed.

64- N K B M G College, Chandausi. Muradabad. 1964. B.Ed.

65- N M S N Dass College, Badaun. 1967. B.Ed.

66- S B D College, Dhampur, Bijnor. 1969. B.Ed.

67- S S Degree College, Shahjahanpur. 1965. B.Ed.

68- Vardhman College, Bijnor. 1960. B.Ed.

Bundelkhand University. Affiliated Colleges

69- Atarra Post Graduate College, Atarra. Banda. 1960. B.Ed., M.Ed.

70- Bundelkhand Degree College, Jhansi. 1949. B.Ed.

71- D V College, orai. 1951. B.Ed., M.Ed.

72- Pt. J L N College, Banda. 1962. B.E.d., M.Ed.

73- Gandhi Degree College, Orai. 1969. B.Ed.

Purvanchal University. Affiliated Colleges

74- Agarsen Mahila Mahavidyalaya, Azamgarh. 1966. B.Ed.

75- G S Degree College, Samodhpur. Jaunpur. 1978. B.Ed.

76- H C College, Varanasi, 1951. B.Ed.

77- K B College, Mirzapur. 1957. B.Ed.

78- L B S Degree College, Mughal Sarai, Varanasi. 1969. B.Ed.

79- Post Graduate College, Ghazipur. 1957. B.Ed.

80- R S K D Degree College, Jaunpur. 1959. B.Ed.

81- Raja Harpal Singh Degree College, Singramau. Jaunpur. 1965. B.Ed.

82- S C College, Ballia. 1947. B.Ed.

83- S D J College, Chandeshwar. Azamgarh. 1958. B.Ed.

84- SGR PG College, Dobhi. Jaunpur. 1964. B.Ed.

85- S N College, Azamgarh. 1958. B.Ed.

86- Sakaldiha Degree College, Varanasi. 1965. B.Ed.

87- Sri Gandhi Degree College, Maltari Azamgarh. 1965. B.Ed.

88- Sri M M T D College, Ballia. 1955. B.Ed.

89- TD College, Jaunpur. 1948. B.Ed.

90- UP Singh. College, Varanasi. 1909. B.Ed.

Table - 5.8

Teacher's Training College, and Degree Colleges under different Universities in which B.Ed. and M.Ed. Classes are running

S.N.	Name of University	No. of Colleges.
1-	Banaras Hindu University, Varanasi.	2
2-	Lucknow University, Lucknow.	3
3-	Agra University, Agra.	8
4-	Gorakhpur University, Gorakhpur.	3
5-	Kanpur University, Kanpur.	17
6-	Meerut University, Meerut.	8
7-	Kumaun University, Nainital.	2
8-	Garhwal University, Garwhal.	6
9-	Avadh University, Faizabad.	10
10-	Rohilkhand University, Bareilly.	9
11-	Bundel Khand University, Jhansi.	5
12-	Purvanchal University, Jaunpur.	17
	Total	90

Law College and Degree College in which LLB. LLM. classes are running.

Allahabad University. Associated Colleges

1- Allahabad Degree College, Allahabad. 1956. LLB.

2- C.P.M. Degree College, Allahabad. 1950. LLB.

Lucknow University. Associated Colleges

3- DAV Degree College, Lucknow. 1948. LLB.

4- Shia Degree College, Lucknow. 1947. LLB.

Agra University. Affiliated Colleges

5- Agra College, Agra. 1823. LLB. LLM.

6- Babu Shivnath Agarwal College, Mathura. 1958. LLB.

7- Dharam Samj College, Aligarh. 1947. LLB.

8- Shri Varshney College, Aligarh. 1947. LLB.

Gorakhpur University. Affiliated Colleges

9- Ambika Pratap Narain Degree College, Basti. 1972. LLB.

10- Sant Vinoba Degree College, Deoria. 1961. LLB.

11- St. Andrews College, Gorakhpur. 1889. LLB.

Kanpur University. Affiliated Colleges

12- Brahamanand Degree College, Kanpur. 1961. LLB.

13- Dayanand College of Law. Kanpur. 1958. LLB.

14- V S S D College, Kanpur. 1921. LLB.

Meerut University. Affiliated Colleges

15- D A V College, Muzaffar Nagar, 1950. LLB.

16- J V Jain College, Saharanpur. 1955. LLB.

17- M M H College, Ghaziabad. 1948. LLB.

18- Meerut College, Meerut. 1892. LLB. LLM.

19- NAS College, Meerut. 1952. LLB.

20- N R E C College, Khurja. 1946. LLB.

Kumaun University

21- Almora Constituent College, Almora. 1940. LLB.

H N B Garwhal University. Constituent Colleges

22- Dr. BG Reddy Post Graduate College. Pauri. 1970. LLB.

23- Swami Ramtirth College, Tehri. 1970. LLB.

24- D A V PG College, Dehradun. 1946. LLB.

Avadh University. Affiliated Colleges

25- K N Institute of physical & Social Science. Suntanpur. 1973. LLB.

26- K S Saket PG College, Faizabad. 1951. LLB.

Rohilkhand University. Affiliated Colleges

27- Bareilly College, Bareilly. 1837. LLB.

28- K G K College, Muradabad. 1948. LLB.

Bundelkhand University

29- Bundelkhand Degree College, Jhansi. 1949. LLB.

Affiliated to Bundelkhand University. Jhansi.

Purvanchal University. Affiliated Colleges

30- H C College, Varanasi, 1951. LLB.

31- S N College, Azamgarh. 1958. LLB.

32- T D College, Jaunpur. 1948. LLB.

Table - 5.9

Law College and Degree Colleges under different universities in which LLB., LLM. Classes are running.

S.N.	Name of University	No. of Colleges.
1-	Allahabad University, Allahabad.	2
2-	Lucknow University, Lucknow.	2
3-	Agra University, Agra.	4
4-	Gorakhpur University, Gorakhpur.	3
5-	Kanpur University, Kanpur.	3
6-	Meerut University, Meerut.	6
7-	Kumaun University, Nainital.	1
8-	H N B Garhwal University, Sri Nagar, Garhwal.	3
9-	Avadh University, Faizabad.	2
10-	Rohilkhand University, Bareilly.	2
11-	Bundelkhand University, Jhansi.	1
12-	Purvanchal University, Jaunpur.	3
	Total	32

शासकीय महाविद्यालय

शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना वर्ष 1948 में रामपुर स्टेट का भारत राज्य में सम्मिलित होने के फलस्वरूप रामपुर में संचालित महाविद्यालय के प्रान्तीयकरण से हुई, बाद में वर्ष 1951 में दो शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई जिनमें से एक नैनीताल व दूसरा वाराणसी जनपद में ज्ञानपुर नामक स्थान पर खोला गया। ठाकुर देवसिंह विष्ट राजकीय महाविद्यालय, नैनीताल की स्थापना में उस क्षेत्र के तत्कालीन जमींदार एवं लकड़ी के व्यवसायी ठाकुर देवसिंह विष्ट ने नैनीताल में एक पब्लिक स्कूल की भूमि भवन तथा छात्रावास क्रय करके महाविद्यालय की स्थापना हेतु शासन

को दान दिया जबकि ज्ञानपुर में तत्कालीन काशी नरेश (रामनगर स्टेट) ने अपनी सम्पत्ति से लगभग 62 एकड़ भूमि, खुर्शीद मंजिल भवन तथा अन्य भवन महाविद्यालय हेतु दिये तथा इस महाविद्यालय का नाम काशी नरेश महाविद्यालय रखा गया। प्रारम्भ में शासन द्वारा अन्य अशासकीय महाविद्यालयों की तुलना में इन दोनों शासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों को उच्च वेतनमान दिया गया तथा इन महाविद्यालयों के अध्यापकों का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया। इन दोनों महाविद्यालयों में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में स्नातकोत्तर स्तर तक की कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इस शताब्दी के छठें दशांक से अन्य शासकीय महाविद्यालय खोलने का क्रम आरम्भ हुआ। अधिकांश शासकीय महाविद्यालय उत्तराखंड एवं शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुये क्षेत्रों में है।

उत्तर प्रदेश में शासकीय महाविद्यालयों की विभिन्न वर्षो में स्थापना की स्थिति

तालिका - 5.10

क्र.स.	महाविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष
1.	राजकीय रजा महाविद्यालय, रामपुर	1949
2.	ठाकुर देवासिंह विष्ट राजकीय महाविद्यालय, नैनीताल	1951
3.	के. एन. राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर, वाराणसी	1951
4.	राजकीय महाविद्यालय, पिथौरागढ़	1963
5.	राजकीय महाविद्यालय, गोपेश्वर, चमोली	1966
6.	राजकीय महाविद्यालय, उत्तरकाशी,	1969
7.	डॉ. पी. डी. बी. हिमालय राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार	1971
8.	राजकीय महाविद्यालय, जाखिनी (वाराणसी)	1972
9.	राजकीय महाविद्यालय, जहारीखाल, लेन्सडाउन	1972
10.	पंडित एल. एम. एस. राजकीय महाविद्यालय, ऋषिकेश	1972
11.	राधे हरि राजकीय महाविद्यालय, काशीपुर, नैनीताल	1973
12.	राजकीय महाविद्यालय, दुधी, सोनभद्र	1973
13.	राजकीय महाविद्यालय, चन्दौली, वाराणसी	1973

14.	राजकीय महाविद्यालय, रानीखेत, अल्मोड़ा	1973
15.	राजकीय महाविद्यालय, रूद्रपुर, नैनीताल	1974
16.	राजकीय महाविद्यालय, बागेश्वर, अल्मोड़ा	1974
17.	श्री ए. पी. बहुगुणा राजकीय महाविद्यालय, अगस्तमुनि, चमोली	1974
18.	राजकीय महाविद्यालय, हमीरपुर	1975
19.	राजकीय महाविद्यालय, बेरीनाग, पिथौरागढ़	1975
20.	पी. एल. एन. के. जी. राजकीय महाविद्यालय, रामनगर, नैनीताल	1975
21.	राजकीय महाविद्यालय, बिसालपुर, पीलीभीत	1976
22.	राजकीय बालिका महाविद्यालय, रामपुर	1976
23.	राजकीय महाविद्यालय, महमूदाबाद, सीतापुर	1976
24.	राजकीय बालिका महातिद्यालय, गाज़ीपुर	1977
25.	राजकीय महाविद्यालय, चाकिया, वाराणसी	1978
26.	राजकीय महाविद्यालय, ऊँचाहार, रायबरेली	1978
27.	राजकीय महाविद्यालय, चरखारी, हमीरपुर	1978
28.	राजकीय बालिका महाविद्यालय, देवरिया	1978
29.	राजकीय बालिका महाविद्यालय, बाँदा	1978
30.	राजकीय बालिका महाविद्यालय, कंघाला, मुजफ्फर नगर	1979
31.	राजकीय महाविद्यालय, घानापुर, वाराणसी	1979
32.	राजकीय महाविद्यालय, हरदोई	1979
33.	राजकीय महाविद्यालय, मुहम्मदाबाद, गोहाना, मऊ	1979
34.	राजकीय महाविद्यालय, वेदीखाल, पौड़ी गढ़वाल	1979
35.	राजकीय महाविद्यायल, सयालदे, अल्मोड़ा	1979
36.	राजकीय महाविद्यालय, चौबट्टाखाल, पौड़ी गढ़वाल	1979
37.	राजकीय महाविद्यालय, लोहाघाट, पिथौरागढ़	1979

38.	राजकीय महाविद्यालय, कर्ण प्रयाग, चमोली	1979
39.	राजकीय महाविद्यालय, चम्बा, टेहरी गढ़वाल	1979
40.	राजकीय महाविद्यालय, ललितपुर	1981
41.	राजकीय महाविद्यालय, जालौन	1981
42.	एम. बी. राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल	1982
43.	राजकीय महाविद्यालय, नोएडा, गाजियाबाद	1982
44.	राजकीय महाविद्यालय, ओवरा, सोनभद्र	1982
45.	राजकीय महाविद्यालय, महोबा, हमीरपुर	1982
46.	राजकीय महाविद्यालय, देववन्द, सहारनपुर	1983
47.	राजकीय महाविद्यालय, जलेसर, एटा	1983
48.	राजकीय महाविद्यालय, द्वाराहाट, अल्मोड़ा	1983
49.	राजकीय महाविद्यालय, दिदीहाट, नारायण नगर, पिथौरागढ़	1983
50.	राजकीय महाविद्यालय, मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर	1986
51.	राजकीय महाविद्यालय, कर्वी, बाँदा	1988
52.	राजकीय महाविद्यालय, सैदपुर, गाज़ीपुर	1988
53.	राजकीय महाविद्यालय, खटीमा, नैनीताल	1988
54.	राजकीय महाविद्यालय, बांगरमऊ, उन्नाव	1988
55.	राजकीय महाविद्यालय, मनीला, अल्मोड़ा	1989
56.	राजकीय बालिका महाविद्यालय, फतेहपुर	1990

तालिका 5.11

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या

संस्था	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1990-91
विश्वविद्यालय						
लड़के	19105	29785	51799	94221	100218	145580
लड़कियां	1671	4033	11906	20091	30132	55411
योग	20776	33818	63705	114312	130350	200991
डिग्री कालेज						
लड़के	27294	48959	146242	275948	311036	614212
लड़कियां	2504	8743	39133	69221	84351	182311
योग	29798	57702	185375	345169	395387	796523

शिक्षा की प्रगति 1994 शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0 इलाहाबाद पृष्ठ - 74

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या

700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

19105
29785
51799
94221
100218
145580

1671
4033
11906
20091
30132
55411

27284
48959
146242
275948
311036
614212

2504
8743
39133
69221
84351
182311

Boys (University)
Girls (University)
Boys(Degree College)
Girls(Degree College)

1950-51
1960-61
1970-71
1980-81
1985-86
1990-91

उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु छात्रों का नामांकन

संविधान में सबके लिये शिक्षा उपलब्ध कराना, शैक्षिक सुविधाओं को उच्च स्तर का बनाना तथा विद्यालयों महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शैक्षिक माहौल दूषित न हो, आदि कुछ ऐसे तथ्य है जिनका सीधा सम्बन्ध विद्यार्थियों के नामांकन से है। विशेष रूप से जब उच्च स्तर की शिक्षा की बात आती है तो हमारा ध्यान छात्रों के नामांकन के साथ-साथ उनके रोजगार की सुविधाओं से जुड़ जाता है। देश में नई शिक्षा नीति 1986 के लागू होने के बाद डिग्री स्तर की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि स्नातक स्तर की शिक्षा 2 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष कर दी गई। तालिका से स्पष्ट होता है कि स्वतंन्त्रता प्राप्ति के प्रारम्भिक वर्षो (1950-51) में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा ग्रहण करने वाले लड़को की संख्या 19105 थी जबकि 1671 लड़कियॉं अध्ययनरत थी इस प्रकार कुल 20776 छात्र विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे थे। जबकि इसी अवधि में महाविद्यालयों में अध्ययनरत् लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्रमशः 27294 तथा 2504 जिनका कुल योग 29798 था।

वर्ष 1960-61 में विश्वविद्यालयों में नामांकित लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 33818 तक पहुँच गई जिनमें 29785 लड़के व 4033 लड़कियां थी। दूसरी ओर महाविद्यालयों में अध्ययनरत् लड़के एवं लड़कियां क्रमशः 48959 तथा 8743 थे जिनकी कुल संख्या 57702 थी। वर्ष 1970-71 में अध्ययन हेतु पंजीकृत विश्वविद्यालय लड़कों की संख्या 51799 तथा लड़कियों की संख्या 11906 थी जबकि महाविद्यालयों में अध्ययनरत् लड़के ओर लड़कियों की संख्या क्रमशः 146242 तथा 39133 थी जबकि दोनों स्तरों पर कुल संख्या क्रमशः 63705 व 185375 थी। वर्ष 1980-81 में महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन हेतु पंजीकृत लड़के और लड़कियों की कुल संख्या क्रमशः 345169 तथा 114312 थी जबकि अलग-अलग यह संख्या क्रमशः 94221 तथा 275948 और 20091 तथा 69221 थी।

वर्ष 1985-86 में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर बढ़कर क्रमशः 100218 तथा 311036 और 30132 तथा 84351 तक पहुँच गई इस प्रकार इन दोनों स्तरों पर यह संख्या कुल मिलाकर क्रमशः 130350 तथा 395387 थी। वर्ष 1990-91 में विश्वविद्यालयों में नामांकित लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 200991 तक पहुँच गई जिनमें 145580 लड़के व 55411 लड़कियां थी। दूसरी ओर महाविद्यालयों में अध्ययनरत् लड़के और लड़कियां क्रमशः 614212 तथा 182311 थे जिनकी कुल संख्या 796523 थी।

तालिका 5.12

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में स्तरानुसार छात्रों / छात्राओं की संख्या

स्तर	वर्ष / संख्या	1964-65	1970-71	1979-80	1985-86	1990-91
स्नातक	कुल	60354	160080	262817	334752	388000
	बालिका	12593	33237	59177	82930	116000
स्नातकोत्तर	कुल	18051	38671	82766	85529	105000
	बालिका	3578	9879	24566	25206	45000

शिक्षा की प्रगति 1991 शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0 इलाहाबाद पृष्ठ - 76

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में स्तरानुसार छात्रों/छात्राओं की संख्या
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
60354
160080
262817
334752
388000
12593
33237
59177
82930
116000
18051
38671
82766
85529
105000
3578
9879
24566
25206
45000
Total Graduate
Total Graduate Girls
Total Post Graduate
Total Post Graduate Girls
1964-65
1970-71
1979-80
1985-86
1990-91
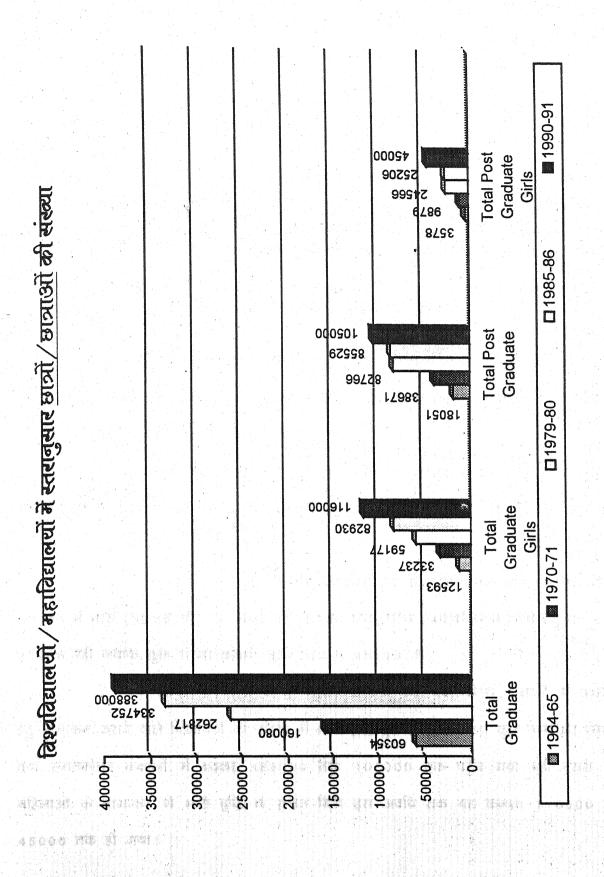
विश्विद्यालयों/महाविद्यालयों में स्तरानुसार छात्रों की संख्या

उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नामांकन प्रक्रिया स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारम्भिक वर्षो में काफी धीमीं रहीं परन्तु वर्ष 1964-65 में उसमे अचानक काफी वृद्धि हुई जो वर्ष 1990-91 तक लगातार बढ़ती ही रहीं। वर्ष 1964-65 में स्नातक कक्षाओं में कुल नामांकन 60354 था जबकि महिलाओं का नामांकन 12593 था। इन वर्षो में स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन हेतु कुल नामांकन 18051 था। जिनमें 3578 महिलाएं शामिल हैं।

वर्ष 1970-71 में स्नातक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन 33237 हो गया जबकि कुल नामांकन 160080 तक पहुँच गया। इसी अवधि में स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु बालिकाओं का नामांकन 9879 तथा कुल नामांकन 38671 था।

वर्ष 1979-80 में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में महिलाओं का नामांकन क्रमशः 59177 तथा 24566 था जबकि कुल नामांकन 262817 तथा 82766 तक पहुँच गया।

वर्ष 1985-86 में स्नातक स्तर पर अध्ययन करने वाली बालिकाओं के नामांकन में भारी वृद्धि हुई और यह बढ़कर 82930 हो गया जबकि स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु यह संख्या 25206 रही जबकि कुल संख्या क्रमशः 334752 व 85529 थी।

वर्ष 1990-91 तक पहुँचते-पहुँचते स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन हेतु नामांकन कराने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई एक और जहाँ कुल नामांकन स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में बढ़कर 388000 तथा 105000 तक पहुँच गया वहीं दूसरी और महिलाओं के नामांकन में भारी वृद्धि के संकेत दिखे इस अवधि तक यह क्रमशः 116000 तथा 45000 तक हो गया।

तलिका 5.13

उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षकों की संख्या

संस्था	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1885-86	1990-91
विश्वविद्यालय						
पुरुष	1201	2089	3078	5184	5940	6789
महिला	71	159	390	796	1099	1261
योग	1272	2248	3468	5980	7039	8050

डिग्री कालेज						
पुरुष	1175	3113	6820	10123	10864	11515
महिला	74	331	1446	2264	2521	3011
योग	1249	3444	8266	12387	13385	14526

शिक्षा की प्रगति 1994-95 शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0 इलाहाबाद
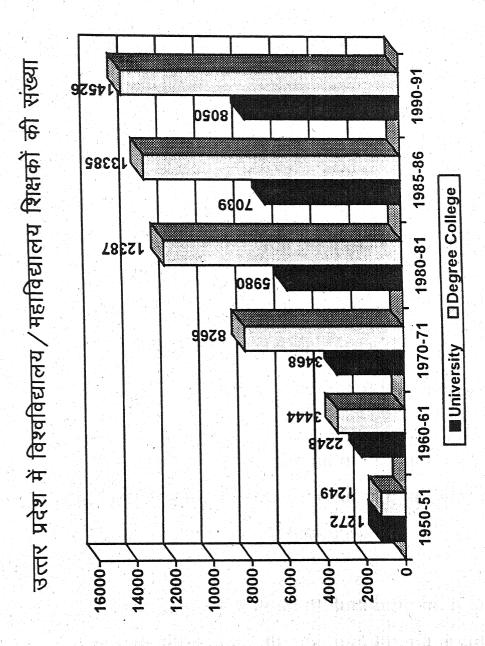
उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षकों की संख्या

उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या

शिक्षा का कोई भी स्तर हो, शिक्षा दिये जाने का स्थान कहीं भी हो, शिक्षा की नीति कितनी ही अच्छी हो, इन सबको एक सूत्र में बांधकर क्रियान्वित करने का मुख्य सूत्रधार शिक्षक ही है। यद्यपि उच्च शिक्षा का स्तर एक ऐसा चरम बिन्दु है जहॉ पहुॅच कर छात्र छात्रा स्वंय बहुत कुछ कर गुजरने का मन बना लेता है परन्तु जब तक उसे सही दिशा का ज्ञान न कराया जाये जब तक वह अभिमन्यु की तरह चक्रव्यवूह में फंसकर दिशाविहीन बनकर अपने मन और मस्तिष्क को केन्द्रित करने में असमर्थ ही रहेगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एंव महाविद्यालयों में शिक्षकों की स्थिति कुछ इस प्रकार ही है।

वर्ष 1950-51 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुल 1272 शिक्षक अध्यापनरत् थे जिनमें पुरुष शिक्षकों की संख्या 1201 थी तथा महिला शिक्षकों की संख्या मात्र 71 थी। दूसरी और महाविद्यालयों में शिक्षण कर रहे कुल शिक्षकों की संख्या 1249 थी जिनमें 74 महिला शिक्षक शामिल थी।

वर्ष 1960-61 में विश्वविद्यालय स्तर पर 159 महिला शिक्षकों की नियुक्तियां की गई तथा पुरूष शिक्षकों की संख्या भी बढ़कर 2089 तक पहुॅच गई जबकि महाविद्यालयों में अध्यापन हेतु नियुक्त शिक्षकों की संख्या 3444 थी जिनमें 3113 पुरूष तथा 331 महिला शिक्षक शामिल थी।

वर्ष 1970-71 में शिक्षण कर रहे विश्वविद्यालय स्तर के पुरूष तथा महिला शिक्षकों की संख्या 3468 तक पहुॅच गई जबकि यदि अलग अलग देखा जाये तो जहॉ महिला शिक्षक 390 थी वहीं पुरूष शिक्षक 3078 थे। महाविद्यालय स्तर पर शिक्षकों की कुल संख्या 8266 थी जिनमें 1446 महिला तथा 6820 पुरूष शामिल थे।

वर्ष 1980-81 में विश्विद्यालय स्तर पर शिक्षण कर रहे शिक्षकों की संख्या 5980 थी जिनमें 796 महिला शिक्षक तथा 5184 पुरूष शिक्षक थे। इन्हीं वर्षो में महाविद्यालयों में

अध्यापनरत् महिला शिक्षकों की संख्या 2264 तथा पुरूष शिक्षकों की संख्या 10123 थी इस प्रकार कुल 12387 शिक्षक कार्यरत थे।

वर्ष 1985-86 विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य अपनाने वाली महिलाओं की संख्या 1099 तक हो गई जबकि कुल संख्या 7039 थी जिनमें 5940 पुरूष शिक्षक शामिल थे। इसी प्रकार महाविद्यालयों में अध्यापन करने वाले पुरूष और महिला शिक्षकों की संख्या क्रमशः 10864 तथा 2521 थी, इस प्रकार यह संख्या कुल 13385 थी।

वर्ष 1990-91 के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि इस अवधि के वर्षों में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापनरत् महिला शिक्षकों की संख्या क्रमशः 1261 तथा 3011 थी। पुरूष शिक्षक क्रमशः 6789 तथा 11515 थे जबकि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत कुल शिक्षक क्रमशः 8050 व 14526 थे।

षष्टम अध्याय

षष्टम अध्याय

उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश कालीन एवं ब्रिटिश काल के बाद भी उच्च शिक्षा के विकास का तुलनात्मक विवेचन

विश्वविद्यालय

तालिका 6.1

ब्रिटिश काल में स्थापित विश्वविद्यालय

क्र.स.	विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष
1.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	1887
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	1917
3.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	1920
4.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	1921
5.	आगरा विश्वविद्यालय, आगरा	1927

तालिका 6.1 से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश काल में 40 वर्ष में 5 विश्वविद्यालय स्थापित किये गये, जिनमें 2 विश्वविद्यालय-बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है, अन्य 3 विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है जिनमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है।

तालिका 6.2

ब्रिटिश काल के पश्चात स्थापित विश्वविद्यालय

क्र.स.	विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष
1.	रूड़की विश्वविद्यालय, रूड़की	1949
2.	गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	1956
3.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	1962
4.	कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर	1965
5.	मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ	1965

6.	कुमाँऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल	1973
7.	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्री नगर, गढ़वाल	1973
8.	काशी विद्यापीठ, वाराणसी	1974
9.	अवध विश्वविद्यालय, फैज़ाबाद	1975
10.	रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	1975
11.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी	1975
12.	पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	1987
13.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ (विशिष्ट)	1989

तालिका 6.2 से यह बोध होता है कि उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात 40 वर्ष के अन्तराल में 13 विश्वविद्यालय स्थापित किये गये, ये सभी विश्वविद्यालय बहुसंकाय विश्वविद्यालय है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ एक विशिष्ट विश्वविद्यालय है। उपरोक्त विश्विद्यालयों के आंकड़ो से स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश काल के बाद विश्वविद्यालयों की संख्या में 3.25 गुना वृद्धि हुई है। -

कृषि विश्वविद्यालय

तालिका 6.3

ब्रिटिश काल के पश्चात स्थापित कृषि विश्वविद्यालय

क्र.स.	कृषि विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष
1.	गोविन्द बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एन्ड टैक्नोलॉजी पन्त नगर, नैनीताल	1960
2.	नरेन्द्र देव यूनीवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एन्ड टैक्नोलॉजी, फैजाबाद	1974
3.	चन्द्रशेखर आजाद यूनीवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एन्ड टैक्नोलॉजी, कानपुर	1974

तालिका 6.3 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति के 11 वर्ष पश्चात प्रदेश में पहला कृषि विश्वविद्यालय सन् 1960 में स्थापित किया गया, इसके 13 वर्ष पश्चात सन् 1974 में 2 अन्य कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये गये। तीनो ही विश्वविद्यालय प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र एवं उत्तरी क्षेत्र की कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे है। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक भी कृषि विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की कृषि के प्रति उदासीनता का ही परिचायक है।

संस्कृत विश्वविद्यालय

तालिका 6.4

ब्रिटिश काल के पश्चात स्थापित संस्कृत विश्वविद्यालय

क्र.स.	संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष
1.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	1956

तालिका 6.4 से यह ज्ञात होता है कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति के 8 वर्ष पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत भाषा एवं सहित्य के विकास के लिये सन् 1956 में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया, यह विश्वविद्यालय संस्कृत भाषा एवं साहित्य सामाजिक विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, ग्रंथालय विज्ञान आदि की प्रगति के लिये सतत् प्रयत्नशील है।

ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा एवं साहित्य के विकास के लिये पर्याप्त ध्यान नही दिया और न ही उस क्षेत्र में एक भी विश्वविद्यालय स्थापित किया।

संस्थान

तालिका 6.5

ब्रिटिश काल में स्थापित संस्थान

क्र.स.	संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष
1.	इन्डियन बेटेरेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर	1889
2.	इन्डियन काउंसिल आफ फोरेस्टरी रिचर्स एन्ड एजूकेशन, देहरादून	1906

तालिका 6.5 से ज्ञात होता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने शासन काल में 2 संस्थान स्थापित किये गये। दोनों ही संस्थान अपने कार्यक्षेत्र के आधार पर एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है।

तालिका 6.6

ब्रिटिश काल के पश्चात स्थापित संस्थान

क्र.स.	संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष
1.	इन्डियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलॉजी, कानपुर	1959
2.	सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ हायर तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी	1967
3.	दयाल बाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा	1973
4.	संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल सांइसेज, लखनऊ	1983
5.	इन्डियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, लखनऊ	1984

तालिका 6.6 से अवगत होता है कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति के 11 वर्ष पश्चात सन् 1959 में प्रदेश का पहला राष्ट्रीय महत्व का संस्थान केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया, सन् 1959 से 1984 के बीच 25 वर्ष के अन्तराल में 5 संस्थान स्थापित किये गये। दयालाबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा एक विश्वविद्यालय वत संस्थान है जो शिक्षा के सभी क्षेत्रों में कार्यरत है। इन सभी संस्थानों का कार्यक्षेत्र एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न एवं विशिष्ट है।

तालिका 6.5 व 6.6 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश काल के बाद इन संस्थानों की संख्या में 2.5 गुना वृद्धि हुई है।

महाविद्यालय

तालिका 6.7

ब्रिटिश काल में स्थापित महाविद्यालय

क्र.स.	महाविद्यालयों की संख्या	स्थापना वर्ष
1.	1	1823
2.	1	1837
3.	1	1850

4.	1	1866
5.	1	1888
6.	1	1889
7.	1	1892
8.	1	1895
9.	1	1896
10.	1	1902
11.	1	1905
12.	1	1909
13.	1	1910
14.	1	1914
15.	1	1917
16.	1	1919
17.	1	1921
18.	3	1922
19.	1	1939
20.	2	1940
21.	1	1941
22.	6	1946
23.	8	1947
योग	38	

तालिका 6.7 से बोध होता है कि सन् 1823 से सन् 1921 तक लगभग एक शताब्दी के ब्रिटिश शासन काल में मात्र 17 महाविद्यालय स्थापित किये गये। सन् 1922 से सन् 1947 तक 25 वर्ष के ब्रिटिश शासन काल में 21 महाविद्यालय स्थापित किये गये जो

भारतवासियों की उच्च शिक्षा के प्रति उनकी जागृति को प्रकट करते है। ये सभी महाविद्यालय निजी प्रयत्नों द्वारा एवं मिशनरियों द्वारा स्थापित किये गये।

तालिका 6.8

ब्रिटिश काल के पश्चात स्थापित महाविद्यालय

क्र.स.	महाविद्यालयों की संख्या	स्थापना वर्ष
1.	06	1948
2.	05	1949
3.	04	1950
4.	06	1951
5.	02	1952
6.	02	1953
7.	03	1954
8.	07	1955
9.	05	1956
10.	11	1957
11.	15	1958
12.	18	1959
13.	20	1960
14.	17	1961
15.	07	1962
16.	09	1963
17.	09	1964
18.	15	1965
19.	15	1966

20.	05	1967
21.	09	1968
22.	17	1969
23.	17	1970
24.	27	1971
25.	27	1972
26.	35	1973
27.	06	1974
28.	09	1975
29.	05	1976
30.	05	1977
31.	08	1978
32.	12	1979
33.	01	1980
34.	18	1981
35.	06	1982
36.	07	1983
37.	03	1984
38.	02	1985
39.	03	1986
40.	05	1988
41.	01	1989
42.	01	1990
योग	403	

तालिका 6.8 अवगत कराती है कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश में 403 नये महाविद्यालय स्थापित किये गये। सन् 1973 में 35 महाविद्यालय स्थापित किये गये जो ब्रिटिश काल के बाद स्थापित महाविद्यालयों की सबसे अधिक संख्या है सन् 1980, 1989, 1990, में क्रमशः एक-एक महाविद्यालय खोला गया जो ब्रिटिश काल के बाद स्थापित महाविद्यालयों की सबसे कम संख्या को दर्शाता है। उपरोक्त तालिकाओं के विवेचन से स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश काल की अपेक्षा ब्रिटिश काल के बाद महाविद्यालयों की संख्या में 10.6 गुना वृद्धि हुई।

मेडिकल कालेज

तालिका 6.9

ब्रिटिश काल में स्थापित मेडिकल कालेज

क्र.स.	मेडिकल कालेज का नाम	स्थापना वर्ष
1.	एस. एन. मेडिकल कालेज, आगरा	1939
2.	किंग जार्जस मेडिकल कालेज, लखनऊ	

तालिका 6.9 से ज्ञात होता है कि ब्रिटिश शासन काल में 2 मेडिकल कालेज स्थापित किये गये ये दोनों ही मेडिकल कालेज राज्य सरकार के नियंत्रण में है।

तालिका 6.10

ब्रिटिश काल के पश्चात स्थापित मेडिकल कालेज व संस्थान

क्र.स.	मेडिकल कालेज व संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष
1.	इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, वाराणसी	-
2.	जी. एस. वी. एम. मेडिकल कालेज, कानपुर	1952
3.	मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	1961
4.	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़	1962
5.	एल. एल. आर. एम. मेडिकल कालेज, मेरठ	1966
6.	एम. एल. बी. मेडिकल कालेज, झाँसी	1969
7.	बाबू राघव दास मेडिकल कालेज, गोरखपुर	1972

तालिका 6.10 से ज्ञात होता है कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात प्रदेश में 6 मेडिकल कालेव व 1 इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया। ये सभी मेडिकल कालेज विभिन्न विश्वविद्यालयों के अर्न्तगत कार्यरत है। जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अर्न्तगत, इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के आधीन कार्यरत है। दोनों ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण इनसे सम्बन्धित कालेज एवं संस्थान सीधे केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है।

उपरोक्त तालिकाएं यह ज्ञान कराती है कि ब्रिटिशकाल की अपेक्षा ब्रिटिश काल के बाद मेडिकल कालेजों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है।

यूनानी मेडिकल कालेज

तालिका 6.11

ब्रिटिश काल के पश्चात स्थापित यूनानी मेडिकल कालेज

क्र.स.	यूनानी मेडिकल कालेज का नाम	स्थापना वर्ष
1.	अजमल खान तिब्बिया कालेज, अलीगढ़	
2.	तक-मील-उत-तिब आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ	1971
3.	यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	1971

तालिका 6.11 से यह बोध होता है कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात प्रदेश में 3 यूनानी कालेज स्थापित किये गये। ब्रिटिश शासन काल में यूनानी चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। इस काल में कोई भी यूनानी मेडिकल कालेज स्थापित नहीं किया गया।

आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज

तालिका 6.12

ब्रिटिश काल में स्थापित आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज

क्र.स.	आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज का नाम	स्थापना वर्ष
1.	गुरूकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक कालेज, गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार	1922
2.	स्टेट कालेज आफ आयुर्वेद, लखनऊ	

तालिका 6.12 से बोध होता है कि ब्रिटिश शासन काल में आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई।

तालिका 6.13

ब्रिटिश काल के पश्चात स्थापित आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज

क्र.स.	आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज का नाम	स्थापना वर्ष
1.	आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, बाँदा	1955
2.	साहू राम नारायण मुरली मनोहर आयुर्वेदिक कालेज, बरेली	1971
3.	बुन्देलखन्ड आयुर्वेदिक कालेज, झाँसी	1972
4.	ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार	1972
5.	स्वामी कल्याण देव आयुर्वेदिक कालेज, बघारा, मुजफ्फरनगर	1974
6.	श्री लाल बहादुर शास्त्री आयुर्वेदिक कालेज, हंडिया, इलाहाबाद	1981

तालिका 6.13 से बोध होता है कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात प्रदेश में 6 नये आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज स्थापित किये गये। ये सभी आयुर्वेदिक कालेज बी. ए. एम. एस. स्तर की शिक्षा प्रदान करते है एवं कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बद्ध है।

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश काल की अपेक्षा ब्रिटिश काल के बाद आयुर्वेदिक कालेजों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है।

होम्योपैथिक मेडिकल कालेज

तालिका 6.14

ब्रिटिश काल के पश्चात स्थापित होम्योपैथिक मेडिकल कालेज

क्र.स.	होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का नाम	स्थापना वर्ष
1.	नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ	1971
2.	बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, फैज़ाबाद	1981
3.	गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गाज़ीपुर	1981
4.	होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, तिगरी (नगीना) बिजनौर	1981

5.	के. जी. के. होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मुरादाबाद	1981
6.	लाल बहादुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	1981
7.	मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ	1981
8.	श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, चन्द्रेश्वर, आजमगढ़	1981
9.	स्टेट कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर	1981
10.	टी. डी. होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर	1981

तालिका 6.14 से ज्ञात होता है कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात सन् 1971 में प्रदेश का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कालेज स्थापित किया गया। इसके पश्चात सन् 1981 में 9 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज स्थापित किये गये।

ब्रिटिश काल में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में कोई भी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज स्थापित नहीं किया गया।

इंजीनियरिंग कालेज व तकनीकी संस्थान

तालिका 6.15

ब्रिटिश काल में स्थापित इंजीनियरिंग कालेज व तकनीकी संस्थान

क्र.स.	इंजीनियरिंग कालेज व तकनीकी संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष
1.	जाकिर हुसैन कालेज आफ इंजीनियरिंग एन्ड टैक्नोलॉजी अलीगढ़ (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधीन)	
2.	इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलॉजी, वाराणसी (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अधीन)	
3.	गवर्मेट काजेल आफ आर्किटेक्चर, लखनऊ	
4.	गवर्मेट सेन्ट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, कानपुर	1914

ब्रिटिश शासन काल में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 4 इंजीनियरिंग कालेज व तकनीकी संस्थान स्थापित किये गये।

तालिका 6.16

ब्रिटिश काल के पश्चात स्थापित इंजीनियरिंग कालेज व तकनीकी संस्थान

क्र.स.	इंजीनियरिंग कालेज व तकनीकी संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष
1.	एच. बी. टैक्नोलोजीकल इंस्टीट्यूट, कानपुर	1958
2.	कालेज आफ टैक्नोलॉजी, पन्त नगर, नैनीताल	-
3.	मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद	1961
4.	एम. एम. एम. इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद	1962
5.	के. एन. इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलॉजी, सुल्तानपुर	1976
6.	इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एन्ड टैक्नोलॉजी, लखनऊ	1984
7.	एस. डी. कालेज आफ इंजीनियरिंग एन्ड टैक्नोलॉजी, मुजफ्फर नगर	-

तालिका 6.16 से बोध होता हैं ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात प्रदेश में 7 इंजीनियरिंग कालेज व तकनीकी संस्थान स्थापित किये गये।

उपरोक्त तालिकाओं के अध्ययन से बोध होता है कि इंजीनियरिंग कालेज व तकनीकी संस्थान की संख्या में ब्रिटिश काल की अपेक्षा 1.75 गुना वृद्धि हुई है।

मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट

तालिका 6.17

ब्रिटिश काल के पश्चात स्थापित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट

क्र.स.	मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का नाम	स्थान
1.	लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एन्ड टैक्नोलॉजी	बरेली
2.	इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, सोशल स्टडीज एन्ड रिचर्स	देहरादून
3.	यूनिक इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट	मोदी नगर
4.	इंस्टीट्यूट आफ प्रोडक्टीविटी एन्ड मैनेजमेंट 1977	कानपुर, लखनऊ मेरठ, गाजियाबाद
5.	मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट आफ रिचर्स एन्ड विजनेस एडमिनिसट्रेशन	इलाहाबाद

6.	शिवा इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज	गाजियाबाद

तालिका 6.17 से बोध होता है कि प्रबन्धकीय शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के पश्चात प्रदेश में 6 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्थापित किये गये। ये सभी इंस्टीट्यूट प्रबन्धकीय शिक्षा के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, स्नातक एवं परास्नातक स्तर की शिक्षा प्रदान कर रहे है।

कृषि संस्थान एवं महाविद्यालय

तालिका 6.18

ब्रिटिश काल में स्थापित कृषि संस्थान एवं महाविद्यालय

क्र.स.	कृषि संस्थान एवं महाविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष
1.	यू. पी. सिंह कालेज, वाराणसी	1909
2.	इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, नैनी	1910
3.	राजा बलवन्त सिंह कालेज, आगरा	1940
4.	ए. एस. कालेज, लखोटी - 245407	1941

तालिका 6.18 से ज्ञात होता है कि ब्रिटिश शासन काल में प्रदेश का पहला एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट सन् 1010 में स्थापित किया गया। 3 अन्य महाविद्यालय बहुसंकाय महाविद्यालय थे एवं कृषि विज्ञान के क्षेत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रदान कर रहे थे।

तालिका 6.19

ब्रिटिश काल के पश्चात स्थापित कृषि संस्थान एवं महाविद्यालय

क्र.स.	कृषि संस्थान एवं महाविद्यालयों की संख्या	स्थापना वर्ष
1.	1	1948
2.	1	1954
3.	2	1955
4.	2	1956
5.	4	1958
6.	3	1959

7.	4	1960
8.	1	1964
9.	1	1971
10.	1	1972
11.	1	1977
योग	21	

तालिका 6.19 से ज्ञात होता है कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात प्रदेश में कृषि विज्ञान के क्षेत्र में 21 एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट व महाविद्यालय स्थापित किये गये। अधिकांश महाविद्यालय बहुसंकाय महाविद्यालय है एवं कृषि विज्ञान के क्षेत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रदान कर रहे है।

उपरोक्त तालिकायें स्पष्ट करती है कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में महाविद्यालयों की संख्या में ब्रिटिश काल की अपेक्षा 5.25 गुना वृद्धि हुई।

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

तालिका 6.20

ब्रिटिश काल में स्थापित ऐसे महाविद्यालय जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण (बी.एड़) स्तरीय प्रदान किया जा रहा था।

क्र.स.	महाविद्यालयों की संख्या	स्थापना वर्ष
1.	1	1892
2.	1	1895
3.	1	1896
4.	1	1905
5.	1	1909
6.	1	1921

7.	2	1940
8.	2	1946
9.	4	1947
योग	14	

तालिका 6.20 से बोध होता हैं कि ब्रिटिश शासन काल में 14 महाविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। ब्रिटिश शासन काल के 55 वर्षो मे 14 महाविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

तालिका 6.21

ब्रिटिश काल के पश्चात स्थापित ऐसे महाविद्यालय जिनमें शिक्षक प्रशिक्षण (बी.एड़. एवं एम.एड. स्तरीय) प्रदान किया जा रहा है।

क्र.स.	महाविद्यालयों की संख्या	स्थापना वर्ष
1.	2	1948
2.	3	1949
3.	1	1950
4.	3	1951
5.	1	1952
6.	1	1953
7.	1	1954
8.	5	1955
9.	5	1957
10.	5	1958
11.	4	1959
12.	7	1960

13.	4	1961
14.	2	1962
15.	3	1963
16.	3	1964
17.	4	1965
18.	6	1966
19.	3	1967
20.	5	1969
21.	1	1970
22.	2	1971
23.	1	1972
24.	3	1973
25.	1	1978
	योग - 76	

तालिका 6.21 से बोध होता है कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात सन् 1948 -1978 तक 30 वर्षो के अन्तराल में 76 महाविद्यालयों में (बी.एड. एवं एम. एड. स्तरीय) शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

उपरोक्त तालिकाओं से ज्ञात होता है कि बी. एड. एवं एम. एड. स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के लिये महाविद्यालयों की संख्या में 5.4 गुना वृद्धि हुई है।

विधि महाविद्यालय

तालिका 6.22

ब्रिटिश काल में स्थापित ऐसे महाविद्यालय जिनमें विधि स्नातक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी

क्र.स.	महाविद्यालयों की संख्या	स्थापना वर्ष
1.	1	1823
2.	1	1837
3.	1	1889
4.	1	1892
5.	1	1921
6.	1	1940
7.	2	1946
8.	3	1947
	योग - 11	

तालिका 6.22 से बोध होता है कि ब्रिटिश शासन काल में 124 वर्षो के अन्तराल में 11 महाविद्यालयों में विधि स्नातक स्तर की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई।

तालिका 6.23

ब्रिटिश काल के पश्चात स्थापित ऐसे महाविद्यालय जिनमें विधि स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रदान की जा रही है।

क्र.स.	महाविद्यालयों की संख्या	स्थापना वर्ष
1.	4	1948
2.	1	1949
3.	2	1950
4.	2	1951

5.	1	1952
6.	1	1955
7.	1	1956
8.	3	1958
9.	2	1961
10.	2	1970
11.	1	1972
12.	1	1973
योग - 21		

तालिका 6.23 से बोध होता है कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश में सन् 1948-1973 तक 25 वर्षों के अन्तराल में 21 महाविद्यालयों में विधि स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त तालिकाओं का तुलनात्मक विवेचन स्पष्ट करता है कि ब्रिटिश काल की अपेक्षा ब्रिटिश काल के बाद विधि स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले महाविद्यालयों की संख्या में 1.9 गुना वृद्धि हुई है।

छात्र संख्या

तालिका 6.24[1]

ब्रिटिश कालीन विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की स्थिति

वर्ष	विश्वविद्यालय		महाविद्यालय	
	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
1945-46	9730	605	16843	1585

1. U. C. Dutt, Educational Survey of Uttar Pradesh, P. - 239

1946-47	9760	758	20643	1700
1947-48	9465	809	21487	1928

तालिका 6.24 से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1945-46 में प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों में छात्रों एवं छात्राओं की संख्या 10335 थी वर्ष 1946-47 में यह संख्या 10518 हो गई। वर्ष 1947-48 में बालकों की संख्या में गिरावट आई जबकि बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हो गई। वर्ष 1947-48 में यह संख्या 10274 हो गई। विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत् बालको की संख्या में उतार चढ़ाव आया जबकि महाविद्यालयों में अध्ययनरत् बालकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहीं। वर्ष 1945-46 में महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं की संख्या 18428 थी। वर्ष 1946-47 व 1947-48 में यह संख्या बढ़कर क्रमशः 22343 व 23415 हो गई।

तालिका 6.25[2]

ब्रिटिश काल के पश्चात विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रों की स्थिति

संस्था	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1990-91
विश्वविद्यालय						
लड़के	19105	29785	51799	94221	100218	145580
लड़किया	1671	4033	11906	20091	030132	55411
योग	20776	33818	63705	114312	130350	200991
डिग्री कालेज						
लड़के	27294	48959	146242	275948	311036	614212
लड़किया	2504	8743	39133	69221	84351	182311
योग	29798	57702	185375	345169	395387	796523

तालिका 6.25 से स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश शासन के पश्चात प्रदेश में वर्ष 1950-51 से 1990-91 तक 40 वर्षो के अन्तराल में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में

2. शिक्षा की प्रगति - 1994 शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

अध्ययनरत् लड़के एवं लड़कियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1947-48 में विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की संख्या 9465 थी जबकि 1990-91 में यह संख्या बढ़कर 145580 हो गई। ब्रिटिश काल के पश्चात विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की संख्या में 15.38 गुना वृद्धि हुई।

वर्ष 1947-48 में विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं की संख्या 809 थी जबकि वर्ष 1990-91 में यह संख्या बढ़कर 55411 हो गई। ब्रिटिश काल के पश्चात विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं की संख्या में 68.49 गुना वृद्धि हुई।

वर्ष 1947-48 में महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की संख्या 21487 थी जबकि वर्ष 1990-91 में यह संख्या बढ़कर 614212 हो गई। ब्रिटिश काल के पश्चात महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की संख्या में 28.58 गुना वृद्धि हुई।

वर्ष 1947-48 में महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं की संख्या 1928 थी जबकि वर्ष 1990-91 में यह संख्या बढ़कर 182311 हो गई। ब्रिटिश काल के पश्चात महाविद्यालयों में अध्ययरत् छात्राओं की संख्या में 94.55 गुना वृद्धि हुई है।

अध्यापक संख्या

तालिका 6.26[3]

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापनरत अध्यापकों की स्थिति

वर्ष	विश्वविद्यालय		महाविद्यालय	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1945-46	-	-	-	-
1946-47	-	-	-	-
1947-48	-	-	-	-

3. U. C. Dutt, Educational Survey of Uttar Pradesh. P. - 243

1948-49	-	-	-	-
1949-50	958	77	1274	156
1950-51	1201	71	1175	74
1951-52	1188	83	1375	169
1952-53	1192	71	1871	211
1953-54	1248	100	1984	148
1954-55	1307	108	2072	160
1955-56	1331	114	2155	172
1956-57	1451	107	2196	210
1957-58	1474	102	2308	227

तालिका 6.26 से बोध होता है कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात वर्ष 1949-50 से 1957-58 तक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापनरत अध्यापकों (पुरूष एवं महिला) की संख्या में कुछ उतार-चढ़ाव के साथ निरंतर वृद्धि होती रही है।

तालिका 6.27[4]

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापनरत अध्यापकों की स्थिति

संस्था	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1985-86	1990-91
विश्वविद्यालय						
पुरूष	1201	2089	3078	5184	5940	6789
महिला	71	159	390	796	1099	1261
योग	1272	2248	3468	5980	7039	8050
डिग्री कालेज						
पुरूष	1175	3113	6820	10123	10864	11515
महिला	74	331	1446	2264	2521	3011
योग	1249	3444	8266	12387	13385	14526

4. शिक्षा की प्रगति - 1994-95, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

तालिका 6.27 से बोध होता है कि ब्रिटिश शासन के पश्चात उत्तर प्रदेश में वर्ष 1950-51 से 1990-91 तक 40 वर्षो के अन्तराल में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापनरत अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

उपरोक्त तालिकाएं यह स्पष्ट करती है कि वर्ष 1949-50 में विश्वविद्यालयों में अध्यापनरत पुरूष अध्यापकों की संख्या 958 थी जबकि वर्ष 1990-91 में यह संख्या बढ़कर 6789 हो गई। वर्ष 1949-50 की अपेक्षा विश्वविद्यालयों में अध्यापनरत् पुरूष अध्यापकों की संख्या में 7.08 गुना वृद्धि हुई।

वर्ष 1949-50 में विश्वविद्यालयों में अध्यापनरत् महिला अध्यापकों की संख्या 77 थी जबकि वर्ष 1990-91 में यह संख्या बढ़कर 1261 हो गई। वर्ष 1949-50 की अपेक्षा विश्वविद्यालयों में अध्यापनरत् महिला अध्यापकों की संख्या में 16.37 गुना वृद्धि हुई।

वर्ष 1949-50 में महाविद्यालयों में अध्यापनरत् पुरूष अध्यापकों की संख्या 1274 थी जबकि वर्ष 1990-91 में यह संख्या बढ़कर 11515 हो गई। वर्ष 1949-50 की अपेक्षा महाविद्यालयों में अध्यापनरत् पुरूष अध्यापकों की संख्या में 9.03 गुना वृद्धि हुई।

वर्ष 1949-50 में महाविद्यालयों में अध्यापनरत् महिला अध्यापकों की संख्या 156 थी जबकि वर्ष 1990-91 में यह संख्या बढ़कर 3011 हो गई। वर्ष 1949-50 की अपेक्षा महाविद्यालयों में अध्यापनरत् महिला अध्यापकों की संख्या में 19.30 गुना वृद्धि हुई।

बजट

तालिका 6.28[5]

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिये स्वीकृत बजट

वर्ष	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय
1945-46	3017300	-
1946-47	2691900	-

5. U.C. Dutt, Educational Survey of Uttar Pradesh. P. 234-35

1947-48	3195900	-
1948-49	4228800	-
1949-50	5941100	-
1950-51	2952100	1825000
1951-52	3145700	2331900
1952-53	3614100	2846500
1953-54	3655200	3200000
1954-55	3950500	3849100
1955-56	4283700	4664000
1956-57	4562400	4938400
1957-58	5220500	5190400
1958-59	5177800	5848500

तालिका 6.28 से ज्ञात होता है कि वर्ष 1945-46 में उत्तर प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों के लिये रु० 3017300 का बजट स्वीकृत किया गया लेकिन इसी वर्ष में महाविद्यालयों के लिये अलग से बजट निर्धारित नहीं किया गया। वर्ष 1946-47 में 5 विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली बजट राशि को घटाकर Rs. 1946-47 में 5 विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली बजट राशि को घटाकर Rs.2691900 कर दिया गया! वर्ष 1949-50 तक महाविद्यालयों को अलग से कोई भी बजट स्वीकृत नहीं किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने से पहले महाविद्यालयों को बजट स्वीकृत नहीं किया गया और इस समय तक सभी महाविद्यालय अपने निजी संसाधनों द्वारा अपने व्यय को पूरा करते रहे।

वर्ष 1950-51 में विश्वविद्यालयों को रु० 2952100 का बजट स्वीकृत किया गया जबकि महाविद्यालयों को पहली बार रु० 1825000 का बजट स्वीकृत किया गया। इसी समय में निजी प्रयत्नों एवं सरकारी सहयोग द्वारा महाविद्यालयों का विकास होने लगा लेकिन विश्वविद्यालय अभी भी पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में है। और अपने वित्तीय संसाधनों के लिये राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर निर्भर है।

सप्तम अध्याय

सप्तम अध्याय

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की उच्च शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास किया गया। इसके लिये शोधकर्ता ने विभिन्न श्रोतों से आंकड़ों का एकत्रीकरण करके वास्तविक स्थिति जानने का प्रयांस किया है तथा जो महत्वपूर्ण तथ्य इस शोध से सामने आये है वह निम्न प्रकार हैः-

सांख्यिकीय निष्कर्ष : इसके अर्न्तगत निम्नलिखित बिन्दुओं पर आंकड़े प्राप्त किये गये थे जिनसे निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुये।

1. **विश्वविद्यालयों की संख्या :** ब्रिटिश काल में प्रदेश में 5 विश्वविद्यालय सन् 1887 से 1927 के मध्य स्थापित किये गये। इसके विपरीत ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात सन् 1949 से 1989 के मध्य 40 वर्षो के अन्तराल में 13 नये विश्वविद्यालय स्थापित किये गये। संख्यात्मक आधार पर विश्वविद्यालयों में 3.25 गुना वृद्धि हुई है।

ब्रिटिश शासन में एक भी कृषि विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया। ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात प्रदेश में 3 नये कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये गये।

ब्रिटिश शासन काल में संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में एक भी संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया जबकि ब्रिटिश शासन काल की समाप्ति के 8 वर्ष पश्चात् सन् 1956 में प्रदेश में संस्कृत भाषा एवं साहित्य के विकास के लिये सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।

2. **संस्थानों की संख्या :** ब्रिटिश शासन काल में 2 संस्थान उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य में संलग्न थे जबकि ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात प्रदेश में 5 नये संस्थान स्थापित किये गये है। जो उच्च शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में एवं अनुसंधान कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर रहे है। सांख्किीय आधार पर इनकी संख्याओं में 2.5 गुना वृद्धि हुई है।

3. **महाविद्यालयों की संख्या :** सन् 1823 से सन् 1947 के मध्य 124 वर्षो के ब्रिटिश शासन काल में मात्र 38 महाविद्यालय स्थापित किये गये। इसके विपरीत ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात सन् 1948 से सन् 1990 तक 42 वर्षो के अन्तराल में 403 महाविद्यालय स्थापित किये गये।

तुलनात्मक आधार पर महाविद्यालयों की संख्या में 10.6 गुना वृद्धि हुई है।

4. **मेडिकल कालेजों की संख्या :** ब्रिटिश शासन काल में प्रदेश में 2 मेडिकल कालेज चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न थे। ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात प्रदेश में 6 नये मेडिकल कालेज स्थापित किये गये। ब्रिटिश काल की अपेक्षा इनकी संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई।

5. **यूनानी मेडिकल कालेजों की संख्या :** ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात प्रदेश में यूनानी चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में 3 यूनानी मेडिकल कालेज स्थापित किये गये।

6. **आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों की संख्या :** ब्रिटिश शासन काल में प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में 2 मेडिकल कालेज कार्यरत थे। ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात प्रदेश में 6 नये आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज स्थापित किये गये। संख्यात्मक आधार पर इनमें 3 गुना वृद्धि हुई।

7. **होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों की संख्या :** ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात प्रदेश में होम्यापैथी चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में 10 मेडिकल कालेज स्थापित किये गये।

8. **इंजीनियरिंग कालेज व तकनीकी संस्थानों की संख्या :** ब्रिटिश शासन काल में प्रदेश में 4 इंजीनियरिंग कालेज व तकनीकी संस्थान कार्यरत थे ब्रिटिश शासन काल के पश्चात 7 नये इंजीनियरिंग कालेज व तकनीकी संस्थान और स्थापित हो गये, सांख्किीय आधार पर इनकी संख्या में 1.75 गुना वृद्धि हुई है।

9. **मैनेजमैंट इंस्टीट्यूट की संख्या :** ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात प्रदेश में 6 मैनेजमैंट इंस्टीट्यूट स्थापित किये गये जो प्रबन्धकीय शिक्षा के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नाकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रदान कर रहे है।

10. **कृषि संस्थान एवं महाविद्यालयों की संख्या :** ब्रिटिश शासन काल में 4 संस्थान एवं महाविद्यालय कृषि विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत थे, ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात प्रदेश में 21 नये संस्थान एवं महाविद्यालय स्थापित किये गये जो कृषि विज्ञान के शिक्षण कार्य में संलग्न है। ब्रिटिश काल की अपेक्षा इनकी संख्या में 5.25 गुना वृद्धि हुई है।

11. **शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या :** ब्रिटिश शासन काल में प्रदेश में 14

महाविद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण (बी. एड. स्तरीय) प्रदान कर रहे थे। ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात सन् 1948 से सन् 1978 तक 30 वर्षो के अन्तराल में 76 महाविद्यालयों में (बी. एड. एवं एम. एड. स्तरीय) शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश काल की अपेक्षा इनकी संख्या में 5.4 गुना वृद्धि हुई।

12. विधि महाविद्यालयों की संख्या : ब्रिटिश शासन काल में 11 महाविद्यालय विधि शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत थे। ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात प्रदेश में 21 नये ऐसे महाविद्यालय स्थापित किये गये जो विधि शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे है। सांख्किीय आधार पर इनकी संख्या में 1.9 गुना वृद्धि हुई है।

13. विद्यार्थियों का नामांकन : वर्ष 1947-48 में विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं की संख्या क्रमशः 9465 व 809 थी। वर्ष 1990-91 में यह संख्या बढ़कर क्रमशः 145580 व 55411 हो गई। ब्रिटिश काल के पश्चात छात्रों की संख्या में 15.38 गुना व छात्राओं की संख्या में 68.49 गुना वृद्धि हुई।

वर्ष 1947-48 में महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं की संख्या क्रमशः 21487 व 1928 थी। वर्ष 1990-91 में यह संख्या बढ़कर क्रमशः 614212 व 182311 हो गई। ब्रिटिश शासन काल की समाप्ति के पश्चात छात्रों की संख्या में 28.58 गुना व छात्राओं की संख्या में 94.55 गुना वृद्धि हुई।

14. अध्यापकों की संख्या : वर्ष 1949-50 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन पुरूष शिक्षकों एवं महिला शिक्षकों की संख्या क्रमशः 958 व 77 थी। वर्ष 1990-91 में यह संख्या बढ़कर क्रमशः 6789 व 1261 हो गई। वर्ष 1949-50 की अपेक्षा पुरूष शिक्षकों की संख्या में 7.08 गुना व महिला शिक्षकों की संख्या में 16.37 गुना वृद्धि हुई।

वर्ष 1949-50 में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन पुरूष शिक्षकों की संख्या 1274 व महिला शिक्षकों की संख्या 156 थी। वर्ष 1990-91 में यह संख्या बढ़कर क्रमशः 11515 व 3011 हो गई। वर्ष 1949-50 की अपेक्षा पुरूष शिक्षकों की संख्या में 9.03 गुना व महिला शिक्षकों की संख्या में 19.30 गुना वृद्धि हुई।

मूल्यांकन : स्वतंत्रता के पश्चात संविधान में किये गये प्रावधान, राजनेताओं द्वारा शिक्षा को विकास प्रदान किये जाने हेतु किये गये वादे तथा समय समय पर गठित किये गये आयोग, उनके द्वारा प्रस्तावित नीतियां सबकी सब बेकार ही साबित हुई है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा सबसे जटिल दौर से गुजर रही है।

स्वतंत्रता के पश्चात एक ओर जहाँ देश में विश्वविद्यालय शिक्षा को नई दिशा प्रदान करने के लिये राधाकृष्णन कमीशन (1949) द्वारा की गई संस्तुतियों को आधार बनाया गया वहीं दूसरी ओा मुदालियर कमीशन (1952) द्वारा माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिये की गई संस्तुतियों को भी ध्यान में रखा गया परन्तु शिक्षा आयोग (1964-66) में पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित किये जाने की नीति तथा 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू किये जाने की सम्भावना के परिणामस्वरूप देश में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में ठहराव आ गया तथा शिक्षकों और छात्रों के बीच शैक्षिक समन्वय न हो पाने के कारण शैक्षिक गति में ठहराव सा आ गया। कोठारी आयोग द्वारा संस्तुत की गई यह संरचना उत्तर प्रदेश में भी लागू न की जा सकी तथा विश्वविद्यालय शिक्षा ने अलगाव की स्थिति पैदा हो गई।

1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा पद्धति को पूरी तरह बदलकर नया रूप देने की कल्पना की गई थी जिससे कि वह लोगों के जीवन से अधिक सम्बद्ध हो सके, वह बढ़े हुये शैक्षिक अवसर प्रदान कर सके, सभी स्तरों पर शिक्षण की गुणवत्ता, स्तर में सुधार के लिये लगातार गहन प्रयत्न शुरू किये जा सके, विज्ञान और तकनीकी के विकास पर बल दिया जा सके और नैतिक व सामाजिक मूल्यों का पोषण किया जा सके। शिक्षा नीति का लक्ष्य एक ऐसा वातावरण बनाना था जिससे कि ऐसे चरित्रवान योग्य युवा पुरुष और स्त्री नागरिकों की पीढ़ी तैयार की जा सकें, जो राष्ट्रीय सेवा और विकास के प्रतिवचनवद्ध हो। यह सुस्पष्ट है कि हम इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके है।

नई शिक्षा नीति - 1986 में एक बार पुनः कोठारी आयोग की संरचना स्वीकार कर इसे इक्कीसवीं सदी हेतु तैयारी किये जाने की संज्ञा दी गई तथा स्नातक स्तर की शिक्षा (बी.ए., बी.ए.सी., बी.काम.) को 2 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष तक बढ़ाये जाने की व्यवस्था की गई।

विभिन्न वर्षों में उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा नीति का

क्रियान्वयन, पाठ्यक्रम का निर्माण तथा शिक्षण की विधियों का परिपक्व न हो पाना इस बात का घोतक है कि सरकार ने इस स्तर की शिक्षा हेतु कोई उचित प्रयास करना उचित नहीं समझा जिसका परिणाम यह हुआ कि छात्रों की संख्या, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों की संख्या में संख्यात्मक वृद्धि तो देखने को मिली परन्तु गुणात्मक वृद्धि का पूरा अभाव रहा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विश्वविद्यालयों की संख्या में यद्यपि पर्याप्त वृद्धि हुई है परन्तु देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले इस प्रदेश में समुचित उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना वर्तमान विश्वविद्यालयों की क्षमता के बाहर है। सीमित वित्तीय साधनों को देखते हुये राज्य सरकार द्वारा नये विश्वविद्यालयों की स्थापना किया जाना निकट भविष्य में प्रतीत नहीं होता है।

आज उत्तर प्रदेश की सरकार अपने युवाओं को विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान कराने में अक्षम प्रतीत होती है क्योंकि जहाँ एक और इस स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में भारी गिरावट आयी है वहीं दूसरी ओर इसकी विश्वसनीयता भी संदिग्ध हो गई है। आज का विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, चाहे उसने स्वर्णपदक ही क्यों प्राप्त न किया हो, नौकरी पा जायेगा इसकी कोई गांरटी नहीं है। उसे उच्च कक्षाओं में प्रवेश हेतु पुनः प्रवेश परीक्षा देने के लिये बाध्य होना पड़ता है। और स्थिति इतनी अधिक गम्भीर है कि तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रवेश पा लेता है।

आज का सम्पूर्ण शिक्षा जगत राजनीति से ओतप्रोत है। सरकारें आती है, नीतियां बनायी जाती है। जब तक लागू करने की बारी आती है तब तक सरकार ही बदल जाती है और शुरू हो जाती है पुनः नीति निर्धारण की प्रक्रिया।

अभिभावक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई के आधार पर कम, जोड़तोड़, धन और राजनीतिक पैतरेबाजी से अधिक, परीक्षा में अच्छे अंको में उत्तीण कराने में लगा रहता है जिसके कारण विद्यार्थी विषय शून्य रहते हुये भी अच्छे अंकों में उत्तीर्ण होने पर भी अच्छी नौकरियां नहीं पाते है।

विश्वविद्यालयों में अब न तो कोई प्रवेश की अन्तिम तिथि निश्चत होती है और न परीक्षाएं सम्पन्न होने की। प्रदेश के बड़े-बड़े विश्वविद्यालय जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, आदि में भी प्रवेश तथा परीक्षाएं वर्ष भर चलते रहते है। वैसे प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालयों में प्रवेश तथा परीक्षा हेतु

वार्षिक कलेन्डर बनाये जाते है परन्तु वह सब धरे के धरे रह जाते है।

महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों ने अपने तरीकों से विद्वान इंजीनियर, तकनीशियन, डाक्टर व उच्च कोटि के प्रबन्ध कर्मियों को तैयार किया है जिनकी तुलना विश्व के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किये गये अच्छे कर्मियों से की जा सकती है किन्तु यह भी सच है कि इस कोटि के थोड़े से लोगों की तुलना में काफी संख्या में उच्च शिक्षा की संस्थाओं से ऐसे लोग निकलते है जिनके पास थोड़ा बहुत पुस्तकीय ज्ञान और एक डिग्री होती है लेकिन उनमें स्वतः अध्ययन की बहुत कम क्षमता, घटिया भाषा तथा सीमित विश्वदृष्टिकोण होता है तथा उनमें किसी प्रकार की सामाजिक अथवा राष्ट्रीय जिम्मेदारी की प्रवृत्ति का पूर्ण आभाव रहता है।

वर्तमान परीक्षा प्रणाली न केवल छात्रों के भाग्य का निर्णय करती है बल्कि शिक्षा के सभी स्तरों पर उसकी विषय वस्तु और गुणवत्ता का निर्धारण करती है। परीक्षा प्रणाली रटे रटाये अध्ययन तथा समरण शक्ति के आधार पर परीक्षार्थी के मूल्यांकन का एक ऐसा वातावरण बनाती है जिसमें छात्र वर्ष का अधिकांश भाग व्यर्थ व्यतीत करतें है तथा परीक्षा के समय में परिश्रम करते हैं। इसीलिये पढ़ाई में निरन्तर रूप से न लगे रहने का परिणाम यह होता है कि परीक्षा काल में मस्तिष्क पर असहनीय दबाब पढ़ता है जिससे परीक्षाओं का बहिष्कार, प्रश्नपत्रों का पहले पता लगाना, सामूहिक रूप से नकल करना, मूल्यांकन कर्ताओं को रिश्वत देना तथा अन्य अनैतिक साधनों का प्रयोग होता है परिणामस्वरूप सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में जनता तथा नियोकताओं के लिये उनकी डिग्रियां व डिप्लोमा सामान्य तौर पर विश्वसनीय सिद्ध नहीं होते तथा इससे उच्च शिक्षा की पूरी प्रक्रिया विकृत, दिशाहीन तथा निष्क्रिय हो गई है और काफी संख्या में युवक व युवतियां बेरोजगार हो रहे है।

विश्वविद्यालय पद्धति में व्यापक रूप से अनुसंधान कार्य किया जाता है और उसे खर्चीला समझा जाता है लेकिन मुख्य राष्ट्रीय निविष्टियां विश्वविद्यालयों के बाहर प्रयोगशालाओं में लगाई जाती है। इस प्रकार मुख्य कार्य की सुविधाएं नहीं मिल पाती है। इस स्थिति को ठीक करना जरूरी है क्योंकि उच्च कोटि के अनुसंधान कार्य के बिना स्नातकोत्तर शिक्षा की न तो पद्धति और न ही उसकी गुणवत्ता व स्तर में सुधार हो पायेगा! शैक्षिक अनुसंधान तथा विज्ञान के निष्कर्षो का प्रयोग करतें हुये ज्ञान के विस्तार के अनुरूप पाठ्यचर्या में परिर्वतन करने के लिये संगठित कार्य आवश्यक है। वास्तव में कालेज व

विश्वविद्यालय शिक्षा की आलोचना प्रायः इसलिये की जाती है क्योंकि वे अध्यापन पर अत्यधिक जोर देते है जिसमें वर्षो पहले तैयार किये गये पुराने नोटस लिखवाएं जाते हैं।

शिक्षकों और छात्रों के बीच तालमेल और अनौपचारिक सम्पर्क के आभाव में सामूहिक जीवन, सांस्कृतिक कार्यकलाप तथा खेलकूद या तो होते हीं नही है अथवा उनका उपयोग बहुत कम किया जाता है यही कारण है कि कालेजों और विश्वविद्यालयों में अध्यापन एवं अध्ययन करना एक अंशकालीन कार्य से अधिक नहीं है जिसका मुख्य उद्देश्य डिग्री प्रदान करना है।

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिक्षक हो या न हो, पढ़ाई होती हो या न होती हो, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उसे तो बस इतनी चिन्ता करना काफी है कि सम्बन्धित विधायक, संसद सदस्य, मंत्री, मुख्यमंत्री, अथवा किसी राजनैतिक जोड़ तोड़ वाले व्यक्ति के क्षेत्र में कितने महाविद्यालय व विश्वविद्यालय खोल दिये गये है और कितने नये खोले जा सकते है। यदि इस दृष्टि से देखा जाये तो उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर की संस्थाओं की संख्यात्मक वृद्धि पर्याप्त मात्रा में हुई है परन्तु जनसंख्या के अनुपात में यह दर आज भी बहुत कम है।

2 सितम्बर, 1993 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आर. सी. मेहरोत्रा की अध्यक्षता में गठित 'राज्य विश्वविद्यालय सुधार समिति' ने विश्वविद्यालयों में गुणात्मक सुधार के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये है। यथः विश्वविद्यालयों में अपराधिक गति विधियों को रोकने के लिये पुलिस अधीक्षक स्तर के एक आई. पी. एस. अधिकारी की नियुक्ति, राजिस्ट्रार पद पर प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अफसरों की नियुक्ति, छात्र संघ के समाप्त किये जाने, अपराधिक मुकदमों में फंसे छात्रों का प्रवेश न करने, शिक्षकों को 'स्वमूल्यांकन करने तथा कर्मचारियों के लिये अनेक प्रकार की सुविधाओं की सिफारिश की है, इसके अतिरिक्त समिति ने शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने, वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ बनाने, सत्र नियमितीकरण, व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने, परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा परिसर में शॉंति एवं सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अपने सुझाव दिये है।

कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर यदि राज्य सरकार द्वारा समुचित ध्यान दिया जाये तो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में अवश्य ही उल्लेखनीय सुधार सम्भव हो सकता है।

1. नियमित रूप से विद्यार्थियों की कक्षा में उपस्थिति अनिवार्य की जानी चाहिये। 75% से कम

उपस्थिति होने पर किसी भी दशा में उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

2. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया जुलाई माह के स्थान पर मार्च/अप्रैल में ही प्रारम्भ कर दी जानी चाहिये, ताकि जुलाई माह में सत्र प्रत्येक दशा में प्रारम्भ हो जाये।
3. परीक्षाएं समय पर सम्पन्न होनी चाहिये इसके लिये कम से कम 3 माह पूर्व परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जाना चाहिये।
4. परीक्षाओं में मूल्यांकन हेतु योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिये सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों से ही प्रश्न पत्र निर्माण एवं मूल्यांकन कार्य कराया जाना चाहिये।
5. विश्वविद्यालय शिक्षकों को अच्छे वेतनमान के साथ साथ अच्छे पुस्तकालय, रहने के आवास, आदि की व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य सरकार को लेना चाहिये।
6. विश्वविद्यालय शिक्षकों में नैतिक बल उत्पन्न करने हेतु उन्हें अच्छे कार्यो के लिये पुरुष्कृत किया जाना चाहिये।
7. राष्ट्र की मुख्य धारा में रहने और जागरूपता उत्पन्न करने के लिये नागरिकता, संविधान के सिद्धान्तों और लोकतन्त्रीय समाजवादी समाज के स्वरूप को पाठ्यक्रमों में स्थान दिया जाना चाहिये।

भावी अनुसंधान के लिये सुझाव

उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अत्यन्त विशाल है और भारत का सर्वाधिक आबादी वाला यह प्रदेश बेकारी, बेरोजगारी अशिक्षा, कुशिक्षा, अराजकता, अनुशासनहीनता एवं कामचोरी आदि-आदि विपुल समस्याओं से कराह रहा है। इसमें जब हम शिक्षा की ओर विहंगम दृष्टि डालते हैं तो पाते है कि उच्च शिक्षा का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों की अपनी तरह-तरह की समस्याएं है। इन समस्याओं की जानकारी और उनका गहन अध्ययन करके किसी निश्चित और विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुँचना तथा उसके समाधान के लिये सुझाव देना एक बड़ा कार्य है। प्रस्तुत शोध से प्राप्त निष्कर्षो से स्पष्ट हो गया है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी और गहन शोध अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिये निम्न शीर्षकों पर भी शोध कार्य किया जा सकता है :

1. उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों की उच्च शिक्षा के विकास का तुलनात्मक अध्ययन
2. उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा की वित्त व्यवस्था का आलोचनात्मक अध्ययन
3. उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा का विकास एवं समस्याओं का आलोचनात्मक अध्ययन।
4. उत्तर प्रदेश में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन।
5. उत्तर प्रदेश में स्थित केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालयों का तुलनात्मक अध्ययन।
6. उत्तर प्रदेश में स्थित शासकीय महाविद्यालयों एवं अशासकीय महाविद्यालयों के विकास का आलोचनात्मक अध्ययन।
7. उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र अंसतोष-एक समस्या।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1.	घोष, डी. के.	यूनीवर्सिटी सिस्टम इन इण्डिया जबलपुर, राहुल पब्लिकेशन, 1983.
2.	श्रीवास्तव, आनन्द पी.	पेथोलोजी ऑफ हायर एजूकेशन कानपुर, रिप्रिन्ट पब्लिशर्स (इण्डिया) 1979
3.	दत्त यू. सी.	एजूकेशनल सर्वे ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, दि इण्डियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, 1960
4.	भटनागर, सुरेश	कोठारी कमीशन, मेरठ, लायल बुक डिपो, 1975-76
5.	पाठक, पी. डी.	भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1976.
6.	प्रो. मदन मोहन व डॉ सारस्वत मालती	भारतीय शिक्षा का इतिहास और समस्याएं इलाहाबाद, कैलाश प्रकाशन, 1982
7.	डॉ. रस्तोगी, कृष्ण गोपाल	भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएं मेरठ, रस्तोगी पब्लिकेशन, 1985-86
8.	गुप्त, रामबाबू	भारतीय शिक्षा और उनकी समस्याएं कानपुर, सामाजिक विज्ञान प्रकाशन, 1982-83
9.	डॉ. अदावल, सुबोध उनियाल, माघवेन्द्र	भारतीय शिक्षा की समस्याएं तथा प्रवृत्तियां लखनऊ, उ0प्र0 हिन्दी संस्थान, 1982
10.	अग्रवाल, जे. सी.	नई शिक्षा नीति, दिल्ली, प्रभात प्रकाशन, 1986
11.	पाठक, पी. डी. व त्यागी जी. एस. डी.	भारतीय शिक्षा के आयोग एवं समितियां आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर, 1982
12.	ओड़, एल. के.	शिक्षा के नूतन आयाम जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ आकादमी, 1990

13. डॉ. कुदेशिया, उमेश चन्द्र — शिक्षा प्रशासन,
आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1990-91

14. मल्होत्रा पी. एल. व अन्य — भारत में विद्यालयी शिक्षा वर्तमान स्थिति और भावी आवश्यकताएं
नई दिल्ली, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 1986

15. सारस्वत, एम. — भारतीय शिक्षा का विकास,
इलाहाबाद, कैलाश प्रकाशन, 1982

16. अल्टेकर, ए. एस. — एजूकेशन इन एनशिएन्ट इन्डिया
वाराणसी, नन्द किशोर एण्ड संस

17. शर्मा, ओम प्रकाश — एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजूकेशन बोर्ड इन इन्डिया
नई दिल्ली, आशीष पब्लिशिंग हाउस, 1991

18. आइवर मोरिश — एजूकेशन सिन्स 1800
लन्दन, जार्ज एलिन एण्ड अनविन लिमिटेड, 1976

19. फ्रेन्क पेरिपोन्ट ग्रेव्स — हिस्ट्री ऑफ एजूकेशन विफोर द मिडिल एजेज I वाल्यूम
देहरादून, रिशाभ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स 1993.

20. फ्रेन्क पेरिपोन्ट ग्रेव्स — हिस्ट्री आफ एजूकेशन इन गॉडर्न टाइम्स, II वाल्यूम
देहरादून, रिशाभ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स, 1993.

21. गुप्ता, जे. एस., श्रीवास्तव एच0डी0 व सिंह, टी0 — भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्या
तिलक नगर, कानपुर, अलका प्रकाशन

22. गुप्ता, रामबाबू — भारतीय शिक्षा का इतिहास
कानपुर, सामाजिक विज्ञान प्रकाशन, 1974,

23. चौबे, सरयू प्रसाद — भारतीय शिक्षा का इतिहास
इलाहाबाद, राम नारायण लाल, 1959,

24. शर्मा. आर. ए. — शिक्षा अनुसंधान,
मेरठ, आर. लाल बुक डिपो, 1992-93

25. सुखिया, एम. पी. — शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व
मेहरोत्रा, पी. वी. — आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर

26. मलैया, के. सी. व — शिक्षा प्रशासन एवं पर्यवेक्षण
मलैया डॉ विधावती — भोपाल, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

27. गुप्ता, वी. आर. — भारतीय शिक्षा का इतिहास (तत्कालीन समस्याओं सहित),
मेरठ, रस्तोगी एण्ड कम्पनी

28. डॉ भाटिया, एस. के. — डायरेक्टरी ऑफ यूनीवर्सिटीज एण्ड कालेज ऑफ इन्डिया
नई दिल्ली, रिलायंस पब्लिशिंग हाउस, 1995

29. ओड़. एल. के. — द रोल ऑफ गवर्मेंट इन एजूकेशन
न्यू देहली, मैनेजर आफ पब्लिकेशन, 1962

30. कौल, जे. एन. — हायर एजूकेशन इन इन्डिया, शिमला,
इन्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स स्टडीज, 1974

31. कपूर, के. सी. — भारतीय शिक्षा का इतिहास,
आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1982

32. दयाल, भगवान — द डबलपमेंट ऑफ मार्डन इन्डियन एजूकेशन
न्यू देहली, गुड पब्लिकेशन, 1955

33. चौबे, एस. पी. — हमारी शिक्षा समस्याएं,
आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर, 1989

34. जायसवाल, सीताराम — भारतीय शिक्षा की समस्याएं,
लखनऊ, प्रकाशन केन्द्र, 1980

35. जौहरी, वी. पी. — भारतीय शिक्षा का इतिहास,
आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1972

36. नायर, जे. बी. — द रोल ऑफ गवर्मेंट इन एजूकेशन
न्यू देहली, मैनेजर पब्लिकेशन्स, 1962

37. पाण्डे, रामशकल — राष्ट्रीय शिक्षा,
आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1987

38. बासू, ए. एन. — यूनीवर्सिटी एजूकेशन इन इन्डिया
कलकत्ता, बुक इम्पोरियम, 1944

39. भारद्वाज, दिनेश चन्द्र — भारतीय शिक्षा का इतिहास,
आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1968

40. मुकर्जी, एस. एन. — एजूकेशन इन इन्डिया टूडे एन्ड टूमारो
बड़ौदरा, आचार्य बुक डिपो, 1976

41. मुकर्जी, आर. के. — एन्शियेन्ट इन्डियन एजूकेशन,
बाम्बे, मैकमिलन, 1947

42. सिकयूरिया, टी. एन. — दि एजूकेशन ऑफ इण्डिया,
बाम्बे, आक्सफोर्ड पब्लिकेशन, 1952

43. सेन, एन. वी. — प्रोग्रेस ऑफ एजूकेशन इन फ्री इन्डिया,
बाम्बे, आक्सफोर्ड पब्लिकेशन, 1941

44. सेन, जे. एम. — हिस्ट्री ऑफ एजूकेशन इन इन्डिया
कलकत्ता, कलकत्ता बुक डिपो, 1943

45. सिंह, रामपाल — भारतीय शिक्षा की आधुनिक समस्याएं
आगरा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, 1980

46. शर्मा, बेदराम, — मुदालियर कमीशन - 1953
अलीगढ़, चन्द्र प्रकशन, 1963

47. श्रीमाली, के. एल. — एजूकेशन इन चेन्जिंग इन्डिया
बाम्बे, एशिया पब्लिकेशन, 1965

48. हैग्रटी, डब्लयू. जे. — हायर एन्ड प्रोफेशनल एजूकेशन इन इन्डिया
वाशिंगटन, यू. एस. डिपार्टमेंट आफ वेलफेयर, 1969

49. डॉ. कपिल, एच. के. — अनुसंधान विधियाँ (व्यवहार परक विज्ञानों में)
आगरा, हर प्रसाद मार्गव, 1984

50. डॉ राय, पारसनाथ — अनुसंधान-परिचय,
आगरा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, 1985

भारत सरकार के प्रकाशन

(मैनेजर आफ पब्लिकेशन, नई दिल्ली)

51. रिपोर्ट ऑफ यूनीवर्सिटी एजूकेशन कमीशन, 1954

52. इन्डियन यूनीवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, 1958

53. फ्यूचर आफ एजूकेशन इन इन्डिया, 1958

54. एजूकेशन इन यूनीवर्सिटीज इन इन्डिया, 1962

55. नेशनल पोलिशी आफ एजूकेशन, 1968

56. नेशनल पोलिशी आन एजूकेशन, 1986

57. एजूकेशन आफ ए चेलेन्ज

अन्य प्रकाशन

58. एजूकेशनल इनवेस्टीगेशन इन इन्डियन यूनीवर्सिटीज, 1939-1961.

एन. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली, 1966

59. दि इन्डियन ईयर बुक आफ एजूकेशन, फर्स्ट ईयर बुक,

एन. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली, 1961

60. द थर्ड इन्डियन ईयर बुक आफ एजूकेशन

एन. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली, 1967

61. शिक्षा आयोग (1964-66) प्रतिवेदन,

एन. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली, 1970

62. जनरल आफ हायर एजूकेशन

एन. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली, मार्च 1981

63. जनरल आफ इन्डियन एजूकेशन

एन. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली, नवम्बर, 1983 जनवरी, 1984

64. इन्डियन एजूकेशनल रिव्यू

एन. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली, नवम्बर 1983, जनवरी, 1984, जनवरी 1985, जनवरी 1989

65. भारतीय आधुनिक शिक्षा,

एन. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली, जनवरी 1984, जनवरी 1985, फरवरी 1988

66. उत्तर प्रदेश वार्षिकी (1986-87) सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश; लखनऊ 1988

67. उत्तर प्रदेश एनुअल (1987-88) सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ, 1988

68. उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी,

एस. सी. ई. आर. टी. लखनऊ, 1994-95

69. जनरल आफ हायर एजूकेशन, यू. जी. सी. नई दिल्ली, स्प्रिंग, 1979, 1983,

जनवरी 1989

70. शिक्षा की प्रगति - 1988-89, 1994-95, शिक्षा निदेशालय, उ. प्र. इलाहाबाद

71. यूनीवर्सिटी डवलपमेंट इन इण्डिया, पार्ट II बेसिक फेक्टस एन्ड फिगर्स 1982-83,

यू. जी. सी. नई दिल्ली, 1990

परिशिष्ट

APPENDIX - I

Macaulay's Minute

2nd February, 1835

"As it seems to be the opinion of some of the gentlemen who compose the committee of Public Instruction, that the course which they have hitherto pursued was strictly prescribed by the British Parliament in 1813, and as, if that opinion be correct. a Legislative Act will be necessary to warrant a change. I have thought it right to refrain from taking any part in the preparation of the adverse statements which are now before us, and to reserve that I had to say on the subject till it should come before me as a member of the council of India".

"It does not appear to me that the Act of Parliament can, by any art of construction, be made to bear the meaning which has been assigned to it. It contains nothing about the Particular Language or Sciences which are to be studied. A sum it set apart. 'For the revival and promotion of litrature and the encouragement of the learned natives of India, and for the introduction and promotion of a Knowledge of the sciences among the inhabitants of the British territories'. It is argued, or rather taken for granted, that by literature the parliament can have given only Arabic and Sanskrit litrature, that they never would have given the honourable appellation of a learned native to a native who was familiar with the poetry of Milton, the metaphysics of Locke, and the physics of Newton, but that they meant to designate by that name only such persons as might have studied in the sacred books of the Hindus, all the uses of cusagrass, and all the mysteries of absorption into the Deity. This does not apper to be a very satisfactory interpretation. To take a parallel case, Suppose that the Pacha of Egypt, a country one superior in Knowledge to the nations of Europe but now sunk for below them, were to appropriate a sum for the purpose of 'reviving and promoting literature, and encouraging learned nations of Egypt, would anybody infer that

he meant the youth of his pathalic to give years to the study of hieroglyphics, to search into all the doctrines disguised under the fable of Osiris and to ascertain with all possible accuracy the ritual with which cats and onions were anciently adored? Would he by justly charged with inconsistency, if, instead of employing his young subjects in deciphering obelisks, he were to order them to be instructed in the English and French languages, and in all the Sciences to which those languages are the chief key ?"

"The words on which the supporters of the old system realy do not bear them out, and other words follow which seem to be quite decisive on the other side. This lac of rupees is set apart, not only for reviving literature in India. The phrase on which their whole interpretation is founded, but also for 'the introduction and promotion of Knowledge of the Sciences among the inhabitants of the British Territories,- words which are alone sufficient to authorize all the changes for which I contend."

" If the Council agree in my construction, no legislative Act will be necessary. If they differ from me, I will prepare a short Act rescinding that clause of the Charter of 1813 from which the difficulty arises".

" The argument which I have been considering affects only the form of proceeding. But the admirers of the Oriental sytem of education have used another argument, which if we admit it to be valid, is decisive against all change. They conceive that the public faith is pledged to the present system, and that to alter the appropriation of any of the funds which have hither to been spent in encourging the study of Arabic and Sanskrit would be downright spoliation . It is not easy to understand by what process of reasoning they can have arrived at this conclusion. The grants which are made from the public purse for the encouragement of litreature differed in no respect from the grants which are made from the same purse for other objects of real or supposed utility. We found a sanatorium on a spot which we suppose

to be healthy. Do we thereby pledge ourselves to keep a sanatorium there, if the result should not answer our expectation ? We commence the erection of a pier. It is a violation of the public faith to stop the works, if we afterwards see reason to believe that the building will be useless ? The rights of property are undoubtedly sacred. But nothing endangers those rights so much as the practice, now unhappily too common of attributing them to things to which they do not belong. Those who would impart to abuses the sanctity of proprety are in truth imparting to the institution of property the unpopularity, and the fragility of abuses. If the Government has given to any person a formal assurance, nay, if the government has excited in any person's mind a reasonable expection that he shall receive a certain income as a teacher or a learner of Sanskrit or Arabic, I would respect that person's pecuniary interests - I would rather err on the side of liberality to individuals than suffer the public faith to be called in question. But to talk of a Government pledging itself to teach certain languages and certain sciences, though those languages may become useless, though those Sciences may be expalded, seems to me quite un-meaning. There is not a single word in any public instructions from which it can be inferred that the Indian Government ever intended to give any pledge on this subject or ever considered the destination of these funds as unalterly fixed. But had it been otherwise, I should have denied the competence of our predecessors to build us by any pledge on such a subject. Suppose that a Government had in the last century enacted in the most solemn manner that all its subjects should, to the end of time, be inoculated for the small-pox, would that Government be bound to persist in the practice after Jenner's discoveries ? These promises of which no body claims the performance, and from which no body can grant a release these vested rights, which vest in no body, this property without proprietors, this robbery, which makes nobody poorer may be comprehended by persons of higher faculties than mine, I consider this plea nearly as a set form of words, regularly used both in england and in India, in

defence of every abuse for which no other plea can be set up".

" I hold this lac of rupess to be quite at the disposal of the Governer General in council for the purpose of promoting learing in India, in any way which may be thought most advisable. I hold his lordship to be quite as free to direct that it shall no longer be employed in encouraging Arabic and Sanskrit, as he is to direct that the reward for killing tigers in Mysore shall be diminished, or that no more public money shall be expended on the chanting at the cathedral".

"We now come to the gist of the matter. We have a fund to be employed as Government shall direct for the intellectual improvement of the people of this country. The simple question is, what is the most useful way of empolying it ?"

"All parties seem to be agreed on one point, that the dialects commonly spoken among the natives of this part of India curtain neither literary nor scientific information, and are, moreover, the claims of our own language it is hardly necessary to recapitulate. It stands pre-eminent even among the languages of the West. It abounds with works of imagination, not inferior to the noblest which Greece has bequeathed to us, with models of every species of eloquence : with historical compositions, which considered merely as narrations, have seldom been surpassed, and which considered as vehicles of ethical and political instruction, have never been equalled, with just and lively representations on metaphysics, morals, Government jerisprudence and trade, with full and correct information respecting every experimental science which tends to preserve the health, to increase the comfort, or to expand the intellect of man. whoever knows that language, has ready access to all the vast intellectual wealth, which all the wisest nations of the earth have created and hoarded in the literature now extant in that language is of far greater value than all the literature which three hundred years ago was extent in all the languages of the world together, Nor is this all. In India . English is the language spoken by the ruling class, It is spoken

by the higher class of natives at the seats of Government. It is likely to become the language of commerce throughout the seas of the East. It is the language of two great Europen communities which are rising, The one in the South of Africa, the other in Australasia, communities which are every year becoming more important, and more closely connected with out Indian empire. whether we look at the intrinsic value of our literature or at the particular situation of this country, we shall see the strongest reason to think that, of all foreign tongues, the English tongue is that which would be the most useful to our native subjests".

" The question now before us is simply whether, when it is in our power to teach this languages, we shall teach language in which, by universal confession, there are no books on any subject which deserve to be compared to our own, whether, when we can teach European Science, we shall teach system which, by universal confession, whenever we can patronise sound philosophy and true History, we shall countenance, at the public expense, medical doctrines which would disgrace an english farries-Astronomy, which would move laughter in girs at an English boarding school, History, abounding with kings thirty feet high, and reigns thirty thousand years long-and Geography, made up of seats of treacle and seas of butter".

" We are not without experience to guide us. History furnishes, serveral analogous cases, and they all teach the same lesson. There are in modern times, to go no further, two memorable instances of a great impulse given to the mind of a whole society-of prejudices overthrown, of Knowledge diffused of taste purified, of arts and sciences planted in countries which had recently, been ignorarnt and barbarous".

The first instance to which I refer is the great rival of letters among the western nations at the close of the fifteenth and the beginning of the sixteenth century. At the time almost everything that was worth reading was contained in writings

of the ancient Greeks and Romans. Had our ancestors acted as the Committee of public instruction has hither to acted, had they neglected the language of cicero and Tacitus,. had they confined their attention to the old dialects of our own islands, had they printed nothing and taught nothing at the universities but chronicles in Anglo-Saxon and Romances in Norman-French, wauld England have been what she now is? what the Greek and Latin were to the Contemporaries of more and Ascham, our tongue is to the people of india,. The literature of England is now more valuable than that of Classical antiquity. I doubt whether the sanskrit literature be as valuable as that of our Saxon and norman progenitors. In some departments, in History, for example, I am certain that it is much less so.

" Another instance may be said to be still before our eyes. with in the last hundred and twenty years, a nations which had previously been in a state as barbarous as that in which our ancestors were before the crusades, has gradually emerged from the ignorance in which it was sunk, and has taken its place among civilized communities-I speak of Russia. There is now in that country a large educated class, abounding with persons fit to serve the state in the highest functions, and in nowise inferior to the most accomplished men who adorn the best circles of Paris and London. There is reason to hope that this vast empire, which in the time of our grand fathers was probably behind the Punjab, may, in the time of our grand children, be pressing close on France and Britain, in the career of inmprovement. And how was this change effected? Not by flattering national prejudices, Not by feeding the mind of the young Muscovite with the old women's stories which his rude fathers had believed, not by filling his head with lying legends about st. Nicholas. not by encouraging. him to study the great question, whether the world was or was not created on the 13th of September. not by calling him a learned native, when he has mastered all these points of knowledge. But by teaching him those foreign languages in which the greatest mass

of information had been laid up, and thus putting all that information with in his reach. The languages of western Europe civilized Russia. I can not doubt that they will do for the Hindoo what they have done for the Tartar.

" And what are the arguments against that course which seems to be alike recommended by theory and by experience? It it said that we ought to secure the cooperation of the native public, and that we can do this only by teaching Sanskrit and Arabic.

" I can by no means admit that, when a nation of high intellectual attainments undertakes to superinted the education of a nation comparatively ignorant. The learners are absolutely to prescribe the course which is to be taken by the teachers. It is not necessary, however to say nothing on this subject. For it is proved by unanswerable evidence that we are not at present securing the cooperation of the natives. It would be bad enough to consult their intellectual taste at the expense of their intellectual health. But we are consulting neither-we are with holding from them the learning for which they are craving. we are forcing on them the mock-learning which they nauseate.

" This is proved by the fact that we are forced to pay our Arabic and Sanskrit students, while those who learn English are willing to pay us. All the declamations in the world about the love and reverence of the natives for their sacred dialects will never, in the mind of any impartial person, out weigh the undisputed fact, that we can not find, in all our vast empire, a single student who will let us teach him those dialects unless we will pay him.

" I have now before me the accounts of the madrassa for one month-the month of December, 1833. The Arabic students appear to have been seventy seven in number. All receive stipends from the public. The whole amount paid to them is above 500 rupees a month. On the other side of the account stands the

following item.

Deduct amount realized from the out students of English for the months of May, June, and July last, 103 rupees.

" I have been told that it is mearly from want of local experience that I am surprised at these phenomena, and that it is not the fashion for students in India to study at their own charges. This only confirms me in my opinion. Nothing is more certain than that it never can in any part of the world be necessary to pay men for doing what they think pleasant and profitable. India is no exception to this rule. The people of India do not require to be paid for eating rice when they are hungry, or for wearing woolen cloth in the cold season. They come nearer to the case before us, The children who learn letters and a little elementary Arithmetic from the village schools master are not paid by him,. He is paid for teaching them. Why them it is necessary to pay people to learn Sanskrit and Arabic? Evidently because it is universally felt that the Sanskrit and Arabic are languages the knowledge of which does not compensate for the trouble of acquiring them. On all such subjects the state of the market is the decisive test.

" Other evidence is not wanting, if other evidence were required. Petition was presented last year to the committee by several ex-students of the sanskrit college, The petitioners stated that they had studied in the college ten or twelve years, that they had made themselves acquainted with Hindoo literature and science, that they had received certificates of profeciency, and what is the fruit of all this? Not with standing such testimonials, they say, " we have but little prospect of bettering our condition with out the kind assistance and your Honourable committee, the indiffer- ence with which we are generally looked upon by our countrymen leaving no hope of encouragement and assistance from them" They there fore, beg that they may be recommended to the Governer General for places under the Government, not places

of high dignity or emolument, but such as may, just enable them to exist. we want means they say, for a decent living, and for our progressive -improvement, which, however, we can not obtain with out the assistance of Government, by whom we have been educated and maintained from childhood, They conclude by representing very pathetically, that they are sure that it was never the intention of Government, after behaving so liberally to them during their education, to abondon them to destitution and neglect .

" I have been used to see petitions to Government for compensation. All these petitions, even the most unreasonable of them, proceeded on the supposition that some loss had been sustained-that some wrong had been inflicted These are surely the first petitioners who ever demaded compensation for having been educated grattis-for having been supported by the public during twelve years, and then sent forth in to the world well-furnished with literature and science. They represent their education as an injury which gives them a claim on the Government for red ress, as an injury for which the stipends paid to them during the infliction were a very inadequate compensation. And I doubt not that they are in the right. They have wasted the best years of life in learning what procures for them neither bread nor respect, Surely we might, with advantage, have saved the cost of making these persons useless and miserable, Surely men may be brought up to be burdens to the public and objects of contempt to their neighbour at a some what smaller charge to the state, But such is our policy. We do not even stand neuter in the contest between truth and falsehood. we are not content to leave the natives to the influence of their own hereditary prejudices. To the natural difficulties which obstruct the progress of sound science in the East we add fresh difficulties of our own making. Baunti and premiums, such as ought not to be given even for the propagation of truth, we lavish on false taste and false philosophy.

" But acting thus we create the very evil which we fear. we are making that opposition which we do not find, what we spend on the Arabic and sanskrit college is not merely a dead loss to the cause of truth. It is bounty-money of helpless place-hunters, but of bigots prompted alike by passion and by interest to raise a cry against every useful scheme of education. If there should be any opposition among the natives to the charge which I recommend, that opposition will be effect of our own system. It will be headed by persons supported by our stipends and trained in our colleges. The longer we persevere in our present course, the more formidable will that opposition be. It will be every year re-inforced by recruits whom we are paying. From the native society left to itsself we have no difficulties to apprehend, All the murmuring will come from that oriental interest which we have, by artificial means, called into being, and nursed into strength.

" There is yet another fact, which is alone sufficient to prove that the feeling of the native public, when left to it self, is not such as the supporters of the old system represent it to be. The committee have thought fit to lay out above a lac of rupees in printing Arabic and sanskrit books. Those books find no purchasers. It is very rarely that a simgle copy is disposed of. Twenty three thousand volumes, most of them folios and quartors, fill the libraries, or rather the lumber-romms of this body. The committee contrive to get rid of some portion of their vast stock of oriental literature by giving books away, But they can not give so fast as they print. About twenty thousand rupees a year are spent in adding fresh masses of waste paper to a hoard which, I should think, is already sufficiently ample. During the last three years, about sixty thousand rupees have been expended in this manner. The sale of Arabic and Sanskrit books during those three years, has not yielded quite one thousand rupees. In the meantime the schools-books society is selling seven or eight thousand English volumes every year, and not only pays the expenses of printing, but realizes a profit of 20

percent of its out lay.

" The fact that the Hindoo Law is to be learned chiefly from Sanskrit books, and the Mohammadan Law from Arabic books, has been much insisted on, but seems not to bear at all on the question. We are commanded by Parliament to ascertain and digest the law of India. The assistance of law commission has been given to us for that purpose. As soon as the code is promulgated, the Shastras and the Hedaya will be useless to a Moonsiff or Sudder Ameen. I hope and trust that before the boys who are now entering at the Madarssa and the Sanskrit college have completed their studies, this graet work will be finished It would be manifestly absurd to educate the rising generation with a view to a state of things which we mean to alter before they reach manhood.

" But there is yet another argument which seems even more untenable. It is said that the Sanskrit and Arabic are the languages in which the sacred books of a hundred millions of people are written, and that they are, on that account, entitled to peculiar, encouragement. Assuredly it is the duty of the British Government in India to be not only tolerant but neutral on all religious questions. But to encourage the study of a literature admitted to be of small intrinsic value only because that literature inculcates the most serious errors on the most important subjects, is a course hardly reconcilable with reason, with morality or even with that very neutrality which ought, as we all agree, to be sacredly preserved. It is confessed that a language is barren of useful knowledge. We are to teach it because it is fruitful of monstrous superstitions. We are to teach false history, false astronomy, false medicine because we find them in company with a false religion. We abstain, and I trust shall always abstain, from giving any public encouragement to those who are engaged in the work of converting natives to Christianity. And while we act thus, can we reasonably and decently bribe men out of the revenues of the state to waste their youth in learning how they are

to purify them selves after touching an ass, or what text of the Vedas they are to repeat to expiate the crime of killing a goat ?

" It is taken for granted by the advocates of oriental learing that no native of this country can possibly attain more than a mere smattering of English, They do not attempt to prove this, but they perpetually insinuate it. They designate the education which their opponents recommend as a more spelling book education. They assume it is undeniable, that the question is between a profound knowledge of Hindoo and Arabian literature and Science on the one side, and a superficial knowledge of the rudiments of English on the other. This is not merely an assumption, but an assumption contrary to all reason and experience we know that foreigners of all nations do learn our language sufficiently to have access to all the most abstruse knowledge which it contains, Sufficiently to relish even the more delicate graces of our most idiomatic writers. There are in this very town natives who are quite competent to discuss political language. I have heard the very question on which I am now writing discussed by native gentlemen with a liberality an an intelligence which would do credit to any member of the committee of public Institution. Indeed, it is unusual to find, even in the literary circles of the continent any foreigner who can express him self in English with so much facility and correctness as we find in many Hindoos. Nobody, I suppose, will contend that English is so difficult to a Hindoo as Greek to an Englishman yet and intelligent English yauth. in a much smaller number of years than our unfortunate pupils pass at the Sanskrit college, becomes able to read, to enjoy, and even to imitate, not unhappily, the compositions of the best Greek authors. Less than half the time which enable them-on English yauth read Herodotus and Sophocles ought to enable a Hindoo to read Hume and Milton.

" To sum up what I have said, I think it clear that we are not fettered by the Act of Parliament of 1813, that we are not fettered by any pledge

expressed or implied, that we are free to empty our funds as we choose, that we ought to empoly them in teaching what is best worth knowing, that English is better worth knowing than Sanskrit or Arabic, that the natives are desirous to be taught English, and are not desirous to be taught Sanskrit or Arabic, that neither as the languages of law nor as the languages of the religion has the Sanskrit and Arabic any peculiar claim to our encouragement, that it is possible to make natives of this country thoroughly good English scholors, and that to this end our efforts ought to be directed.

In one point I fully agree with the gentlemen to whose general views I am opposed. I feel, with them, that it is impossible for us, with our limited means, to attempt to educate the body of the people. We must at present do our best to form a class who may be interpreters bet ween us and the millions which we govern, a class of persons, Indian in blood and colour but english in taste, in opinions morals, and in intellect, To that class we may leave it to refine the vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with terms of science borrowed from the western momenclature, and to render them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of the population.

" I would strictly respect all existing interests. I would deal even generously with all individuals who have had fair reason to expect a pecuniary provision. But I would strike at the root of the bad system which has hither to been fostered by us, I would at once stop the printing of Arabic and Sanskrit books. I would abolish the Madrassa and the Sanskrit college at Culcutta. Benaras is the great seat of Brahmanical learing, Dehli, of Arabic learning. If we retain the Sanskrit college at Benaras and the Mohomedan college at Dehli, we do enough, and much more than enough in my opinion, for the Eastern language. If the Banaras and Dehli colleges should be retained, I would at least recommend that no stipends shall be given to any students who may hereafter repair thither, but that the people shall be left to make their

own choise bet ween the rival system of education with out being bribed by us to learn what they have no desire to know. The funds which would thus be placed at our disposal would enable us to give larger encouragement to the Hindoo college at Culcutta, and to establish in the principal cities throughout the presidencies of Fort William and Agra schools in which the English language might be well and thoroughly taught.

" If the decision of his Lordship in council should be such as I anticipate, I shall enter on the performance of my duties with the greatest zeal and alacrity. If on the other hand, It be the opinion of the Government that the present system ought to remain unchanged, I beg that I may be permitted to retire from the chair of the committee. I feel that I could not be of the smallest use there-I feel, also, that I should be lending my countenance to what I firmly believe to be a mere delusion. I believe that the present system tends, not to accelarate the progress of truth, but to delay the natural fo death of expiring errors. I conceive that we have at present no right, to the respectable name of a Board of Public Instruction. We are a Board for wasting public money, for printing books which are of less value than the paper on which they are printed while it was blank, for giving artificial encouragement to absurd history, absurd metaphysics, absurd physics, absurd theology, for raising up a breed of scholars who find their scholarship an encumbrance and a blemish, who live on the public while they are receiving their education, and whose education is so utterly useless to them that when they have received it, they must either starve or live on the public all the rest of their lives. Entertaining these opinions, I am naturally desirous to decline all share in the responsibility of a body which unless it alters its whole mode of proceeding, I must consider not merely as unless, but as positively moxious.

Extracts from the Central Educational Dispatch of 1854 with Special Refrence to such Paragraphs as Relate to North Western Provinces. (U.P.)

2- Among many subjects of importance, none can have a stronger claim to our attention than that of education. It is one of our most secred duties to be means, as for as in us lies, of conferring upon the natives of India those vast moral and material blessing which flow from the general diffussion of useful knowledge, and which India may, under Provinces, derive from her connexion with England. For, although British influence has already, in many remarkable instances, been appllied with great energy and success to uproot demoralising practices and even crimes of a deeper dye, which for ages had prevailed among the natives of India, the good results of those effarts must, in order to be permanent, possess the farther sanction of a general sympathy in the native mind which the advance of education alone can secure.

7- Before proceeding further, we must emphatically declare that the education which we desire to see extended in India is that which has for its object the diffusion of the improved arts, science, philisophy and literature of Europe, in short, of European knowledge.

8- The systems of science and philosophy which form the learning of the East abound with grave errors, and Eastern literature is at best very deficient as regards all mordern discovery and improvements, Asiatic learning, therefore, however widely diffused, would but little advance our object. We do not wish to diminish the opportunities which are now afforded in special institutions for the study of Sanskrit, Arabic and Persian literature, or for the cultivation of those languages which may be called the classical languages of India. An acquaintance with the works contained in them is valuable for historical and antiquarian purposes, and a knowledge of the language them selves is required in the study of Hindoo and Mohamedan Law and is also

of great inportance for the critical cultivation and improvement of the vernacular languages of India.

From the court of Directors of the East India Company to the Govern or General of India in council-(No.49 dated 19 th July, 1854) North Western Provinces is the old name of the United Provinces in British India.

9- We are unaware of the success of many distinguished oriental scholars in their praiseworthy endeavour to ingraft upon portions of Hindoo philosophy the germs of sounder morals and of more advanced science, and we are far from underrating of the good effect which has thus been produced upon the learned classes of India, who pay hereditary-veneration to those ancient languages, and whose assistance in the spread of education is so valuable, from the honourable and influential position which they occupy among their fellow countrymen. But such attempts, although they may usefully cooperate, can only be considered as auxiliaries, and would be a very inadequate foundation for any general scheme of Indian education.

13- It is neither our aim nor desire to substitute the English language for the venracular dialects of the Country. We have always been most sensible of the impartance of the use of the languages which alone are understood by the great mass of the population. These languages, and not English, have been put by us in the place of Persian in the administration of justice and in the inter course between the officers of Government and the people. It is indispensible, therefore, that in any general system of education, the study of them should be assiduously attended to and any acquaintance with improved European knowledge which is to be communicated to the great mass of the people whose circumstances prevent them from acquiring a high order of education, and who can not be expected to overcome the difficulties of a foreign language that can only be conveyed to them through one or other of these vernacular languages.

14- In any general system of education, the English language should be taught where there is a demand for it, but such instruction should always be combined with a careful attention to the study of the vernacural languages to be made use of, as by for the most perfect medium for the education of those persons who have acquired a sufficient knowledge of it to receive general instrution through it, The vernacular language must be employed to teach the far larger classes who are ignorant of, or imperfectly acquainted with English. This can only be done effectually through the instrumentality of masters and professors, who may be themselves, knowing English, and thus having full access to the latest improvements in knowledge of every kind, impart to their fellow countrymen through the medium of their mother-tongue, the information which they have thus obtained. At the same time, as the importance of the vernacular languages becomes more appreciated, the vernacular literature of India will be gredually enriched by translations of European books or by the original compositions of men whose minds have been imbued with the spirit of European advancement, so that European knowledge may gradually be placed in this manner with in the reach of all classes of the people. We look, therefore, to the English language and to the vernacular languages of India together as the media for the diffusion of European knowledge, and it is our desire to see them cultivated to gether in all schools in India of a sufficiently high class to maintain a schools master possessing the requisite qualifications.

16- The Lieutenant, Governor of Agra has, since the separation of the educational institution of the North-Western Provinces from those of Bengal, taken upon himself the task of their management, and we can not allow this opportunity to pass without the observation that, in this, as in all other branches of his administration, Mr. Thomas displayed that accurate knowledge of the condition and requirements of the people under his charge, and that clear and ready perception of the practical

measures best suited for their welfare, which make his death a loss to India, which we deplore the more deeply, as we fear that this unremitting exertions tended to shorten his career of usefulness.

91- In the North-Western Provinces the demand for education is so limited by circumstances fully detailed by the L.ieutenant Governor in one of his early reports, that it will probably be long before private efforts will become energatic enough to supply the place of the establishment, support and management by Government, of places of instruction of the highest grade, where there may be sufficient reason for their institution.

92- At the same time, the system for the promotion of general education throughout the country, by means of the inspection and encouragement of indigenous schools, has laid the foundation of a great advancement in the education of the lower classes. Mr. Thomason ascertained, from statistical information, the lementable state of ignorance in which the people were sunk, while the registration of land, which is necessary under the revenue settlement of the North-Western Provinces, appared to him to offer the stimulus of a direct interest for the acquisition of so much knowledge, at least of reading and writing, of the simple rules of arithmatic, and of land measurement, as would enable each man to look after his own rights.

93- He, therefore, organised a system of encouragement of indigenous schools, by meant of a constant inspection by zillah and pergunnah visitors, under the superintendence of a visitor-general, while at the head quarters of each tahsildar, a school was established for the purpose of teaching, reading and writing the vernacular languages, both Urdu and Hindi accounts, and the mensuration of land. A school house is provided by Government, and the masters of the tehsil schools receive a small salary, and are further entitled to the tuition fees paid by the pupils, of whom none are educated gratuitously, except. " On recommendation given by village schools-masters

who may be on the visitor's list" A certain sum is annually allotted to each Zillah for the reward of deserving teachers and scholars, and the attention of the visitor-general was expressly directed to the preparation of elementary school books in the vernacular language, which are sold through the agency of the zillah and pergunnah visitors. We shall be prepared to sanction the gradual extension of some such system as this to other districts of the Agra Presidency, and we have already referred to it as the model by which the efforts of other presidencies for the same object should be guided.

97- We have now concluded the observations which we think it is necessary to address to you upon the subject of the education of the natives of India. We have declared that our object is to extend European knowledge throughout all classes of the people. We have shown that this object must be effected by means of the English language in the higher branches of instruction, and by that of the vernacular languages of India to the great mass of the people. We have directed such a system of general superintendence and inspection by Government to be established as will, if properly carried out, give efficiency and uniformity to your efforts. we porpose by the institution of universities to provide the highest test and encouragement of a liberal education. By sanctioning grants-in-aid of private efforts, we hope to call to the assistance of Government private exertions and private liberality. The higher classes will now be gradually called upon to depend more upon themselves, and your attention has been more especially directed to the education of the middle and lower classes, both by the establishment of fitting schools for this purpose, and by means of a careful encouragement of the native schools which exist, and have existed from time immemorial, in every village, and none of which perhaps can not, in some degree, be made available to the end we have in view. We have noticed some particular points connected with education, and we have reviewed the condition of the different presidencies in this respect, with a desire to point out what should be imitated, and what is

wanting, in each.

99- We believe that the measures we have determined upon are calculated to extend the benefits of education throughout India, but at the same time, we must add that we are not sanguine enough to expect any sudden, or even speedy, results to follow from their adoption. To imbue a vast and ignorant population with a general desire for knowledge, and to take advantage of that desire when excited to improve the means for diffusing education amongst them, must be a work of many years, which, by the blessing of Divine Providence may largely conduce to the moral and intellectual improvement of the mass of the natives of India.

100- As a Government, we can do no more than direct the efforts of the people, and aid them where ever they appear to require most assistance. The result depends more upon them than upon us, and although we are fully aware that the measures we have now adopted will involve in the end a much larger expenditure upon, education from the revenues of India, or in other words, from the taxation of the people of India than at present so applied, we are convinced, with sir Thomas Munro, in words used many years since, that any expense which may be incurred for this objects " Will be amply repaid by the improvement of the country, for the general diffusion of knowledge is inseparably followed by more orderly habits, by increasing industry, by a taste for the comforts of life, by exertion to acquire them and by the growing prosperity of the people"

APPENDIX - 2

The Report of the University Education Commission

December, 1948 - August, 1949

The university education commission was appointed by the Government of India to report on Indian University Education and suggest improvement and extension that may be desirable to suit present and future requirements of the country.

The following were appointed member of the commission:-

1- Dr. S. Radha Krishnan, Spalding professar of Eastern Religious and Ethics at the University of Oxford. (Chairman)

2- Dr. Tara Chand, Secretary and Educational Adviser to the Govt. of India.

3- Dr. (Now sir) James F. Duff, vice-chancellor, university of Durham.

4- Dr. Zakir Hussain, vice-chancellor, Muslim university, Aligarh.

5- Dr. Arthur E. Morgan, president, community service Inc.

6- Dr. A. Lakshmanaswami Mudaliar, vice-chancellor, university of Madras.

7- Dr. Meghnad saha, palit professor of physics and president, post -graduate council of science, university of Calcutta.

8- Dr. Karm Narayan Bhal, professor of Zoology, university of Lucknow.

9- Dr. John J. Tigert, formly commissioner of Education of the United States and President Emeritus of the University of Florida.

10- Sri. Nirmal Kumar Sidhanta, professor of English and Dean of the Faculty of Arts, university of Lucknow. (Secretary)

The commission held its first meeting in New Delhi on 6 th December, 1948, when the Hon'ble maulana Abul kalam Azad, Minister of Education, Govt. of India, addressed the meeting in regard to the purpose and scope of the inquiry. Then the members of the commission visited the different university centres of

India from December, 13, 1948 to july 19, 1449, met edcationists of different types and recorded their evidence. A comprehensive question naire was circulated to prominent men throughout the country.

About 600 replies were received from the people addressed. The result of their survey are embodied in the Report published in 1949.

The important recommendations of the commission under different heads are noted below:-

Teaching staff - Universities and Colleges.

1- The importance of the teacher and his responsibility be recognised.

2- Conditions in universities which are suffering from lack of finances and consequent demoralization be greatly improved.

3- There be four classes of teachers, professors, Readers, Lecturers and instructors.

4- Each university should have some Research Fellows.

5- Promotion from one category to another be solely on graunds of merits.

6- The seales of salaries for university teachers be:-

Professors-	Rs. 900-50-1350
Readers-	Rs. 600-30-900
Lecturers-	Rs. 300-25-600
Instructors and Fellows -	Rs. 250
Research Fellows -	Rs. 250-25-500

7- The scales of pay for affiliated colleges with no post-graduate classes be-

Lecturers-	Rs. 200-15-320-20-400
Senior posts-	Rs. 400-25-600 (two in each college)
Principal-	Rs. 600-40-800

for colleges which have post-graduate classes, the grade be-

Lecturers-	Rs. 200-15-320-20-400-25-500
Senior posts-	Rs. 500-25-800 (two in each college)
Principal-	Rs. 800-40-1000

8- The age of retirement be ordinarily 60, but extensions be allowed up to 64 in the case of a professor.

9- Conditions regarding Provident Fund, leave and hours of work be definitely laid down.

Standard of Teaching.

1- The standards of admission of the university courses should correspond to that of the present intermediate examination i,e, after the completion of 12 years of study.

2- In each province a large number of well equipped and well-staffed intermediate colleges (C IX to XII or VI to XII) to be established.

3- In order to divert students to different vocations arter 10 to 12 years of schooling, a large number of occupational institutes be opened.

4- Refresher courses be organised by the universities for high schools and intermediate college teachers.

5- To avoid over-crowding the maximum number in the Arts and Science Faculties of a teaching university be fixed at 3000 and in and affiliated college at 1,500.

6- The number of working days be substantially increased to ensure a minimum of 180 in the year, exclusive of examination days.

7- Lectures be carefully planned and supplemented by tutorials, library work and written exercieses.

8- There be no prescribed text-books for any courses of study.

9- Tuturial instruction be developed in all institutions imparting univerrsity eudcation

in the following manners :-

a- Students should report to tutors in groups not exceeding 6 in number.

b- Tutorials should be made avilable to all under-graduates (both pass and honours)

c- Tutorials should stimulate the mental development of students and should not become mere coaching for examinations.

Courses of study - Arts and Science.

1- The Master's Degree be given to Honours students after one year of study beyond the bachelor's degree and to pass students after two years beyond the bachelor's degree.

2- Both universities and secondary schools begin study of the theory and practice of general education and prepare syllabuses some what after the manner out lined in this section.

3- Without unnecessary delay the principle and practice of general education be introduced, so as to correct the extreme specialization which now is common in our intermediate and degree programmes.

Post-graduate Training and Research

1- There should be a uniformity in the regulations for the M.A. and M.Sc. degrees. The course should include advanced study of one special subject and training in method of research but not actual research. There should be the closest personal touch between the staff and the students.

2- The training for the Ph.D. degree should extend over a period of at least two years. A Ph.D. student should not be a narrow specialist, but his grasp of the subjects should be characterized by breadth and depth. The examination should include a thesis and a viva voce examination to test the condidates's general knowledge of the whole field of the subject.

3- Teaching universities should develop research training in as many branches of knowledge as they can, while the affiliating universities should develop post graduate and research departments in subjects in which they can secure services of scholars of high quality.

4- The D.Litt. and D.Sc. degree should be awarded on published work of outstanding quality and conspicuous originality.

5- Generous capital and maintenance grants should be made to the scientific departments of universities to enable them to extend and consolidate their post-graduate and research.

6- Greater facilities should be provided for study and research in border-line-sciences, like Bio-chemistry, Bio-physics, Geochemistry, Geophysics, etc.

PROFESSIONAL EDUCATION

AGRICULTURE

1- Agricutural education be recognized as a major national issue.

2- The study of agricultural in primary, secondary, and higher education be given high priority in national economic planning.

3- New agricultural colleges, where possible, be associated with new rural universities so that agricultural education may be supported end enriched by contact with other fields, and by common use of personnel and equipment.

COMMERCE

1- During the period of his study at the university a commerce student should be given opportunities for practical work in three or four different kinds of firms.

2- After graduating some of them be advised to specialise in a particular profession like accountancy and receive the requisite practical training.

EDUCATION

1- The courses be remodelled and more time to school practice and more weight

given to practice in assessing the student's performances.

2- Suitable schools be used for practical training.

3- The bulk of a staff of the training college be recruited from people who have first hand experience of schools teaching.

4- The courses on the theory of Education be flexible and adaptable to local circumstances.

ENGINEERING AND TECHNOLOGY

1- The existing engineering and technological institutes of the country should be regarded as national assets, and steps should be taken to improve their usefulness according to the recommendations of the advisory Panel of Engineers and technologists to be set up.

2- The number of engineering schools of different grades be increased particularly for training of grades 4 and 5 (foreman, craftsman, draftsman, overseers, etc.)

3- Engineering schools cover a large number of fields and branches of engineering to meet the increasing demands by varied needs of the country.

4- Steps be taken to start without delay the higher technological institutes as recommended by the higher Technological Education Committee for training much needed engineer scientists and design and development engineers.

5- In establishing new engineering colleges or institutes there be fresh, critical enquiry as to the types of engineering service needed in India. Uncritical repetition and imitation of existing institutions here and abroad should be avoided.

LAW

1- Our law colleges be thoroughly re-organized.

2- Staff of law faculties be recruited and controlled by the universities in a fashion similar to Art and Science faculties.

3- A three year degree course in pre-legal and general studies be required for

admission to law courses.

4- A three year degree course be offered in special legal subjects, the last year to be given over largely to practical work, such as apprenticeship in advocates chambers.

5- Opportunities for research be available in every law faculty, particularly in constitutional law, Jurisprudence, International law; Administrative law and our systems of Hindoo and Muslim law.

MEDICINE

1- The maximum number of admissions to a medical college be 100 provided the staff and equipment for that number are available.

2- All the departments of study which require hospital facilities be located in a single campus.

3- There be 10 beds per-student admitted to a college.

4- Training in a rural centre be required both in the under-graduate and graduate stages.

5- Faculties for research in indigenous systems be provided and History of Medicine with special reference to Indian system be taught in first degree course in medicine.

RELIGIOUS EDUCATION

1- All educational institutions start work with a few minutes for silent meditation.

2- In the first year of the degree course lives of the great religious leaders like Gautam Buddha, Confucius, zoroaster, Socrates, Jesus, Sankara, Ramanuja, Maddva, Mohammed, Kabir, Nanak, Gandhi, be taught.

3- In the second year some selections of a universalist, character from the scriptures of the world be studied.

4- In the third year the central problem of the philosophy of religion be considered.

MEDIUM OF INSTRUTIONS

1- The Federal language be developed through the assimilation of words from various sources and the retention of words which have already entered into Indian language from different sources, there by avoiding the dangers of exclusiveness.

2- International technical and scientific terminology be adopted and the borrowed words by properly assimilated.

3- For the medium of instruction for Higher Education,English be replaced as early as practicable by an Indian language which can not be Sanskrit on account of vital difficulties.

4- Pupils at the Higher Secondary and university stages be made conversant with three languages. The regional language, the federal language and English.

5- Higher education be imparted through the instrumentality of the regional language with the option to use the federal language as the medium of instruction either for some subjects or for all subjects.

6- For the federal language one script devanagri be employed and some of its defects be removed.

7- Immediate steps be taken for developing the Federal and Regional languages.

(i) A Board consisting of Scientists and linguists be appointed to prepare a scientific vocabulary of words which will be common to all Indian languages and also to arrange for the preparation of books in different sciences to be rendered in to all Indian languages.

(ii) Provincial government be required to take steps to introduce the teaching of the Federal language in all classes of Higher Secondary Schools, in degree colleges and in universities.

(iii) English be studied in High schools and in universities in order that we may keep

in touch with the living stream of ever-growing knowledge.

EXAMINATIONS

1- A university degree should not be required for government administrative services. Specially state examinations for recruitment to the various services should be orginized and should be open to who ever cares to take them.

2- One third of the marks alloted to each subject be reserved for work done during the course of instruction and this be adopted forthwith for the B.A.,& B.Sc., M.A., & M.Sc. examinations.

3- A candidate should get 70% or more marks to receive a first class, 55 to 69% for a second and at least 40% for a third.

4- The system of awarding grace marks be abolished for the first degree and all higher examinations.

5- Viva voce examination should be employed for post-graduate and professinonal degrees. They should be degsigned, however, to test the candidates competence in the fundamentals of the field of study to which the problem of his research belongs.

Besides the essay-type of examination which prevails and suffers from some major defects the commission recommends that a thorough study of the scientific methods of educational testing and appriasal be undertaken by the Ministry of Education engaging experts who are skilled in the preparation and use of objective tests.

A battery of psychological and achievement tests be developed for use with higher secondary school students for the final test at the end of twelve years of schooling.

A set of objective progress tests for guidance and for evaluating class room progress should also be developed immediately.

WOMEN'S EDUCATION.

1- The ordianary amenities and decencies of life should be provided for women in colleges, originally planned for men, but to which women are being admitted in increasing numbers.

2- Women's and men's education should have many elements in common, but should not in general be identical in all respects, as usually the case today.

3- Through educational council and by example the prevailing prejudice against study of home economics and home management should be over-come.

4- Women teachers should be paid the same salaries as men teachers for equal work.

CONSTITUTION AND CONTROL

1- University education should be placed on the concurrent list.

2- The concern of central Govt. with the universities be with regard to finance, coordination of facilities in special subject, adoption of National policies, ensuring minimum standard of efficient administration, etc.

3- A central Grant Commission helped by panels of experts be established for allocating grants to universities.

4- There should be no university of the purely affiliating type.

5- Govt. colleges are to be gradually transformed into constituent colleges of the university.

6- The aim of an affiliated college should be to develop into a unitary university and later into a federative one.

7- The authorities of the university are to be as follows:-

The visitor (G.G. OR PRESIDENT) the chancellor, (Governor), the vice-chancellor, the senate (Court), the executive council (Syndicate), the Academic council, the faculties, the Board of studies, the Finance Committee

and the Selection Committee.

8- A Grants Allocation Committee is to be constituted for province with universities of teaching and affiliating type.

FINANCE

1- The state should recognise its responsibility for the financing of higher education.

2- The aid to private colleges, should be for buildings and equipment as also for the re-curring expenditure on a uniform basis, say half of the teacher's salaries and a third of other approved expenditure.

3- Steps are to be taken to amend income-tax laws to encourage donations for educational purpose.

4- Additional grants should be made to colleges and universities in order to enable them to give effect to the recommendations of the commission.

5- The Govt. should contribute an additional annual amount of about ten crores for the development of university education dunring the next quinquennium.

6- The University Grants Commission be set up for allocating grants.

NEW UNIVERSITIES.

1- During the transition from affiliated or independent college to university status or during the initial period of a new university a provisional charter should be granted by the president upon the recommendation of the university grants commission and the permanent charter is to be granted after a provisional period.

2- Visva-Bharti at Shantiniketan and Jammia Millia at Jamia Nagar deserved provisional charter as universities and suitable capital and recurring grants.

3- In the establishing of new universities freedom should be given for pioneering and experiment in educational methods.

4- In planning new universities, both urban and rural, effort should be made to get

as good distribution as possible with reference to total educational needs of the country.

RURAL UNIVERSITIES

The commission recommends that special attention be paid to the development of higher education in rural areas along the lives suggested in the Post-Basic (Secondary) Education and a village industrialisation scheme.

Most of the provinces are already committed to the principle of basic education. Each of them might establish are or more rural universities. Similar efforts might be made by the central government and the Gandhi Memorial Turst. The growth of the new system will depend largely on the supply of suitable teacher, for which one or more training schools for teachers might be established.

In order to consider the Report of the University Commission a special sitting of the Central Advisory Board was held on April 22 and 23, 1960. The important recommendations of the commission were mostly accepted and at some places modified according to neccssity, Recommendations regarding the Post-Graduate studies and Researches were fully accepted while those on Professional Education like Agricultural, Commerce Engineering and Technology, Law and Medicine were accepted after certain alterations. Similarly the medium of instructions, grouping of the teaching staff, their salaries, service condition, syllabus, objective tests, female education, establishment of new universities, constitutions and control, finance, etc. were accepted by the Board. The recommendation of placing the universities on the concurrent list was rejected.

In a meeting of the Board in January, 1951 the Honourable minister for education expressed his view that Hindi would replace English. The process of gradual replacement would take fifteen years.

The Secondary Education Commission.

(October 1952 - June 1953)

The Central Advisory Board of Education at its 14 th meeting held in January, 1948 made the recommendation that a commission be appointed to examine the prevailing system of secondary education in the country and suggest measures for its reorganization and improvement. The Board reiterated its recommendation in Jaunary, 1951. The Govt. of India appointed the Secondary Education Commission in September, 1952 It consists of the following:

1- Dr. A. Lakshamanswami Mudaliar, Vice-Chancellor, Madras University (Chairman)
2- Principal John Christie, Jesus College, Oxford.
3- Dr. K. R. Williams, Associate Director, Southern Regional Education Board, Atlanta. (U.S.A.)
4- Mrs. Hansa Mehta, Vice-Chancellor, Baroda University.
5- Sir, J.A. Taraporwala, Director of Technical Education, Govt. of Bombay.
6- Dr. K.L. Shrimali, Principal, Vidya Bhavan Teachers Training College, Udaipur.
7- Shri M.T. Vyas, Principal, New Era Schools, Bombay.
8- Shri K.K. Saiyidain, Joint secretary to the Govt. of India, Ministry of Education.
9- Principal A.N. Basu, Central Institute of Education, Delhi. (Member-secretary)

Dr. S.M.S. Chari, Education officer, Ministry of Education, acted as Assistant secretary to the commission.

Terms of Reference

Under the terms of reference the commission was asked :

(a) " To enquire into and report on the present position of secondary education in India in all its aspects, and

(b) Suggest measure for its re-organization and improvement with particular reference to.

(I) The aims, organization and content of secnodary education,

(ii) Its relationship to Primary Basic and Higher Education,

(iii) The interrelationship to Primary, Basic and Higher Education:

(iv) The inter-relation of secondary schools of different type's and

(v) Other allied problems so that a sound and resonably uniform system of Secondary Edcation suited to our needs and resources may be provided for the whole country"

The Hon'ble Minister of Education, Maulana Abul Kalam Azad, inougurated the commission on the 6th October, 1952 in New Delhi. The Chairman and the Secretary sent out a detailed questionnaire to a large number of educationists, administrators and leaders of public opinion interested in education. Replies were received from many of them. The commission visited various states and elicited public opinion from educationists and other citizens all over the country to lay down a clear policy on an all-India basis. The Indian constitution guarantees the right of every citizen to free and compulsory education up to the age of 14 For the proper functioning of democracy, the centre must equip every individual with the necessary knowledge skill, and aptitudes to discharge his duties as a responsible citizen. So a type of balanced education promoting social virtues, intellectual powers and practical skill was envisaged on an all-India basis.

As a document of great importance this report may take its place by the side of the university commission report. Now we have got a complete picture of education at different stages with basic education at the primary stage. Recommendations of the report, if implemented, will go a long way in removing many evils of the existing pattern.

The vital problem of secondary education is how to change a

system that is treated as a preparation for and an entrance to the universities. The system has got to be self-sufficient, enabling pupils to become useful citizens taking their place in the life of the community. The commission seeks to achieve this aim by the introduction of multilateral or multi-purpose schools which besides offering a central core of subjects to be studied by all, there will be a variety of technical and vocational subjects for different tasts and temperaments. The commission decries the idea of differentiating the vocational subjects from the cultural subjects and emphasizes that the technical subjects will be taught as much for their cultural value as for their vocational fitness.

The commission has made many useful recommendations on the formation of a High Power Text Book. Committee which will approve and publish text books and look into the status and working conditions of teachers, the Role of inspectors and the management of schools. As regards language the medium of instruction through out should be the mother tongue of the pupil or the regional language in which both Hindi and English should be taught. The language are to be introduced one after the other in succeeding years when the pupils reach the middle schools stage. In a multilingual country like India three languages have to be learnt.

The commission emphasises that the school should be more in touch with the community and many of the activities should help to link the life of the community. In the old system there was no such relation and consequently the community in town and villages lost. the cultural value of such contacts and the pupils who came out of the schools, found it difficult to fit themselves in the life of the community. The commission suggests provision for the study of agricultural and the allied subjects like horticulture and animal husbandry, specially in rural schools. A school must make provision for teaching a craft which flourishes in that particular area. The teaching must be of practical nature and provide opportunities to give training in the field or

factory, Vacations in rural areas should be given during the busy agricultural season when students can help their parents at work. In this way education is related to life.

The commission pleads that though secondary education is a state subjects the centre can not evade its responsibilities for such aspects of education as coordination, the training for citizenship and economic development. It has also suggested the imposition of an industrial education-cess on industry and the levy of a certain percentage of net revenue on railways, posts and telegraphs. The endowment for education should be exempted from income tax and other taxes. Finance for educational purposes must come from the surplus arising out of the increaesed development activities, but till them the resources avilable are to be tabbed or utilized. The recommendation that do not invlove much expenditure should be implemented as early as possible.

The important recommendations of the commission under different heads with special reference to Higher Education are as follows.

New Organisation Pattern

3- As a consequence of the preceding recommendations the first degree course in the unvirsity should be of three years duration.

4- Admission to professional colleges should be open to those who have completed the Higher secondary course, or have taken the one-year pre-university course.

Improvement of the teaching Personnel

8- The training college should conduct research work in various important aspects of pedagogy and this purpose it should have under its control on experimental or demonstration schools.

APPENDIX - 3

Universities in Uttar Pradesh

S.N.	Name of University	Place	Year of Establishment.
1-	Allahabad University	Allahabad	1887
2-	Indian Veterinary Research Institute.	Izzat nagar	1889
3-	Indian Council of Forestry Research and Education	Dehradun	1906
4-	Banaras Hindu University	Varanasi	1917
5-	Aligarh Muslim University	Aligarh	1920
6-	Lucknow University	Lucknow	1921
7-	Agra University	Agra	1927
8-	Roorkee University	Roorkee	1949
9-	Gorakhpur University	Gorakhpur	1956
10-	Sampurnanand Sanskrit Vishva Vidyalaya	Varanasi	1956
11-	Indian Institute of Technology	Kanpur	1959
12-	Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology.	Pant nagar Nainital.	1960
13-	Gurukul kangri Vishva Vidyalaya	Hardwar	1962
14-	Kanpur University	Kanpur	1965
15-	Meerut University	Meerut	1965

16-	Central Institute of Higher Tibetan Studies.	Varanasi	1967
17-	Kamaun University	Nainital	1973
18-	Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University	Sri nagar	1973
19-	Dayal bagh Educational Institute.	Agra	1973
20-	Narendra Deva University of Agriculture and Technology	Faizabad	1974
21-	Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology.	Kanpur	1974
22-	Kashi Vidyapeeth	Varanasi	1974
23-	Avadh University	Faizabad	1975
24-	Rohilkhand University	Bareilly	1975
25-	Bundelkhand University	Jhansi	1975
26-	Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences.	Lucknow	1983
27-	Indian Institute of Management	Lucknow	1984
28-	Purvanchal University	Jaunpur	1987
29-	Dr. Bhim Rao Ambedkar University	Lucknow	1989

University of Allahabad. Est. 1887

Faculty of Arts.

Fauclty of commerce.

Faculty of engineering. (MLN regional engg. college)

Faculty of law. Faculty of science.

Faculty of medicine. Constituent college.

Motilal Nehru Medical College (1961)

MBBS, MD, D,phil, DCH, DCP, DOMS, DGO, DO, DMRE, DLO, DA

University Colleges

Kali prasad university college, (1922) B.A. B.Com.

Madan Mohan malviya university college. (1950) B.A. B.Com.

William Holland university college, (1922) B.A.

Associated colleges

Allahabad Agricultural institute. Naini. (1910)

B.Sc., (Ag Engg), B.Sc., (Home Ecom) M.Sc., (Ag)

Allahabad Degree college, Allahabad. (1956) B.A., B. Com., LLB.

Arya Kanya Degree college, Allahabad. (1975) B.A.

CPM Degree college, Allahabad. (1950) B.A., B.Sc.,B.Com., LLB.

Ewing christion college, Allahabad. (1902) B.A., B.Sc.

Hamidia Girls Degree college, Allahabad. (1975) B.A.

Ishwar Saran Degree college, Allahabad. (1977) B.A., B.Com.

Jagat Taran Girls Degree college, Allahabad. (1975) B.A.

Motilal Nehru Regional Engineering college, Allahabad. (1961) B.E., M.E.

Rajarishi Tandon Mahila Mahavidyalaya, Allahabad. (1975) B.A.

Sanwal Dass S Lal Khanna Girls Degree college. Allahabad. (1975) B.A.

Motilal Nehru Institute of Research and Bussiness Adminitration. MBA.

Indian Veterinary Research Institute. Est. 1889.

Izzat Nagar - 243122

Departments

Animal Genetics. Animal Nutrition.

Animal Physiology, Animal Production.

Avian Diseases. Biochemistry. Biophysics.

Epidemiology Extension education.

Live stock Economics.

Live stock & Production management.

Live stock Production Technology.

Faculty of Science.

Veterinary Bacteriology.

" " Immunology.

" " Medicine.

" " Parasitology.

" " Pathalogy.

" " Pharmacology.

" " Public Health.

" " Surgery.

" " Virology.

Indian Council of Forestry Research & Education

Est. 1906 - Dehradun

Departments

Botany, Cellulose & Paper, Ecology & Environ ment.

Entomology, Forest Soil & Land Reclamation.]

Forest products, Forest Operation.

Genetics & Tree Propagation, Minor forest products.

Pathalogy, Resource Survey & management.

Silviculture, Social Forestry, General.

Banaras Hindu University, Varanasi

This university is a living memorial to the great work of Pandit Madan Mohan Malviya. It was established as a teaching and residential university at Banaras by an act of 1915 and began its operation in 1917.

Departments of university

Faculty of Agriculture.

Institute of Agricultural Sciences.

Agicultural Economics. Agronomy.

Animal Husbandry & Dairying.

Entomology & Agricultural Zoology.

Extension Education.

Farm Engineering. Genetics & Plant Breeding.

Horticulture. Mycology & Plant Pathalogy.

Plant Physiology.

Soil Science & Agricultural chemistry.

Faculty of Arts.

Ancient Indian History, Culture & Archaeology.

Arabic. Bengali. English.

Foreign languages. French studies.

Germanic Studies. Hindi.

History of Arts. Indian languages.

Journalism & Mass communication.

Library & Information Science.

Linguistics. Marathi. Pali & Budhist Studies.

Persian. Philosophy. Physical Education.

Sanskrit. Telgu.

Faculty of Commerce. Faculty of Education.

Faculty of Engineering & Technology.

Institute of Technology.

Ceramic Engineering. Chemical Engg & Tech.

Civil Engg. Electrical Engg. Electronics Engg.

Meterial Sciences. Mechnical Engineering.

Metallurgical Engg. Mining. Pharmaceutics.

Chemistry (Applied) Mathematics. Physics (Applied)

Faculty of law.

Mahila Mahavidyalaya.

Faculty of Management studies. M.B.A.

Institute of Medical Sciences.

Anaesthesiology. Anatomy. Biochemistry.

Biophysics. Dental surgery. ENT.

Forensic Medicine. Medicine.

Microbiology. Obstetrics & Gynaecology.

Ophthalmology. Orthopaedic surgery.

Paediatrics. Pathology. Pharmacology.

Physiology. Preventive & Social medicine.

Psychiatry. Radiology.

Radio therapy & Rediation Medicine. Surgery.

Basic Principles.

Dravya Guna. Kaya Chikitsa.

Medicinal Chemistry. Prasuti Tantra.

Shalya shalakya. Rasa shastra.

Faculty of performing Arts.

Instrumental Music. Musicology.

Vocal Music.

Faculty of Sanskrit Vidya Dharam Vigyan.

Vedanta Darshan. Dharmashastra & Mimansa.

Dharmagame. Jyotish. Sahitya.

Veda. Vyakaran.

Faculty of Science.

Biochemistry. Botany. Chemistry. Geography. Geology. Geophysics.

Home science. Mathematics. Physics. Psychology. Statistics. Zoology.

Faculty of Social Science.

Economics. History. Political Science. Psychology. Sociology.

Faculty of Visual Arts.

Applied Arts. Painting. Plastic Arts.

Constituent College

Central Hindu college, B.A. B.com.

Affiliated Colleges

1- Arya Mahila Degree college, 1958. B.A. B.Ed.

2- DAV Degree college, 1947. B.A. B.com.

3- Vasanta college for women. 1946. B.A.B.Ed.

4- Vasanta kanya Mahavidyalaya. 1954. B.A.

Aligarh Muslim University, Aligarh. Est. 1920.

The Mohammadan Anglo-Oriental college was converted into Aligarh Muslim University in 1920 by an Act of Indian Legislature. This University is a living

Memorial to the great work of Sir Saiyed Ahmed Khan.

Departments

Faculty of Arts

Courses- B.A. M.A.

Subjects- Arabic, English, Fine Arts, Hindi, Linguistics, Persian, Morden Indian languages, Philisophy, Sanskrit, Urdu, Home Science, (For women candidates only)

Faculty of commerce

Courses- B.Com., M.Com., M.B.A., D.B.A., D.S.W., Dip- in steno- typing,

Business Administration, Commerce.

Faculty of Engineering & Technology

Zakir Husain college of Engineering and Technology.

Courses- B.Sc. (Engg)- Chemical, Civil, Electrical & Mechanical,

M.Sc. (Engg)- Civil, Electrical, Mechanical.

B.E. - (Civil, Electrical, Mechanical)

PG diploma in petroleum processing.

Faculty of law

Courses- LLB., LLM.

Faculty of Life Sciences

Courses- B.Sc., M.Sc.

Subjects- Biochemistry, Botany, Home science, Zoology,

centre of wildlife and ornithology.

Faculty of Medicine

Jawahar Lal Nehru Medical College, 1962.

Courses- M.B.B.S., M.D., M.S., PG., Diploma Courses.

M. D. courses

1- Bio-chemistry. 2- General medicine. 3- Gynaecology & obst.

4- Microbiology. 5- Paediatrics. 6- Pathology.

7- Pharmacology. 8- Physiology. 9- preventive & Scoial Medicine.

10- Radio diagnosis. 11- Radio Therapy.

M. S. Courses

1- Anaesthesiology. 2- Anatomy. 3- E.N.T.

4- General Surgery. 5- Opthalmology. 6- Orthopaedic Surgery.

P. G. Diploma Courses

1- Anaesthesiology.(DA)

2- Child Health. (DCH)

3- Obst. & Gynaecology. (DGO)

4- Laryngology & Otology. (DLO)

5- Medical Radio Diagnosis. (DMRD)

6- Medical Radio Therapy. (DMRT)

7- Ophthalmology. (D.O)

8- Orthopaedic. (D. orth.)

Faculty of Science

Courses- B.Sc., M.Sc., M.C.A.

PG Diploma in Hydro-Geology.

Post B.Sc. Diploma in computer science & Application-(PDCA),

Diploma in Statistics.

B.Sc. - Botany, chemistry, Geography, Geology, Mathematics, physics, Statistics & Zoology.

Home Science. (For Women candidates)

M.Sc.- Chemistry, Bio-chemistry, Zoology, Botany, Physics, Geology, Geography, Mathematics, Statistics, Operation Research.

Faculty of Social Sciences

Courses- B.A., M.A., B. Lib.Sc., M. Lib. Sc., B.Ed., M.Ed.

B.A.- Economics, Education, History, Islamic studies, Psychology, Political Science, Sociology, Fine Arts.

Home Science (For women candidates only)

M.A.- Economics, Education, History, Islamic studies, Sociology,

Psychology, Political Science.

Centre of west Asian studies.

General education centre.

Faculty of Theology

courses- B. Th. (Sunni) B. Th. (Shia)

M. Th. (Sunni) M. Th. (Shia)

Faculty of unani Medicine

Ajmal Khan Tibbiya college.

Courses- Kamile-tib-o-jarahat - BUMS.

ILmul- Advia- M.D.

Kulliyat. Moalijat.

University Polytechnic

Courses :

Diploma in Engg. - Civil, Mechanical, Electrical, Electrical instrumentation,

Architectural Assistantship.

Drafting & Designing (Civil/mech.)

Certificate in Draftsmanship. (Civil/Mech.)

Women'S polytechnic

Courses- Diploma in Electronics Engg.

Diploma in Costume Design & Dress-making.

Diploma in office Assistantship & Secretarial practice.

Applied Science & Humanities.

Costume Design & Dress making centre.

Drawing & Painting.

Office Assistantship & Secretarial Practice.

Professional Courses

Job-oriented Diploma courses under the supervision of

the centre of professional courses.

a- Electronic Data Processing machine operation.

b- Museology.

c- Pest management.

d- Company law, Banking & Insurance.

e- Labour law and Labour Relations.

f- Criminology and Criminal Administration.

g- Laboratory Technology (Psysical & Chemical)

h- Gem Testing and Art of Lapidary

i- Medical lab. Technology (Radiology)

j- Jaurnalism

k- Applied Art

l- Instrument Technology

m- Medical Lab. Technology. (Clinical pathalogy)

n- Cartography

o- Computer Programming

p- Orthoptics

q- Pesciculture

University of Lucknow

Lucknow. Est. 1921

Faculty of Arts. Faculty of Science.

Faculty of commerce. Faculty of law.

Faculty of Medicine. Faculty of Ayurveda.

Contituent Colleges

1- College of Arts & Crafts.

2- Govt. college of Architecture. Lucknow. B. Arch.

3- Institute of engineering & Technology, Lucknow. 1984. B.Tech.

4- King Gearge's Medical college. Lucknow.

MBBS., MS., MD., Mch., Ph.D., Diplomas, BDS., MDS.

5- State college of Ayurveda. Lucknow. Ayurvedacharya.

Associated Colleges

1- Avadh girls Degree College. Lucknow. 1956. B.A.

2- Bappa Sri Narain Vocational Degree College, Lucknow. 1917. B.A., B.Sc.

3- DAV Degree College, Lucknow. 1948. B.A., B.Sc., LLB.

4- Isbella Thoburn College, Lucknow. 1896. B.A., B.Sc., B.Ed., B.Lib. Sc.

5- Jai Narain Degree College, Lucknow. 1946. B.A., B.Sc., B.Com.

6- Jubilee Girls College, Lucknow. 1955. B.A.

7- Kalicharan Degree College, B.A.

8- Karamat Husain Muslim Girls College, Lucknow. 1946. B.A.

9- Khunkhunji College, Lucknow. 1959. B.A.

10- Krishna Devi degree College, Lucknow. 1974. B.A.

11- Lucknow Christian College, Lucknow. 1888. B.A., B.Sc., DPE.

12- Mahila Vidyalaya College, Lucknow. 1895. B.A., B.Sc., B.Ed.

13- Mumtaz Degree College, Lucknow. 1972. B.A.

14- Nari Shiksha Niketan. Lucknow. 1963. B.A., B.Sc.

15- National Degree College, Lucknow. 1973. B.A., B.Com.

16- Navyug Kanya Vidyalaya. Lucknow. 1953. B.A., B.Sc., B.Ed.

17- Shashi Bhushan Balika Vidyalaya. Lucknow. 1959. B.A.

18- Shia Degree College, Lucknow. 1947. B.A., B.Sc., B.Com., LLB.

19- Vidyant Hindu Degree College, Lucknow. 1954. B.A.

Department of Business Administration

BBA+MBA Integrated programme. (After 10+2)

Department of Commerce

Institute of Finance & Management.

BMS(Bachelar of Management Science)

PGDFMPM (Post Graduate Diploma in Financial Markets & Portfolio Management)

Institute of Taurism Studies

MTA (Master of Tourism Administration)

Department of Applied economics.

MIBM (master of International Business Management)

Agra University, Agra

Est. 1927,

Departments of university.

Chemistry, History, Library Science, Mathematics, Physics, Zoology,

Institute of Social Sciences, Agra.

K.M. Institute of Hindi Studies & linguistics, Agra.

Institute of Home Science, Agra.

Affiliated colleges

1- A.K. (PG) college, Shikohabad. (1957) B.A., B.Com., M.A., M.Com.

2- Agra college, Agra. (1823) B.A., B.Sc., M.A., M.Sc., LLB., LLM.

3- B.D.M. Municipal Girls college, Shikohabad. (1973) B.A., M.A.

4- B.V. Rural institute. Bichpuri, Agra. (1971) B.A. M.A.

5- Babu Shivnath Agarwal College, Mathura. (1958) B.A., B.Sc., M.A., M.Sc., LLB.

6- Baikunthi Devi Kanya Mahavidyalaya, Agra. (1967) B.A., B.Sc., M.A., B.Ed., M.Ed.

7- Bhadawara Vidya Mandir Degree College, Bah. Agra. (1969) B.A.

8- Brij Bihari degree college, Kosi Kalam, Mathura. (1970) B.A.

9- Brij kishore Homeopathic medical college, Faizabad. (1981) BHMS., BMS.

10- C.L. Jain Degree College, Firozabad. (1959) B.Sc., M.Sc.

12- D.D. Girls degree college, Firozabad. (1971) B.A.

13- Dharam Samaj college, Aligarh. (1947)

B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., B.Ed., M.Ed. L.L.B.

14- Ganjdundwara college, Ganjdundwara. (1958) B.A., B.Sc., M.A., M.Sc., B.Ed.

15- Ghazipur Homepathic Medical College, Ghazipur. (1981) BHMS/BMS.

16- Government Degree college, Jalesar. (Etah) (1983) B.A., B.Com.

17- Homeopathic Medical College, Tigni. (Nagina) Bijnor. (1981) BHMS/BMS.

18- Institute of Oriental Philosophy, Vrindavan. (1950) B.A., M.A.

19- Jawaharlal Nehru Degree College, Etah. (1966) B.A.,M.A.

20- KGK Homeopathic Medical College, Moradabad. (1981) BHMS/BMS.

21- K A Postgraduate College, Kasganj, Etah. (1963) B.A., B.Com., M.A.

22- K.R. College, Mathura. (1947) B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Com., M.Sc.

23- K.R. Girls College, Mathura. (1957) B.A., B.Ed.

24- Kr. R.C. Mahila Degree College, Mainpuri. (1981) B.A.

25- Lal Bahadur Homeopatic Medical College, Allahabad. (1981) BHMS/BMS.

26- Lok Rastriya degree college, Tasrana. (1985) B.A.

27- Mahatma Gandhi Balika Vidyalaya Degree College, Firozabad. (1986)

B.A.,B.Sc.,M.A.,

28- Mohan Homeopathic Medical College, Lucknow. (1981) BHMS/BMS.

29- Municipal Girls college, kasganj, Etah. (1973) B.A.

30- Narain (PG) college, Shikohabad. (1956) B.A., B.Sc. (Ag), M.Sc.

31- National degree college, Bhongaon, Mainpuri. (1961) B.A., M.A.

32- P C Bagla Postgraduate College, Hathras, (1958) B.A., B.Com., M.A., M.Com.

33- Paliwal Degree College, Shikohabad. (1969) B.Sc.

34- RCA Girls Degree College, Mathura. (1971) B.A.

35- RDA Girls college, Hathras, Aligarh. (1973) B.A.

36- Raja Balwant singh college, Agra. (1940) B.A.,B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com.

B.Sc. (Ag), M.Sc. (Ag), B.Ed., M.Ed.

37- SBJ Degree College, Busawar, Mathura. (1968) B:A.

38- S.N. Medical College, Agra. (1939)

MBBS., MD., MS., DCH., DOMS., DMRE., DA., DCP.

39- SRK college, Firozabad. (1959) B.A., B.Com., M.A., M.Com.

40- Smt. Bhagwati Devi Jain Girls college, Agra Cantt. (1964) B.A.,M.A., B.Ed.

41- Shri Chitra Gupta Degree College, Mainpuri. (1961) B.A., M.A.

42- Shri Tikraram kanya Mahavidyalaya, Aligarh. (1957) B.A., M.A., B.Sc., B.Ed.

43- Shri varshvey college, Aligarh. (1947)

B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com., B.Ed., LLB.

44- Shri Durgaji Homeopathic Medical College, Chandreshwar, Azamgarh. (1981)

BHMS/BMS.

45- St. John's College, Agra. (1850) B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com.

46- State kanpur Homeopathic Medical College, Kanpur. (1981) BHMS/BMS.

47- TD Homeopathic Medical College, Jounpur. (1981) BHMS/BMS.

48- Thakur Biri Singh Degree College, Tundla. Agra. (1986) B.A.

49- Shiva Institute of Management Studies. Ghaziabad. B.B.A.

University of Roorkee

Roorkee, Est. 1949

The Roorkee University owes its existence to the constructive vision of the U.P. Government that converted the Thomason College of Engineering, Roorkee into a University by passing the Roorkee University Act.

Department of university

Architecture & Planning. Bioscience.

Chemical Engineering. Chemistry.

Civil. Earthquake Engineering.

Earth Science. Elecrical.

Elecronics & Computer.

Humamitics & Social Sciences.

Institute of Paper Technology.

Mathematics. Mechanical & Industrial.

Metallurgical. Physics.

Water Resources Development Training Centre.

Alternate Hydro Energy Centre.

Audo Visual Research Centre.

Department of Biosciences & Biotechnology.

Continuing Education Department.

Quality Improvement Programme centre.

Regional Computer centre.

Department of Hydrology.

University Science Instrumentation Centre.

University of Gorakhpur

Gorakhpur, Est. 1956.

Grakhpur University Act, 1956 was passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on May 19, 1956. and by the Lagistative Council on May, 23, 1956. It received the assent of the Governor on June, 05, 1956 and was Published in the U.P. Gazette Extraordinary dated June, 09, 1959.

Faculty of Agricultural. Faculty of Arts.

Faculty of commerce. Faculty of law.

Faculty of Science.

Associated colleges.

Babu Raghava Das Medical College, Gorakhpur. (1972) MBBS., MD., MS., Dips.

MMM Engineering College, Groakhpur. (1962) B.E.

Affiliated colleges.

1- Ambika pratap Narain Degree College, Basti, (1972) B.A., LLB.

2- BRD Degree College, Deoria. (1954) B.A., B.Sc. (Ag), B.Sc., B.Ed., M.Sc. (Ag)

3- Babu Raghavdas Bhagwandas Degree College, Barhaj, Deoria. (1970) B.A.

4- Bapu Degree College, Peepiganj, Gorakhpur. (1970) B.A.

5- Bhatwali Bazar degree college, Gorakhpur. (1973) B.A.

6- Buddha Degree College, Kushinagar, Deoria. (1955)
B.A., B.Sc., B.Com., M.A., B.Ed., M.Ed.

7- Buddha Vidyapeeth Degree College, Buddha Nagar, Nowgarh, Basti, (1965) B.A.

8- Dayanand Degree College, Gorakhpur. (1970) B.A., B.Sc.

9- Digvijainath Degree College, Gorakhpur. (1969) B.A.

10- Hiralal Ram Niwas Degree College, khalilabad, Basti, (1966) B.A.

11- Jawaharlal Nehru Samark Degree College, Maharajganj. Gorakhpur. (1966) B.A.

12- Kishan Degree College, Basti, (1959) B.A., B.Sc., M.A.

13- Krishak MV Gour Degree College, Basti, (1973) B.A.

14- Kutar Degree College, Chakke, Jaunpur. (1971) B.Sc.

15- Lal Bahadur Shastri Degree College, Anandnagar. Gorakhpur. (1973) B.A.

16- Madan Mohan Malviya Degree College, Bhatpar-rani, Deoria. (1963) B.A., B.Sc.,B.Ed.,

17- Mahajan Degree College, Chauri Chaura, Gorakhpur. (1972) B.A

18- Mahatma Gandhi Degree College, Gorakhpur. (1969) B.Sc.

19- Mahila Mahavidyalaya, Basti, (1967) B.A.

20- National Degree College, Barhalganj, Gorakhpur. (1960) B.A., B.Sc., B.Sc. (Ag)

21- Pavitra Degree College, Maniram. Gorakhpur. (1973) B.A.

22- Ramji Sahai Degree College, Rudrapur. Deoria. (1972) B.A.

23- Ratan sen Degree College, Bansi, Basti, (1968) B.A.

24- Sant Vinoba Degree College, Deoria, (1961) B.A.; LLB.

25- Sheopati Degree College, Shoharatgarh. Basti. (1964) B.A., B.Sc.

26- Shri B M Mahavidyalaya, pawa nagar. Deoria. (1974) B.A.

27- Shyameshwar Mahavidyalaya, Shikariganj, Gorakhpur.(1972) B.A.

28- St. Andrews Colleges, Gorakhpur. (1889) B.A., B.Sc., M.A.,M.Sc., LLB.

Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya

Varanasi, Est. 1956.

An Act to establish and incorporate a Sanskrit Vishva Vidyalaya at Varanasi was passed in Hindi, by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on July 20, 1956 and by the Legislative Council on August, 14, 1956. The assent of the Governor was received on September 11, 1956 and the Act was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary in September, 1956.

The University was opened on March 22, 1958.

Departments of university

Ved-vedang Sankaya

Dharmashastra. Jyotish.

prachina Vyakaran & Navya Vyakaran.

Ved Vibhag.

Sahitya & Sanskrit Sankaya

Prachina Rajashastra & Arthshastra.

Punanetihas.

Sahitya. Lalitkala & Sanskrit.

Darshana Sankaya

Nyay Vaisheshik. Purva Mimansa.

Sankhya Yogatantra Agam.

Tulnatamk Dharmdarshana Vedant.

Sharmana Vidya Sankaya

Budha Darshana. Bhartiya vidya Sanskrit.

Jaina Darshana. Pali & Therawoda.

Prakrita & Jainagama.

Adhunik Gyan Vijan Sankaya.

Adhunik Bhasha & Bhasha Vijnan. Samajik Vigyan.

Shiksha Shastra. Vijnan.

Granthalya Vigyan.

Indian Institute of Technology

Kanpur, Est. 1959.

Departments of Institute

Aerospace. Chemical. Chemistry. Civil.

Computer Science Engineering. Electrical.

Humatrities & Social Sciences. Materials Science.

Mathematics. Mechanical. Metallurgical.

Govind Ballabh Pant University of Agriculture & Technology

Pant nagar, Nainital, Est. 1960.

Departments of university

College of Agriculture.

Agricultural communication. Agricultural Economics. Agronomy.

Animal Science. Entomology. Food Technology.

Horticulture. Plant Breeding. Plant Pathalogy. Soil Science.

College of Veterinary Sciences

Anatomy & Histology. Gynaecology & Obstetrics.

Semen Biology. Medicine.

Microbiology & Public Health. Parasitology.

Pharmacology & Toxicology. Surgery & Radiology.

Veterinary pathology. Veterinary Physiology.

Veterinary Clinic.

College of Technology

Farm machinery & power. Irrigation & Drainage.

Post Harvest & process & Food Engg. Soil & Water conservation Engg.

Mechnical Engg.

College of Basic Science & Humanities

Biological Science. Chemistry. Environmental Science.

Mathematics & Statistics. Microbiology.

Plant Psysiology. College of Home Science.

Faculty of Forestry.

Gurukula Kangri Vishvavidyalaya

Hardwar, Est. 1962

Arts College

Ancient Indian History, English, Hindi, Philosophy, Psychology.

Veda college

Sanskrit Vedic Literature.

College of Science

Botany, Microbiology, Chemistry, Mathematics, Physics, Zoology.

Kanya Gurukul Mahavidyalaya. Dehradun.

Kanpur University

Kanpur, Est. 1965

Departments of university

Commerce, Social Science, English.

Engineering, Management, Education, Life Science.

Faculty of Commerce & Business Management. - M.B.A.

Constituent College

GSVM Medical College, Kanpur. (1952)

MBBS., MD., MS., Dips. in - Med.

Affiliated Colleges

1- Acharya Narendra Deo Mahila Mahapalika Mahavidyalaya. Kanpur. (1963)

B.A., B.Sc., M.A., M.Sc., B.Ed., M.Ed.

2- Armapur Degree College, Armapur. Kanpur. (1979) B.A.

3- Arya Kanya Degree College, Hardoi. (1970) B.A.

4- Ayurvedic College, Atarra, Banda. (1955) BAMS.

5- Badri Vishal Degree College, Farrukhabad. (1960) B.A., M.A.

6- Baiswara Degree College, Lalganj, Rae Bareli. (1966) B.A., B.Ed.

7- Bhagwandin Arya Kanya Degree College, Lakhimpur, Kheri. (1965) B.A. M.A.

8- Bhartiya Degree College, Farrukhabad. (1972) B.A.

9- Bhavan's Mehta College, Bharwari, Allahabad. (1968) B.A., B.Sc., M.Sc.

10- Brahamanand Degree College, Kanpur. (1961) B.Sc., LLB.

11- Brahmavart Degree College, Mandhana. Kanpur. (1970) B.A.

12- Bundelkhand Ayurvedic college, jhansi. (1972) B.A.M.S.

13- Cane Growers Nehru Degree College, Gola Gokarannath.

Lakhimpur-Kheri. (1968) B.A.

14- Cane Socities Nehru Degree College, Hardoi, (1965) B.A., M.A.

15- Chirst Church college, Kanpur. (1966) B.A.,B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com.

16- Chaudhari Charan Singh Degree College, Etawah. (1983) B.A.

17- College of Nursing. Kanpur. 24-7-1972. B.Sc. Nursing.

18- DAV College, kanpur. (1919) B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com.

19- DBV College, Kanpur. (1959) B.A., B.Sc., M.A., M.Sc., B.Ed.

20- DN Degree College, Fatehgarh. (1958) B.A., B.Com., M.Com.

21- Dayanand Bachhrayan Degree College, Bachhrayan, Rae Bareli. (1981) B.A.

22- Dayanand College of Law. Kanpur. (1958) LLB.

23- Dayanand Girls College, Kanpur. (1957) B.A. B.Sc., M.A., M.Sc., B.Ed.

24- Dayanand Subhash National College, Unnao. (1948)

B.A.,B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., B.Ed.

25- Dayanand Women's Training College, Kanpur. (1958) B.Ed., M.Ed.

26- Feroz Gandhi College, Rae Bareli. (1960) B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., B.Ed.

27- Gandhi Mahavidyalaya, Siddhauli, Sitapur. (1980) B.A.

28- Govt. Central Textile Institute. Kanpur. (1914) B. Text.

29- Govt. Degree College, Unchahar, Rae Bareli, (1978) B.A.

30- Govt. Degree College, Mahamudabad. Sitapur. (1976) B.A., B.Com.

31- Govt. Degree College, Hardoi, (1979) B.Sc., B.Com.

32- Gurukul Kanrgi Ayurvedic College, Gurukul kangri.Haridwar. (1922) BAMS.

33- Guru Nanak Girls Degree College,Kanpur. (1965) B.A.

34- HB Technological Institute, Kanpur. (1958) B Tech (Engg), B Tech (Chem Tech)

M Tech.

35- H S Degree College, kanpur. (1972) B.Com.

36- Halim Muslim Degree College, Kanpur. (1959) B.A.,B.Com., M.A., B.Ed.

37- Handia Degree College, Allahabad. (1973) B.A.,B.Ed.

38- Hindu Kanya Mahavidyalaya, Sitapur, (1961) B.A., B.Ed., M.A.

39- International Centre of Education, kanpur. (1972) B.Ed.

40- J D Vidya Mandir Degree College, Kanpur. (1963) B.A.,M.A.

41- Janta College, Bakewar. Etawah. (1959) B.Sc., B.Com., B.Sc.(Ag), M.Sc.

42- Janta Mahavidyalaya, Ajitmal, Etawah. (1964) B.A.,B.Sc., B.Sc. (Ag), M.Sc.

43- Juhari Devi Girls Degree College, kanpur. (1963) B.A.,M.A.

44- KN Degree College, Tejgaon, Rae-Bareli. (1973) B.A.

45- Karam Kshetra College, Etawah. (1959) B.A., B.Sc., M.A., M.Sc.

46- Kulbhaskar Ashram Degree College, Allahabad. (1960)

B.Sc., B.Sc. (Ag), M.Sc. (Ag)

47- Lalit Hari Ayurvedic College, Pilibhit. (1971) B.A.

48- Lala Laxmi Narain Degree College, Sirsa. Allahabad. (1970) B.A.,B.Sc.

49- Laxmi Yadunandan Degree College, kaimganj, Farrukhabad. (1971) B.A.

50- Mahatma Gandhi Degree College, Fatehpur. (1961) B.A.

51- Mahila Mahavidyalaya kidwainagar, Kanpur. B.A., B.Ed. (1969)

52- Mahila Seva Sadan, Allahabad. (1970) B.A.

53- Narayan Arya kanya Pathshala. Farrukhabad. (1965) B.A.

54- Nehru College, Chhibramau. Farrukhabad.(1968) B.A., B.Sc., M.Sc.

55- Nehru Institute of Opthalmology & Research. Sitapur. (1971) DOMS.

56- Panchayat Raj Mahila Mahavidyalaya, Etawach, (1985) B.A.

57- PPN College, Kanpur. (1959) B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc.

58- Prayag Mahila Vidyapith Mahavidyalaya. Allahabad. (1971) B.A.

59- PS Memorial Degree College, Kannauj, Farrukhabad. (1973) B.A.

60- RMP College, Sitapur. (1961) B.A. M.A.

61- Ram Prasad College, Kamalganj, Farrukhabad. (1969) B.A., B.Sc.

62- Ram Swaroop Gram Udyog Degree College, Pukhrayan. Kanpur. (1969)

B.A., M.A.

63- Rishikul Ayurvedic College, Haridwar. (1972) BAMS.

64- S N Sen Balika Vidyalaya Degree College, Kanpur. (1953) B.A., B.Sc.

65- Sadanand Degree College, Chhivalaha. Fatehpur. (1973) B.A., B.Ed.

66- Sahu Ram Narain Murli Manohar Ayurvedic College, Bareiblly. (1971) BAMS.

67- Sorvodaya Mahavidyalaya Solan. Raebareli. (1976) B.A.

68- Shri Lal Bhadur Shastri Ayurvedic College, Handia. Allahabad. (1981) BAMS.

69- Shri Narain Girls Degree College, Unnao. (1966) B.A.,B.Ed.

70- Swami Kalyan Deo Ayurvedic College, Baghara. Muzaffarnagar. (1974) BAMS.

71- Tak-Mil-ut-Tib Ayurvedic College, Lucknow. (1971) BUMS.

72- Teachers Training College, Sitapur. (1962) B.Ed.

73- Tilak Degree College, Ayraiya. Etawah. (1967) B.A., B.Com., B.Ed.

74- Unani Medical College, Allahabad. (1971) BUMS.

75- VSSD College, Kanpur. (1921)

B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com., B.Ed., LLB.

76- Vidyamandir Mahavidyalaya, Kaimganj, Farrukhabad. (1971) B.Com.

77- Vidyamandir Degree College, Kanpur. (1984) B.A., B.Sc., M.A.

78- Vivekhanand Gram Udyog Degree College, Dibiyapur. Etawah. (1972) B.A.

79- Yuvraj Datta College, Lakhimpur Kheri. (1949) B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc.

80- National Homeopathic College, Lucknow. (1971) BHMS/BMS.

81- Kanpur Vidya Mandir, Kanpur. B.A.

82- N.A.K.P. College, Farrukhabad. B.A.

83- Smt. Indira Gandhi Government Degree college, Bangermau. Unnao. (1988) B.A.

84- Govt. Girls College, Fatehpur. (1990) B.A.

Meerut University

Meerut, Est. 1965.

Department of University

Agricultural Botany.	Botany.	Economics.	Education.
English.	Hindi.	Horticulture.	Mathematics.
Psysics.	Political Science.	Psychology.	Russian.
Sanskrit.	Sociology.	Statistics.	Zoology.

Constituent Colleges

LLRM Medical college, Meerut. (1966) MBBS. MD. MS. Diploma.

Affiliated Colleges.

1- AS College, Lakhaoti- 245407 (1941) B.A., B.Sc. (Ag), M.Sc. (Ag)

2- AS Degree College, Mawana. (1961) B.Sc. B.Com.

3- AS Degree College, Sikandrabad. (1972) B.Com. M.Com.

4- Arya Kanya Pathshala Degree College, Hapur. (1959) B.A.

5- Arya Kanya Pathshala Degree College, Khurja. (1966) B.A.

6- BSM College, Roorkee. (1960) B.A., M.A.

7- Ch. Chhoturam Degree College, Muzaffar Nagar.(1959)
B.Sc., B.Sc. (Ag), M.Sc. (Ag)

8- DAV College, Muzaffar Nagar. (1950) B.Sc., M.Sc., B.Ed., LLB.

9- DAV College, Bulandshahar. (1956) B.A., M.A.

10- Dev Nagri College, Gulaoti. (1966) B.A., B.Sc.

11- Dev Nargi College, Meerut. (1958) M.A., B.Sc., M.Sc.

12- Digamber Jain College, Baraut. (1947) Meerut. B.A., B.Sc., M.A., M.Sc., B.Ed.

13- Digamber College, Dibai, Bulandshahar. (1960) B.A.

14- Durga Prasad Degree College, Anupshahar. (1965) B.A., B.Sc.

15- GVN Degree College, Budhpur Ramola. Meerut. (1973) B.A.

16- Ginni Devi Modi Girls Degree College, Modi Nagar. Ghaziabad. (1983) B.A.

17- Gochar Agricultural College, Rampur. (Mani Aran) (1959) B.A., B.Sc., B.Sc.(Ag)

18- Govt. Degree College, Deoband, Sharanpur. (1983) B.A.

19- Govt. Degree College, Noida. Ghaziabad. (1982) B.A. B.Com.

20- Govt. Girls Degree College, kandhala. Muzaffar Nagar. (1979) B.A.

21- Ismail National Degree College for Women, Meerut. (1962) B.A.

22- Iswar Dayal Parsandi Devi Degree College, Bulandshahar. (1970) B.Sc., B.Com.

23- JAV Girls College, Baraut. Meerut. (1973) B.A.

24- JV Jain College, Saharanpur. (1955)

B.A. B.Sc. B.Com. M.A. M.Sc. M.Com. B.Ed. M.Ed. LLB.

25- Jain Kanya Pathshala Degree College, Muzaffar Nagar. (1963) B.A.

26- Janta Degree College, Patla. Meerut. (1973) B.A.

27- Janta Vedic College. Baraut. Meerut. (1971)

B.A., B.Sc., B.Sc. (Ag), M.A., M.Sc., M.Sc. (Ag)

28- Janta Swaroop College, Sikandrabad. (1959) B.A.

29- KL DAV College, Roorkee. (1960) B.Sc., B.Ed.

30- KV Degree College, Machhra - 250106 (1956) B.A.,B.Sc.,B.Sc. (Ag), B.Ed.

31- Kanohar Lal Mahila Mahavidyalaya, Meerut. (1969) B.A.

32- Kanya Mahavidyalaya, Satikund, Kankhal. (1965) B.A.

33- Kishan Degree College, Simbhaoli. (1956) B.A., B.Sc. (Ag)

34- Krishak College, Mawana. (1969) B.A.

35- Lala Lajpat Rai Memorial College, Sahibabad. Ghaziabad. (1966)

B.A., B.Sc., M.A.

36- MMH College, Ghaziabad. (1948) B.A. B.Sc. B.Com. M.A. M.Sc. M.Com. LLB.

37- Mahamana Malviya Degree College, Khera. (1959) B.A., B.Sc.

38- Maharaj Singh College, Saharanpur. (1957) B.A., B.Sc., M.A., M.Sc.

39- Meerut College, Meerut. (1892) B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc.,M.Ed.,LLB., LLM.

40- Mihir Bhoj Degree College, Dadri. (1968) B.Sc.

41- Multani Mal Modi College, Modinagar. Ghaziabad. (1957)

B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com.

42- Munna Lal Girls College, Sharanpur. (1965) B.A., M.A.

43- NAS College, Meerut. (1952) B.A., B.Sc., M.A., M.Sc., B.Ed., M.Ed., LLB.

44- NREC College, Khurja. (1946) B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com., LLB.

45- Raghunath Girls College, Meerut. (1948) B.A., B.Sc., M.A.

46- Raja Mahendra Pratap Prem Vidyalaya College, Narsan. (1958)

B.Sc. (Ag), M.Sc. (Ag)

47- Rana Shiksha Shivir Degree College, Palikhava. (1960) B.A., B.Sc., B.Sc. (Ag)

48- Rashtriya Kisan College, Shamli. (1958) B.Sc., B.Sc. (Ag)

49- SD College, Muzaffar Nagar. (1949) B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com.

50- SDPP Girls College. Roorkee. (1966) B.A.

51- SSSS Degree College, Rasana. Meerut. (1981) B.A.

52- SSV College, Hapur. (1951) B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com.

53- Sanjay Gandhi Memorial Janta Degree College, Saroarpur Khurd. Meerut. (1982)

B.Sc.

54- Shambhu Dayal College, Ghaziabad. (1962) B.A. M.A.

55- Shrawan Nath Muth Jawaharlal Nehru Degree College, Hardwar. (1961) B.A.

56- Shri Kund Kund Jain Degree College, Khatauli. (1961) B.Sc.

57- St. Joseph Girls Degree College, Sardhana, Meerut. (1981) B.A.

58- V V College, Shamli. (1957) B.A., B.Sc., M.A., M.Sc.

59- Vidyawati Mukundlal Girls Degree College, Ghaziabad. (1961) B.A., M.A., M.Ed.

60- S.D. College of Engineering & Technology. Muzaffar Nagar.

B. Tech. Computer Science & Engineering.

B. Tech. Chemical & Alcohal Technology.

B. Tech. Sugar Technology.

Institute of Advanced Studies

M.A./M.Sc./M.Sc.(Ag) & M.Phil - Agricultural Botany, Botany, Economics, Education, English, History, Mathematics, Physics, Political Science, Psychology, Sociology, Statistics, Zoology, Horticulture, Micro-Biology, Bio-Technology, Environmental Science, Sanskrit.

M.Ed., Advanced Diploma in Personal management & Industrial Reletion.

(PMIR) Master in Human Resource Development) (MHRD)

Master in public Administration. (M.P.A.)

Diploma in Journalism. Diploma in English Language.

Russian Language (Certificate, Dioloma, Advanced Diploma Courses)

Central Institute of Higher Tibetan Studies

Sarnath,Varanasi, Est. 1967

Departments of institute.

Mool Shastra.

Sanskrit.

Kumaun University

Nainital, Est. 1973.

Constient Colleges

DSB College, Nainital. (1951) B.A.,B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com.

Almora constituent college, Almora. (1940)

B.A.,B.S.c.,B.Com.,M.A., M.Sc., M.Com.,B.Ed., M.Ed. L.L.B.

Affiliated colleges

1- Arya Kanya Degree College, Almora. (1975) B.A.

2- Govt. Postgraduate College, Bageshwar. Almora. (1974) B.A. M.A.

3- Govt. Degree College, Berinag. Pithoragarh. (1975) B.A., B.Sc.

4- Govt. PG College, Pithoragarh. (1963) B.A.,B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., B.Ed.

5- Govt. Degree College, Lohaghat. Pithoragarh. (1979) B.A. B.Com.

6- Govt. Degree College, Narayan Nagar. Didhihat. Pithoragarh. (1983) B.A.

7- Govt. Postgraduate College, Ranikhet. Almora. (1973) B.A., B.Sc., M.A.

8- Govt. Postgraduate College, Rudrapur. Nainital. (1974) B.A. M.A.

9- Motiram Baburam Govt. Postgraduate College, Haldwani. Nainital. (1982)

B.A., B.Sc., M.A., M.Sc.,

10- Govt. Postgraduate College, Ramnagar, Nainital. (1975)

B.A., B.Com., M.A., M.Com.

11- RH Govt. postgraduate College, Kashipur. Nainital. (1973)

B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.com.

12- Govt. Degree College, Dwarahat. Almora. (1983) B.A.

13- Govt. Degree College, Khatima. Nainital. (1988) B.A.

14- Govt. Degree College, Mailani, Almora. (1989) B.A.

Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University

Srinagar, Garhwal District, Est. 1973.

Department of university.

Faculty of Arts

Drawing & Painting.	Economics.	English.
Geography.	Hindi.	History & Archaeology.
Home Science.	Journalism.	Philosophy.
Political Science.	Psychology.	Sanskrit.
Sociology.	Tourism.	

Faculty of Sciences

Anthrology.	Botany.	Chemistry.	Forestry.

Geology. Horticulture. Mathematics. Militery Studies.

Psysics. S'atistics. Zoology.

Faculty of Commerce

Secretarial practice.

Faculty of Education.

Faculty of Law

Institute of Himalayan Studies & Regional Development.

High Altitude plant physiology Research Centre.

Adult Education unit.

Constituent Colleges

1- Birla Postgraduate College, Srinagar. Garhwal. (1961)

B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com., B.Ed., M.Ed.

2- Dr. B G Reddy Postgraduate College, Pauri. (1970)

B.A., B.Sc., M.A., M.Sc., LLB.

3- Swami Ramtirth College, Tehri. (1970) B.A., B.Sc., M.A., B.Ed., M.Ed., LLB.

Affiliated colleges

1- DAV PG College, Dehradun. (1946)

B.A.,B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com., B.Ed., M.Ed.

2- Dayanand Brijendra Swaroop postgraduate College, Dehradun. (1961)

B.A., B.Sc., M.A., M.Sc.

3- Dayanand Women's Training College, Dehradun. (1961) B.Ed.

4- Govt. Postgraduate College, Agustmuni. 246421. Chamoli. (1974)

B.A., B.Sc., M.A.

5- Govt. Degree College, Vedikhal. Pauri Garhwal. (1979) B.A.

6- Govt. Degree College, Champa. 262523. Tehri Garwhal. (1979) B.A.

7- Govt. Degree College, Chaubatakhal. Pauri Garwhal. (1979) B.A.

8- Govt. PG College, Gopeshwar. 246401. Chamoli. (1966)

B.A. B.Sc. B.com. B.Ed. M.A. M.Sc.

9- Govt. Degree College, Karanprayag Chamoli. 246444. (1979) B.A., B.Com.

10- Govt. Postgraduate College, Kotdwara. 246149. (1971)

B.A., B.Sc., B.Com., B.Ed., M.A., M.Sc.,M.Com.

11- Govt. Degree College, Lansdowne. Jaharikhal. 246155. (1972) B.A., B.Sc., B.Com.

12- Govt. PG College Rishikesh. (1972) B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Com.

13- Govt. PG College, Uttar Kashi. (1969) B.A.,B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc.

14- Mahadevi Kanya pathshala. (PG) Dehradun. (1958) B.A. B.Sc. M.A. M.Sc.

15- Municipal Postgraduate College, Mussoorie. (1963) B.A., B.Sc., M.A., M.Sc.

16- SGRR College, Dehradun. (1960) B.A.,B.Sc., M.Sc.

Dayalbagh Educational Institute.

Agra, Est. 1973.

Departments.

Faculty of Arts

Drawing and Painting. Economics, English,

Hindi, Home Science, Music,

Political Science, Psychology, Sanskrit,

Sociology

Faculty of Commerce

Accountancy & Law. Applied Business Economics.

Business Administration.

Faculty of Education

Faculty of Engineering

Electrical, Engineering, Mathematics, Mechanical,

Faculty of Science

Botany Chemistry Computer Sc. & Application.

Mathematics, Physics, Zoology.

Narendra Deva University of Agriculture & Technology

Faizabad, Est. 1974

Department

Agricultural Economics, Agricultural Engineering.

Agricultural Statistics, Animal Science.

Biochemistry, Crop Physiology,

Entomology, Extension Education

Fisheries, Forestry.

Food Technology, Genetics & Plant Breeding.

Horticulture, Languages, Microbiology.

Hematology, Plant Pathology, Soil Science.

Vegetable Science.

Chadra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology

Kanpur, Est. 1974.

Department of university.

College of Agriculture, Kanpur

Agricultural Biochemistry. Agricultural Economics & Statistics.

Agricultural Extension, Agronomy

Animal Husbandry & Dairying. Crop Physiology.

Entomology. Horticulture.

Plant Breeding & Genetics. Plant Pathology.

Seed Technology. Soil Conservation.

Soil & Agricultural Chemistry. Agricutural Engineering.

Home Science.

College of Veterinary Science & Animal Husbandry, Mathura

Agricultural & Fodder crops.
Anotomy.
Animal genetics & Breeding.
Animal Husbandary extension.
Animal Nutrition.
Biochemistry.
Dairying.
Live stock Economics & Statistics.
Medicine. Microbiology & Immunology.
Obstetrics & Gynaecology.
parasitology.
Pathology.
pharmacology.
physiology.
Poultry Science.
Surgery.

Kashi Vidyapith

Varanasi, Est, 1974.

Department of university

Commerce.
Economics.
Education.
English & Foreign language.
Fine Arts & Music.
Hindi & Indian languages.
History.
Journalism.
Law.
Philosophy.
Physical Edcucation & Yoga.
Political Science.
Psychology.
Sanskrit & Ritual learning.
Social Work.
Sociology.
Computer Science.

Avadh University

Faizabad, Est. 1975.

Affiliated Colleges

1- AND Kisan PG College, Baghnan, Gonda. (1973) B.A., M.A.

2- BNKB PG College, Akbarpur. Faizabad. (1969) B.A., M.A., B.Ed.

3- Baba Baruadas PG College, Paruiahram. Faizabad. (1971)
B.A., B.Com., M.A., M.Com.

4- Bajrang Degree College, Kunda, Pratapgarh. (1971) B.A.

5- Degree College, Patil, pratapgarh. (1971) B.A.

6- Ganpat Sahai PG College, Sultanpur. (1967) B.A., B.Sc., M.A.

7- Gayatri Vidyapith Degree College, Risia, Bahraich. (1972) B.A., B.Com.

8- Govt. Degree College, Musafirkhana. Sultanpur. (1986) B.Sc., B.Com.

9- Gramodaya Ashram Degree College, Saya, Faizabad. (1988) B.A.

10- H.N. Bahuguna PG College, Lalganj, Pratapgarh. (1973) B.A., M.A.

11- Indira Gandhi Degree College, Gauriganj, Sultanpur. (1981) B.A.

12- J L N PG College, Barabanki. (1964) B.A., M.A.

13- KN Institute of Physical & Social Science, Sultanpur. (1973)

B.A., B.Sc., B.Com., B.Ed., LLB., M.Ed., M.A.,M.Sc., M.Com.

14- KN Institute of Technology. Sultanpur. (1976) B.Tech.

15- K.S. Saket PG College, Faizabad. (1951) B.A., B.Sc., M.A., M.Sc., B.Ed., LLB.

16- Kisan PG College, Bahraich. (1960) B.A.,B.Sc.,M.A., B.Ed.

17- LB Shastri PG College, (Gonda) (1966) B.A., B.Sc., M.A., B.Ed.

18- MLK PG College, Balrampur. (Gonda) (1955) B.A., B.Sc., B.Ed., M.A., M.Sc.

19- MMM PG College, Kalakankar, Pratapgarh. (1966) B.A., M.A., B.Ed., M.Ed.

20- Mahila Degree College, Bahraich. (1973) B.A.

21- Munishwar Dutt PG College, Pratapgarh. (1960) B.A.,B.Sc., B.Ed., M.A.

22- PB Degree College, Pratapgarh. City. (1964) B.A., B.Sc.

23- RM Girls Degree College, Faizabad. (1972) B.A., M.A.

24- RR PG College, Amethi, Sultanpur. (1959) B.A., B.Ed., M.A., M.Ed.

25- Ramnagar Degree College, Ramnagar. Barabanki. (1981) B.A.

26- Rana Pratap Degree College, Sultanpur. (1971) B.A., M.A.

27- Sanjay Gandhi Degree College, Chaukia, Sultanpur. (1982) B.A.

28- Sant Tulsidas Degree College, Kadipur. Sultanpur. (1973) B.A.

29- Sewa Ashram Degree College, Dhidhui, pratapgarh. (1971) B.A., B.Ed.

30- Sevra Degree College, Serva, Faizabad. (1979) B.A.

31- TN PG college, Tanda Faizabad. (1960) B.A., M.A.

Rohilkhand University

Bareilly, Est. 1975.

Department of university

Adult Education.

Ancient History & Culture.

Animal Science.

Applied & Regional Economics.

Business Administration.

Education.

Law

Plant Science.

Affiliated colleges.

1- Arya Kanya Mahavidyalaya, Shahjahanpur. (1984) B.A.

2- Bareilly College, Bareilly. (1837) B.A., B.Sc., B.Com., LLB., M.A., M.Sc.

3- DAK College, Moradabad. (1960) B.A., B.Sc., B.Ed.

4- DSM Degree College, kanth. Muradabad. (1960) B.A.

5- GB Pant Degree College, Kachla, Budaun. (1961) B.A

6- GDHG College, Moradabad. (1905) B.A., B.Sc., B.Ed., M.A.

7- GF College, Shahjahanpur. (1947) B.A.,B.Sc., M.A., M.Sc.

8- GS College, Surjan Nagar, Moradabad. (1973) B.A.

9- GS Hindu College, Chandpur. Siau. Bijnor. (1962) B.A.

10- GU Degree College, Baheri, Bareilly. (1978) B.A.

11- Gindo Devi Mahila Mahavidyalaya, Budaun. (1983) B.A.

12- Govt. Degree College, Bisalpur. Pilibhit. (1976) B.A.

13- Govt. Girls Degree College, Rampur. (1976) B.A.

14- Govt. Raza College, Rampur. (1949)

B.A.,B.Sc., B.Com., B.Ed., M.A., M.Com., M.Sc.

15- Hindu College, Moradabad. (1949)

B.A., B.Sc., B.Com., B.Ed., M.A., M.Sc., M.Com., M.Ed.

16- KGK College, Moradabad. (1948) B.A.,B.Sc., M.A., M.Sc., LLB.

17- KMV Bhoor College, Bareilly, (1960) B.A.

18- JSH College, Amroha, Moradabad. (1960) B.A., B.Com., M.A.

19- MGM College, Sambhal. Moradabad. (1971) B.A.

20- M.H. Degree College, Moradabad. (1973) B.A.

21- NKBMG College, Chandausi, Moradabad. (1964) B.A.,B.Ed.

22- NMSN Dass College, Baduan. (1967) B.A.,B.Com., B.Ed.,M.A.

23- RBD College, Bijnor. (1971) B.A., M.A.

24- RP Degree College, Meerganj, Bareilly. (1968) B.A.

25- RSM Degree College, Dhampur. Bijnor. (1958) B.A.,B.Sc., B.Sc. (Ag)

26- SBD College, Dhampur. Bijnor. (1969) B.A., B.Ed.

27- SRS Girls Degree College, Bareilly. (1965) B.A., M.A.

28- S.M. College, Chandusi, Moradabad. (1946)

B.A., B.Sc.,B.Com., M.A., M.Sc., M.Com.

29- S.S. Degree College, Shahjanpur. (1965) B.A., B.Sc.,B.Ed.

30- Sahu Jain College, Najibabad. Bijnor. (1965) B.A.,B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc.

31- Upadhi Mahavidyalaya, Pilibhit, (1964) B.A., B.Com., M.A.

32- Vardhman College, Bijnor. (1960) B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com., B.Ed.

Departemnt of Business Administration

M.B.A.

Postgarduate Diploma in Marketing & Sales Management.

Postgraduate Diploma in Personnel management & industrial relation.

Bundelkhand University

Jhansi, Est. 1975

Departments of University

Business Administration. Mathematics, Statistics.

Rural Economics & Cooperation. Library & Information Science.

Constituent College.

MLB Medical College, Jhansi. (1969) MBBS., MD., MS., PG. Diploma.

Affiliated colleges.

1- Agrassen Mahavidyalaya, Mauranipur. Jhansi. (1972) B.A., M.A.

2- Arya Kanya Degree College, Jahnsi. (1962) B.A.,M.A.

3- Atarra Postgraduate College, Atarra. Banda. (1960)

B.A., B.Sc., M.A., M.Sc., B.Ed., M.Ed.

4- BNV College, Rath, Hamirpur. (1960) B.Sc., M.Sc. (Ag)

5- Bipin Behari Degree College, Jhansi. (1959) B.Sc., M.Sc.

6- Bundelkhand Degree College, Jhansi. (1949)

B.A., B.Com., M.A., M.Com., LLB., B.Ed.

7- D V College, Orai. 285001 (1951) B.A., M.A., B.Ed., M.Ed.

8- Govt. College, Hamirpur, (1975) B.A., B.Sc., M.A.

9- Govt. College, Charkhari, Hamirpur. (1978) B.A.

10- Govt. College, Mohaba. Hamirpur. (1982) B.A., B.Com.

11- Govt. Girls College, Banda. (1978) B.A.

12- Jalaun Govt. College, Jalaun. (1981) B.A., B.Com.

13- Kalpi College, Kalpi, Jalaun. (1971) B.A.

14- Mahanati Prannath College, Mau. Banda. (1982) B.A.

15- Lalitpur Govt. College, Lalitpur. (1981) B.Sc., B.Com.

16- Mathura Prasad College, Konch. Jalaun. (1973) B.A.

17- Nehru College, Lalitpur. (1968) B.A.

18- Pt. JLN College, Banda. (1962) B.A., B.Sc., M.A., M.Sc., B.Ed.

19- Sant Tulsi Das Mahavidyalaya, Karvi, (Chitrakoot) B.A.

20- Govt. College, Karvi, Banda. (1988) B.A.

21- Gandhi Degree College, Orai. (1969) B.A., B.Ed., M.A.

22- S. D. College, Orai. (1993) B.A.

23- Jabbad Hussain Abidi Degree College, Orai, (1996-97) B.A.

Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences

Lucknow, Est. 1983

Departments.

Anaesthesiology. Bio Statistics

Cardiology. Cardiovascular Surgery

Endo Medicine. Endo Surgery. Gastro medical.

Gastro Surgery. Genetics. Immunology.

Microbiology. Nephrology. Neurology.

Neurosurgery. Nuclear Medicine. Pathalogy.

Radiology. Radiotherapy. Transfusion medicine.

Urology.

Indian Institute of Management

Lucknow, Est. 1984

Indian Institute of Management, Lucknow was set up in 1984. It is the forth national level Institute of management besides Ahmedabad, Calcutta and Bangalore. It has been engaged on several executive development Programmes, research projects and releted activities.

Faculty Position

Business Policy. Business History.

Social Environment. Economics.

Control & Informantion system. Financial management & International finance.

International Business. Computer Science.

Marketing & International Marketing Management.

Management Accounting. Organisational Behaviour.

Operations management. Operations Research.

Personnal & Industrial Relations. Statistics.

Public system Management. Rural development policy

Management of Public Service Institutions.

Non profit organisations : Such as -

Hospitals, Educational and innovative organisations.

Purvanchal University

Jaunpur, Est. 1987

Department of University

Faculty of Business Management. M.B.A.

Affiliated Colleges

1- Agarsen Kanya Mahavidyalaya, Town Hall, Varanasi. (1973) B.A.,M.A.

2- Agarsen Mahila Mahavidyalaya, Azamgarh. (1966) B.A.,B.Ed.

3- Bajarng Mahavidyalya, Dadar Asram, Ballia. (1971) B.A.

4- Baladeo Degree College, Baragava. Varanasi, (1971) B.A., B.Sc.

5- Bayalasi Degree College, Jalalpur. Jounpur. (1972) B.A.

6- DCSK PG College, Mau Nath Bhanjan. (1966) B.A.,B.Sc.

7- DAV College, Azamgarh. (1957) B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc.

8- Degree College, Dubey Chhapra. Ballia. (1973) B.A.

9- Degree College, Malikpur. Ghazipur. (1973) B.A.,B.Com.

10- Devendra Degree College, Belthra Road. Ballia. (1978) B.A.

11- Dr. Ram Manohar Lohia Degree College, Bhairava Talab. Varansi. (1970) B.A.

12- G B Pant Degree College, Pratap Ganj, Jaunpur. (1964) B.A.

13- G D Binnani Degree College, Mirzapur. (1969) B.A., B.Com., M.Com.

14- G S Degree College, Samodhpur, Jaunpur. (1978) B.A., B.Sc., B.Ed.

15- Gandhi Satabadi Smarak Degree College, Koilsa, Azamgarh. (1970) B.A., M.A.

16- Gandhi Smarak Degree College, Baradah. Azamgarh. (1970) B.A.

17- Ganna krisak Degree College, Takha Shanganj, Jaunpur. (1977) B.A.

18- Govt. Degree College, Dudhi, Sonabhadra. (1973) B.A.

19- Govt. Degree College, Mohammadabad. Gohna. Mau Nath. (1979) B.A.

20- Govt. Degree College, Obara. Sonabhadra. (1982) B.A.,B.Sc., B.Com.

21- Govt. Degree College, Chandauli, Varanasi. (1973) B.A.

22- Govt. Degree College, Dhanapur. Varanasi. (1979) B.A.

23- Gulab Devi Girls Degree College, Ballia. (1979) B.A.

24- H C College, Varanasi, (1951)

B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com., B.Ed., LLB.

25- Hindu Degree College, Jaminiya, Ghazipur, (1957) B.A.,B.Sc.

26- Jagatapur Degree College, Jagatpur. Varanasi. (1970) B.A.

27- Janta Degree College, Ranipur, Mau. B.A.

28- K B College, Mirzapur. (1957) B.A., B.Sc., B.Ed., M.A.

29- KDV Dubahar. Ballia. (1960) B.A.

30- KN Govt. Degree College, Ghayanpur. Varanasi. (1951)

B.A.,B.Sc., B.Com., M.A., M.Com.

31- Kalika Dham Degree College, Sevapuri, Varanasi. (1973) B.A.

32- Kamala Maheshwari Araya Kanya Degree College, Mirzapur. (1968) B.A.

33- Kharadiha Degree College, Kharadiha. Ghazipur. (1973) B.A.

34- Krishna Geeta Rastriya Degree College, Lalganj, Azamgarh. (1973) B.A.

35- Kooba Degree College, Deriyapur. Nevada. Azamgarh. B.A.

36- Kunwar Singh Degree College, Jaunpur. (1971) B.A., B.Sc.

37- LBS Degree College, Mugal Sarai, Varanasi, (1969) B.A.,B.Ed.,M.A.

38- Maharaja Balwant Singh Degree College, Gehangapur. Varanasi, (1973) B.A.

39- Mahanth Rama S.araya Dash Degree College, Bhurkura. Ghazipur. (1972) B.A.

40- Mahatma Gandhi Sati Smarak Degree College, Garuva. Makashudapur. Ghazipur. (1972) B.A.

41- Marayada Purusotama Degree College, Ratanpura. Mau. (1972) B.A.

42- Mariyahu Degree College, Jaunpur. (1969) B.A.

43- Mathura Degree College, Rasana, Ballia. (1972) B.A.

44- Nagrik Degree College, Jamuhai, Jaunpur. (1970) B.A.

45- Postgraduate College, Ghazipur. (1957) B.A.,B.Sc.,B.Ed.

46- RSKD Degree College, Jaunpur. (1959) B.A.,B.Sc.,B.Ed.

47- Raja Harpal Singh Degree College, Singramau, Jounpur. (1965) B.A., B.Sc., B.Ed.

48- Rajakiya Degree College, Chaukiya, Varanasi. (1978) B.A.

49- Rajakiya Mahila Degree College, Ghazipur. (1977) B.A., B.Sc. (Ag)

50- Rajakiya Degree College, Jakhini, Varanasi. (1972) B.A.,B.Sc.(Ag)

51- Rajakiya Degree College, Shaidpur. Ghazipur. (1988) B.A.

52- Rastriya Degree College, Jamuhai, Jounpur. (1972) B.A., B.Sc.

53- SC College, Ballia. (1947) B.A., B.Sc., B.Ed., M.A., M.Sc.

54- SDJ College, Chadeshwar. Azamgarh. (1958)
B.A., B.Sc., B.Sc. (Ag), B.Ed., M.Sc. (Ag)

55- SGR PG College, Dobhi, Jaunpur. (1964) B.A., B.Sc., B.Com., B.Ed., M.Sc.

56- SN College, Azamgarh. (1958)
B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc., M.Com., B.Ed., LLB.

57- Sahakari Degree College, Mehrawa. Jaunpur. (1970) B.A.

58- Sakaldiha Degree College, Varanasi, (1965) B.A., B.Ed.

59- Saltanat Bahadur Degree College, Badalapur. Jaunpur. (1973) B.A.

60- Samata Degree College, Sadat. Ghazipur. (1978) B.A.

61- Sarbodal Degree College, Ghoshi, Azamgarh. (1971) B.A.

62- Swami Sahajanand Saraswati vidyapeeth Degree College, Ghazipur. B.A.

63- Shiva Degree College, Terahi, Captanganj, Azamgarh. (1965) B.A.

64- Sri Gandhi Degree College, Maltari, Azamgarh. (1965) B.A., M.A., B.Ed.

65- Sri MMTD College, Ballia. (1955)

B.A., B.Sc., B.Com., B.Sc.(Ag), B.Ed., M.A., M.Sc., M.Sc.(Ag).

66- Sudristhi Baba Degree College, Sudrishthpuri, Ballia. (1972) B.A.

67- TD College, Jaunpur. (1948)

B.A., B.Sc., B.Com., B.Sc. (Ag), M.A., M.Sc., M.Com., B.Ed., LLB.

68- U P Singh College, Varanasi. (1909)

B.A., B.Sc., B.Com., B.Sc.(Ag), M.A., M.Sc., M.Com., M.Sc. (Ag), B.Ed.

69- School of Management Sciences. Varanasi. B.B.A.